लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित सस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र
Tenth Session]

5th Lok Sabha

[खंड 36 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XXXVI contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय-सूची CONTENTS

अंक 18, शुक्रवार, 15 मार्च 1974/24 फाल्गुन, 1895 (शक)
No. 18, Friday, March 15, 1974/Phalguna 24, 1895 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
321.	अशोधित तेल की कीमत में वृद्धि होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से धन निकालना।	Drawal on International Monetary Fund due to increase in prices of Crude Oil	1-4
323.	मानकीकृत लट्ठे के उत्पादन में वृद्धि	Increase in Production of Standardised Long Cloth	4-7
324.	अखवारी कागज का आयात	Import of Newsprint	7-11
328.	मुद्रा सप्लाई के संबंध में राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् द्वारा किया गया अध्ययन	Study conducted by NCAER on Money Supply	11-12
329.	इंडियन एयरलाइंस में फालतू विमान चालक	Surplus Pilots in Indian Airlines ..	12-13
330.	चाय अधिनियम में संशोधन	Amendment of Tea Act	13-15
336.	इंडियन एयरलाइंस का एवरो विमानों को बेचने का निर्णय	Decision on Disposal of Avro Aircraft by Indian Airlines	15-16
338.	खनिज धातु व्यापार निगम द्वारा एल्यूमीनियम का आयात	Import of Aluminium by MMTC	16

प्रश्नों के लिखित उत्तर — WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

322.	सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के होटलों में उपलब्ध बिस्तरों की संख्या	Beds available in Public and Private Sector Hotels	17
325.	सोमनाथ में शिवर-स्थल स्थापित करने की योजना	Scheme for putting up Camping Sites at Somnath	17-18

किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० सख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
326.	भारत और युगोस्लाविया के बीच व्यापार में वृद्धि	Increase in Trade between India and Yugoslavia	18
327.	विमान-यात्रा सुरक्षा बोर्ड की स्थापना	Setting up of an Air Safety Board ..	18-19
331.	बम्बई में बेलड पियर पर जब्त शुदा वस्तुओं का जमा हो जाना	Accumulation of confiscated Articles at Ballard Pier, Bombay	19
332.	फ्रांस के साथ ऋण करार	Agreement for Loan from France ..	19-20
333.	शिमला में हवाई अड्डे का निर्माण	Construction of Aerodrome at Simla	20
334.	विश्व व्यापार में भारत के निर्यात में गिरावट	Decline in India's share of Export in World Trade	20-21
335.	विदेशी विमान कम्पनियों द्वारा भारतीय हवाई अड्डों से ईंधन लेना	Fuel Uplift from Indian Airports by Foreign Airlines	21
337.	इंडियन एयरलाइंस में छटनी किये गये नैमित्तिक श्रमिकों की संख्या	Number of Casual Labourers retrenched in Indian Airlines	22
339.	यूरोपीय साझाबाजार के देशों के साथ व्यापार में वृद्धि	Increase in Trade with ECM Countries	22-23
340.	उड़ान भरने के स्तरों में विमान चालकों की योग्यता का मूल्यांकन करने पर व्यय की गई धनराशि	Amount spent on assessing the Proficiency of the Pilots in Flying Standards	23

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.			
3180.	डाक-घर बचत बैंक लेखों के जमाकर्ताओं को ब्याज की अदायगी	Payment of Interest to Account Holders of P. O. Savings Banks Accounts	23-24
3181.	मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के बारे में कृषि पुनर्वित निगम की योजना	Scheme of Agriculture Refinance Corporation re: Expansion of Irrigation Facilities in Raisen District of Madhya Pradesh	24
3182.	उत्तर प्रदेश हथकरघा उद्योग में बेरोजगारी	Unemployment in U. P. Handloom Industry	24
3183.	'कोसे' कपड़े का विकास	Development of Kosa Cloth ..	24
3184.	नोटों की छपाई में वृद्धि	Increase in Printing of Notes	25
3185.	50 रुपये मूल्य के नये नोट जारी करना	Introduction of New Notes of Rs. 50 denomination	25-26
3186.	इंडियन एयरलाइंस में कर्मचारियों के वेतनमान	Pay scales of Employees in Indian Airlines	26
3187.	वर्ष 1973-74 के दौरान विदेशों में पर्यटन प्रचार अभियान पर खर्च की गई राशि	Amount spent on Tourism Publicity Campaign abroad during 1973-74 ..	26
3188.	इंडियन एयरलाइंस को एच० एस०-748 विमान की डिलीवरी	Delivery of HS-748 Aircraft to Indian Airlines	27

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3189.	पूर्वी जर्मनी को निर्यात	Exports to East Germany	27
3190.	कनाडा से आयात का मूल्य	Value of Imports from Canada ..	28
3191.	सिंडीकेट बैंक की आंध्र प्रदेश में बंगनापल्ले स्थित शाखा में चोरी	Theft in Banganappalle Branch of Syndicate Bank, Andhra Pradesh ..	28
3192.	प्राकृतिक रबड़ उत्पादक देशों का संघ	Association of Natural Rubber producing Countries	28
3193.	मद्रास हवाई अड्डे के विस्तार की योजना	Scheme to expand Madras Airport ..	28
3194.	पांचवीं योजना के दौरान तमिलनाडु में पर्यटन केन्द्रों का विकास	Development of Tourist Centres in Tamil Nadu during Fifth Plan ..	29
3196.	रियायती दर ब्याज योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश को दिया गया ऋण	Amount advanced to Madhya Pradesh under Preferential Rates of Interest Scheme	29-30
3197.	बैंकों द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को दी गई अग्रिम राशि	Bank Advances made to Priority Sector	30
3198.	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को देय मकान किराया भत्ता	House Rent Allowance payable to Central Government Employees ..	30-31
3199.	विदेशी कम्पनियों का विस्तार	Expansion of Foreign Companies	32
3200.	बम्बई में कपड़ा मिल कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के कारण हानि	Loss due to Strike by Textile Millmen in Bombay	33
3201.	उर्वरक के आयात के लिये करार	Agreement for Import of Fertilizers ..	33-34
3202.	सूती वस्त्र उद्योग के विस्तार के लिए लाइसेंस नीति	Licensing Policy for expansion of Cotton Textile Industry	34
3203.	विदेशी स्वामित्व की कम्पनियों में भारत का योगदान	Indian participation in Foreign owned Companies	34-35
3204.	उन देशों के नाम जिनके साथ भारत में अखबारी कागज की कमी के प्रश्न पर विचार किया गया	Names of the Countries with whom the question of Newsprint Shortage in India was taken up	35
3205.	कपड़ा मिलों के उत्पादन पर तेल संकट का प्रभाव	Effect of Oil Crisis on production of Textile Mills	35
3206.	राज्य सरकारों से सरकारी उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारी	Deputationists from State Governments to Public Enterprises ..	36
3207.	बंगला देश को कोयले की सप्लाई	Coal Supply to Bangladesh	36
3208.	अखबारी कागज के आयात के लिये राज्य व्यापार निगम तथा कनाडा के बीच करार	Agreement between STC and Canada for Import of Newsprint	37

अता० प्र० सं० U S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3209.	भारत के नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक द्वारा महालेखाकारों के पदों की रचना	Creation of posts of Accountant Generals by Comptroller and Auditor General of India	37
3210.	संयुक्त परियोजना के विकास के लिए ब्रिटेन से पुर्जों की खरीद	Purchase of Components from Britain for Development of United Project	37-38
3211.	वित्त मंत्री से यूनियनों के प्रतिनिधियों की भेंट	Meeting of Representatives of Unions with Finance Minister	38
3212.	नायलोन तथा फिलामेंट धागों का उचित वितरण	Fair Distribution of Nylon and Filament Yarn	38-40
3213.	आंध्र प्रदेश में मार्केट यार्ड-योजना के लिये विश्व बैंक से ऋण	World Bank loan for Market Yard Scheme in Andhra Pradesh ..	40
3214.	अकाल राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत केरल को केन्द्रीय सहायता	Central Aid to Kerala under Famine Relief Programme	40
3215.	रूस से यूरिया का आयात	Import of Urea from U.S.S.R. ..	40-41
3216.	नौवहन सुविधाओं के अभाव में चमड़ा निर्यात में कमी	Fail in Leather Exports due to lack of Shipping facilities	41
3217.	मद्रास पत्तन पर अखबारी कागज को उतारने में विलंब	Delay in Unloading of Newsprint at Madras Harbour	41
3218.	कृषि कार्यक्रम की गति तेज करने के लिये धन के भुगतान के बारे में कृषि पुनर्वित्त निगम की योजना	Scheme of ARC Re : Disbursement of Money to increase the Pace of Agricultural Programme	41-42
3219.	तिलहनों का निर्यात	Export of Oil Seeds	42
3220.	चौथी योजना में वैगनों के निर्यात के लक्ष्य	Target for Export of Wagons during Fourth Plan	42-43
3221.	पांचवीं योजना के पहले वर्ष में रेलवे वैगनों के निर्यात का लक्ष्य	Target of Export of Railway Wagons for 1st Year of Fifth Plan	43
3222.	भारतीय पटसन उद्योग के पटसन उत्पादों की सप्लाई की मांग करने वाली विदेशी कम्पनियों के नाम	Names of Foreign Countries who have asked Indian Jute Industry for Supply of Jute Goods	43
3223.	ऋणों पर प्रतिबंध के फलस्वरूप बम्बई की सूती कपड़ा मिलों में तीसरी पाली का समाप्त किया जाना	Discontinuation of Third Shift in the Textile Mills in Bombay as a result of Imposition of Credit Squeeze	44
3224.	सरकारी क्षेत्र के कार्यकरण और ऊंचे पदों पर कर्मचारियों की भर्ती संबंधी नीति के संबंध में योजना आयोग का असंतुष्ट होना	Planning Commission's disappointment at the performance of Public Sector and the Policy of Personnel recruitment to higher posts ..	44-45

अता० प्र० सं० U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3225.	कम्पनियों को तदर्थ लाइसेंस जारी किया जाना।	Issue of *ad hoc* licence to Companies	45
3226.	सोवियत संघ से अखबारी कागज का आयात	Import of Newsprint from USSR ..	45
3227.	सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की लाइसेंस क्षमता का उपयोग	Utilisation of Licenced Capacities of public Sector Enterprises	46
3328.	डाकघर बचत बैंक खाता इनामी योजना	Post Office Savings Bank Deposit prize Scheme	46
3229.	वर्ष 1973-74 में सर्वाधिक शीत-ग्रस्त होने वाले स्थानों के नाम	Names of Places which Experienced Serverest Cold during Winter of 1973-74	47
3230.	50 हजार रुपये से अधिक आय वाले आयकर दाता	Income Tax payees having Income of above Rs. 50 thousands	47
3231.	डाकघर बचत बैंक योजना के अधीन प्राप्त हुई जमा राशि	Deposits received under P.O. Savings Bank Prize Scheme	47-48
3232.	निर्यात की शर्त पर फर्मों को तदर्थ लाइसस जारी करना	Issue of *adhoc* licence to firms on the condition of export ..	48
3233.	सूती कपड़ा मिलों की स्थापना	Setting up of Cotton Textile Mills ..	48
3234.	पांचवीं योजना के लिये विदेशी सहायता	Foreign Aid for Fifth plan ..	48
3235.	पांचवीं योजना के बाद सूती कपड़े की मांग	Requirement of Cotton Cloth after Fifth Plan	48-49
3236.	इलैक्ट्रोनिक सामान के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange earned on account of export of Electronic Goods	49-50
3237.	चौथी योजना अवधि में आयातित अखबारी कागज की मात्रा	Amount of Newsprint imported during the Fourth Plan	50
3238.	एशियाई वाणिज्य तथा उद्योग मंडल महासंघ का सम्मेलन	Conference of Confederation of Asian Chamber of Commerce and Industry	51-52
3239.	हथकरघा उद्योग की समस्यायें	Problem of Handloom Industry ..	52-54
3240.	भारतीय फिल्मों की पाकिस्तान में तस्करी	Smuggling of Indian Films into Pakistan	54-55
3241.	टेलीविजन सेटों का निर्यात	Export of TV Sets	55
3242	कटवा (पश्चिम बंगाल) में पटसन मिलें स्थापित करने का प्रस्ताव	Proposal to set up Jute Mills in Katwa (West Bangal)	55
3243.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में रिक्त पड़े उच्च पद	Top posts lying vacant in public Sector undertaking	55-56

अता० प्र० सं० U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3244.	तैयार चमड़े और चमड़े से बने सामान का निर्यात	Export of finished Leather and Leather Goods	56
3245.	चमड़ा विकास एजेंसी	Lether Development Agency ..	56-57
3246.	आवश्यक वस्तुओं की कृत्रिम कमी पैदा करने के लिए जमाखोरों के विरुद्ध की गई कार्यवाही	Steps taken against Hoarders for creating artificial scarcity in Essential Commodities	57
3247.	आल इंडिया कान्फेडरेशन आफ गवर्नमेंट आफिसर्स एसोसियेशन द्वारा राष्ट्रीय मजूरी नीति तथा प्रशासन में कर्मचारियों के भाग लेने की मांग	Demand by All India Confederation of Central Government Officers' Association for a National Wage Policy and Workers participation in Administration	57-58
3248.	कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा बंगलादेश कृषि बैंक को सहायता	Help to Bangladesh Krishi Bank by Agricultural Refinance Corporation	58
3249.	नौवहन सुविधाओं की कमी के कारण वैगनों के निर्यात में बाधा	Lack of Shipping facilities hampering export of Wagons	58
3250.	नगरों का वर्गीकरण	Classification of cities	58-59
3251.	कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र	Kandla Free Trade Zone	59
3252.	अयस्क उत्पादन करने वाले देशों का संगठन	Organisation of Ore Producing countries	59
3253.	रबड़-प्रधान उद्योगों को कच्चे रबड़ की सप्लाई	Supply of raw rubber to rubber oriented Industries	59-60
3254.	सिंचाई परियोजनाओं के लिये विदेशी सहायता	Foreign assistance for irrigation projects	60-61
3255.	पश्चिम बंगाल में सूती कपड़ा मिलों को नियंत्रण में लेने के बाद उनमें उत्पादन	Production in textile Mills of West Bengal after take over ..	61
3256.	आस्ट्रेलिया के व्यापारिक दल की भारत यात्रा	Visit by Trade team from Australia	61
3257.	अपरिकृत पटसन का व्यापार अपने नियंत्रण में लेना	Take over of raw jute trade ..	61-62
3258.	श्रीलंका के साथ संयुक्त उपक्रम	Joint venture with Sri Lanka ..	62
3259.	भारतीय उद्योगों में विदेशी साम्य पूंजी	Foreign Equity participation in Indian industries	62
3260.	ऋण प्रतिबंधों में उद्योगों को छूट देने के बारे में कर्नाटक सरकार द्वारा किया गया अनुरोध	Request made by Karnataka Government in regard to exemption of Industries from credit restriction ..	62-63
3261.	वर्ष 1972-73 में विदेशों में राज्य व्यापार निगम के कार्यालय स्थापित करना	Offices set up by STC in foreign countries during 1972-73	63

अता० प्र० सं० U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3262.	बिजली के समान के निर्यात विषयक समिति का प्रतिवेदन	Report of the Committee on export of electrical goods	63
3263.	अहमदाबाद टैक्सटाइल्स मिल्स द्वारा प्रोसेसिंग विभाग बंद किये जाने से प्रभावित श्रमिक	Workers affected by closure of processing departments by Ahmedabad textile mills	63-64
3264.	इण्डस्ट्रियल प्लांटस लिमिटेड को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा दी गई सहायता	Assistance given by Industrial Development Bank of India to Industrial Plants Limited	64-65
3265.	प्रशुल्क आयोग द्वारा आटोमोबाइल एन्सीलियरी उद्योग का पुनरीक्षण	Review of Automobile Industry by Tariff Commission ..	65
3266.	लौह अयस्क का निर्यात	Export of Iron Ore	65-66
3267.	ऋण पर प्रतिबंध और कड़ा करने के बारे में रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा निदेश जारी किया जाना	Issue of Directives by RBI Re : further Credit squeeze	66-67
3268.	जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों द्वारा एक दिन की सांकेतिक हड़ताल	Observance of one day Token Strike by Employees of LIC ..	68
3269.	तेल उत्पादक देशों में जूट कारखाने स्थापित करने के लिए की गई कार्यवाही	Steps to establish Jute Factories in Oil producing countries	68
3270.	सरकारी उपक्रमों का कार्यकरण	Functioning of Public Undertakings..	68-69
3271.	एक निर्यात/आयात बैंक की स्थापना	Setting up of an Export/Import Bank	69
3272.	तेल संकट के कारण विश्व-बैंक से ऋण	Loan from World Bank due to Oil Crisis	70
3273.	संकट-ग्रस्त चाय बागानों का अधिग्रहण	Taking over of Sick Tea Gardens ..	70
3274.	युवक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये कार्यवाही करना	Steps to attract Youth Tourists	70
3275.	पश्चिम एशिया के देशों में भारतीय बैंकों की शाखाएं खोलना	Opening of Branch offices of Indian Banks in West Asia Region ..	71
3277.	उत्पादन-अभिमुख व्यापार अभियान	Production oriented Trade Movement	71-72
3278.	चाय की लाभप्रद कीमतें प्राप्त करने के लिये भारत और श्रीलंका द्वारा साझी नीति का निर्धारण	Evolution of Common Strategy by India and Sri Lanka for Remunerative Tea prices	72
3279.	एयर इंडिया का दिल्ली से निकलने वाले अंग्रेजी दैनिक से समझौता	Air India's Agreement with a Delhi based English Daily	72-73

अता० प्र० सं० U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3280.	पश्चिम बंगाल बंद के दिनों में इंडियन एयरलाइंस द्वारा न्यूनतम विमान सेवाओं की व्यवस्था करना	Skeleton Services arranged by Indian Airlines on West Bengal Band days	73-74
3281.	इंडियन एयरलाइंस द्वारा कारवेलस तथा बोइंग-737 के पट्टे पर लेने के लिये विदेशी मुद्रा के रूप में दी गई धन राशि	Amount paid in Foreign Exchange for Lease of Carevelles and Boeing-737 by Indian Airlines	74
3282.	स्टेट बैंक आफ इंडिया और राष्ट्रीयकृत बैंकों के लाभ और हानि के लेखे	Profits and loss account of State Bank of India	74
3283.	सुपारी और लौंग के आयात पर राज्य व्यापार निगम को हुआ घाटा	Loss suffered by STC in Handling Imports of betelnut and cloves ..	75
3284.	भारत और उत्तर कोरिया के बीच व्यापार समझौता	Trade Pact between India and North Korea	75
3285.	फारस की खाड़ी के देशों के लिये नई निर्यात नीति	New Export Strategy for Gulf States :	75-76
3286.	उत्तर कोरिया से व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल की भारत यात्रा	Visit by North Korean Trade Delegation	76-77
3287.	दोहरे कर से बचने के लिये भारत और बेल्जियम के बीच समझौता	Pact between India and Belgium to avoid Double Taxation	77
3288.	विशाखापत्तनम तथा विजयवाड़ा का दर्जा बढ़ाया जाना	Upgradation of Visakhapatnam and Vijayawada	77-78
3289.	इंडियन एयरलाइंस में लागू किये गये बचत उपाय	Ecomomy Measures introduced in Indian Airlines	78
3290.	एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन द्वारा हाल ही में भाड़ा बढ़ाये जाने का प्रभाव	Effect of Recent Increase in Fares by Air India and IAC	79
3291.	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा फार्मों की छपाई	Printing of Forms by Nationalised Banks	79-80
3292.	राज्य व्यापार निगम द्वारा बनाई गई निर्यात सहायता योजना	Export Assistance Scheme drawn up by STC	80-81
3293.	हिमाचल प्रदेश में भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा शुरू की गई परियोजनाएं	Projects undertaken by ITDC in Himachal Pradesh	81
3294.	आयात लाइसेंसों की मंजूरी के लिये आवेदन-पत्र	Applications for Grant of Import Licences	81-82

अता० प्र० सं० U.S.Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3295.	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कृषि प्रयोजन के लिये ऋण दिया जाना	Advancing of Loans by Nationalised Banks for Agricultural purposes ..	82-83
3296.	वर्तमान विमान देख-रखाव 'शैड्यूल' का पुनरीक्षण करने का प्रस्ताव	Proposal to Revise present Aircraft Maintenance Schedules ..	83
3297.	सरकारी क्षेत्रीय प्रतिष्ठानों के मुख्य कार्यकारियों के चयन के लिये निकाय	Body for selection of Chief Executives of public Sector Enterprises ..	83-84
3298.	चाय के मूल्यों के संबंध में श्रीलंका के साथ हुए समझौते की व्यवहारिकता	Workability of pact with Sri Lanka on tea prices	84
3299.	इंडियन एयरलाइंस की अंतर्देशीय सेवा चलाने से हुआ लाभ	Profit on operation of Indian Airlines domestic Service	84-85
3300.	रसायनिक निर्यातकर्ताओं को दी जाने वाली आयात पुन: पूर्ति की दरों तथा नकद सहायता के पुनरीक्षण में असाधारण विलंब	Inordinate delay in revision of rates of import replenishment and cash assistance to chemical exporters ..	85
3301.	केन्दु पत्ते के निर्यात में उड़ीसा सरकार को हुई हानि	Loss suffered by Orissa Government in export of Kendu Leaf transsaction ?	85
3302.	गत दो वर्षों में सरकारी क्षेत्र के यूनिटों द्वारा निर्यात	Exports by Public Sector Units during the last two years	85
3303.	तेल उत्पादक देशों को निर्यात	Exports to oil producing countries ..	86
3304.	दीनापुर छावनी तथा खगोल में काम कर रहे कर्मचारियों को मकान-किराया भत्ता तथा प्रतिपूर्ति भत्ता	HRA and City Compensatory Allowance to employees working at Dinapore Cantonment and Khagual	86-87
3305.	बिहार में बेरोजगार तकनीशयनों तथा शिक्षित व्यक्तियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋणों का दिया जाना	Advancing loans by nationalised banks to unemployed technicians and educated persons in Bihar	87
3306.	रक्षा लेखा नियंत्रक कार्यालय, पटना के लिए भवन का निर्माण	Construction of building for the office of CDA Patna	88
3307.	रक्षा लेखा नियंत्रक, पटना से कार्य का विकेन्द्रीकरण	Decentralisation of works from Controller of Defence Accounts, Patna	88
3308.	निर्यात व्यापार का पुनरीक्षण	Review of Export Trade ..	88-89
3309.	तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिये भारत-फ्रांस आयोग की स्थापना	Setting up of Indo-French Commission for Technical and Economic Cooperation	89
3310.	वर्ष 1972-73 में तस्करी के सामान का पकड़ा जाना	Seizure of smuggled goods in 1972-73	89

अता० प्र० सं० U S.Q.Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3311.	राज्य व्यापार निगम द्वारा अखबारी कागज की सप्लाई	Supply of newsprint by STC ..	90
3312.	मध्यम तथा निम्न वर्गीय पर्यटकों को सुविधाएं	Facilities for middle and low income tourists	90
3313.	रुई के मूल्य में वृद्धि	Rise in price of cotton.. ..	90-91
3314.	जीवन बीमा निगम का लाभ	Profits of LIC	91
3315.	उर्वरकों का आयात करने हेतु खनिज तथा धातु व्यापार निगम का सहायक निगम स्थापित करने का प्रस्ताव	Proposal to establish a subsidiary MMTC for handling fertiliser imports	91
3316.	विमान-पेट्रोल की कमी के कारण इंडियन एयरलाइंस द्वारा उड़ानों की संख्या में कमी किया जाना	Reduction in the number of flights by Indian Airlines due to shortage of Aviation fuel	91-92
3317.	विदेशी शराब का आयात	Import of Foreign liquor ..	92-93
3318.	कूच-बिहार जिले में तम्बाकू व्यापारी	Tobacco traders in Cooch Bihar District	93-94
3319.	कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली और मद्रास हवाई अड्डों से इंडियन एयरलाइंस तथा एयर इंडिया के विमानों द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या	Number of passengers carried by Indian Airlines and Air India at Calcutta, Bombay, Delhi and Madras Airports	94
3320.	कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई और मद्रास से लंदन तक रियायती किराये	Economy class fare to London from Calcutta, Delhi Bombay and Madras	94-95
3321.	कलकत्ता-कूच बिहार के बीच इंडियन एयरलाइंस द्वारा सेवा पुनः चालू किया जाना	Restoration of services between Calcutta, Cooch Bihar by Indian Airlines	95
3322.	मात्र विदेशी पर्यटकों के लिये विमान सेवायें चलाने का प्रस्ताव	Proposal to run Air service exclusively for foreign tourists	95-96
3323.	कुवैत के साथ दीर्घकालीन व्यापार करार	Long Term trade agreement with Kuwait	96
3324.	फिल्म उद्योग में कालाधन लगाया जाना	Flow of black money in film Industry	96-97
3325.	जीवन बीमा निगम करार पर हस्ताक्षर करने में विलंब	Delay in signing the LIC agreement	97
3326.	इंडियन एयरलाइंस में तालाबंदी के दौरान हुई हानि तथा रद्द की गई उड़ानें	Loss suffered and flights cancelled during lock out in Indian Airlines ..	97

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3327.	एकमात्र निर्यात निरीक्षण प्राधिकरण की स्थापना	Setting up of a single Export Inspection Authority	98
3328.	विदेशी मुद्राओं की कीमतों में अस्थिरता का मुकाबला करने संबंधी योजना	Seheme to deal with fluctuation in values of Foreign Currencies ..	98
3329.	आयकर की बकाया राशि को घटाने के लिए इनाम की योजना	Reward scheme for reducing Arrears of Income Tax	98-99
3330.	देश में विमान सेवायें बढ़ाने का प्रस्ताव	Proposal to extend Air Services in the country	99-100
3331.	पेंशन नियमों के पुनरीक्षण के बारे में पेंशनभोगी संगठनों द्वारा की गई मांग	Demand made by Pensioners Organisation re : Revision of Pension Rules	100-101
3332.	कम्पनियों को पूंजी लेने की अनुमति	Permission to companies to raise Capital	101-102
3333.	भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त व्यापार आयोग का गठित किया जाना	Setting up of a Joint Trade Commission by India and France	102
3334.	स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा आयातित कारों की खरीद	Purchase of Imported Cars by State Bank of India	102-103
3335.	उत्तर बंगाल में चाय बागानों का सरकारीकरण	Taking over of Tea Gardens in North Bengal	103
3336.	बंगला देश के साथ व्यापार समझौता	Trade Agreement with Bangladesh ..	103
3337.	भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के बीच विषमता	Disparity between IAS and other Class I Officers of Government ..	103
3338.	कानपुर में हवाई अड्डे के निर्माण का निर्णय	Decision on construction of Airport in Kanpur	104
3339.	पश्चिम बंगाल में पर्यटन केन्द्र विकसित करने की योजना	Plan to develop Tourist spots in West Bengal	104
3340.	जले हुए करेन्सी नोटों के लिए क्षतिपूर्ति	Compensation for Burnt Corrency Notes	104-105
3341.	राजस्थान को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Rajasthan ..	105
3342.	चालू फसल के दौरान भारतीय पटसन निगम द्वारा खरीदा गया पटसन	Jute Purchased by JCI during the Current Harvest	105
3343.	पश्चिम बंगाल के हथकरघा उद्योग में संकट	Crisis in Handloom Industry of West Bengal	106
3344.	बाढ़ राहत कार्यों के लिए पश्चिम बंगाल को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to West Bengal for Flood Relief Works	106

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3345.	कलकत्ता हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाये रखने के लिये कार्यवाही	Steps to preserve Calcutta Airport as an International Airport ..	107
3346.	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता	Dearness Allowance to Central Government Employees	107-108
3347.	पोलैंड से यूरिया तथा अमोनियम फास्फेट का आयात	Import of Urea and Ammonium Phosphate from Poland	108
3348.	चाय व्यापारियों पर आर्थिक भार	Burden on Tea Traders	108-109
3349.	अखबारी कागज का आयात	Imports of Newsprint ..	109
3350.	नारियल जटा तथा नारियल जटा उत्पादनों के निर्यात में कमी	Decline in the Export of Coir and Coir Products	109-110
3351.	किसानों को आर्थिक सहायता देने के संबंध में स्टेट बैंक आफ इंडिया, कुट्टानाड की विशेष योजना	Special Seheme of State Bank of India, Kuttanad, Kerala regarding Financial Assistance to Farmers ..	110
3352.	इंजीनियरों एवं डाक्टरों को सवारी-भत्ता	Conveyance Allowance for Engineers and Doctors	110-111
3353.	मोटर कार सवारी भत्ता	Motor Car Conveyance Allowance ..	111
3354.	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संबंधी सुधार	International Monetary Reforms	111
3355.	जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के मजदूर संघों के साथ हुई बातचीत	Negotiations held with Trade Unions of Employees of LIC	111-112
3356.	काले धन को रोकने के लिए कार्यवाही	Steps to check Black Money	113-114
3357.	छोटे साबुन बनाने वालों को सप्लाई करने हेतु राज्य व्यापार निगम के साथ हुए ठेके के अंतर्गत बकरे की चर्बी/ताड़ के तेल से ग्लिसिरीन निकाला जाना	Glycerine Extraction from Mutton Tallow/Palm Oil under Contract with STC for supply to Small Soap Manufacturers	115
3358.	छोटे साबुन निर्माताओं को राज्य व्यापार निगम द्वारा सप्लाई किया गया कच्चा माल	Raw Material supplied by STC to Small Scale Soap Manufacturers ..	115-116
3359.	बुनकरों और कतइयों को विस्कोस फिलामेंट यार्न का वितरण	Distribution of Viscose Filament Yarn to Weavers and Spinners ..	116-117
3360.	विदेशी पर्यटकों को भारत में दोबारा आने की पेशकश	Offer to Foreign Tourists to visit India	117
3361.	पांचवीं योजना के दौरान केरल में होटलों के निर्माण का प्रस्ताव	Proposal to construct Hotels in Kerala during Fifth Plan	118

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3362.	रबड़ बोर्ड के कर्मचारियों को बोनस की अदायगी	Payment of Bounus to Rubber Board Employees	118
3363.	प्राकृतिक रबड़ के निर्यात में वृद्धि	Increase in Natural Rubber Export..	118
3364.	रिज़र्व बैंक की ऋण नीति का पुनरीक्षण	Revision in Reserve Bank's Credit Policy ..	119
3365.	अन्य देशों को मूंगफली का निर्यात	Export of Groundnut to other countries	119
3366.	वर्ष 1972-73 में पकड़ा गया तस्करी का सामान	Smuggled Goods seized in 1972-1973	119-120
3367.	त्रिपुरा के बेरोजगार स्नातकों को ऋण दिया जाना	Advancing of loans to Unemployed Graduates in Tripura	120
3368.	जापान द्वारा विकासशील देशों को दी जाने वाली सहायता पर रोक	Curbs on Japanese Aid to Developing Countries	120-121
3369.	गुजरात में बैंकिंग कार्य	Banking operations in Gujarat	121
3370.	इंडियन एयरलाइंस से तालाबंदी हटाने का प्रस्ताव	Proposal to lift lock out in Indian Airlines	121-122
3371.	हुबली-धारवाड़ निगम का दर्जा बढ़ाया जाना	Upgradation of Hubli Dharwar Corporation	122
3372.	मुजफ्फरनगर में एक प्रेस से जाली करेन्सी नोट पकड़ा जाना	Seizure of Fake Currency Notes from a Press in Muzaffarnagar ..	122-123
3373.	कोचीन हवाई अड्डे के स्थापना स्थल का चयन	Selection of Site for Cochin Airport	123
3374.	गत 6 मास में कच्चे काजू का आयात	Import of Raw Cashew during last six months	123
3375.	त्रिपुरा में छोटे किसानों और छोटे उद्योगपतियों को दिए गए ऋण	Loans given to Small Farmers and small Industrialists in Tripura ..	123-124
3376.	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों के किसानों को दिए गए ऋण	Loans advanced by Nationalised Banks to Farmers of Flood Affected Areas	124-125
3377.	इंडियन एयरलाइन्स द्वारा कोचीन में भवन का निर्माण	Construction of Building at Cochin by Indian Airlines	125
3378.	रेयन उद्योग के वितरण की नीति	Distribution Policy of Rayon yarn ..	125-126
अविलंबनीय लोक महत्व के मामले की ओर ध्यान दिलाना		Calling Attention to a Matter of Urgent Public Importance	126-130
बिजलीघरों को कोयले की सप्लाई की गंभीर स्थिति का समाचार		Reported critical supply position of Coal to Power Houses	126-130

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्री वसन्त साठे	Syri Vasant Sathe ..	126
श्री के० डी० मालवीय	Shri K. D. Malaviya	126-130
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	Re : Motion for Adjournment ..	130-131
'पेट्रीयाट' दिल्ली के संपादक के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privilege against the Editor of the Patriot, Delhi ..	131
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	Papers Laid on the Table ..	132-133
राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha	134
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee ..	134
98वाँ प्रतिवेदन	Ninety-eighth Report	134
सूती कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा सूती धागे के निर्यात पर लगाई गई लैवी के बारे में वक्तव्य	Statement re: Levy imposed by Cotton Textiles Export promotion Council on Yarn exports	134-135
प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय	Prof. D. P. Chattopadhyaya	134-135
सभा का कार्य	Business of the House ..	136-137
शहडोल, मध्य प्रदेश स्थित कोयला खान प्राधिकार लिमिटेड के पश्चिमी डिविजन के बुरहार संख्या एक में हुई दुर्घटना के फलस्वरूप सात कोयला-खान कर्मकारों की मृत्यु के बारे में वक्तव्य	Statement re: Death of seven coal miners in an accident at Burhar No. 1 Mines of Coal Mines Authority Ltd. in Shahdol, M. P.	138
श्री के० डी० मालवीय	Shri K. D. Malaviya	138
सामान्य बजट, 1974-75—सामान्य चर्चा	General Budget, 1974-75—General Discussion	138-145
श्री मुल्की राज सैनी	Shri Mulki Raj Saini	138-139
श्री अटल बिहारी बाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee ..	139-141
श्री नाथू राम मिर्धा	Shri Nathu Ram Mirdha	141
श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी	Shri Swami Brahmanandji	141
श्री जी० विश्वनाथन	Shri G. Viswanathan	142-143
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy ..	143
श्री के० बालकृष्णन	Shri K. Balakrishnan ..	144
श्री सतपाल कपूर	Shri Sat Pal Kapur ..	144-145
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—37वां प्रतिवेदन	Committee on Private Members' Bills and Resolutions—37th Report ..	145

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनावों के बारे में संकल्प	Resolution re : Free and Fair Elections	.. 145—155
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	.. 145—147
श्री नरसिंह नारायण पाण्डे	Shri Narsingh Narain Pandey	.. 147—148
श्री पी० के० देव	Shri P. K. Deo	.. 148—149
श्री बी० आर० शुक्ल	Shri B. R. Shukla	.. 149—150
श्री मूल चन्द डागा	Shri M. C. Daga ..	.. 150
श्री सी० एच० मोहम्मद कोया	Shri C. H. Mohamed Koya ..	.. 150
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	.. 151
श्री नवल किशोर शर्मा	Shri Nawal Kishore Sharma	.. 151
श्री सुरेन्द्र महन्ती	Shri Surendra Mohanty	.. 151—152
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C. M. Stephan	.. 152
श्री अमरनाथ विद्यालंकार	Shri Amarnath Vidyalankar ..	.. 152—153
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye ..	.. 153
श्री नीतिराज सिंह चौधरी	Shri Nitiraj Singh Chaudhary	. 153—154
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	. 154—155
मूल्यों तथा कृषि उत्पादन संबंधी नीति के बारे में संकल्प	Resolution re : Policy in respec of prices and Agricultural Production :	156
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaya ..	.. 156
आधे घंटे की चर्चा	Half-an-Hour Discussion	.. 156
मतदान आयु कम करने के लिए संविधान में संशोधन	Amendment of Constitution in order to lower the voting age ..	.. 156—157
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C. K. Chandrappan	.. 156—157
श्री नीतिराज सिंह चौधरी	Shri Nitiraj Singh Chaudhary	.. 157

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 15 मार्च, 1974/24 फाल्गुन, 1895 (शक)

Friday, March 15, 1974/Phalguna 24, 1895 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजकर तीन मिनट पर समवेत हुई

The Lok Sabha met at Three Minutes past Eleven of the Clock

{**अध्यक्ष महोदय**, पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*}

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अशोधित तेल की कीमत में वृद्धि होने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से धन निकालना

*321. **श्री पीलू मोदी**
श्री पुरुषोत्तम काकोडकर } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात किये जाने वाले अशोधित तेल तथा पेट्रोलियम की कीमत में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से धन निकालने का निर्णय किया है।

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कितनी राशि निकालने का निर्णय किया है; और

(ग) इससे हमारी विदेशी मुद्रा की रिजर्व बैंक राशि में कितनी कमी हो जाएगी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) तथा (ख) भारत ने, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की क्षतिपूर्ति-वित्त प्रबन्ध-सुविध के अन्तर्गत विभिन्न मुद्राओं में उक्त कोष से 620 लाख रुपए के एस० डी० आर० लिए हैं।

(ग) इस राशि के लेने से हमारी विदेशी मुद्रा प्रारक्षित राशि लगभग 60 करोड़ रुपए बढ़ गयी।

श्री पीलू मोदी : मूल प्रश्न यह है कि क्या अशोधित तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में वृद्धि हो जाने पर भारत में तेल के लिए अपनी विदेशी मुद्रा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा

करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से धनराशि निकालने का निर्णय किया है। यतः मूल प्रश्न का यह अनुपूरक प्रश्न नहीं है।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैंने इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया है। हो सकता है यह पूरा उत्तर न हो परन्तु आंशिक रूप में मेरा प्रयास उसी प्रश्न का उत्तर देने का रहा है।

श्री पीलू मोदी : जहां तक मैं समझता हूं यदि मैंने ठीक प्रकार सुना है तो मंत्री महोदय ने यह उत्तर दिया है कि उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 620 लाख रुपए के एस० डी० आर० लिए हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अशोधित तेल तथा तेल के मूल्यों के बढ़ जाने के कारण सरकार का यह विचार है कि वे अशोधित तेल की मूल्य वृद्धि के विदेशी मुद्रा बिल भुगतान करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से धन राशि निकालना चाहते हैं।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से धन राशि निकालने के लिए कुछ नियम तथा तरीके हैं। आपकी समस्या चाहे जो हो, मेरा तात्पर्य शेष राशि के भुगतान से है। से पूरा करने के लिए, चाहे यह तेल की समस्या है चाहे आयात की अथवा और कोई समस्या है, कुछ शर्तों पर पैसा निकाला जा सकता है उसके लिए यह भी एक मद है। ऐसा करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि हमारी शेष राशि के भुगतानों की स्थिति सरल हो जाए। मुझे आशा है कि मैंने उनके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया है।

श्री पीलू मोदी : मेरे विचार से उपभोग के लिए उधार लेना बुरी अर्थव्यवस्था है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इस ढंग से कार्य करता है कि वह बकाया राशि के भुगतान की समस्या समाधान के लिए अस्थायी ऋण देती है। यदि वे ऋण तीन, चार पांच, वर्ष में नहीं लौटाये जाते तो ब्याज पर दंड देना पड़ता है। इस पर भी यदि भुगतान नहीं किए जाते तो ब्याज और बढ़ जाता है। अत : मैं यह प्रश्न पूछकर सरकार को इस बात के लिए सचेत करना चाहता हूं कि देश की उपभोग संबंधी आवश्यकताओं के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। फिर भी, हमारी उपभोग संबंधी आवश्यकतायें तथा शेषराशि के भुगतान संबंधी कठिनाइयां सरकार के लिए परेशानी पैदा कर सकती हैं जिनके समाधान के लिए सरकार समायोजन हेतु अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से धनराशि निकालने के लिए उत्सुक हो सकती है। इसीलिए मैं यह जाना चाहता था कि सरकार विदेशी मुद्रा की बढ़ी हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या करना चाहती है। मेरे प्रश्न का यह उद्देश्य था।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जहां तक हमारी प्रमुख समस्याओं का संबंध है, हमें अपने निर्यात प्रयासों पर निर्भर रहना होगा। यही इसका अंतिम उत्तर है और हम इस दिशा में भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। परन्तु मैं यह नहीं कह सकता कि हम केवल उपभोग आवश्यकताओं के लिए धनराशि निकाल रहे हैं। मैं इतना कह सकता हूं कि हम इस पूरी समस्या पर बुद्धिमत्ता से ध्यान देंगे और इस बात का प्रयास करेंगे कि देश के हित में सभी उपलब्ध ऋण संसाधनों का प्रयोग किया जाए।

श्री पीलू मोदी : क्योंकि मंत्री महोदय ने बुद्धिमान होने का वायदा किया है। इसलिए अब में अन्य कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछूंगा।

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर : क्या वर्ष 1967 में भी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से इसी प्रकार धनराशि निकाली गई थी और यदि हां, तो कितनी तथा किस कारण से ? क्या सरकार निकट

भविष्य में फिर से धनराशि निकालने की संभावना का अनुमान करती है और यदि हां, तो कब ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : वर्ष 1967 में धनराशि निकालने की बात सच है। धनराशि निकाली गई और इसका पूरा भुगतान कर दिया गया है। इस बारे में अब कोई प्रश्न नहीं है। यदि आवश्यक होगा, तो विचार करना पड़ेगा परन्तु इस समय ऐसा कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है।

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर : भविष्य के बारे में ?

एक माननीय सदस्य : भविष्य के बारे में कौन बता सकता है।

श्री आर० एस० पांडे : मैं सरकार का ध्यान एक वक्तव्य की ओर दिलाना चाहता हूं जो ईरान के शहनशाह द्वारा भारत को अशोधित तेल की सप्लाई के बारे में दिया गया था, विशेषतया · · ·

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न से यह अनुपूरक नहीं बनता।

श्री आर० एस० पांडे : यह भी तेल की समस्या के बारे में है, अन्ततः विदेशी मुद्रा से संबंधित है। मान लीजिए · · ·

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है।

श्री आर० एस० पांडे : ठीक है, मैं दूसरे ढंग से अपना अनुपूरक प्रश्न पूछूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आपके लिए आवश्यक नहीं है कि आप अनुपूरक प्रश्न पूछें ही।

श्री आर० एस० पांडे : ठीक है।

Shri Narsingh Narain Pandey : The Hon. Minister has said that we should not depend for drawing from IMF and we should try to increase our exports. There is abnormal price rise of sugar in the world market and the time of our agreement with U.S.A. and U. K. is going to be over by this year. In view of increase in price of sugar in the world market, the Government should try to see that maximum foreign exchange is earned.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : श्री काकोडकर के प्रश्न के संबंध में मैं इसलिए स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरे उत्तर का अर्थ गलत न समझा जाए। हम इस बात को सिद्धांत रूप देना नहीं चाहते कि हमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से इसलिए राशि नहीं निकालनी चाहिए क्योंकि इस राशि का उपभोग तभी किया जाना चाहिए जब देश कठिनाई की स्थिति में हो। यदि तुम समझते हो कि स्थिति ठीक नहीं है तो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से राशि निकालकर उपभोग में ला सकते हैं। हमने राशि निकाली थी और उसका भुगतान भी कर दिया है। अतः यदि आवश्यक समझा जाता है तो हम ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने पूछा है कि क्या भविष्य में राशि निकालने का विचार है। मैंने बताया है कि इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि हम फिर राशि नहीं निकाल सकते। मान लीजिए यह आवश्यक हो जाता है, तब हमें राशि निकालनी पड़ सकती है क्योंकि निधि से राशि निकालने के लिए सदस्य देशों के कुछ अधिकार हैं। यदि आवश्यक होगा, तो हम धनराशि फिर निकाल सकते हैं, इस महीने अथवा अगले महीने, यह नहीं कहा जा सकता। मैंने अपने उत्तर को गलत ढंग से समझे जाने के भ्रम से स्थिति का स्पष्टीकरण किया है। चीनी निर्यात की स्थिति बहुत अच्छी है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : किस मूल्य पर।

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मूल्य निरन्तर बदल रहे हैं, मूल्य मोड़ अच्छे हो गए हैं। इसके साथ ही हमें देश के उत्पादन के साथ संतुलन बनाए रखना होता है और कृषि मंत्रालय इन दोनों बात पर विचार करेगा और योजना बनाएगा।

श्री पी० जी० मावलंकर : मंत्री महोदय ने बताया है कि सरकार से बकाया राशि के भुगतान के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से राशि निकालनी पड़ेगी। मैं दो महत्वपूर्ण बातों का स्पष्टीकरण चाहता हूं। अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के उद्देश्य से निर्यात कार्यक्रम को किस प्रकार बढ़ावा दिया जाएगा दूसरे अशोधित तेल तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य बढ़ गए हैं। इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ? सरकार पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर आने वाली लागत में किस प्रकार कमी करेगी जिससे कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से अधिक राशि न निकाली जाए ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : माननीय सदस्य को भली प्रकार ज्ञात है कि तेल के मूल्यों में पहले की अपेक्षा बहुत अधिक वृद्धि हो गई है। मूल्यों में वृद्धि यकायक हुई है। दोनों बातों पर ध्यान रखना है। तेल का आयात अधिक मूल्य पर होगा और इस पर हमारी निर्यात आय का अच्छा खासा भाग व्यय हो जाएगा। पेट्रोलियम और रसायन, आर्थिक कार्य तथा अन्य मंत्रालय ऐसी योजना बना रहे हैं कि हमें तेल मिल सके क्योंकि हम तेल की उपलब्धता पर निर्भर हैं। यह हमारी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण भाग है। इसके साथ ही हम इस बात पर भी ध्यान दे रहे हैं कि तेल की खपत में कमी हो सके। यह एक बात है। दूसरे, हमें ऋण सुविधाएं खोजनी पड़ेंगी। हमें विभिन्न दिशाओं में प्रयास करने होंगे (**व्यवधान**) जहां तक निर्यात संवर्धन कार्यक्रमों का संबंध है, यह प्रश्न माननीय सदस्य सम्बद्ध मंत्रालय से पूछ सकते हैं।

मानकीकृत लट्ठे के उत्पादन में वृद्धि

*323. **श्री डी० डी० देसाई**
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी } : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश भर की सूती कपड़ा मिलों को निदेश दिया है कि वे उचित मूल्य की दुकानों पर बेचे जाने के लिए मानकीकृत लट्ठा और अन्य किस्म का कपड़ा बनायें ;

(ख) यदि हां, तो क्या गत 14 महीनों में अनुमानित 55 करोड़ मीटर स्टैन्डर्ड कपड़े का उत्पादन हुआ है ;

(ग) क्या इसमें से 6-7 करोड़ मीटर कपड़ा अब भी मिलों में पड़ा है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (घ) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) सूती कपड़ा मिलों द्वारा नियंत्रित कपड़े, जिसमें लट्ठा भी शामिल है, के उत्पादन की योजना चालू है।

(ख) बताया जाता है कि 1 जनवरी, 1973 से 31 जनवरी, 1974 तक 4025.9 लाख वर्ग मीटर नियंत्रित कपड़े का उत्पादन हुआ।

(ग) 31 जनवरी, 1974 को मिलों के पास लगभग 290 लाख वर्ग मीटर नियंत्रित कपड़ा पड़ा था जो उठाया नहीं गया है।

(घ) वस्त्र आयुक्त के कार्यालय द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को नियंत्रित कपड़े का सारा भंडार रिलीज़ किया जा चुका है और संबंधित राज्य माध्यमों द्वारा उसे मिलों से उठाने का काम चल रहा है।

श्री डी० डी० देसाई : मैंने विवरण देखा है। नियंत्रित किस्म के कपड़े की योजना भारतीय जनता के गरीब लोगों के लिए, जिनमें 40 प्रतिशत गरीबी के स्तर से भी नीचे के स्तर पर रहते हैं, आरम्भ की गई थी। वे गांवों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। विवरण से इस बात का पता नहीं चलता है कि नियंत्रित किस्म के कपड़े की योजना में कपड़ा कितनी मात्रा में गरीब लोगों को दिया गया। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि नियंत्रित किस्म के कपड़े की योजना से 50 करोड़ रुपए की राशि समाज विरोधी तत्वों तथा सहकारी क्षेत्र के भ्रष्ट राजनीतिज्ञों के हाथ लगती और यदि ऐसा है, तो सरकार इस बात के लिए क्या प्रयास कर रही है कि जनता के 40 प्रतिशत लोग जो गरीबी से भी नीचे के स्तर पर जीवन-यापन करते हैं नियंत्रित किस्म का कपड़ा कपड़े पर छपे मूल्यों पर उन्हें मिल सके ?

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैंने प्रश्न के उत्तर में बताया है कि 1 जनवरी, 1973 से 31 जनवरी, 1974 तक 4025.9 लाख वर्ग मीटर नियंत्रित किस्म के कपड़े का उत्पादन हुआ। जनवरी के अन्त तक मिलों के पास 290 लाख वर्ग मीटर कपड़ा पड़ा था। अतः कपड़ा लोगों को दिया गया और कुल उत्पादन तथा वितरण की तुलना में मिलों के पास बहुत थोड़ी मात्रा में कपड़ा पड़ा है। यह भी राज्य सरकारों अथवा उद्योग निदेशकों अथवा कपड़ा उद्योगों के बैंकों तथा सम्बद्ध मिलों को समाचार भेजने में समय लगने के कारण हुआ है। इसमें हमारा दोष नहीं है। जैसा कि माननीय सदस्य को पता है कि विभिन्न प्रणालियों से कपड़ा वितरित किया जाता है। मिलों की अपनी फुटकर दुकानें हैं, सुपर बाजार से राष्ट्रीय सहकारी विपणन संघों के माध्यम से यह कपड़ा वितरित किया जाता है परन्तु मैं न तो यह कहता हूं और न ही कह सकता हूं कि इसमें कोई दोष नहीं है। समेकित तथा अधिक कार्यकुशल वितरण प्रणाली निकालने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं और इसके लिए केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों से सम्पर्क बनाये हुये है।

श्री डी० डी० देसाई : मंत्री महोदय की जानकारी के लिये मैं कह सकता हूं कि उन ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब लोगों को एक इंच भी कपड़ा नहीं मिलता है जहां 40 प्रतिशत लोग गरीबी से भी नीचे के स्तर पर जीवन-यापन करते हैं। फिर भी, मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूं। मंत्री महोदय ने घोषणा की थी कि नियंत्रित किस्म के कपड़े के विस्तार और उत्पादन आधुनिकीकरण के लिए गत वर्ष सितम्बर में समेकित कपड़ा नीति की घोषणा की जायेगी। छः महीने गुजर चुके हैं अभी तक कोई घोषणा नहीं की गई है और कोई योजना प्रकाश में नहीं आई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह नीति कब घोषित की जायेगी और सरकार नियन्त्रित किस्म के कपड़े के सम्बन्ध में किस नीति का अनुसरण करना चाहती है।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : यह सच है कि हम निर्धारित समय में समेकित नीति घोषित नहीं कर सके। यह निर्धारण निश्चित नहीं था। यद्यपि हम इस नीति की पहले ही घोषणा करना

चाहते थे परन्तु ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि हमें कुछ मामले तय करने थे तथा औद्योगिक विकास मंत्रालय से बातचीत करनी थी जो राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अन्तर्गत इन मिलों के प्रशासक हैं और उनकी अपनी कठिनाइयां हैं। हमने कुछ समय लिया है। मुझे आशा है कि नीति शीघ्र ही घोषित कर दी जायगी। यह बात नहीं कि हमने नीति निर्णय की घोषणा के लिये आवश्यक तैयारी नहीं की है। नीति निर्णय की औपचारिक घोषणा से पूर्व नीति सम्बन्धी कुछ बातें बतायी जा सकती हैं। अर्थात् हम नियंत्रित किस्म के कपड़े का उत्पादन 400 मिलियन के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 800 अथवा 900 मिलियन तक ले जाना चाहते हैं। अर्थात् नियंत्रित किस्म के कपड़े के उत्पादन में शतप्रतिशत वृद्धि करना चाहते हैं। हम यह भी सुनिश्चित कराना चाहते हैं कि जो नियन्त्रित किस्म का कपड़ा नहीं बनायेंगे उन्हें कठोर दंड दिया जायेगा और दंड की दर में शतप्रतिशत अथवा इससे भी अधिक वृद्धि की जायेगी। वितरण प्रणाली का विस्तार किया जायेगा और इसे अधिक क्रियाशील बनाया जायेगा।

Shri Ramavatar Shastri: Sir, May I know the quantity of controlled cloth required annually for weaker section of the population? What is the quantity produced in the country at present? May I know whether any scheme has been drawn to meet the requirement if the production is short than the demand and if so, the particulars thereof?

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय: मांगों की रूप रेखा परिवर्तनशील है। गरीब और कम गरीब लोगों की भी वरीयता सूची है। कभी-कभी गरीब लोग भी उन वस्तु-श्रेणियों और किस्मों की मांग करते हैं जिनकी उन्हें 3-4 वर्ष पूर्व कोई आवश्यकता नहीं थी। अतः गरीब वर्गों के लिए अपेक्षित उत्पादन को परिभाषित करना कठिन है क्योंकि ये वर्ग स्थायी नहीं हैं। फिर भी हम कह सकते हैं 12½ प्रतिशत उत्पादन पर नियंत्रण है और हमारा इसे बढ़ाने का विचार है और वे वस्तुएं भी नियंत्रणाधीन लाई जायेंगी जिन पर अब नियंत्रण नहीं है ताकि गरीब वर्गों को कुछ राहत मिल सके।

श्री विश्व नारायण शास्त्री: मंत्री महोदय के विवरणानुसार नियंत्रित कपड़े का उत्पादन 4025.9 लाख वर्ग मीटर बताया गया है। क्या इसका अर्थ है कि उन्हें स्टेन्डर्ड कपड़े के उत्पादन के बारे में पक्का पता नहीं है यद्यपि कपड़ा आयुक्त का इस पर नियंत्रण है। 'बताया गया है' शब्द क्यों बर्ते गए? दूसरे साधारण कपड़े और स्टेन्डर्ड कपड़े में उत्पादन का क्या अनुपात है? क्या प्रति व्यक्ति उत्पादन बढ़ जाने पर इस अनुपात में कोई परिवर्तन होगा?

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय: गलती की घटबढ़ छोड़कर हम कह सकते हैं कि यह आंकड़ा ठीक है। दूसरे प्रश्न का उत्तर 'जी हां' है।

श्री के० लक्कप्पा: क्या कपड़ा मिलों के कुछ संगठन यह सुनिश्चित करते हैं कि उनका उत्पादन खुले बाजार में न जा पाए? उदाहरणार्थ, कर्नाटक में एक व्यक्ति अग्रवाल नाम का है, जिसने पूरा स्टाक कपड़ा आयुक्त के अधिकारियों की सांठ-गांठ से बेच दिया है। इस प्रकार करोड़ों रुपये की लूट मचायी गई है और इसकी सूचना राज्य और केन्द्र सरकार को दे दी गई है। क्या यह सच है कि कपड़ा आयुक्त के कार्यालय ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की है और इसी कारण देश के विभिन्न भागों में लोगों में कपड़ा नहीं बांटा जा सकता है? क्या इस प्रकार की काले-बाजार की कार्यवाही से सरकार को लगभग 50 करोड़ रुपये की आय का घाटा हो रहा है। इसे रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? विशेषकर इस संगठन और अग्रवाल के विरुद्ध जिसके विरुद्ध विशिष्ट आरोप हैं?

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : पहले तो मैं सदस्य महोदय की इस बात का खण्डन करूंगा कि कपड़ा आयुक्त का कार्यालय कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वे रुपये ले रहे हैं।

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : मुझे तो पता नहीं है। श्री बसु शायद बेहतर जानते हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें तो बहुत कुछ पता है।

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : यदि कोई विशिष्ट आरोप ब्यौरे सहित मेरे पास आये तो मैं अवश्य उसकी जांच करूंगा ।

अखबारी कागज का आयात

+

*324. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :**
श्री चन्दूलाल चंद्राकर : } : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974 के दौरान अखबारी कागज की सप्लाई के लिये विदेशी मिलों के साथ जो ठेके किये गये हैं उनके कार्यान्वित होने की आशा नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में सरकार का विचार क्या वैकल्पिक कदम उठाने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : राज्य व्यापार निगम ने जब से अखबारी कागज का आयात अपने हाथ में लिया है तब से कठिनाई होने लगी है। इस मामले में भी क्या निगम द्वारा विदेशी कागज मिलों के साथ नियत समय पर सम्पर्क न करने के कारण ही अखबारी कागज़ उपलब्ध नहीं हो सका ?

श्री ए० सी० जार्ज : मूल प्रश्न सौदों के अनुसार माल प्राप्ति के बारे में था और मेरा उत्तर था कि माल प्राप्त होगा। यद्यपि राज्य व्यापार निगम इस कागज के आयात का माध्यम है फिर भी हमने सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा ए० आई०एन०ई०एस० को भी खरीद, सौदे और माल सप्लाई में सम्बद्ध कर रखा है। वास्तव में 1971 के अन्त तक यह कागज काफी मात्रा में उपलब्ध था। बाद में इसकी विश्वव्यापी कमी हो गई और निगम द्वारा 1971 में किए गए अनेक दीर्घावधि सौदों में विक्रेताओं ने बढ़ते मूल्यों के कारण सप्लाई नहीं भेजी। अब हमारे पास बातचीत, सुलह-सफाई और अन्य मार्ग ही शेष थे, जिन्हें हमने बेकार समझा। अत : हमने उनसे पुन : सौदा करने का निर्णय किया। अब हमने पक्के सौदे कर रखे हैं :—

कनाडा (नया सौदा)	38,000	मीटरी टन
(पुराना सौदा)	28,860	,,
सोवियत संघ	45,000	,,
बंगला देश	12,000	,,
स्केनन्यूज़ (पुराना सौदा)	11,000	,,
फिन्निश पेपर मिल्स	5,000	,,
चेकोस्लोवाकिया	5,700	,,

कुल मिलाकर यह 1,46,000 मीटरी टन है । हमारी कुल आवश्यकता 2,40,000 है जिसमें से 40,000 नेपा मिल का उत्पादन है । इस प्रकार 20 से 25 प्रतिशत की कमी रहती है ।

हम कभी भी सौदे करने और पर्याप्त प्रबन्ध करने में कभी पीछे नहीं रहे हैं ।

श्री चन्दू लाल चन्द्राकर : मंत्री महोदय ने कहा है कि यह कागज समय पर आ रहा है क्या इससे इस सप्लाई में पुन : सामान्यता आ जाएगी ?

श्री ए० सी० जार्ज : मैं अभी स्वीकार कर चुका हूं कि लगभग 20-25 प्रतिशत तक की कमी रहेगी । 1973-74 में सप्लाई की स्थिति यह थी :

जनवरी--	10,468	मीटरी टन
फरवरी--	9,495	,,
मार्च--	9,616	,,
अप्रैल--	10,945	,,

हमारी आवश्यकता 12,000 की है--वहां तक तो कमी है ही ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस समय स्केंडेनिवियाई देश और बंगला देश 200 डालर प्रति टन मूल्य मांगते हैं जबकि कनाडा इससे कहीं अधिक मूल्य मांगता है ।

इस बात को देखते हुए कि हमारे लिए जितना अधिक अखबारी कागज मंगाया जा सकता था, मंगाया जाता, क्या यह सच है कि जिस 20,000 टन के लिए सौदे हुए थे वह राज्य व्यापार निगम के घोटाले के कारण नहीं मंगाया जा सका और उन्होंने दो तिहाई अर्थात् 13,000 टन ही मंगाया, और 10,000 से 20,000 टन इसी घोटाले के कारण नहीं मंगाया जा सका जिस से न केवल विदेशी मुद्रा की भारी हानि हुई बल्कि समाचारपत्रों को भी काफी परेशानी हुई है ?

श्री ए० सी० जार्ज : यह मूल्य 170 डालर प्रतिटन था परन्तु गत 8-10 मास से मूल्य बढ़ गए हैं--(**व्यवधान**) उन्होंने स्केनन्यूज़ और बंगलादेश के मूल्यों का उल्लेख किया है स्केनन्यूज़ से जितना भी कागज मिल सकता था हमने लिया और यह पहुंचने वाला है और जहां कहीं से भी उचित मूल्यों पर कागज उपलब्ध हो हम खरीदने को तैयार हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : ठेके की बातों के अनुसार आप स्केनन्यूज़ से 20,000 टन उठा सकते थे, जो नहीं हुआ है--क्यों ? आपने केवल 2/3 भाग अर्थात 13,000 टन ही क्यों उठाया ? ठेके की एक धारा के अनुसार 10,000 से 20,000 टन अतिरिक्त कागज भी आप उठा सकते थे यह कतई नहीं किया गया--क्यों ?

श्री ए० सी० जार्ज : स्केनन्यूज़ के बारे में शायद आप पुराने ठेके की बात कर रहें हैं । उसके अनुसार 11,000 टन हम उठा सकते थे जो हमने उठा लिया है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : ठेके में कितनी मात्रा उल्लिखित है ?

श्री ए० सी० जार्ज : स्केनन्यूज़ का मूल्य कुछ अधिक था । उस समय हम कम मूल्य पर सौदे कर सकते थे, इसीलिए 10,000 टन का सौदा भी स्वीकार नहीं किया गया ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : ऐसे नहीं चलेगा । स्केनन्यूज़' के साथ 20,000 टन का ठेका था, फिर पूरी मात्रा क्यों नहीं ली गई--क्यों ? साथ ही 10,000 से 20,000 टन का अतिरिक्त उपबन्ध था उसे क्यों नहीं उठाया गया ?

श्री ए० सी० जार्ज : प्रश्न मात्रा का ही नहीं है--प्रश्न मूल्य का भी है । स्पष्ट है कि उक्त विकल्प का हम ने लाभ नहीं उठाया क्योंकि हमें तब सस्ते भाव कागज मिल रहा था और स्केनन्यूज़ का मूल्य कुछ अधिक था ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप सभा को गुमराह कर रहे हैं । मैं पहले भी सरकार को कई बार रंगे हाथों पकड़ चुका हूं ।

श्री पीलू मोदी : इन विशिष्ट प्रश्नों का उत्तर मिलना चाहिए ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हमें उत्तर दिलाया जाए ।

श्री ए० सी० जार्ज : प्रश्न मूल्यों का भी तो है । हमें माल सब से अधिक लाभदायक मूल्यों पर ही लेना चाहिए ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या सौदे की मात्रा 20,000 टन नहीं थी--उसे क्यों नहीं उठाया गया ?

श्री ए० सी० जार्ज : क्या हम अधिक मूल्य पर उसे खरीद लेते ?

Shri Jyotirmoy Bosu : Today the newsprint is selling at 4,000 Rupees per tonne in the black market but this Government did not lift it even after signing a contract @ 210 $ per tonne.

Shri Shankar Dayal Singh : There is shortage of white print as well as newsprint in the country. In reply to my unstarred Question, Government have admitted that the price of paper, which was 2150 Rupees per tonne only in June-July, 1973 has gone up to 3,500 rupees in December, 1973 and at present it is 4,500 rupees per tonne. In 1972-73 the import bill was to the extent of 30·47 crores of rupees. May I know that whether Government are aware that big paper mills in the country are manufacturing hard-board or rough paper rather than white or newsprint ? If so, whether they would be directed to manufacture this kind of paper to meet the shortage.

Mr. Speaker : How hard board or Card board comes in ?

Shri Shankar Dayal Singh : Sir, my supplementary relates to part (6) of the main question.

श्री ए० सी० जार्ज : यह प्रश्न अखबारी कागज के बारे में है और देश में केवल 'नेपा मिल्स' ही यह कागज बनाती है जिसकी क्षमता 40,000 टन की है । हाल में वहां उत्पादन वृद्धि का समाचार मिला है और आशा है कि वहां उत्पादन 50,000 टन वार्षिक का होगा । तथापि हमारी वार्षिक आवश्यकता में आयात के बावजूद 40,000 टन की कमी रह जाती है । इसलिए हम देश में 4 बड़े कारखाने लगाने जा रहे हैं, और कम से कम दो उत्पादन की दिशा में काफ़ी प्रगति कर रहे हैं ।

श्री एच० एम० पटेल : मंत्री महोदय के अनुसार दो बातों पर ध्यान रखना होता है--(1) मात्रा और (2) मूल्य--तो क्या राज्य व्यापार निगम को मूल्य वृद्धि के बारे में पता नहीं था कि मूल्य घटने की कोई संभावना नहीं है और अब अधिक मूल्यों पर सौदे करने पड़ रहे हैं क्योंकि पहले विकल्प से लाभ नहीं उठाया गया ? क्या उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय कागज बाजार में तेज़ी का पता नहीं था ?

श्री ए० सी० जार्ज : जैसा मैंने पहले स्पष्ट किया है, राज्य व्यापार निगम इन क्रय-कार्यों में आई० ई० एन० एस० तथा अन्य सम्बद्ध पक्षों को सम्बद्ध करता रहा है ....

अध्यक्ष महोदय : सीधा सा प्रश्न यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ते मूल्यों को देखते हुए विकल्प से लाभ क्यों नहीं उठाया गया ?

श्री ए० सी० जार्ज : मैं वही बताने वाला था। उस स्थिति में जबकि विश्व में कागज के भाव 1½ वर्ष पूर्व 170 डालर से बढ़कर 320 डालर प्रति टन हो गए हैं और ये भाव सभी जगह बढ़े हैं ..... (**व्यवधान**)

श्री एच० एम० पटेल : उन्होंने प्रश्न टालने का प्रयत्न किया है। जब आपको कोई मात्रा विशेष लेने का विकल्प था जबकि बाजार-भाव बढ़ रहे हों, तो सभी बुद्धिमान व्यक्ति वह माल उठाना ही चाहेंगे क्योंकि तब आपको 300 डालर प्रति टन का भाव नहीं देना पड़ता।

श्री ए० सी० जार्ज : मैं यही बात कहता रहा हूं कि स्केनन्यूज के मुकाबले जब हम अन्यत्र सस्ते भाव कागज खरीद सकते थे तो अधिक मूल्य क्यों देते ?

श्री बसन्त साठे : इस क़रार का मूल्य क्या था? नकद मूल्य पर आप कितनी मात्रा खरीद सके ? कृपया उनसे कहें कि वह इस प्रश्न का उत्तर दें। कितनी मात्रा खरीदी गई ?

श्री एच० एम० पटेल : मंत्री महोदय, ने कहा है कि क्योंकि नक़द मूल्य कम थे तो उन्होंने अपनी स्वैच्छा का उपयोग नहीं किया। फिर मेरा प्रश्न यह होगा कि उनको नक़द मूल्य पर कितनी मात्रा में माल मिला ?

श्री बसन्त साठे : मूल्य क्या था ?

श्री ए० सी० जार्ज : अखबारी कागज खरीदने के लिए हमारे पास 7 महत्वपूर्ण स्रोत हैं। जैसा कि मैंने पहले स्पष्ट किया, हम कनाडा, रूस, बंगला देश से खरीद रहे हैं ... (**व्यवधान**) मैं इस प्रश्न पर भी आ रहा हूं। नक़द मूल्य देकर हम 11,000 टन खरीद सके।

श्री एच० एम० पटेल : अब प्रश्न यह है कि क्या यह स्पष्ट नहीं है कि जहां 22,000 टन खरीदने का अवसर उपलब्ध था वहां उन्होंने केवल 11,000 टन खरीद लिया और 22,000 टन जाने दिया।

अध्यक्ष महोदय : सब स्थिति आपके सामने है।

श्री बसन्त साठे : मूल्य क्या थे और उन्होंने क्यों जाने दिया। इससे कितनी हानि हुई ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया इतने विस्तार में मत जाईये। अब हमारे पास कुछ प्रश्न शेष बचे हैं।

श्री पीलू मोदी : शेष समय इस प्रश्न के लिये है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। इस समय आप यहां अध्यक्ष बनकर नहीं बैठे हैं।

श्री एच० एम० पटेल : आप मंत्री महोदय को इस प्रश्न का उत्तर देने को कहें।

अध्यक्ष महोदय : इस सप्ताह अखबारी कागज के बारे में कई प्रश्न हमारे सामने आये हैं। मैं इसे बहुत उत्तम समझूंगा कि बड़े अनुपूरक प्रश्नों की बजाय ....

श्री ए० सी० जार्ज : मेरा उत्तर तो बड़ा ही सादा था। वाणिज्यिक कारोबार में कुछ मूल्य होते हैं। नक़द मूल्यों के लिये ....

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको कोई उत्तर देने को नहीं कहा है। मैं तो सुझाव दे रहा था।

श्री ए० सी० जार्ज : नक़द मूल्य तो 170 डालर थे और लम्बी अवधि के मूल्य 220 डालर थे। स्पष्ट है कि हमने नक़द मूल्य देना ठीक समझा।

श्री एच० एम० पटेल : और 11,000 टन खो दिया।

श्री पीलू मोदी : मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय स्वयं को देश का सबसे बड़ा व्यापारी समझें और वह यह अनुभव करें कि व्यापार के कुछ ऐसे नियम भी होते हैं कि जब बाजार की हालत सुधर रही हो और दाम बढ़ रहे हों तो व्यापारी को तुरन्त ही खरीद कर लेनी चाहिए। इस पर उनका यह कहना है कि हमने आई० ई० एन० एस० से, या और किसी से या किसी ज्योतिषी आदि से पूछा था। यदि आप ऐसा ही कुछ करना चाहते हैं तो फिर उन्हें व्यापारिक बातों से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए।

अब एक विशिष्ट प्रश्न पूछा गया है कि क़रार के आधार पर क़रार के मूल्यों पर न केवल पूरी मात्रा में कागज नहीं खरीदा गया बल्कि अपने स्वेच्छा का उपयोग भी नहीं किया गया। हमारे विचार से यह व्यापार संबंधी प्रक्रिया के बारे में एक भारी भूल है। हम एक स्पष्टीकरण चाहते हैं और मंत्री महोदय से यह उत्तर चाहते हैं कि उन्होंने देश को इस बुरी तरह से असफल क्यों किया ?

श्री ए० सी० जार्ज : वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय विपणन स्थिति को देखते हुए मूल्य दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और हमें उसी संदर्भ में अपने विवेक तथा स्वेच्छा का उपयोग करना है ताकि हमें सस्ती दरों पर अन्य स्रोतों से माल मिल जाये। इस समय तो मूल्य बढ़ रहे हैं। यह बात किसी भी वस्तु और किसी भी दिन के साथ है। ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति पीठ मोड़ सकता है तथा कह सकता कि आपको एक सप्ताह पूर्व खरीदना चाहिए था। परन्तु हम, जोकि सरकार चला रहे हैं जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा, देश की ओर से व्यापार कर रहे हैं और यह देखना हमारा दायित्व है कि हमें सबसे अच्छी शर्तों पर माल मिले। स्वभावतः ही वह अवसर विचार-विमर्श का था। वहां जाने वाले अधिकारी तुरन्त ही तो कोई निर्णय नहीं कर सकते। इसलिए हमें परामर्श तो करना ही होता है।

श्री पीलू मोदी : इस प्रकार उन्होंने अपनी अयोग्यता स्वीकार करली है..... (**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। जो कुछ उन्हें मालूम था उन्होंने बता दिया। पटेल साहेब, आपको अवसर मिल चुका है। अब हम अगला प्रश्न लेंगे।

मुद्रा सप्लाई के संबंध में राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान परिषद् द्वारा किया गया अध्ययन

*328. **श्री ज्योतिर्मय बसु**
श्री एस० एम० बनर्जी } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद द्वारा देश में मुद्रा सप्लाई की स्थिति के बारे में हाल ही में किये गये अध्ययन की ओर दिलाया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) **और** (ख). ऐसा लगता है कि प्रश्न में जिस अध्ययन का उल्लेख किया गया है उसका संबंध राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद, नयी दिल्ली, द्वारा फरवरी 1974 में प्रकाशित एक त्रैमासिक पत्रिका 'मार्जिन' के विशेषांक में प्रकाशित अध्ययन रिपोर्ट से है। 25 फरवरी, 1974 में सभा में प्रस्तुत किये गये आर्थिक सर्वेक्षण 1973–74 में मुद्रा सप्लाई की वृद्धि को प्रोत्साहन देने वाले तथ्यों का व्यापक विश्लेषण किया गया है और मुद्रा की सप्लाई की वृद्धि की रोकथाम के लिये सरकार द्वारा किये गये विभिन्न वित्तीय और मुद्रा संबंधी उपायों का भी वर्णन किया गया है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उन्होंने कोई बात स्पष्ट नहीं की है। मैं दो प्रश्न पूछना चाहता हूं मेरा प्रश्न 1(क) यह है: रिजर्व बैंक ने मुद्रा सप्लाई में इस भारी वृद्धि को रोकने के लिये क्या सलाह दी है मेरा प्रश्न 1 (ख) यह है : रिजर्व बैंक द्वारा ऋणों पर प्रतिबन्धों तथा विशिष्ट ऋण नियंत्रण का अपेक्षित प्रभाव क्यों नहीं पड़ा। और सरकार के मतानुसार इसके क्या कारण हैं ।

श्री यशवन्त राव चह्वाण : वस्तुतः यह प्रमुख प्रश्न है। यह कहना सही है कि ऋणों पर रोक के परिणाम नहीं निकले हैं। निश्चय ही इसका फल मिला है। कुछ उपाय किये गये हैं। इस बारे में विचार-विमर्श जारी है। मैं इस समय सारा ब्यौरा नहीं दे सकता हूं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : अनुत्पादक व्यय को कम करने तथा मुद्रा स्फीति को रोकने के लिए क्या विशेष कदम उठाए गये हैं ; 400 करोड़ रुपए का उल्लेख किया गया है। विकास तथा समाजिक सेवाओं के खर्च में कमी करने का विचार किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि वास्तविक रूप से विकास तथा समाजिक सेवाओं के व्यय में कितनी कमी की गयी है।

श्री यशवन्त राव चह्वाण : वह यह जानना चाहते हैं कि हमने क्या कदम उठाए हैं––

श्री ज्योतिर्मय बसु : अनुत्पादक व्ययों के बारे में ।

श्री यशवन्त राव चह्वाण : यह भी एक कदम हमने उठाया है। हमने विकास संबंधी व्ययों में भी कटौती तो की है परन्तु अनिवार्य चीज़ों के लिये तथा प्राथमिकता क्षेत्र में कटौती नहीं की है।

श्री बसन्त साठे : गत वर्ष वास्तविक मुद्रा सप्लाई कितनी थी और देश में इस समय मुद्रा की सप्लाई कितनी है ।

श्री यशवन्त राव चह्वाण : वह कृपया इस अध्याय के 32 पृष्ठ से आगे पढ़ लें।

श्री बसन्त साठे : वह तो मैं बाद में पढ़ लूंगा इस समय तो वह मुझे दो आंकड़े बता दें।

श्री यशवन्त राव चह्वाण : इस समय तो वे आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। यदि आप चाहेंगे तो मैं उन्हें एकत्रित करके आपको दे दूंगा।

इंडियन एयरलाइंस में फालतू विमान चालक

*329. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयर लाइंस में बहुत से विमान चालक फालतू हैं ; और

(ख). यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और सरकार का विचार उनको किस प्रकार खपाने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) :(क) और (ख) , इंण्डियन एयरलाइंस में टर्बो-प्राप वर्ग में कुछ सह-विमानचालक फालतू हैं जिनका एक भाग निर्धारित सम्परिवर्तन कार्यक्रम द्वारा जेट विमान चालकों में खपा दिया जाएगा । इसके अतिरिक्त विमानचालकों का और अधिक सुचारु रूप से उपयोग करने के प्रश्न पर कारपोरेशन में विचार किया जा रहा है । और फालतू विमानचालक, यदि कोई होंगे तो, कारपोरेशन के विस्तार कार्यक्रमों में खपा लिये जायेंगे ।

श्री वीरभद्र सिंह : इस समय इंडियन एयरलाइंस की आवश्यकता से कितने विमान चालकों को फालतू समझा जाता है ।

श्री राजबहादुर : इंडियन एयर लाइन्स के 10 बोइंग, 9 केरेवील, 22 एवरो तथा 9 एफ-27 विमानों के लिए उपलब्धता के आधार पर उसकी विमान चालकों की आवश्यकता इस प्रकार हैं । बोइंग 737 के लिये 100 तथा उपलब्ध हैं 80, केरेवील के लिये 90 तथा उपलब्ध हैं, 82, एफ० 27 के लिये 68 चाहिए तथा उपलब्ध हैं 87, इसी प्रकार एच० एस० 748 के लिये ये आंकड़े 164 तथा 178 हैं ।

श्री वीरभद्र सिंह : हमारी विमान कम्पनियों में नियुक्त विमान चालकों के अलावा देश में कमर्शियल पायलट लाइसेंस वाले अनेक विमान चालक हैं जो अभी तक बेरोजगार हैं क्या उन विमान-चालकों को रोजगार देने का सरकार के पास कोई उपाय है ।

श्री राजबहादुर : अनेक ऐसे बेरोजगार विमान चालक हैं जिन्होंने लाइसेंस आदि प्राप्त कर लिये हैं परन्तु अपने लिए कोई नौकरी नहीं पा सके हैं । हमने उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कुछ उपाय किये है । हमने वाणिज्यिक विमान चालकों को शामिल करने के लिये यदि वे निर्धारित अर्हतायें पूरी करें, नागर विमानन विभाग में सहायक एयरोड्रोम अधिकारी की सीधी भर्ती संबंधी नियमों में संशोधन किया है । कृषि मंत्रालय फसलों पर छिड़काव के अभियान हेतु वाणिज्यिक विमान चालकों के भर्ती करने का विचार कर रही है । कृषि मंत्रालय तथा अन्य राज्य सरकारों ने इस बारे में विचार किया है । इण्डियन एयरलाइन्स तथा एयर इण्डिया को भी सलाह दी गई है कि यथासंभव इन बेरोजगार विमान चालकों को स्थलीय ड्यूटियों के लिए भर्ती करें । विमान परिवहन सेवा तथा अन्य ऐसी ही सहायक सेवा में चलाने के लिये हम उनकी सहकारिताओं को भी प्रोत्साहन देंगे ।

चाय अधिनियम में संशोधन

*330. **श्री एम० कतामुतु :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय बोर्ड ने चाय अधिनियम में कुछ अत्यावश्यक संशोधन करने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण तथा ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) कलकत्ता में 13 तथा 14 फरवरी, 1974 को हुई चाय बोर्ड की बैठक में, बोर्ड ने भारत सरकार का ध्यान चाय उद्योग तथा विशेषकर बन्द पड़े तथा संकट-ग्रस्त बाग़ानों के कर्मचारियों के सामने आई तात्कालिक कठिनाइयों की ओर दिलाने का तथा सरकार से यह अनुरोध करने का निश्चय

किया कि वह उपयुक्त विधि-निर्माण द्वारा अविलम्ब कार्यवाही करे और उपयुक्त अभिकरणों के माध्यम से ऐसे संकट-ग्रस्त तथा बन्द पड़े बाग़ानों का प्रबन्ध करे।

श्री एम० कतामुतु: इस दृष्टि से कि सरकार द्वारा नियुक्त "टास्क फोर्स" ने संकट-ग्रस्त या बन्द पड़े चाय-बाग़ानों को अपने हाथ में लेने की सिफारिश की है। पश्चिम बंगाल विधान सभा ने भी अपने एक संकल्प द्वारा ऐसे अधिग्रहण का अनुरोध किया था परन्तु केन्द्र सरकार ने उसे स्वीकार नहीं किया। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उसके फलस्वरूप बहुत सारे श्रमिकों को बेरोज़गार होने से बचाने के लिए संकट-ग्रस्त चाय-बाग़ानों की पूरी तरह अपने हाथ में लेने का विचार कर रही है?

श्री ए० सी० जार्ज: चाय उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों की जांच करने के लिए नियुक्त टास्क फोर्स ने कुछ पहलुओं के बारे में अपनी सिफारिशें दी हैं। उदाहरणार्थ, मैं उन के बारे में कुछ मुख्य बातें बताता हूं। वह चाहते हैं कि चाय अधिनियम में सरकार को संकट-ग्रस्त बाग़ानों का प्रबन्ध हाथ में लेने की शक्ति देने के प्रावधान किए जाएं और वे शक्ति औद्योगिक विकास तथा विनियमन अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप हो। उनका दूसरा मुख्य सुझाव यह है कि सरकार चाय बाग़ानों के कार्यकरण, यदि उन का कोई अपना कारखाना हो तो, के बारे में जांच करने के आदेश दे सकने की वैधानिक शक्तियों प्राप्त करे। निर्धारित मानदण्डों की दृष्टि से इसे बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। महत्वपूर्ण सिफारिशें यही हैं और यह माननीय सदस्य के प्रश्न से संम्बधित हैं। उस चाय बाग़ान को संकट-ग्रस्त समझा जाना चाहिए जिसे गत चाय उद्योग के औसत उत्पादन में पांच वर्षों के दौरान तीन वर्ष तक घाटा होता रहा हो तथा यदि चाय बाग़ान अपने संविधिक दायित्व पूरे करने में आदतन दोषी पाया गया हो। टास्क फोर्स ने ये मानदण्ड सुझाए हैं।

इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए, हम कर्मचारियों की समस्या को हल करने तथा उनकी शिकायतों को दूर करने के उद्देश्य से कदम उठा रहे हैं।

श्री एम० कतामुतु: क्या टास्क फोर्स ने मूल स्वामियों से चाय बाग़ानों से अभिग्रहीत करने और जब वे कुछ वर्ष तक लाभ कमाना आरंभ कर दें तब उन्हें वापस कर देने की भी कोई सिफारिश की है?

श्री ए० सी० जार्ज: यही मूल प्रश्न है और इस बारे में कुछ सुझाव थे कि हम पांच या छः वर्ष के लिए संकट ग्रस्त चाय बाग़ानों को अपने हाथ में ले लें और उन्हें संकट-मुक्त करा लें। इसके बाद यह एक खुला प्रश्न है। इस पर हमने कोई निर्णय अभी तक नहीं किया है।

श्री के० नारायण राव: सभी चाय बाग़ानों को अपने हाथ में लेने की बजाय केवल संकट ग्रस्त चाय बाग़ानों को ही हाथ में लेने की नीति का क्या अभिप्राय है? क्या समूचे चाय उद्योग को भी अपने हाथ में ले लेना ही उसको सर्वथा आत्मनिर्भर बनाने के लिए अधिक न्यायोचित नहीं होगा?

श्री ए० सी० जार्ज: इस समय तो समस्या यह है: 38 ऐसे चायबाग़ान हैं जो या तो बन्द पड़े हैं या विभिन्न चरणों में संकट ग्रस्त घोषित किए जा चुके हैं। हमारी पहली चिन्ता

तो आप के उत्पादन तथा बैरोज़गारी की समस्या है। वह एक व्यापक प्रश्न है। इस समय तो हम इन्हीं बातों पर चर्चा कर रहे हैं।

श्री जे० माता गोडर : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार आर्थिक संकट ग्रस्त चाय बाग़ानों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने का है और क्या मन्त्री महोदय सदन को इस बात का आश्वासन देंगे कि जिन आर्थिक संकट-ग्रस्त चायबाग़ानों का सरकार प्रबन्ध अपने हाथ में लेती है, उनका अन्ततः राष्ट्रीयकरण किया जाएगा ?

श्री ए० सी० जार्ज : शुरू में ही मैंने कहा था कि यह एक पूर्णतः खुला हुआ प्रश्न है। हम आर्थिक संकट ग्रस्त चाय बाग़ानों में स्वस्थ स्थिति बनाने और उन की हालत फिर से ठीक करने के लिए व्यग्र हैं।

इण्यिन एयर लाइन्स का एवरो विमानों को बेचने का निर्णय

*336. **श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइंस ने अपने एवरो-748 विमानों को बेचने का निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रबोध चन्द्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने ध्यान में निरीक्षकों की इस आशय की रिपोर्ट लाई गई है कि अगर इनको तुरन्त सेवा में से नहीं हटाया गया, तो इन में से कुछ एवरो विमानों से यात्रियों के लिए संकट है।

श्री राज बहादुर : मुझे ऐसी किसी रिपोर्ट की जानकारी नहीं है। वस्तुतः, डा० धवन, जिन से एयर इण्डिया और अन्य सम्बन्ध संगठनों के मूल्यांककों की सहायता से इस प्रश्न की जांच करने का काम सौंपा गया है, अभी भी एवरो विमानों के सभी पहलुओं, विशेषकर उनकी संचालन-क्षमता की सम्बन्धी जांच कार्य में व्यस्थ हैं।

श्री प्रबोध चन्द्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पायलटों के एसोसिएशन अथवा एवरो विमानों में काम करने वाले कर्मचारियों ने सरकार के ध्यान में यह बात लाई है कि अगर विमान बेड़े से कुछ विमानों को नहीं हटाया गया, तो वे अपने उड़ान करने वाले यात्रियों के लिए खतरा उत्पन कर सकते हैं ?

श्री राजबहादुर : पायलटों ने कुछ आशंकायें व्यक्त की थीं, परन्तु उन्हें आश्वस्त करने का प्रत्येक प्रयास किया गया है और पायलट विमानों की उड़ान कर रहे हैं और जहां तक विमान की उड़ान-क्षमता का सम्बन्ध है, कोई भी खतरा नहीं उठाया जा रहा है।

माननीय सदस्य की जानकारी के लिए, मैं यह बताना चाहता हूं कि 33 अन्य सिविल विमान कम्पनियों इन्हीं विमानों का उपयोग कर रही हैं और 30 देशों में इनका उपयोग हो रहा है। इस समय 170 विमान उड़ान कर रहे हैं। जिन में के इन सिविल कम्पनियों के और हमारे विमानों के अलावा सात एयर फोर्स भी इनका प्रयोग कर रहे हैं।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा एल्यूमीनियम का आयात

*338. **श्री राम अवतार शास्त्री**
श्री गजाधर माझी } : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने एल्यूमीनियम का आयात करने से मना कर दिया है :

(ख) क्या एल्यूमीनियम की कमी को पूरा करने के लिए कनाडा से 10,000 टन एल्यूमीनियम आयात करने के सरकारी निर्णय के बाद भारी उद्योग मंत्रालय ने खनिज तथा धातु व्यापार निगम से एल्यूमीनियम का आयात करने की जिम्मेदारी संभालने का अनुरोध किया था; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकारी नीति की मुख्य रुप रेखा क्या है और चालू वर्ष के दौरान एल्यूमीनियम की कितनी कमी होने की आशा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) देश में ई० सी० ग्रेड एल्यूमीनियम की वर्तमान कमी पूरी करने के लिए इस धातु के 10,000 मी० टन के आयात के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। धातु का आयात-कौन-सा अभिकरण सम्भालेगा इसका निर्धारण अभी नहीं किया गया।

Shri Ramavtar Shastri : I would like to know as to how long the question of import of 10,000 tonnes of E.C. grade aluminium is under consideration and how long would it take to take a final decision in the matter ?

श्री ए० सी० जार्ज : समस्या यह है कि अभी हाल में बिजली की गम्भीर कमी के कारण ई० सी० ग्रेड एल्यूमीनियम के उत्पादन में कमी हुई है। वर्ष 1972 में इसका उत्पादन 1,79,000 टन हुआ था, जो वर्ष 1973 में घटकर 1,54,000 टन रह गया।

Shri Ramavtar Shastri : The honourable Minister has stated that the agency which would handle import has not been determined. I would like to know as to why the Government is delaying it. The honourable Minister should also state as to how long would it take to arrive at a decision regarding the agency ?

श्री ए० सी० जार्ज : इसका आयात किसी सरकारी एजेन्सी के माध्यम से नहीं किया जाता है। खनिज तथा धातु व्यापार निगम सामान्यत: केवल सरकारी माध्यम से आयात होने वाली वस्तुओं से ही सम्बन्धित हैं। चूंकि यह विशिष्ट समस्या अभी हाल में बिजली की कमी के कारण उत्पन्न हुई है, हम इस बारे में शीघ्र ही अन्तिम निर्णय लेने के बारे में सोच रहे हैं। जैसी कि अभी स्थिति है और चूंकि इसका आयात किसी सरकारी एजेन्सी के माध्यम से नहीं किया जाता, खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने इसके आयात को अपने हाथ में नहीं लिया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के होटलों में उपलब्ध बिस्तरों की संख्या

*322. **श्री वनमाली पटनायक : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी और गैरसरकारी क्षेत्र के होटलों में उपलब्ध बिस्तरों की कुल संख्या का अलग-अलग ब्यौरा क्या है ;

(ख) अगले तीन वर्षों के दौरान देश में तत्सम्बन्धी मांग क्या होगी; और

(ग) इसे किस प्रकार पूरा करने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री [डा० (श्रीमती) सरोजनी महिषी]: (क) 194 होटलों में, जिन का कि उनकी विदेशी पर्यटकों की उपयुक्तता के दृष्टिकोण से पर्यटन विभाग द्वारा अनुमोदन किया गया है, कुल उपलब्ध धारिता इस समय 12,110 कमरे हैं। इन में से 13 होटल जिन में 1,615 कमरे हैं सरकारी क्षेत्र के हैं, तथा शेष 181 होटल जिन में 10,495 कमरे हैं निजी क्षेत्र के हैं।

(ख) यह अनुमान लगाया गया है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि के अन्त तक, उस समय तक आने वाले अनुमानत: 8,00,000 पर्यटकों के लिए आवास व्यवस्था करने हेतु, 15,000 अतिरिक्त होटल कमरों की आवश्यकता पड़ेगी।

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र में भारत पर्यटन विकास निगम और एयर इंडिया की कई होटल/मोटल बनाने की योजनाएं हैं। पर्यटन विभाग की भी देश में अनेक स्थानों पर मध्य एवं निम्न आय वर्ग के पर्यटकों के लिए वन्य पशु शरण स्थानों में विश्रामगृहों, पर्यटक बंगलों, स्वागत केन्द्रों व मोटलों, तथा युवा होस्टलों के रूप में अनुपूरक आवास व्यावस्था का आयोजन करने की परियोजनाएं हैं। निजी क्षेत्र को भी इस प्रकार के विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान करके और अधिक होटल बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जैसे वित्तीय राहत, ब्याज देय ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता, आवश्यक सामग्री के मामलों में अग्रता से विचार, इत्यादि।

सोमनाथ में शिविर-स्थल स्थापित करने की योजना

*325. **श्री वेकरिया**
श्री डी० पी० जदेजा } **: क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोमनाथ में शिवर-स्थल स्थापित करने की सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) उस पर अनुमानत: कितनी लागत आएगी ; और

(घ) कार्य के कब तक आरम्भ होने की सम्भावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री [डा० (श्रीमती) सरोजनी महिषी] : (क) और (ख) : पर्यटन विभाग भारत में 19 स्थानों पर शिवर-स्थल स्थापित करने की एक योजना पर विचार कर रहा है, जिस में सोमनाथ का शिविर-स्थल भी सम्मिलित है।

(ग) अनुमानित लागत लगभग एक लाख रुपए होगी।

(घ) निधि उपलब्ध होने पर इस योजना को पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि में हाथ में लेने का प्रस्ताव है।

भारत और यूगोस्लाविया के बीच व्यापार में वृद्धि

*326. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया**
श्री राम कुवर } : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष भारत यूगोस्लाविया के बीच व्यापार में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी ; और

(ख) दोनों देशों के बीच व्यापार की किन-किन वस्तुओं का विनियम होगा ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) यह अनुमान लगाना कठिन है कि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक पर्यावरण तथा भारत और युगोस्लाविया के बीच चल रही व्यापार प्रणाली के 1 जनवरी 1973 से परिवर्तनीय मुद्रा प्रणाली में बदले जाने के सन्दर्भ में चालू वर्ष के दौरान भारत-यूगोस्लाविया व्यापार में ठीक-ठीक कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। फिर भी जो रूख दिखाई देता है उससे लगभग 15 प्रतिशत वृद्धि का पता चलता है।

(ख) दोनों देशों के बीच जिन मुख्य मदों का लेन-देन किया जाएगा उन में चमड़ा, टायर और ट्यूबों सहित रबड़ से निर्मित माल, चाय, काली मिर्च समेत गर्म मसाले, एच० पी० एस० मूंगफली, विभिन्न प्रकार का इंजीनियरी माल, जैसे तार के रस्से, वातानुकूलन उपस्कर-पुर्जे, बाईसिकल के संघटक, मोटर गाड़ियों के पुर्जे सह-साधन/फालतू पुर्जे, जहाज रोगन आदि भारत से निर्यात किए जाने वाले माल में शामिल हैं और यूगोस्लाविया से आयात किए जाने वाले माल में कृषि के ट्रालर ट्रैक्टर/पुर्जे, पूंजीगत माल, औषध तथा भेषजें, रसायनिक पदार्थ, काग़ज़ और काग़ज़ उत्पाद, अख़बारी काग़ज़, पारा, सीसा, उर्वरक आदि शामिल होंगे।

विमान यात्रा सुरक्षा बोर्ड की स्थापना

*327. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी**
श्री धन शाह प्रधान } : क्या **पर्यटन** और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में विमान यात्रा सुरक्षा बोर्ड स्थापित करने की वांछनीयता पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई निर्णय लिया गया है ; और

(ग) इस नए निकाय की सौंपे जाने वाले उत्तरदायित्व की मुख्य बातें क्या हैं; और क्या यह संगठन अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (इंटरनेशनल एयरपोर्ट एथोरिटी) से असम्बध रह कर कार्य करेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) से (ग) नागर विमानन विभाग के संगठनात्मक ढांचे तथा क्रिया-कलाप की समीक्षा करने के लिए गठित की गई समिति ने, जिसने इस मामले पर भी विचार किया था, अपनी अंतरिम रिपोर्ट दे दी है, तथा सरकार को उस पर निर्णय लेने में कुछ समय लगेगा। तथापि समिति द्वारा अपनी अन्तिम रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का सारांश देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6438/74।]

बंबई में बेलर्ड पियर पर जब्त शुदा वस्तुओं का जमा हो जाना

*331. **श्री शंकर राव सावंत** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमाशुल्क विभाग द्वारा जब्त की गई उन मूल्यवान वस्तुओं के बड़े ढेर जो चोरी छिपे लाई गई हैं तथा सामान को लाने के लिए प्रयोग में लाई गई कार बम्बई में बेलर्ड पियर स्थान पर खुले में पड़ी हैं ;

(ख) क्या बिल्कुल खुले में पड़े रहने के कारण ये चीजें खराब हो रही हैं तथा साथ ही उनके चोरी हो जाने की संभावना है ; और

(ग) उनको शीघ्रता से क्यों नहीं बेचा जा रहा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) हाल ही के विगत समय में तस्कर-आयात के माल के भारी मात्रा में पकड़े जाने तथा गोदामों की कमी के कारण कुछ पकड़े गए माल तथा वाहनों को बैलार्ड एस्टेट स्थित बम्बई सीमाशुल्क गृह के अहाते में अस्थाई रूप से रख गया था। उसके बाद से सीमाशुल्क गृह ने गोदाम के उपयुक्त स्थान का अभिग्रहण कर लिया है और सीमाशुल्क गृह के अहाते में पड़े हुए माल को उस गोदाम में ले जाया जा रहा है।

(ख) सीमाशुल्क गृह के अहाते में माल के अस्थायी रूप से रखे रहने के दौरान खुले में रहने के कारण माल को टूट-फूट से बचाने के लिए उचित व्यवस्था की गई थी तथा चोरियों को रोकने के निमित्त सशस्त्र पुलिस के सन्तरियों द्वारा माल की पहरेदारी की गई थी ।

(ग) माल को तब तक नहीं बेचा जा सकता जब तक कि विभागीय न्याय-निर्णय कार्यवाहियों, अपीलीय उपायों तथा न्यायालय में यदि कोई मामले हों तो उनमें, माल को जब्त करने के बारे में औपचारिकताएं पूरी नहीं कर ली जातीं।

फ्रांस के साथ ऋण करार

*332. **श्री फतह सिंह राव गायकवाड**
श्री अरविन्द एम० पटेल } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करग कि :

(क) क्या फ्रांस ने भारत को हाल में 27.40 करोड़ फ्रैंक का ऋण दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका उपयोग कैसे किया जाएगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) जी, हां ; भारत सरकार और फ्रांस की सरकार के बीच 8 फरवरी 1974 को 2740 लाख फ्रैंच फ्रांक की कुल राशि के लिए

दो वित्तीय करारों पर हस्ताक्षर किए गए थे जो फ्रांस द्वारा 1974-75 के लिए भारत को दी गई सहायता की द्योतक है।

(ख) पहले करार का सम्बन्ध 2140 लाख फ्रैंच फ्रांक के एक ऋण से है जिसमें से 1290 लाख फ्रैंच फ्रांक का निर्धारण औद्योगिक परियोजनाओं और भारी उपकरण के लिए माल और सेवाओं के फ्रांस से किए जाने वाले आयातों के लिए किया गया है और 850 लाख फ्रैंच फ्रांक की रकम फ्रांस से हल्के उपकरण, संघटक, फालतू पुर्जे, रासायनिक पदार्थ, उर्वरक और औद्योगिक कच्चे माल के आयात के लिए निर्धारित की गई है। दूसरे करार का संबंध 660 लाख फ्रैंच फ्रांक के एक ऋण से है ताकि भारत द्वारा परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष विभाग की परियोजनाओं और कार्यक्रमों के लिए फ्रांस से माल और सेवाओं के आयात को वित्तपोषण किया जा सके।

शिमला में हवाई अड्डे का निर्माण

*333. **श्री नारायण चन्द पाराशर:** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करग कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में शिमला में एक हवाई अड्डे के निर्माण के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त सर्वेक्षण के क्या निष्कर्ष निकले ; और

(ग) उक्त हवाई अड्डे के कब तक निर्मित हो जाने की आशा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) और (ख). हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुरोध पर नागर विमानन विभाग तथा केन्द्रीय लोकनिर्माण विभाग के अधिकारियों के एक दल ने शिमला के निकट एक हवाई अड्डे के निर्माण की संभावना की जांच करने के लिए जून 1973 में कुछ स्थलों का निरीक्षण किया और पाया कि जब्बड़हट्टी में एक ऐसे स्थल की संभावना हो सकती है। इण्डियन एयर लाइंस तथा नागर विमानन के महानिदेशक को शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक यातायात तथा तकनीकी विस्तृत सर्वेक्षण करने के अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

(ग) इस समय प्रश्न नहीं उठता।

विश्व व्यापार में भारत के निर्यात में गिरावट

*334. **श्री मनोरंजन हाजरा:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत के निर्यात तथा आयात की क्या प्रवृत्ति रही है ;

(ख) क्या हमारा निर्यात बढ़ने के बावजूद भी समूचे विश्व व्यापार में भारत के निर्यात में उक्त अवधि के दौरान निरंतर कमी हो रही है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका मोटा ब्यौरा क्या है।

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) पिछले तीन वर्षों में भारत के निर्यातों तथा आयातों का रुख निम्न प्रकार था :

(करोड़ रु० में)

	आयात	निर्यात (जिसमें पुनर्निर्यात भी शामिल हैं)
1970-71 . . .	1634	1535
1971-72 . . .	1825	1608
1972-73	1797	1961

(ख) तथा (ग). जी नहीं, संयुक्त राष्ट्र के मंथली बुलेटिन आफ स्टैटिसटिक्स के अनुसार विश्व व्यापार में भारत के भाग में पिछले वर्षों में जो गिरावट का रुख देखा गया था वह 1972 में रोक लिया गया है जैसा कि निम्नलिखित तालिका से प्रकट होता है :

वर्ष	विश्व निर्यातों में भारत के निर्यातों का प्रतिशत भाग (केन्द्र द्वारा योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था को छोड़कर) %
1968	0.83
1969 . . .	0.76
1970 . . .	0.73
1971 . . .	0.66
1972	0.66

विदेशी विमान कम्पनियों द्वारा भारतीय हवाई अड्डों से ईंधन लेना

*335. **श्री राम भगत पासवान**
श्री राम प्रकाश } : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशी विमान कम्पनियों द्वारा भारतीय हवाई अड्डों से ईंधन लिए जाने में कटौती करने के भारत सरकार के अनुरोध पर विदेशी विमान कम्पनियों की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : विश्व-व्यापी ईंधन-संकट को दृष्टि में रखते हुए सभी विदेशी विमान कम्पनियों ने ईंधन खपत के बारे में अधिकतम किफायत करने की आवश्यकता को स्वीकार किया है और इस सम्बन्ध में अपना सहयोग प्रदान कर रही हैं।

इंडियन एयरलाइंस में छंटनी किये गये नैमित्तिक श्रमिकों की संख्या

*337. **श्री वयालार रवि**
श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् } : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस ने गत हड़ताल आरम्भ होने के बाद किन्हीं नैमित्तिक श्रमिकों की छंटनी की है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी कुल संख्या कितनी है तथा उन्हें किन-किन स्टेशनों से छंटनी किया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) अस्थायी प्रकृति के कार्य के लिए अथवा छुट्टी, अनुपस्थिति, आदि के कारण कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए इंडियन एयरलाइंस नैमित्तिक श्रमिकों (कैजुअल लेबर) को नियुक्त करता था। तालाबंदी से तुरन्त पूर्व इंडियन एयरलाइंस द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में नियुक्त नैमित्तिक श्रमिकों की संख्या निम्न प्रकार थी :

बम्बई क्षेत्र	64
कलकत्ता क्षेत्र . .	14
दिल्ली क्षेत्र . .	201
मद्रास क्षेत्र . . .	130

नई शिफ्ट प्रणाली को लागू करने तथा अपव्ययी कार्य-प्रणालियों को समाप्त कर दिए जाने के परिणामस्वरूप उत्पादन में हुई वृद्धि के कारण अभी तक नैमित्तिक श्रमिकों की नियुक्ति की कोई आवश्यकता उत्पन्न नहीं हुई है।

यूरोपीय साझा बाजार के देशों के साथ व्यापार में वृद्धि

*339. **श्री पी० वेंकटासब्बया** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूरोपीय साझा बाजार के देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) अब तक इससे क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) व्यापार की सम्भावनाओं का पता लगाने तथा निर्यात क्षमता का उपयोग करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (ग) यूरोपीय साझा बाजार के देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ साथ व्यापार के संबंध में टैरिफ और गैर-टैरिफ अवरोधों को समाप्त करने/कम करने के लिए हमारे पास तथा अन्य निर्यात संवर्धन उपाय जैसे द्विपक्षीय आधार पर वाणिज्य विकास कार्यक्रम की क्रियान्विति, व्यापार प्रतिनिधि मण्डलों का आदान प्रदान, व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना, संयुक्त कमीशनों की बैठकें आयोजित करना आदि सम्मिलित हैं।

हमारे प्रयासों के फलस्वरूप गत समय में समुदाय से और साथ ही अलग-अलग सदस्य राज्यों से कई रियायतें प्राप्त हुई हैं। इन रियायतों में पटसन तथा कयर करार के अन्तर्गत

की गई पर्याप्त टैरिफ कटौतियां, ईस्ट इंडिया किप्स, चाय, कुछ मसाले आदि जैसी भारत की निर्यात दिलचस्पी वाली कई मदों के बारे में टैरिफ निलम्बन सम्मिलित हैं। 1974 के लिए समुदाय की जी० एस० पी० योजना में और सुधार पहले ही करवा लिए गए हैं।

यूरोपीय साझा बाजार के साथ एक वाणिज्यिक सहयोग करार किया गया है जिसका उद्देश्य तुलनात्मक लाभ और परस्पर फ़ायदे के आधार पर व्यापार आदान-प्रदानों का विकास करना है। यूरोपीय साझा बाजार के साथ हमारा व्यापार बढ़ता जा रहा है।

व्यापार अवसरों का पता लगाने और निर्यात सम्भाव्यता का लाभ उठाने के लिए जो कदम उठाने का विचार किया गया है उन में टैरिफ और गैर-टैरिफ क्षेत्रों में उदारीकृत उपाय प्राप्त करने के लिए हमारे सतत प्रयास शामिल हैं। इन में वाणिज्यिक विकास कार्यक्रम, व्यापार दलों का आदान-प्रदान, निर्यात उत्पादन आधार का विस्तार जैसे अन्य संवर्धनात्मक कार्यकलाप गहन करने के प्रयास भी शामिल हैं।

उड़ान भरने के स्तरों में विमान चालकों की योग्यता का मूल्यांकन करने पर व्यय की गई धन राशि

*340. **डा० कर्णी सिंह :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस ने उड़ान भरने के स्तरों में विमान चालकों की योग्यता का मूल्यांकन करने पर वर्ष 1973 के उत्तरार्ध में 1.5 करोड़ रुपए व्यय किए गए थे ;

(ख) क्या सामान्यता उस प्रयोजन के लिए विमान चालकों का परीक्षण प्रति छः मास बाद लाइसेंस के नवीकरण के समय किया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में इतनी अधिक धनराशि व्यय करने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) बड़े तथा अधिक जटिल विमानों के परिचालन सेवाओं में लाए जाने के परिणामस्वरूप हर विमान कम्पनी के लिए सुरक्षा के हित में अपने विमान-चालकों एवं अन्य कर्मचारियों की दक्षता का स्तर ऊंचा रखना अत्यधिक आवश्यक हो जाता है। सामान्य रूप से एयर लाइंस के विमान-चालकों को कुछ टैस्ट वर्ष में दो बार देने होते हैं, और कुछ अन्य टैस्ट वर्ष में एक बार, परन्तु नागर विमानन के महानिदेशक को किसी भी समय, जब कभी वह आवश्यक समझे, टैस्ट लेने का अधिकार है। कमांडरों की सामान्य उड़ान तथा उपकरण उड़ान निपुणता का पुनर्मूल्यांकन करने का फैसला किया गया था क्योंकि इण्डियन एयर लाइंस के विमानों की कई दुर्घटनाओं का कारण विमान चालक में दक्षता का अभाव स्थापित किया गया था।

इस संबंध में 1973 के उत्तरार्ध के लिए व्यय 20.03 लाख रुपए था।

डाक घर बचत बैंक लेखों के जमाकर्ताओं को ब्याज की अदायगी

3180. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस समय डाक घर अपने जमाकर्ताओं को वे सभी सुविधाएं तथा ब्याज दर दे रहे हैं जो कि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दी जा रही है और यदि नहीं तो राष्ट्रीयकृत बैंकों में क्या विशेष

सुविधाएं दी जातीं हैं तथा डाकघर बचत बैंक खाते में भी यही सुविधाएं देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : डाकघर बचत बैंक खातों के लोगों के लिए दी गई सुविधाएं और ब्याज की दर राष्ट्रीयकृत बैंकों के जमाकर्ताओं को दी गई सुविधाओं के मुकाबले में अधिक हैं। डाक घर बचत बैंक के खाता खोलने वाले जमाकर्ताओं को सरकार द्वारा चालू की गई इनामी योजना का लाभ भी मिलता है।

Scheme of Agriculture Refinance Corporation Re : Extension of Irrigation Facilities in Raisen District of Madhya Pradesh

3181. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(*a*) whether a team of the Reserve Bank of India has recently examined the feasibility of the proposed Rs. 1·14 crore scheme of the Agricultural Refinance Corporation of India for expansion of irrigation facilities in Gairatganj, Begamganj and Silwani Development blocks in Raisen District of Madhya Pradesh; and

(*b*) if so, the further progress made in this regard so far ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (*a*) The Madhya Pradesh State Cooperative Land Development Bank submitted to the Agricultural Refinance Corporation in September, 1973 two minor irrigation schemes covering Gairatganj, Begamganj and Silwani Tehsils of Raisen district of Madhya Pradesh.

(*b*) The economic feasibility studies of these schemes have since been carried out by the Corporation and the schemes are under consideration.

उत्तर प्रदेश हथकरघा उद्योग में बेरोजगारी

3182. श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धागे के कम सप्लाई के कारण उत्तर प्रदेश हथकरघा उद्योग के बहुत बड़ी संख्या में हथकरघा कर्मचारी बेरोज़गार हो गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है और उत्पादन में कितनी कमी हुई है, और

(ग) उत्तर प्रदेश के हथकरघा कर्मचारियों की कठिनाईयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

Development of 'Kosa' Cloth

3183. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(*a*) whether Government of Madhya Pradesh have sent a scheme for the development of textile industry, particularly the 'Kosa' cloth;

(*b*) if so, the salient features thereof and the reaction of Government thereto; and

(*c*) the steps taken for expeditions implementation of the scheme in order to improve the standard of life of lakhs of labourers of 'kosa' cloth industry ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (*a*) No, Sir.

(*b*) & (*c*) Do not arise.

नोटों की छपाई में वृद्धि

3184. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी-फरवरी, 1974 में पूर्व अनुमानों की तुलना में बहुत अधिक नोट छापे गए ;

(ख) यदि हां, तो पहले लगाए गए अनुमानों की तुलना में इन दो महीनों में वास्तव में कितने नोट अधिक छापे गए तथा उसके परिणामस्वरूप नोटों के परिचालन में कितनी वृद्धि हुई; और

(ग) आगामी 6 महीनों में कितने नोट छापे जाने का अनुमान है तथा इस मामले में क्या सावधानी बरती गई है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, नहीं।

(ख) नासिक प्रेस में भारतीय रिजर्व बैंक के "ईन्डेंट" के अनुसार ही नोट छापे जाते हैं। जनवरी, 1974 में नासिक प्रेस में 296.625 करोड़ रुपए की कीमत के 4582.5 लाख नोट छापे गए थे। फरवरी, 1974 में 241.80 करोड़ रुपए की कीमत के 2140 लाख नोट छापे गए थे। मुद्रा का परिचालन नोट छापने से भिन्न हैं और इसका विनियमन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। दिसम्बर, 1973 में 5808 करोड़ रुपए, जनवरी 1974 में 5987 करोड़ रुपए और फरवरी, 1974 में 6169 करोड़ रुपए की मुद्रा परिचालन में थीं।

(ग) अप्रैल-सितम्बर, 1974 के दौरान 1460.50 करोड़ रुपए की कीमत के 23000 लाख नोट छापे जाने का अनुमान है।

परिचालित मुद्रा, जनता के पास मुद्रा की सप्लाई की कुल मात्रा का एक भाग है और अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुकूल मुद्रा प्रसार को नियंत्रित करने के लिए समय-समय पर उपयुक्त उपाय किए गए।

50 रुपये मूल्य के नये नोट जारी करना

3185. **श्री चन्द्र भाल मनी तिवारी**
श्री लम्बोदर बलियार } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार इस वर्ष 50 रुपये मूल्य का नोट चलाने का है;

(ख) क्या 20 रुपये मूल्य के नोट पर लाल स्याही में लिखी गयी संख्या को गर्म पानी अथवा सौडा-साबुन पानी से धोया जा सकता है; और

(ग) क्या सरकार 50 रुपये मूल्य का नोट छापते समय इस बात को ध्यान में रखेंगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सरकार का 50 रुपये के नोट जारी करने का प्रस्ताव है, लेकिन यह इस साल जारी किये जायेंगे यह कहना कठिन है;

(ख) बीस रुपये के नोट में नम्बर काली स्याही से छापा जाता है और यह गर्म पानी या सोडा साबुन पानी से मिटाया नहीं जा सकता;

(ग) मुद्रा नोटों की सभी स्याहियों का हल्के तेजाब, क्षारीय साबुन तथा अन्य तत्वों के प्रभाव से मुक्त करने के लिये परीक्षण किया जाता है और नोटों में जो स्याही प्रयुक्त की जायगी उसके बारे में कोई छूट नहीं दी जायेगी।

इण्डियन एयरलाइन्स में कर्मचारियों के वेतनमान

3168. **श्री वयालार रवि:** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइंस में कुल कितने कर्मचारी हैं तथा इसमें अधिकारियों और कर्मचारियों की श्रेणीवार आंकड़े क्या हैं और उनके वेतनमान क्या हैं ; और

(ख) क्या अधिकारियों तथा अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतनमानों में बहुत अंतर है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) इंडियन एयरलाइंस में कर्मचारियों की संख्या, उनका अधिकारियों तथा कर्मकारों के रूप में विश्लेषण तथा उनके वेतनमानों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6439/74।]

(ख) जी, नहीं। वास्तव में कुछ ऐसे दृष्टांत है जहां अधिकारियों की परिलब्धियां (इमाल्यूमैंट) कर्मकारों के कुछ वर्गों की तुलना में कम हैं।

वर्ष, 1973-74 के दौरान विदेशों में पर्यटन प्रचार अभियान पर खर्च की गयी राशि

3187. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा:** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पर्यटन के विकास को बढ़ावा देने के लिये विदेशों में वर्ष 1973-74 के दौरान प्रचार अभियान पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(ख) इस वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा अर्जित करने में यह अभियान कहां तक सहायक रहा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषी): (क) वर्ष 1973-74 के दौरान भारत के लिये पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिये विदेशों में प्रचार अभियान के लिये की गई 95.77 लाख रुपये की व्यवस्था की तुलना में लगभग 95.70 लाख खर्च किये जा चुके हैं।

(ख) पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा विदेशों में प्रारम्भ किए गए प्रचार एवं प्रोत्साहन अभियानों के साथ-साथ अन्य उपायों तथा पर्यटन यातायात में निष्पादित वृद्धि के परिणामस्वरूप 1973 के दौरान पर्यटन से होने वाली विदेशी मुद्रा की आय में 19.20 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। 1973 के दौरान पर्यटन से होने वाली विदेशी मुद्रा की अनुमानित आय, 1972 के दौरान हुई 48.30 करोड़ रुपए के मुकाबले, 67.50 करोड़ रुपए थी।

इण्डियन एयरलाइन्स को एच० एस०-748 विमान की डिलीवरी

3188. श्री डी० बी० चन्द्र गौडा : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित सात एस० एस०-748 विमान इण्डियन एयरलाइंस को अभी दिए जाने हैं; और

(ख) यदि हां, तो यह विमान कब दिए जाएंगे तथा इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) (हिन्दुस्तान) एयरोनाटिक्स लि० ने इन विमानों के वितरण की अभी कोई निश्चित तारीख नहीं दी है।

Exports to East Germany

3189. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(*a*) what commodities were exported to East Germany during 1970-71, 1971-72 and 1972-73;

(*b*) the value thereof in Indian currency;

(*c*) government's prospective planning and policy in regard to export of indigenous goods to that country; and

(*d*) the approximate value of goods to be exported to that country during the financial year 1974-75 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (*a*) A statement is attached.

(*b*) 1970-71 . . . . . Rs. 245·6 million

1971-72 . . . . . Rs. 179·5 million

1972-73 . . . . . Rs. 150·8 million

(*c*) Government's policy is to increase and diversify exports to all the countries including East Germany. To promote and popularize Indian goods, India has been regularly participating in the annual Leipzig Fair, besides sponsoring trade delegations etc.

(*d*) Trade Plans with East European countries are drawn up on calendar year basis. The value of exports to East Germany envisaged in 1974 trade plan is of the order of Rs. 401 million.

Statement

Principal commodities exported to East Germany during 1970-71, 1971-72 and 1972-73.

1. Deoiled cakes
2. Tanned and semi-tanned hides and skins
3. Finished leather and leather goods including footwear
4. Processed mica
5. Cotton waste
6. Cashew kernels (broken)
7. Tea
8. Jute manufactures
9. Tobacco.
10. Pepper and other spices
11. Engineering goods including fittings, steel pipes and tubes and sanitary fitting

Volume of Imports from Canada

3190. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state the estimated value in Indian Currency of items to be imported during 1974-75 from Canada ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : It is not possible at this stage to estimate the value of imports likely to be made from Canada in 1974-75.

Theft in Banganappalle Branch of Syndicate Bank, Andhra Pradesh

3191. Shri Hukam Chand Kachwai
Shri M. Ram Gopal Reddy } : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(*a*) whether gold and cash worth more than Rs. 14 lakhs were stolen in February, 1974 from a Banganappalle (Andhra Pradesh) branch of the Syndicate Bank; and

(*b*) the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (*a*) & (*b*). Syndicate Bank has reported that, on the night of the 15-16th February, 1974, burglars entered the premises of the Banganappalle branch of the bank, forced open two safes and decamped with cash amounting to Rs. 26,482.68/- and jewels valued at about Rs. 11·7 lakhs. The bank has reported the matter to the State Police and police investigations are continuing. The bank has further reported that some persons have been arrested and a part of the stolen property has been recovered by the Police.

प्राकृतिक रबड़ उत्पादक देशों का संघ

3192. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्राकृतिक रबड़ उत्पादक देशों का संघ बनाने के सम्बन्ध में श्रीलंका सरकार के प्रस्ताव के बारे में जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मद्रास हवाई अड्डे के विस्तार की योजना

3193. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम : क्या **पर्यटन** और **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास हवाई अड्डे का विस्तार किये जाने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). मद्रास विमानक्षेत्र के टैक्सी-ट्रैक व एप्रन सिस्टम के विस्तार तथा उसे मजबूत करने का कार्य प्रारंभ हो गया है । मद्रास विमानक्षेत्र के विस्तार के लिये प्रारंभ की जाने वाली प्रस्तावित नयी योजनाओं में ये सम्मिलित हैं :—

अन्तर्राष्ट्रीय आगमन हाल, अन्तर्देशीय एप्रन एवं अन्तर्देशीय सामान प्राप्ति क्षेत्र का विस्तार तथा विमानों के दिक्चालन, एप्रोच और अवतरण के लिए उन्नत/अतिरिक्त उपकरणों की व्यवस्था ।

पांचवीं योजना के दौरान तमिलनाडु में पर्यटन केन्द्रों का विकास

3194. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तमिलनाडु में कुछ पर्यटन केन्द्रों का विकास करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित स्थान कौन-कौन से हैं तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री [डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषी] : (क) और (ख). केन्द्रीय क्षेत्र में, रामेश्वरम् का पर्यटक बंगला तथा मद्रास का युवा होस्टल पांचवीं योजना के पहले वर्ष में पूरे किए जाएंगे । इसके अतिरिक्त, निधियों के उपलब्ध होने की अवस्था में तथा व्यवहार्यता अध्ययन करने के पश्चात्, भारत पर्यटन विकास निगम का महाबलिपुरम् में अपने काम्प्लेक्स का तथा मदुराई में यात्री लॉज का विस्तार करने, कन्या कुमारी में एक होटल का निर्माण करने, मद्रास में अपने परिवहन यूनिट में वृद्धि करने तथा मद्रास के अन्तर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र पर अपनी शुल्क मुक्त दुकान का विस्तार करने का प्रस्ताव है ।

रियायती दर ब्याज योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश को दिया गया ऋण

3196. **श्री गंगा चरण दीक्षित :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 में मध्य प्रदेश को रियायती दर ब्याज योजना के अन्तर्गत कितना ऋण दिया गया ;

(ख) क्या रियायती दर ब्याज योजना के अन्तर्गत ऋण पाने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या के बारे में जिलावार जानकारी एकत्र कर ली गई है; और

(ग) जिन्हें पिछड़े हुये जिले माना गया है उनके निवासियों को क्या रियायतें, लाभ अथवा प्राथमिकता दी जाती है तथा इनका मध्य प्रदेश के सम्बद्ध जिलों पर व्यावहारिक रूप से क्या प्रभाव पड़ा है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) संभवत: माननीय सदस्य का संकेत ब्याज की विभेदी दरों की उस योजना की ओर है, जिसे 1972 में चालू किया गया था । इस योजना के अन्तर्गत जून, 1973 के अंत तक मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बकाया अग्रिम के संबंध में आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

खातों की संख्या	बकाया राशि
4302	16.90 लाख रुपये

(ख) इस योजना के अन्तर्गत दिए गए अग्रिमों के सम्पूर्ण आंकड़ों का संकलन इस समय विभिन्न बैंकों द्वारा केवल राज्यों के आधार पर ही किया जा रहा है, जिलों के आधार पर नहीं ।

(ग) यह योजना इस समय मध्य प्रदेश के उन 37 जिलों में लागू हैं । जिन्हें या तो औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों में रखा गया है या जो एस० एफ० डी० ए०/एम० एफ० ए० कार्यक्रमों के अन्तर्गत आते हैं । इस योजना के अन्तर्गत, कार्यचालन पूंजी के लिए 1500

रुपये तक तथा सावधिक ऋण के लिए 5000/- रुपये तक के ऋण केवल 4 प्रतिशत की रियायती दर पर तथा बिना किसी मार्जिन वाले ऋणकर्त्ताओं को उत्पादक उद्यमों के लिए दिए जाते हैं।

बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दी गयी अग्रिम राशि

3197. **श्री ए० के० एम० इसहाक :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंकों द्वारा गत तीन वर्षों में, राज्यवार दी गई कुल अग्रिम राशियों में से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दी गई अग्रिम राशियों की प्रतिशतता क्या थी ?

(ख) उपरोक्त अवधि में राष्ट्रीयकृत बैंकों को अग्रिम राशियों के लिए कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए; और

(ग) कितने आवेदन पत्रों पर अग्रिम राशि दी गई और प्रत्येक राज्य में दिसम्बर, 1973 तक कुल कितना ऋण दिया गया ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग). इस समय सरकारी क्षेत्र के बैंक इस तरह के आंकड़े नहीं रखते कि ऋण के लिए कितनी दरखवास्तें आयीं और कितनी दरखवास्तें मंजूर की गयीं।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को देय मकान किराया भत्ता

3198. **श्री विश्वनाथ झुंनझुनवाला :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तीसरे वेतन आयोग के प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों के संदर्भ में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को देय मकान किराया भत्ते के बारे में कोई निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जहां तक श्रेणी II, III और IV के कर्मचारियों का सम्बन्ध है, आयोग की संगत सिफारिशों पर सरकार के निर्णयों का एक विवरण-पत्र सदन-पटल पर रखा गया है।

विवरण

क्र० सं०	तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशें	सरकार का निर्णय
(1)	(2)	(3)
1.	मकान किराया भत्ते की दरें निम्न प्रकार से होनी चाहियें:—	स्वीकृत

(1)	(2)	(3)
	महानगर/नगर की श्रेणी	मकान किराये भत्ते की दरें
	(i) ए, बी०-1 और बी-2	वेतन का 15 प्रतिशत
	(ii) सी	वेतन का 7½ प्रतिशत
	[देखिय अध्याय 56, पैराग्राफ 29 (ii)]	
2.	नगर निवास प्रतिपूर्ति भत्ते की मंजूरी के लिये सिफारिश की गयी "नगरीय समुच्चय" की धारणा को मकान किराये भत्ते की मंजूरी के लिये लागू नहीं किया जाना चाहिये। [देखिये अध्याय 56, पैराग्राफ 30]	स्वीकृत। मकान किराया भत्ते की मंजूरी के लिये श्रेत्रीय सीमाओं से सम्बन्धित वर्तमान कसौटी लागू होती रहनी चाहिये।
3. (क)	किराये की रसीदों को प्रस्तुत करना तथा उनका सत्यापन करना सभी मामलों में आवश्यक बना दिया जाना चाहिये।	(क) स्वीकृत बशर्ते कि संशोधित वेतनमानों में प्रतिमाह 750.00 रु० तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को जिनमें हाल ही में नियुक्त कर्मचारी भी शामिल हैं, सत्यापन के लिये किराये की रसीदें प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।
(ख)	लेकिन, जो कर्मचारी वर्तमान में किराये की रसीद प्रस्तुत किये बिना मकान किराया भत्ता ले रहे हैं, उन्हें तब तक यह सुविधा दी जाती रहनी चाहिये जब तक वे मकान किराये भत्ते की उसी रकम का दावा करते हैं जिसे वे इस समय प्राप्त कर रहे हैं। यह रियायत हाल ही में नियुक्त कर्मचारियों को भी लागू होनी चाहिये [देखिये अध्याय 56, पैराग्राफ 29 (iv)]	(ख) वर्तमान नियमों के अधीन रहते हुए स्वीकृत जिनके अनुसार किराये की रसीद प्रस्तुत करने की, केवल हाल ही में नियुक्त किये गये उन कर्मचारियों के मामले को छोड़ कर छूट है, जिन पर (क) पर दिया गया निर्णय लागू होगा।

विदेशी कम्पनियों का विस्तार

3199. श्री डी० पी० जदेजा
श्री बेकारिया } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन विदेशी कम्पनियों ने अपना उत्पादन बढ़ाने के लिये आवेदन किए हुए हैं जिससे उनके इक्विटी शेयरों की पूंजी उनके आवेदन करने के समय निगमित आस्तियों की प्रतिशतता में शामिल हो, कम हो जायेगी और सी० सी० आई० की अनुमति से क्रियान्वयन पर विदेशी निगमित आस्तियों की प्रतिशतता में कम हो जाएंगी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार विदेशी कम्पनियां जिन्हें पूंजी-इजारा-नियंत्रक द्वारा, पिछले दो वर्षों में विस्तार के कारण अपने सामान्य शेयर को मिलाने की स्वीकृति दी है, उनके नाम निम्नलिखित हैं।

कम्पनी का नाम	पूंजी-इजारा-नियंत्रक को आवेदन करते समय विदेशी संगठनों का प्रतिशत	पूंजी-इजारा-नियंत्रक की स्वीकृति को कार्यान्वित विदेशी संगठनों (लगभग) प्रतिशत
(1)	(2)	(3)
1. मोटर इंडस्ट्रीज कम्पनी लिमिटेड	57.5%	51%
2. इंगलिश इलकट्रीक कम्पनी आफ इंडिया लिमिटेड	75%	66⅔%
3. जे० स्टोन एण्ड कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड	100%	60%
4. इंडियन अलमीनियम कम्पनी लिमिटेड	65%	55.4%
5. विदीया (इंडिया) लिमिटेड	60%	57%
6. पनर कोकिल लिमिटेड	55%	49%
7. बाटा इंडिया लिमिटेड	100%	66¾%
8. फिलिप्स इंडिया लिमिटेड	69.2%	60%
9. एलफेन्ड हरब्रट (इंडिया) लिमिटेड	100%	60%
10. मोलिन्ज आफ इंडिया लिमिटेड	55.44%	50.83%
11. गुडइयर इंडिया लिमिटेड	63.08%	59.93%
12. गैस्ट कीन विलीयम लिमिटेड	60.27%	58.7%
13. जर्मन रेमेडीज लिमिटेड	61.72%	39.29%

बम्बई में कपड़ा मिल के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के कारण हानि

3200. **श्री जगन्नाथ मिश्र**
श्रीमती भार्गव तनकप्पन } : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में कपड़ा मिलों के कर्मचारियों द्वारा दीर्घ अवधि तक हड़ताल के कारण हुए घाटे के बारे में, जिसके कारण कपड़े का निर्धारित उत्पादन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, सरकार ने कोई अनुमान लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो इस अवधि में सरकार को कितनी हानि हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): **(क) तथा (ख)**. ऐसा अनुमान है कि हड़ताल से 1100 लाख मीटर कपड़े और 25 लाख किग्रा० धागे के उत्पादन की हानि हुई। सरकार द्वारा उठाई गई हानि का अनुमान उपलब्ध नहीं है ।

उर्वरक के आयात के लिये करार

3201. **श्री के० मालन्ना**
श्री जी० वाई० कृष्णन }: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनवरी-जून, 1974 में उर्वरक के आयात के लिये विदेशों के साथ नए करार किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो किन देशों के साथ, तथा करार की शर्तें क्या हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) 1974 के दौरान पूर्व यूरोपीय देशों और कोरिया के लोकतंत्रीय जनवादी गणराज्य से उर्वरकों के आयात के लिये सम्पन्न की गई संविदाओं का विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र० सं०	देश का नाम	वस्तु का नाम	जितनी मात्रा के लिये संविदा की गई।	डिलीवरी का कार्यक्रम	12-3-74 तक किये गये निर्यात
1	2	3	4	5	6
1.	जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य	पोटाश का म्यूरीयेट	180,000 पक्का 20,000 विक्रेता के विकल्प के अनुसार	जनवरी-दिसम्बर, 1974।	31,200
2.	सोवियत संघ	यूरिया	200,000	मार्च-दिसम्बर, 1974।	निर्यात इस महीने से आरम्भ होंगे

1	2	3	4	5	6
3.	सोवियत संघ	अमोनियम सल्फेट	75,000	मार्च-दिसम्बर, 1974	—वही—
4.	सोवियत संघ	पोटाश का म्युरियेट	50,000	मार्च-दिसम्बर, 1974	5,615
5.	बल्गारिया	यूरिया	46,000	जुलाई-दिसम्बर, 1974	—
6.	कोरिया का लोकतंत्रीय जनवादी गणराज्य	यूरिया	20,000	जुलाई-दिसम्बर, 1974	—
7.	पोलैंड	यूरिया	180,000	मार्च-दिसम्बर, 1974	—

सूती वस्त्र उद्योग के विस्तार के लिए लाइसेंस नीति

3202. **श्री एम० कतामुतु**
श्री मान सिंह भौरा } : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूती वस्त्र उद्योग के विस्तार के लिये सरकार ने नई लाइसेंस नीति लागू करने का निर्माण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

विदेशी स्वामित्व की कम्पनियों में भारत का योगदान

3203. **श्री नवल किशोर सिंह**
श्री धनशाह प्रधान } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कार्य कर रही शत प्रतिशत विदेशी स्वामित्व वाली कम्पनियों के नाम तथा उनकी संख्या कितनी है ;

(ख) विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम के बारे में मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये जाने के पश्चात उनमें से कितनी कम्पनियों ने भारत को साझीदार बनाना स्वीकार कर लिया है तथा इन कम्पनियों के नाम क्या है; और

(ग) सरकार का ऐसी कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है जिन्होंने भारत को साझीदार बनाने से इंकार कर दिया है अथवा ऐसा करने में अरूचि दिखाई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) इस सम्बन्ध में, लोक-सभा के 19 फरवरी 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 191 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसका उत्तर विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय के उप-वित्त मंत्री ने दिया था और

जिसमें शत-प्रतिशत विदेशी कम्पनियों की सहायक कम्पनियों के नामों की सूची दी गयी थी ।

(ख) अभी तक केवल एक कम्पनी से आवेदनपत्र मिला है और उस पर विचार किया जा रहा है । विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 के अन्तर्गत इस प्रकार के आवेदनपत्र भेजे जाने की आखिरी तारीख 30 जून, 1974 है ।

(ग) इस स्तर पर कोई सूचना देना समय-पूर्व होगा ।

उन देशों के नाम जिनके साथ भारत में अखबारी कागज की कमी के प्रश्न पर विचार किया गया

3204. **श्री डी० वी० चन्द्रगोडा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम तथा संख्या क्या है जिनके साथ भारत में अखबारी कागज की कमी के प्रश्न पर विचार किया गया है ; और

(ख) इन देशों द्वारा भारत को कितनी सहायता देने का आश्वासन दिया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) (क) चूंकि अखबारी कागज की खरीदारियां वाणिज्यिक सौदे हैं, अतः सरकार ने अभी तक यह आवश्यक नहीं समझा कि किसी विदेशी उच्च पदस्थ व्यक्ति के साथ इस विषय पर बातचीत की जाए ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कपड़ा मिलों के उत्पादन पर तेल संकट का प्रभाव

3205. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भट्टी तेल की सप्लाई के लिये भारतीय तेल निगम पर आश्रित सामान्य रूप स देश की तथा विशेष रूप से बम्बई की कई कपड़ा मिलों के बन्द होने का खतरा है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) क्या कुछ मिलों ने सप्लाई में पांच दिन काम करने का निर्णय किया है; और

(घ) तेल संकट का देश के उत्पादन पर कितना प्रभाव पड़ा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं । लेकिन भट्टी तेल का प्रयोग करने वाली कपड़ा मिलों को भट्टी तेल की पर्याप्त पूर्ति हासिल करने में कठिनाइयां उठानी पड़ रही हैं । इनमें से कुछ मिलें भट्टी तेल की पूर्ति के लिये इंडियन आयल कार्पोरेशन पर निभर करती हैं ।

(ख) तेल जलाकर चालू किये जाने वाले बायलरों को कोयले पर आधारित बायलरों में बदलने की योजनाएं विचाराधीन हैं । भट्टी तेल की उपलब्ध मात्रा के न्यायोचित वितरण की व्यवस्था की जा रही है ।

(ग) सरकार को इस प्रकार के किसी निर्णय की सूचना नहीं दी गई है ।

(घ) तेल पूर्ति की कठिनाइयों के कारण अभी तक उत्पादन पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ा है ।

राज्य सरकारों से सरकारी उपक्रमों में प्रति नियुक्ति पर आये कर्मचारी

3206. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों से अधिक से अधिक संख्या में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों को लेने तथा वर्तमान पदाधिकारियों को सरकारी उपक्रमों में स्थायी रूप से खपाने अथवा मूल कार्यालय वापिस चले जाने के लिए कहने की सरकार की नीति अभी तक कायम है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिनियुक्ति पर गए कितने कर्मचारियों ने सरकारी उपक्रमों में स्थायी रूप से खप जाना स्वीकार किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) पांच वर्ष पूर्व सरकारी नीतियों पर किये गये निर्णयों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, सरकारी उद्यमों में प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारी, उपक्रमों में, 2500-3000 रुपये या उससे ज्यादा वेतन वाले पदों पर अधिक से अधिक केवल दो वर्ष तक और अन्य पदों पर तीन वर्ष तक प्रतिनियुक्ति पर रह सकते हैं इस अवधि के अन्त में इन्हें उपक्रम में स्थायी रूप से रख लिए जाने या अपने मूल संवर्गों में वापिस जाने का विकल्प देना होगा। यह नीति अभी भी उचित ही है । सरकार ने सरकारी उद्यमों को, उनके अधीन पदों के सम्बन्ध में, इस नीति निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक अनुदेश जारी किये हैं । सरकारी उद्यमों में, उन पदों के सम्बन्ध में, जिन पर सरकार द्वारा नियुक्तियां की जाती हैं, इस बात को ध्यान में रखा जाता है ।

(ग) 30 सितम्बर, 1973 तक, प्रश्न के भाग क और ख के उत्तर म उल्लिखित नीति-निर्णय के बाद प्रतिनियुक्ति पर आये 360 कर्मचारियों ने सरकारी उद्योगों में स्थायी रूपमे रखे जाने का विकल्प दिया है ।

बंगलादेश को कोयले की सप्लाई

3207. **श्री जगन्नाथ मिश्र**
श्री सी० के० जाफर शरीफ } : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलादेश ने भारत से कोयले की मांग की है ; और

(ख) वर्ष 1972-73 के दौरान भारत द्वारा बंगलादेश को किन मुख्य शर्तों पर कोयला सप्लाई किया गया था ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : वर्ष 1972-73 के दौरान भारत सरकार ने बंगलादेश को 209,530 मे० टन कोयले की सप्लाई की है जिसमें से 50,000 मे० टन वस्तु तथा सहायता अनुदान के अन्तर्गत तथा बकाया सीमित भुगतान व्यवस्था के अन्तर्गत दिया गया था : सीमित भुगतान व्यवस्था के अन्तर्गत सप्लाई पारस्परिक सम्मत कीमतों पर थी जो कि ऐसे कोयले के निर्यातों के लिये खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा कहीं और प्राप्त की गई कीमतों के मुकाबले में कम थी ।

अखबारी कागज के आयात के लिए राज्य व्यापार निगम तथा कनाडा के बीच करार

3208. **श्री नरेन्द्र सिंह**
श्री एम० एस० संजीवीराव } : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राज्य व्यापार निगम ने आगामी पांच वर्षों में प्रति वर्ष 50,000 टन अखबारी कागज के आयात के लिये कनाडा के साथ हाल ही में करार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी शर्तें क्या हैं ;

(ग) क्या कनाडा ने अखबारी कागज के जिस मूल्य की पेशकश की है, वह रूस द्वारा इसी माल के लिये मांगे गये मूल्य से कम है; और

(घ) यदि हां, तो दोनों देशों द्वारा मांगे गये मूल्यों में कितना अन्तर है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) राज्य व्यापार निगम ने पांच वर्षों के लिये प्रति वर्ष 35,000 मे० टन सप्लाई करने के लिये एक संविदा की है।

(ख) करार एक्सपोर्ट सेल्स, कनाडा के साथ किया गया है और कीमत न्यूयार्क की कीमत जमा संविदा में निर्दिष्ट प्रीमियम पर आधारित है तथा उसमें वृद्धि की जा सकती है ।

(ग) तथा (घ). चूंकि अखबारी कागज की कीमत वृद्धि तथा अन्य दशाओं के अध्यधीन है जो सोवियत संघ की सप्लाईज के साथ लागू नहीं होती, अतः दोनों का मुकाबला करना कठिन है ।

भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक द्वारा महालेखाकारों के पदों की रचना

3209. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली**
श्री वयालार रवि } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक ने गत एक वर्ष के दौरान 2,500 रु० प्रति माह वेतन वाले महालेखाकारों के 20 पद बनाए थे;

(ख) यदि हां, तो बड़े पैमाने पर उच्च पदों को बनाने के क्या कारण हैं जबकि सरकार दृढ़ता से व्यय में मितव्ययिता की नीति अपना रही है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) महालेखाकार के पद 1800-100-2000-125-2250 रुपये के वेतनमान में होते हैं। नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक ने, उनको प्रत्यायोजित अधिकार के अन्तर्गत, जनवरी 1973 के बाद महालेखाकार ग्रेड में 8 अस्थायी पदों का सृजन किया है, जिससे उनके संवैधानिक कर्त्तव्यों के निष्पादन में बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लेखापरीक्षा तंत्र में तेजी लायी जा सके।

संयुक्त परियोजना के विकास के लिए ब्रिटेन से पुर्जों की खरीद

3210. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में संयुक्त परियोजना के विकास के लिए पुर्जों की खरीद के बारे में भारत सरकार तथा भारत आने वाले ब्रिटिश संसदीय शिष्टमंडल के बीच समझौता हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त समझौते की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) ब्रिटेन कब तक सहायता उपलब्ध करा देगा तथा यह सहायता किस रूप में दी जाएगी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) जी, नहीं । हाल में जिस संसदीय शिष्ट-मण्डल ने 30 जनवरी से 7 फरवरी, 1974 के दौरान भारत का दौरा किया था वह समुद्रपारीय विकास पर ब्रिटेन के हाउस आफ कामन्स की एक प्रवर समिति थी । प्रवर समिति का शिष्टमण्डल होने के कारण इस शिष्टमण्डल और भारत सरकार के बीच कोई करार नहीं हुआ । उनका मुख्य उद्देश्य, व्यापार और सहायता के बीच सम्बन्ध; ऋण भार; ग्रामीण विकास; विकसित देशों के आयात के प्रभाव और समायोजन सम्बन्धी नीतियों; कुल आय, कृषि सम्बन्धी विकास पर विशेष जोर देते हुए आय का वितरण करना और रोजगार के संदर्भ में तीसरे विश्व के देशों के विकास सम्बन्धी भविष्य और ग्रेट ब्रिटेन के यूरोपीय आर्थिक समिति (ई० ई० सी०) में शामिल हो जाने के कारण कुल मिलाकर ब्रिटिश सहायता कार्यक्रम पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच पड़ताल करना और ब्रिटेन के हाउस आफ कामन्स को रिपोर्ट देना था ।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा नहीं होते ।

Meeting of Representatives of Unions with Finance Minister

3211. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(*a*) whether representatives of five Unions of the Central Government employees had met him recently;

(*b*) whether an assurance was given by him for increasing their pay; and

(*c*) if so, the date from which the pay rise would be effected and how much increase would be made in their pay ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (*a*) Six representatives of some Central Government employees' Unions met the Finance Minister on the 26th December, 1973.

(*b*) No, Sir. They were informed that the points raised by them would be looked into.

(*c*) Does not arise.

नायलोन तथा फिलामेंट धागों का उचित वितरण

3212. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिल्क एण्ड आर्ट सिल्क मिल्स के चेयरमैन ने रेयन तथा नायलोन फिलामेन्ट धागों के उचित वितरण के लिये प्रधानमंत्री द्वारा हस्तक्षेप करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है तथा इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

सिल्क तथा आर्ट सिल्क एसोसियेशन के अध्यक्ष, श्री मगनलाल एच० दोशी ने निम्नलिखित तथ्यों की ओर प्रधानमंत्री का ध्यान दिलाया :

1. भारत सरकार ने रेयन फिलामेन्ट यार्न, संश्लिष्ट रेशों से कत्ते यार्न और नायलोन फिलामेन्ट यार्न के बारे में टैरिफ आयोग की रिपोर्टों पर गत तीन वर्षों से कोई निर्णय नहीं लिया है और इन धागों

के वितरण व कीमतों का विनियमन स्वैच्छिक करारों के आधार पर किया जा रहा है। जो असन्तोषजनक है और कत्तिनों द्वारा ईमानदारी से अमल में नहीं लिया जा रहा है। कत्तिनों द्वारा बुनकरों को अभी भी 90,00,000 किग्रा० से अधिक यार्न दिया जाना है।

(2) यद्यपि विस्कोस फिलामेन्ट यार्न कत्तिनों और बुनकरों के बीच करार की अवधि 31-12-1973 को समाप्त हो गई किन्तु गत 3 महीनों से किसी नये करार पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं।

(3) स्टेपल फाइवर यार्न कत्तिनों को जितना यार्न देना था, उसका उन्होंने एक बहुत थोड़ा-सा अंश ही दिया है यद्यपि मंत्रालय में बार बार इस सम्बन्ध में बैठकें हुई।

(4) नाइलोन कत्तिनों और बुनकरों के बीच हुए स्वैच्छिक करार में नाइलोन यार्न के तीन उत्पादकों को सम्मिलित नहीं किया गया है।

2. विस्कोस फिलामेन्ट यार्न की उचित बिक्री कीमतों के बारे में टैरिफ आयोग की रिपोर्ट 1967-68 की अवधि के दौरान कत्तिनों की कास्टिंग पर आधारित थी, तब से कच्चे माल (आयातित लकड़ी की लुगदी) पावर तथा ईंधन की लागत में और वेतन तथा मजूरी में वृद्धि हो गई है। टैरिफ आयोग से अनुरोध किया गया है कि वे इन वृद्धियों के हिसाब से उचित कीमतों को अद्यतन बनायें।

3. विस्कोस स्टैपल फाइवर स्पन यार्न की उचित बिक्री कीमतों के बारे में टैरिफ आयोग की सिफारिशें विस्कोस स्टैपल फाइबर की उचित बिक्री कीमतों पर आधारित हैं जैसे कि टैरिफ आयोग ने अप्रैल 1970 की अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी। विस्कोस स्टेपल फाइवर की उत्पादन लागत में वृद्धियां हुई हैं। जैसे ही विस्कोस स्टेपल फाइबर की उचित बिक्री कीमत उद्यतन कर दी जायेगी, सरकार विस्कोस स्टेपल फाइबर स्पन यार्न की उचित बिक्री कीमतों के बारे में टैरिफ आयोग की रिपोर्ट पर निर्णय ले सकेगी।

4. नाइलोन यार्न की उचित बिक्री कीमतों के बारे में टैरिफ आयोग की रिपोर्ट में भी वही कमियां हैं जो विस्कोस फिलामेंट यार्न के सम्बन्ध में बताई गई थी।

5. आर्ट सिल्क यार्न के बुनकरों की कठिनाइयां दूर करने की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के धागे के कत्तिनों और बुनकरों को एक साथ लाया गया ताकि इन धागों के वितरण व कीमतों के बारे में सन्तोषजनक व्यवस्था की जा सके। कुल मिलाकर, ये स्वैच्छिक प्रबन्ध 1972 के अन्त तक सन्तोषजनक रूप से चलते रहे हैं। 1973 के उत्तरार्ध में लकड़ी की लुगदी जैसे आयातित कच्चे माल प्राप्त करने में विश्वव्यापी दुर्बलता की स्थिति का अनुभव किया गया है। विस्कोस फाइबर यार्न और विस्कोस स्टेपल फाइबर की कताई मिलों में हड़तालें और ताला बंदियाँ भी हुई हैं। इसके परिणामस्वरूप 1973 में विस्कोस स्टेपल फाइबर और विस्कोस फाइबर यार्न कम मात्रा में उपलब्ध हुआ है। बुनकरों को विस्कोस फाइबर यार्न और विस्कोस स्टेपल फाइबर स्पन यार्न की सप्लाई करने में कमी रही है। ऐसे प्रयत्न किये जा रहे हैं कि कत्तिन स्वैच्छिक करार की शर्तों के अनुसार पहले न दिये गये माल के आधार पर सप्लाइयां कर दें। बुनकरों और विस्कोस फिलामेन्ट यार्न के कत्तिनों के बीच स्वैच्छिक करार की अवधि 31-12-1973 को समाप्त हो गई। बुनकर तथा कत्तिन बराबर एक दूसरे से सम्पर्क बनाये हुए हैं ताकि फिर से सन्तोषजनक प्रबन्ध किया जा सके।

6. नाइलोन यार्न के सम्बन्ध में 1973 में कैप्रोलिक्टम की विश्वव्यापी कम उपलब्धि के कारण नाइलोन यार्न का उत्पादन घटकर एककों की लाइसेंसशुदा क्षमता का 50 प्रतिशत–60 प्रतिशत रह गया। इस संबंध में भी बुनकरों की कठिनाई दूर करने की दृष्टि से 6 सितम्बर, 1973 को बुनकरों और कत्तिनों के बीच एक स्वैच्छिक करार पर हस्ताक्षर हुए थे जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि 4 प्रमुख नाइलोन स्पनर्स का 75 प्रतिशत उत्पादन परस्पर स्वीकृत कीमतों पर वास्तविक प्रयोक्ताओं में वितरित किया जाए। जिन दो छोटे एककों--मै० सेंचुरी एन्का और मै० श्री सिन्थेटिक ने इस स्वैच्छिक करार पर हस्ताक्षर नहीं किये थे, उनसे अब इस करार पर हस्ताक्षर करने और अपने उत्पादन का 55 प्रतिशत भाग परस्पर स्वीकृत कीमतों पर वास्तविक प्रयोक्ताओं को देने के लिये कहा गया है ।

आन्ध्र प्रदेश में मार्केट यार्ड-योजना के लिए विश्व बैंक से ऋण

3213. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने आन्ध्र प्रदेश में मार्केट यार्डस योजना के विकास और प्रसार के लिये 35 करोड़ रुपये की राशि के ऋण देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मात्रा तथा शर्तें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता ।

अकाल राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत केरल को केन्द्रीय सहायता

3214. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान अकाल राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत केरल को किस प्रकार की केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : सम्भवत: माननीय सदस्य का आशय पिछले तीन वर्षों में बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में हाथ में लिए गये राहत कार्यों के लिए केरल सरकार को दी गई सहायता से है, इस सहायता का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपयों में)

	ऋण	अनुदान	जोड़
1970–71	2.20	—	2.20
1971–72	2.55	0.24	2.79
1972–73	1.14	0.11	1.25

रूस से यूरिया का आयात

3215. **श्री के० मालन्ना** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान हरित क्रान्ति कार्यक्रम में सहायता देने के लिये रूस भारत को 2 लाख टन यूरिया सप्लाई करने के लिये राजी हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी शर्तों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कम से कम 46 प्रतिशत होगी।

संविदा की शर्तों के अनुसार मार्च से दिसम्बर, 1974 की अवधि के दौरान लगभग 20,000 टन यूरिया प्रति मास डिलीवर किया जाएगा।

नौवहन सुविधाओं के अभाव में चमड़ा-निर्यात में कमी

3216. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नौवहन सुविधाओं के अभाव में चमड़े का निर्यात ठप्प हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति का सामना करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) यह बात ठीक नहीं है कि नौवहन सुविधाओं के अभाव के कारण चमड़े का निर्यात ठप्प हो गया है। पता चला है कि कुछ निर्यातक कठिनाइयों का अनुभव कर रहे हैं और उनको सभी सम्भव सहायता दी जा रही है।

मद्रास पत्तन पर अखबारी कागज को उतारने में विलम्ब

3217. **श्री राम कंवर** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अखबारी कागज की भारी कमी के बावजूद भी मद्रास पत्तन पर कनाडा से आये 2000 टन अखबारी कागज को कई सप्ताह तक जहाज से उतारा नहीं गया था ;

(ख) अखबारी कागज को उतारने में विलम्ब करने के क्या कारण थे; और

(ग) इस विलम्ब के लिये उतरदायी अधिकारियों के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

कृषि कार्यक्रम की गति तेज करने के लिए धन के भुगतान के बारे में कृषि पुनर्वित्त निगम की योजना

3218. **श्री राम प्रकाश**
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि पुनर्वित्त निगम ने कृषि कार्यक्रम की गति को तेज करने के उद्देश्य से आगामी पांच वर्षों में 900 करोड़ रुपये के भुगतान की एक योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ।

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) :(क) और (ख) भूमि विकास बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और वाणिज्यिक बैंकों के जरिये दिये जाने वाले कृषि निवेश ऋण को पुनर्वित्त करने के अस्थाई कार्यक्रम के अनुसार कृषि पुनर्वित्त निगम को पांचवीं पंच वर्षीय आयोजना के दौरान कुल 900 करोड़ रुपये के ऋणों का वितरण करने की आशा है बशर्ते कि पर्याप्त धनराशि उपलब्ध रहे । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों में लघु सिचाई, भूमि विकास, पौधों तथा फलों के बागों का विकास, दुग्धशाला, मुर्गीपालन और सुअर पालन, भण्डार और विपणन वन, फार्मों का यंत्रीकरण और मछली पालने जैसे सहायक व्यवसाय किये जायेंगे ।

तिलहनों का निर्यात

3219. **श्री आर० पी० उलगनम्बी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973 के दौरान कुल कितने तिलहनों का निर्यात किया गया तथा इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई ;

(ख) प्रति टन तिलहनों पर जहाज तक निःशुल्क विदेशी मुद्रा की आय का ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन-किन देशों को तिलहनों का निर्यात किया गया तथा निर्यातकों के नाम क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :(क)से(ग). एक विवरण संलग्न है जिसमें वित्तीय वर्ष 1972-73 तथा 1973-74 (सितम्बर, 1973 तक) में तिलहनों, आयलनट्स, तथा तेलयुक्त गिरियों के निर्यात दर्शाए गए हैं तथा उन देशों के नाम दिये गये हैं जिनको इनका निर्यात किया गया । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 6440/74]

सितम्बर, 1973 के बाद के निर्यात आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं । निर्यातकों के नाम भी उपलब्ध नहीं हैं चूंकि फर्मवार वास्तविक निर्यात के आंकड़े नहीं रखे जाते ।

चौथी योजना में वैगनों के निर्यात के लक्ष्य

3220. **श्री एम० एस० संजीवी राव :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चौथी पंचवर्षीय योजना में रेलवे वैगनों के निर्यात के लिये निश्चित किये गये लक्ष्य पूर्ण रूपेण प्राप्त कर लिये गये हैं; यदि हां, तो कितने रेलवे वैगन निर्यात किये गये ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : चतुर्थ योजना के दौरान रेल के वैगनों सवारी डिब्बों तथा उनके हिस्सों के वर्षवार निर्यात लक्ष्य तथा निर्यात के आंकड़े नीचे दिये जाते हैं :

वर्ष	निर्यात लक्ष्य (करोड़ रु० में)	वास्तविक निर्यात (करोड़ रु० में)
1969-70	3.50	0.52
1970-71	10.00	2.11
1971-72	17.00	6.57
1972-73	15.00	3.30
1973-74	15.00	4.49 (अनन्तिम) (अप्रैल 1973 से जनवरी 1974)

पांचवीं योजना के पहले वर्ष में रेलवे वैगनों के निर्यात का लक्ष्य

3221. **श्री एम० एस० संजीवी राव** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना के पहले वर्ष में विभिन्न देशों को रेलवे वैगनों के निर्यात सम्बन्धी लक्ष्य निश्चित कर लिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) पांचवीं योजना के पहले वर्ष में लगभग 10 करोड़ रु० मूल्य के लगभग 950 वैगन निर्यात करने की योजना बनाई गई है।

भारतीय पटसन उद्योग के पटसन उत्पादों की सप्लाई की मांग करने वाली विदेशी कम्पनियों के नाम

3222. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया**
श्री श्रीकिशन मोदी } : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विदेशी कम्पनियों के क्या नाम है जिन्होंने हाल ही में भारतीय पटसन उद्योग से पटसन से बनी चीजों की सप्लाई करने को कहा है; और

(ख) भारतीय पटसन से बनी चीजों की अन्तर्राष्ट्रीय मांग में कितनी वृद्धि हुई है।

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) पटसन का माल अनेक देशों को निर्यात किया जाता है जिनमें सं० रा० अमरीका, ब्रिटेन तथा जापान मुख्य बाजार हैं। अभी हाल ही में मांग में वृद्धि हुई है जिसका अनुमान पिछले वर्ष के स्तर से लगभग 20 से 25 प्रतिशत के आसपास लगाया जा सकता है।

ऋणों पर प्रतिबन्ध के फलस्वरूप बम्बई की सूती कपड़ा मिलों में तीसरी पाली का समाप्त किया जाना

3223. **श्री राम भगत पासवान :**
श्री यमुना प्रसाद मंडल : } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऋणों पर प्रतिबन्ध लगाने के फलस्वरूप बम्बई की बहुत सी सूती कपड़ा मिलों में तीसरी पाली समाप्त कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिये क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (क) आवश्यक सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

सरकारी क्षेत्र के कार्यक्रम और ऊंचे पदों पर कर्मचारियों की भर्ती संबंधी नीति के संबंध में योजना आयोग का असन्तुष्ट होना

3224. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने सरकारी क्षेत्र के कार्यकरण और ऊंचे पदों पर कर्मचारियों की भर्ती के सम्बन्ध में असन्तोष व्यक्त किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं तथा इन क्षेत्रों में सुधार करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) सरकार और योजना आयोग इस बात पर पूर्णतया सहमत हैं कि सरकारी उद्यमों के कार्य निष्पादन में सुधार की गुंजाइश है। सरकार द्वारा नियुक्त सरकारी उद्यमों संबंधी एक कार्यकारी समिति सरकारी उद्यमों की कार्रवाई प्रधान समस्याओं का पता लगाने का काम कर रही है। अन्य बातों के साथ साथ इस समिति ने सरकारी उद्म में उच्च पदों पर नियुक्ति किए जाने वाले पदाधिकारियों के चुनाव, मूल्यांकन और विकास के संबंध में अपनी सिफारिशें पेश की थीं। इनको ध्यान में रखते हुए, सरकार ने सरकारी उद्यमों के प्रबन्धक-प्राधिकारियों से संबंधित नीति का पुनरीक्षण किया है और एक नवीन कर्मचारी नीति का ढांचा बनाने का निश्चय किया है जो उद्योगों को प्रधान प्रबन्धक से नीचे के स्तर के पदों पर नियुक्ति के लिए काफी स्वायत्तता प्रदान करने के सिद्धान्त पर आधारित है, ताकि विशिष्ट दक्षता के विकास, अधिक निरन्तरता, उद्यम-विशेष के साथ प्रतिबद्धता, अधिक गतिशीलता की प्रक्रिया में सहायता मिले। उच्च श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए, हाल तक चल रही तालिका-पद्धति को समाप्त करने का निश्चय किया गया है। इसके स्थान पर, एक उच्च स्तरीय चुनाव बोर्ड का निर्माण किया गया है जिसमें ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें उच्च पदों पर व्यक्तियों का चुनाव करने का अनुभव प्राप्त होगा। और जो उच्च श्रेणी के पदों पर नियुक्तियों के लिए उपयुक्त व्यक्तियों के नामों का सुझाव देंगे। बोर्ड को उद्यमों के प्रबन्ध विकास संबंधी प्रयासों की देखरेख करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।

सरकारी उद्यमों की कार्यक्षमता में कार्यकारी समिति की सिफारिशों के अनुसार सुधार करने के लिए जो अन्य कदम उठाए गए हैं वे ये हैं :

(1) प्रबन्ध को सशक्त बनाना,

(2) संयंत्र और निगम स्तर पर संगठनात्मक ढांचे में फेरबदल,

(3) संयंत्र प्रबन्ध में सुधार,

(4) संतुलन और रुकावट दूर करने की सुविधाओं की व्यवस्था करना,

(5) अनुरक्षण संबंधी क्रियाकलापों का विकेन्द्रीकरण,

(6) सामग्री प्रबन्ध, अभिप्रेरण, उत्पादन आयोजन और नियंत्रण में सुधार,

(7) कार्य-संचालन की सामयिक समीक्षा और नियंत्रण के लिए उपयुक्त तंत्र की व्यवस्था करना,

(8) कम्पनी स्तर पर, बेहतर आयोजन,

(9) अनुसंधान और विकास संबंधी क्रियाकलापों और अन्य तकनीकी सेवाओं को सुदृढ़ बनाना,

(10) बिक्री और विपणन प्रयासों को सुदृढ़ बनाना;

(11) औद्योगिक संबंधों में सुधार, और

(12) बहु पारी परिचालन ।

कम्पनियों को तदर्थ लाइसेंस जारी किया जाना

3225. श्री शशि भूषण : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ए० यू० तथा पुनर्भरण लाइसेंस के अतिरिक्त तदर्थ लाइसेंस जारी करने की प्रथा बन गई है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन कम्पनियों को ऐसे तदर्थ लाइसेंस जारी किये गये ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सोवियत संघ के अखबारी कागज का आयात

3226 श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ ने प्रति टन अखबारी कागज के लिये 500 डालरों के मूल्य की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की लाइसेंस-क्षमता का उपयोग

3227. **श्री विक्रम महाजन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की लायसेंस क्षमता का किस सीमा तक उपयोग किया जा रहा है; और

(ख) पांचवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के विकास के लिये क्या प्रस्ताव हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सूचना अनुबन्ध में दी गई है (ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6441/74)

(ख) सूचना अनुबन्धों में दी गई है। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6441/74)

डाकघर बचत बैंक खाता इनामी योजना

3228. **श्री पी० एम० मेहता**
श्री पी० ए० स्वामीनाथन } : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या डाक विभाग द्वारा बचत बैंक लेखाधारियों के लिए घोषित इनामी योजना से काफी राशि जमा की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संम्बधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) डाकघर बचत बैंक के लेखों में अब तक कितनी राशि जमा की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी हां।

(ख) इनामी प्रोत्साहन योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :—

(i) एकल अथवा संयुक्त खातों या नाबालिगों के नाम खातों वाले ऐसे व्यक्ति, जिनके खातों में निर्दिष्ट अवधियों के दौरान कम से कम 200 रुपये की रकम जमा रहे, इनामों की निकासियों में भाग ले सकते हैं।

(ii) जहां तक 1973-74 के वित्तीय वर्ष के खातों का सम्बन्ध है, जिन खातों में दिसम्बर 1973 और मार्च 1974 के बीच की पूरी अवधि में कम से कम 200 रुपये की राशि जमा रहेगी, वे खाते इनामों की निकासी में भाग लेने के हकदार होंगे। कुल 32,50,000 रुपये के 11,116 इनाम होंगे जिनकी राशि 50 रुपये से लेकर 2,50,000 रुपये तक होगी।

(iii) 1974-75 के वर्ष से लेकर, प्रत्येक वर्ष में दो बार इनाम निकाले जायेंगे। प्रत्येक निकासी में कुल 20,50,000 रुपयों के 11,116 इनाम होंगे जिनकी रकम 50 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक की होगी। इनमें से पहले निकासी में वे खाते शामिल होंगे जिनमें अप्रैल से सितम्बर तक की पहली छमाही में कम से कम 200 रुपये की रकम जमा रहेगी। दूसरी निकासी में वे खाते शामिल होंगे जिनमें अक्तूबर से मार्च तक की दूसरी छमाही में कम से कम 200 रुपये की रकम जमा रहेगी।

(ग) अक्तूबर 1973 में इनामी प्रोत्साहन योजना शुरू किये जाने के बाद 31 दिसम्बर, 1973 तक डाकघर बचत बैंक खातों में निकल जमा राशि लगभग 18 करोड़ रुपये थी।

Names of Places which Experienced Severest Cold during Winter of 1973-74

3229. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(*a*) the names of the five places which experienced severest cold and the minimum and maximum temperatures recorded at those places during the winter of 1973-74;

(*b*) whether this unprecedented cold is in any way related to geographical changes; and

(*c*) if so, the broad outlines thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation : (Dr. (Smt.) Sarojini Mahishi) : (*a*) The particulars are given below :

Name of Place	Date	Temperature in degrees Centigrade	
		Maximum	Minimum
Churu	28-12-1973	15	—25
(Rajasthan)	7-2-1974	18	—25
Sikar	28-12-1973	20	—14
(Rajasthan)	7-2-1974	17	—24
	9-2-1974	17	—24
Pilani . . .	30-12-1973	20	—23
(Rajasthan) . .	7-2-1974	18	—24
	9-2-1974	18	—24
Jaisalmer (Rajasthan)	6-2-1974	17	—23
Chandigarh	8-2-1974	17	—23

(*b*) No, Sir.

(*c*) Does not arise.

50 हजार रुपए से अधिक आय वाले आयकरदाता

3230. श्री अटल बिहारी वंजपेयी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में 50 हजार रुपये या उससे अधिक की आय पर आयकर देने वाले व्यक्तियों की संख्या संम्बधी नवीनतम आंकड़े क्या हैं ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा-संभव शीघ्र सदन पटल पर रख दी जायगी ।

डाकघर बचत बैंक योजना के अधीन प्राप्त हुई जमा राशि

3231. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसे डाकघर बचत बक खातों की संख्या कितनी है जिसमें 1 जनवरी 1973 तथा 1 जनवरी 1974 को पृथक-पृथक 200 रुपय से अधिक राशि जमा रही;

(ख) इन दो तारीखों को डाकघर बचत बैंक खातों में पृथक्-पृथक् कुल कितनी राशि जमा हुई; और

(ग) पहला इनामी ड्रा संभवत: किस तारीख को होगा ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायगी ;

(ग) पहले इनामी ड्रा की किसी समय जुलाई, 1974 में किये जाने की सम्भावना है ।

निर्यात की शर्त पर फर्मों को तदर्थ लाइसेंस जारी करना

3232. **श्री नवल किशोर सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार की नीति उन सभी फर्मों को तदर्थ आधार पर लाइसेंस देने की है जिहोंने लिखित रूप में यह वचन दिया है कि इस पर होने वाली विदेशी मुद्रा के व्यय को पूरा करने के लिए वे कम से कम 20 प्रतिशत का योगदान निर्यात के माध्यम से करेंगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : जी नहीं ।

Setting up of Cotton Textile Mills

3233. Shri Hukum Chand Kachwai : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(*a*) whether Government have announced the setting up of some more cotton textile mills in certain States;

(*b*) if so, the name of these States and the time by which these mills are likely to be set up;

(*c*) the names of the parties to whom licences have been issued for the purpose;

(*d*) salient features regarding the experience gained in this field by the parties who have been issued these licences and the names of other industries being run by them; and

(*e*) the number of other cotton mills proposed to be set up in the public sector ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (*a*) to (*d*) : No scheme has been announced for setting up of cotton textile mills by Government.

(*e*) During the Fourth Plan period, licences under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 have been issued for the setting up of 22 cotton textile mills in the public sector.

Foreign Aid for Fifth Plan

3234. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Finance** be pleased to state the amount of foreign aid likely to be received during the Fifth Five Year Plan alongwith the names of countries and the terms and conditions thereof ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : The draft Fifth Five Year Plan has assumed utilisation of gross external assistance to the extent of Rs. 4008 crores during the Fifth Five Year Plan period. The amount of foreign aid likely to be utilised in the Fifth Plan period would partly depend on the utilisation of aid already committed and available in the pipeline and on fresh commitments. As many countries make commitments only on an annual basis, it is difficult to indicate the quantum of aid likely to be received during the Fifth Five Year Plan period, but it is expected that external assistance of the order indicated will be forthcoming from several friendly countries as well as international financial institutions.

पांचवीं योजना के बाद सूती कपड़े की मांग

3235. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में देश में सूती कपड़े की बढ़ी हुई मांग कितनी होगी; और

(ख) इस मांग को पूरा करने के लिए, क्या उपाय करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान आवश्यताओं के आधार पर सूती कपड़े के उत्पादन से सम्बन्धित जिन अनुमानों तथा लक्ष्यों की समीक्षा की गई थी उन्हें अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

इलैक्ट्रोनिक सामान के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा

3236. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रोनिक सामान के निर्यातकर्ता के रूप में विश्व मंडी में प्रवेश कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और वर्ष 1971-72 तथा 1972-73 में कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) इस क्षेत्र में कार्य कर रहे सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही क्षेत्र के महत्वपूर्ण उपक्रम कौन-कौन से हैं; और

(घ) पांचवीं योजना में इलेक्ट्रोनिक उद्योग के विकास कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं तथा इसके फलस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा की आय होने की आशा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) भारत पहले से ही इलैक्ट्रानिक माल का निर्यात कर रहा है।

इस समय इलैक्ट्रानिक माल की ये प्रमुख मदें निर्यात की जा रही हैं : रेडियो रिसीवर्ज और संघटक, डैटा प्रासैस करने की मशीनें, टेलीफोन और टेलीप्रिंटर मशीनें, सार्वजनिक-भाषण उपस्कर, इलैक्ट्रानिक संघटक आदि। नई मदें शुरू करके और निर्यात क्षेत्र में निर्यातकों की संख्या बढ़ा कर तथा शान्ताक्रूज निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र की स्थापना द्वारा निर्यात आधार सुदृढ़ बनाने के लिए प्रयन्त किये जा रहे हैं।

वर्ष 1971-72, 1972-73 और 1973-74 में (अब तक) इलैक्ट्रानिक माल के निम्नलिखित निर्यात किये गये हैं :—

वर्ष	मूल्य
1971-72	5.59 करोड़ रु०
1972-73	4.19 करोड़ रु०
1973-54 (अप्रैल-दिसम्बर 73)	6.04 करोड़ रु०

(ग) इस क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण उपक्रम निम्नलिखित हैं :—

1. आई० वी० एम० वर्ल्ड ट्रेड कार्पोरेशन।
2. भारत इलैक्ट्रानिक्स लि०।
3. इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़।
4. हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लि०।
5. फिलिप्स इंडिया लि०।
6. मूलचंदानी रेडियो एण्ड एप्लायेन्सिज।

7. मर्फी इंडिया लि० ।

8. टेलिफन्कन इंडिया लि० ।

9. इलेक्ट्रानिक कार्पोरेशन आफ इंडिया ।

10. एशियन इलैक्ट्रानिक्स प्रा० लि० ।

11. सेमी कंडक्टर्स लि० ।

(घ) पांचवीं पंचवर्षीय योजना को अवधि के दौरान इलैक्ट्रानिक्स उद्योग के विकास की योजना तैयार की गई है । योजना आयोग द्वारा जो योजना स्वीकार की गई है उसके लिए 253 करोड़ रु० की कुल राशि निर्धारित की गई है जिससे पांचवी योजना की अवधि के दौरान 2300 करोड़ रु० मूल्य का इलैक्ट्रानिक माल तैयार होने की संभावना है ।

इलैक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा इलैक्ट्रानिक माल के निर्यात के सम्बध में निम्नलिखित लक्ष्य रखे गये हैं :—

(करोड़ रु० में)

	74-75	75-76	76-77	77-78	78-79	योग 74-79
1. स्थानीय उत्पादन से निर्यात	9	11	14	18	23	75
2. शान्ताक्रूज ई० पी० सी०	25	40	50	50	50	215
योग	34	51	64	68	73	290

चौथी योजना अवधि में आयातित अखबारी कागज की मात्रा

3237. **श्री एम० एस० संजीवी राव** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में कितनी मात्रा में अखबारी कागज का आयात किया गया ।

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान आयातित अखबारी कागज का मूल्य निम्नोक्त प्रकार है :—

वर्ष	मात्रा (मे० टन)	मूल्य (लाख रू० में)
1969-70	1,55,082	1,857.15
1970-71	1,44,212	1,873.27
1971-72	2,06,856	2,758.52
1972-73	1,53,848	2,051.98
1973-74 (अप्रैल-अगस्त, 73)	60,152	817.08

एशियाई वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल महासंघ का सम्मेलन

3238. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में एशियाई वाणिज्य तथा उद्योग मंडल महासंघ का एक सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो इसमें किन मुख्य बातों पर विचार-विमर्श हुआ था और क्या निर्णय किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां। सम्मेलन भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ द्वारा आयोजित किया गया था।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

विदित हुआ है कि एशियन चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री के महासंघ के पांचवे सम्मेलन के निष्कर्ष तथा सिफारिशें निम्नलिखित थी :

1. सम्मेलन ने इस बात को आवश्यक समझा कि सम्बद्ध सरकारों से निम्नलिखित के लिए अनुरोध किया जायें :--

(i) ऊर्जा आधार का प्रगामी पुनगर्ठन किया जाय और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के लिय अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जाये;

(ii) देश के स्थल भाग तथा तटवर्ती सागर, दोनों ही क्षेत्रों में तेल के स्रोतों खोजने के लिए प्रोत्साहन दिया जाय और इस प्रयोजन के लिए सभी स्तरों पर याथार्थिक प्रोत्साहन दिये जायें, और

(iii) वस्तुओं के कीमत-स्तरों में और अधिक साम्यता लाने के लिए वस्तु करार आरंभ किये जायें।

2. सम्मेलन ने आशा प्रकट की कि पूंजी संबंधी कमी पूरी करने के वास्ते एशियाई विकास बैंक के कार्य क्षेत्र का और अधिक विस्तार व विविधीकरण किया जायगा।

3. एशियाई चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड ईडस्ट्री के सम्मेलन द्वारा उन विद्यमान तत्वों का एक अध्ययन आरंभ किया जायगा जो सदस्य देशों में निवेश संबंधी वातावरण को प्रभावित करते हैं।

4. एशिया चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड ईडस्ट्री का सम्मेलन उस क्षेत्र में विद्यमान व्यापार स्वरूप का व्यापक अध्ययन करेगा और एक समग्र व्यापार तथा निवेश योजना बनाने की संभाव्यता पर विचार करेगा।

5. देशों के बीच व्यापार प्रवाह का संवर्धन करने और व्यापार संबंधी असंतुलनों को सुधारने में सहायता देने के विचार से

(1) कृषि संबंधी विकास की ओर और अधिक ध्यान देना होगा, जिसमें एशियाई खाद्यान्न समीकरण भण्डार का निर्माण करना शामिल है;

(2) विकासशील देशों के लिए प्रशुल्क अधिमानों की नयी आस्ट्रेलियाई प्रणाली और जापान द्वारा किये गये उपायों पर भी समनुमोदन किया गया;

(3) एशियाई व्यापार विस्तार कार्यक्रम पूरी तरह गतिशील तथा कारगर बनाया जायें;

(4) अन्त: क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ाने के वास्ते देशों के बीच दीर्घावधि करार तथा संधियां की जायें;

(5) एशियाई समाशोधन संघ तथा एशियाई रिज़र्व बैंक की स्थापना में आने वाली बाधाओं को दूर किया जायें;

(6) आशा व्यक्त की गई कि सापेक्षत: स्थिर मुद्रा मूल्यों के लिए सन्तोषजनक व्यवस्थाएं की जायेंगी।

6. एशियन चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री सम्मेलन का परिवहन संचार तथा जहाज-रानी आयोग जहाज-रानी सूचना तथा सलाहकार सेवाओं के इकाफे केन्द्र के साथ निकट सम्पर्क रख कर जहाजरानी तथा भाड़ा दरों से संबंधित समस्याओं के सुलझाने का कार्य करता रहेगा। यह सम्मेलन इस क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग की संभाव्यता का भी अध्ययन करेगा। लाइनर सम्मेलनों के लिए एक एकसमान तथा सार्वदेशिक रूप से स्वीकार्य आचार संहिता, विशेषत: भाड़ा दरों के संदर्भ में, भी स्वीकार करनी होगी।

7. पूरे देश में निर्यात प्रलेखन की निर्धारित प्रणाली स्वीकार करने को प्रोत्साहन देने के लिय एशियाई चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री सम्मेलन के एशियाई सीमाशुल्क दलालों तथा अभिकर्त्ताओं संबंधी आयोग का भी गठन किया गया।

8. पर्यटन के क्षेत्र में प्रमुख अभिकरणों का सहयोग प्राप्त करने के लिए एशियाई चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री सम्मेलन का एक विशेष आयोग भी स्थापित किया गया।

9. यह स्वीकार किया गया कि एशियाई चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड ईंडस्ट्री सम्मेलन के सदस्य देशों के वाणिज्य-चैम्बरों को चाहिए कि वे एक-दूसरे के निकट सम्पर्क में रहें, नियमित रूप से जानकारी का आदान-प्रदान करें, व्यापारियों के प्रतिनिधिमण्डलों के व्यापार तथा निवेश संवर्धन संबंधी दौरों का प्रायोजन करें, प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध करें, प्रदर्शनियां तथा उत्पाद-प्रदर्शन आयोजित करें, आदि। एशियाई चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री सम्मेलन के लिए एक स्थायी सचिवालय की स्थापना की संभाव्यता पर भी अध्ययन किया जायेगा।

हथकरघा उद्योग की समस्यायें

3239. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघा उद्योग की समस्याओं का अध्ययन करने के लिये सरकार ने एक उच्चाधिकार प्राप्त दल का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जा '): (क) जी हां,।

(ख) अध्ययन दल ने, जो 29 दिसम्बर, 1973 को गठित किया गया था, निम्नलिखित सदस्य हैं :—

1. श्री बी० शिवरामन,
   उपाध्यक्ष,
   राष्ट्रीय कृषि आयोग तथा सदस्य,
   योजना आयोग, नई दिल्ली . . . . अध्यक्ष
2. निम्नलिखित राज्यों की सरकारों का एक-एक प्रतिनिधि :—
   (1) आंध्र प्रदेश
   (2) आसाम
   (3) जम्मू तथा कश्मीर
   (4) कर्नाटक
   (5) महाराष्ट्र
   (6) मणिपुर
   (7) तमिल नाडु , तथा
   (8) उत्तर प्रदेश . . . . सदस्य
3. श्री कोन्डा लक्षमण बापूजी,
   'जयवरसयाम'
   6-1-2/1, सचिवालय, मार्ग,
   हैदराबाद . . . . सदस्य
4. श्री आविद अली अंसारी,
   सदस्य विधान सभा,
   27, दारुल शफा,
   लखनऊ . . . . . सदस्य
5. श्रीमती पुपुल जयकर,
   अध्यक्ष,
   हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम,
   राउस एवेन्यू, नई दिल्ली . . . . सस्दय
6. श्री एम० सोमप्पा,
   अध्यक्ष,
   अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र,
   विपणन सहकारी समिति लि०,
   211-219, भारतीय भवन,
   फ़रेरे रोड बम्बई-400001 . . . सदस्य
7. श्री टी० आर० एस० विजयराधवाचारी,
   निदेशक,
   तमिलनाडु हथकरघा वित्त तथा
   व्यापार निगम लि०, मद्रास . . . सदस्य

8. श्री मनीनारायण स्वामी
संयुक्त सचिव, वाणिज्य मंत्रालय,
नई दिल्ली सदस्य

9. श्री एस० के० बागची,
वस्त्र आयुक्त,
पी० बा० नं० 11500,
बम्बई-400020 सदस्य

10. श्री ए० एन० वर्मा,
निदेशक,
वाणिज्य मंत्रालय, नई दिल्ली . . . सदस्य सचिव

अध्ययन दल के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं :—

(1) पंचवर्षीय योजना में हथकरघा उद्योग के विकास के लिए कार्यक्रमों के बारे में सुझाव देना,

(2) हथकरघा क्षेत्र की निर्यात संभाव्यता का अधिक से अधिक उपयोग करने के उपायों के बारे में सुझाव देना,

(3) हथकरघा क्षेत्र के लिए अवस्थापना का निर्माण करने तथा पर्याप्त अन्तर्निविष्टों, खासतौर पर से वित्त की व्यवस्था करने के उपयों के बारे में सुझाव देना, तथा

(4) आरक्षण के बारे में स्थिति का पुनर्विलोकन करना और यदि आवश्यक हो तो नीति में परिवर्तन करने के बारे में सुझाव देना।

भारतीय फिल्मों की पाकिस्तान में तस्करी

3240. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या वित्त मंत्री यह बाताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ ऐसी भारतीय फिल्में बरामद की हैं जिनकी पाकिस्तान में तस्करी की जा रही थी ;

(ख) यदि हां, तो उन फिल्मों की संख्या और नाम क्या हैं और गत 6 महीनों के दौरान इस बारे में कितने व्यक्ति गिरफ्तार तथा दण्डित किये गये; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) विगत छः महीनों में भारतीय फिल्मों का पाकिस्तान को तस्कर-निर्यात किये जाने का कोई मामला सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा नहीं पकड़ा गया है।

(ग) देश से बाहर माल के तस्कर-निर्यात को रोकने के लिए, जिसमें फिल्मों का तस्कर-निर्यात भी शामिल है, निम्नलिखित उपाय किये गये हैं।

व्यवस्थित ढंग से सूचना एकत्रित करना, जिन व्यक्तियों पर तस्कर आयात-निर्यात करने का सन्देह हो उन पर निगरानी रखना, जिन जलयानों और वायुयानों पर सन्देह हो उनकी तलाशी लेना, समुद्रतट और भूसीमाओं के सुगमता से पार किये जा सकने योग्य क्षेत्रों की निगरानी रखना। कारगार तरीके से मांग में रोकने, रोक-थाम आदि के लिए समय-समय

पर अतिरिक्त लांच-नौकाओं और वाहनों की व्यवस्था की जा रही है। तस्कर विरोधी कार्य-की अनन्य रूप से देखभाल करने के लिए सीमाशुल्क के समाहर्ताओं, अपर समाहर्ताओं तथा सहायक समाहर्ताओं के ओहदों के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को सुगमता से पार किये जा सकने योग्य क्षेत्रों में तैनात किया गया है। देश से बाहर भेजे जाने वाले संदिग्ध असबाब और पार्सलों की जांच करने में अतिरिक्त सतर्कता बरती जाती है। तस्कर-व्यापार सम्बन्धी अपराधों के लिए अधिक कठोर दण्ड देने तथा खामियों को दूर करने के निमित्त सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 में, हाल में, और संशोधन किया गया है।

तस्कर-व्यापार विरोधी कार्य पर लगे कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने तथा जिन 20 लांच-नौकाओं के लिए पहले ही आर्डर दिया जा चुका है, उनके अलावा, समुद्र में तेज रफ्तार से चलने वाली और लांच-नौकाओं के अभिग्रहण का प्रश्न सक्रिय रूप से विचाराधीन है। स्थिति की निरन्तर समीक्षा की जाती है।

टेलीविजन सैटों का निर्यात

3241. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय टेलीविजन सेटों के निर्माताओं ने विदेशों में टेलीविजन सेटों का निर्यात करने की कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० **सी० जार्ज**) : (क) तथा (ख) टेलीविजन सेटों के निर्यात अभी तक नगण्य हैं। तथापि टेलीविजन विनिर्माताओं द्वारा भारतीय टेलीविजन सेटों के लिए विशेष रूप से पश्चिम यूरोपीय देशों तथा ब्रिटेन में बाजारों का पता लगाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

कटवा (पश्चिम् बंगाल) में पटसन मिलें स्थापित करने का प्रस्ताव

3242. श्री **सरोज मुखर्जी** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का विचार कटवा सब-डिवीजन (पश्चिम बंगाल) में, जो भगीरथी नदी के किनारे स्थित है और जो पटसन उत्पादन करने वाला क्षेत्र है और इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त क्षेत्र है, कुछ पटसन मिलें स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री श्री ए० सी० जार्ज): (क) जी नहीं।

(ख) वर्तमान क्षमता तथा जो माल मार्ग में है वह पटसन के माल की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में रिक्त पड़े उच्च पद

3243. **श्री वसन्त साठे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1973 को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के कितने वरिष्ठ पद रिक्त पड़े थे, ये पद कितनी अवधि से रिक्त पड़े थे और रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) क्या अधिकांश सरकारी उपक्रमों द्वारा चौथी योजना के उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त न कर पाने का एक महत्वपूर्ण कारण उच्च पदों का रिक्त पड़ा होना भी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) एक अनुबन्ध संलग्न है जिसमें बिलकुल हाल की यह सूचना दी गयी है कि पहली मार्च, 1974 तक सरकारी उद्योगों में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के कितने पद खाली थे तथा इन पदों को भरने के लिए क्या-क्या उपाय किये गये हैं और काम को चलाने के लिए क्या-क्या प्रबन्ध किये गये हैं ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6442/74]

(ख) यह कहना सही नहीं है कि चौथी आयोजना की अवधि में प्रबन्धक अधिकारियों की कमी हो जाने से सरकारी उद्योगों के कार्यों पर बुरा असर पड़ा है। जिन मामलों में उत्तराधिकारियों की नियुक्ति करने में देर हुई है उन में सरकार ने इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिए कि सरकारी उद्योगों में काम हर्ज न हों, काम चलाने के लिए आवश्यक प्रबन्ध किया है।

तैयार चमड़े और चमड़े से बने सामान का निर्यात

3244. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे, कि :

(क) क्या चमड़े के निर्यातकर्त्ताओं को कोटा दिए जाने के प्रश्न पर सरकार के रुख और इसके स्थान पर उसके बार-बार तैयार चमड़े और चमड़े के सामान का निर्यात करने का उल्लेख करने के परिणामस्वरूप ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे अनेक आयातकर्त्ता देश ऐसे वैकल्पिक स्रोतों की ओर देखने लगे हैं जिनसे अपनी आवश्यकतानुसार नियमित सप्लाई प्राप्त हो सकेगी ;

(ख) क्या मूल्यों में कमी हुई है और निर्धारित समय में करारों को पूरा न करने से देश के लिए कुछ महत्वपूर्ण परम्परागत मंडियों के स्थायी रूप से खो देने का खतरा उत्पन्न हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की नीति की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सरकार को कोई ऐसी प्रवत्ति की सूचना नहीं है। इसके विपरीत, इन देशों के आयातकों ने भारत से तैयार चमड़ा तथा चमड़े का माल खरीदमे के लिये रजामन्दी प्रकट की है।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सरकार का विचार, तैयार चमड़े तथा चमड़े के माल का निर्यात बढ़ाने तथा अर्ध-साधित चमड़े के निर्यात घटाने और इस प्रकार अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने की नीति जारी रखने का है।

चमड़ा विकास एजेंसी

3245. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चमड़ा विकास एजेंसी की स्थापना करने का सरकार ने निर्णय किया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मंत्री श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) चमड़ा निर्यात विकास निगम स्थापित करने की प्रस्थापना विचाराधीन है।

आवश्यक वस्तुओं की कृत्रिम कमीपैदा करने के लिए जमाखारों के विरुद्ध की गई कार्यवाही

3246. **श्री शंकरराव सावन्त** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जमाखोर देश में कुछ आवश्यक वस्तुओं की कृत्रिम कमी पैदा कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन वस्तुओं का ब्यौरा क्या है, और

(ग) इन जमाखोरों की गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है और इसका क्या परिणाम निकला ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) खाद्यान्न, वनस्पति, मिट्टी का तेल, कोयला, टायर तथा ट्यूब जैसी आवश्यक वस्तुओं की कमी की सूचना देश के विभिन्न भागों से आई है जो कि अंशत: जमाखोरी के कारण हो सकती है, पर इसके अनेक अन्य कारण भी हैं।

जमाखोरी करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने की व्यवस्था आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में पहले ही विद्यमान है और इस अधिनियम के अन्तर्गत शक्तियां राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को भी प्रत्यायोजित कर दी गई है। इसके अलावा भारतीय सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत भी अतिरिक्त शक्तियां उपलब्ध हैं। भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों को साग्रह कहा है कि विभिन्न नियंत्रण आदेशों को, सख्ती से लागू करना आवश्यक है। राज्य सरकारों ने चोरबाजारी तथा जमाखोरी करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए अपनी प्रवर्तन मशीनरी को सुदृढ़ कर लिया है। उन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है जो विभिन्न नियंत्रण आदेशों का उल्लंघन करते हैं।

आल इंडिया कान्डफेरेशन आफ सेन्ट्रल गवर्नमेंट आफिसर्स असोसियेशन द्वारा राष्ट्रीय मजूरी नीतितथा प्रशासन में कर्मचारियों के भाग लेने की मांग

3247. **श्री आर० पी० उलगनम्बी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आल इंडिया कान्फडरेशन आफ सैन्टरल गवर्नमेंट आफिसर्स ऐसोसिएशन ने राष्ट्रीय वेतन नीति तैयार करने की मांग की है जो शैक्षिक प्रवीणता और व्यावसायिक प्रतिभा को मान्यता दे जिससे प्रशासन में भागीदारी व्यवस्था लागू की जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) (क) केन्द्रीय सरकारी अधिकारियों की संस्थाओं के अखिल भारतीय महासंघ ने, श्रेणी-1 की सेवाओं की परिलब्धियों पर तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों से सम्बन्धित अपने ज्ञापनों में से एक ज्ञापन में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह सुझाव दिया था कि परिलब्धियों से सम्बन्धित नीति तय करते समय शैक्षिक विशिष्टता, व्यवसाय सम्बन्धी निपुणता को मान्यता अवश्य दी जानी चाहिये और इसे सामान्यत: लोक प्रशासन में साझेदारी पद्धति को सुविधाजनक बनाना चाहिये।

(ख) तृतीय वेतन आयोग ने श्रेणी-1 की सेवाओं/पदों के वेतनमानों की सिफारिश करते समय इन सेवाओं/पदों के कर्त्तव्यों और उत्तरदायित्वों, उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यों में आने वाली कठिनाई तथा जटिलता, पर्यवेक्षणकार्य की मात्रा, की अपेक्षित अर्हताओं, भरती की पद्धति आदि को ध्यान में रखा है। फिर भी, श्रेणी-1 की सेवाओं/पदों के वेतनमानों के सम्बध में आयोग की सिफारिशों पर विचार करते समय महासंघ के उपरोलिखित सुझावों को भी ध्यान में रखा जायगा।

कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा बंगलादेश कृषि बैंक को सहायता

3248. **श्री राम भगत पासवान**
श्री राम सहाय पाण्डे } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि पुनर्वित्त निगम दवारा बंगलादेश कृषि बैंक को सहायता दिए जाने की संभावना हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सहायता का स्वरूप क्या होगा ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

नौवहन सुविधाओं की कमी के कारण वैगनों के निर्यात में बाधा

3249. **श्री हरी किशोर सिंह** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवहन सुविधाओं की कमी के कारण वैगनों के निर्यात में रुकावट आ रही है ; और

(ख) सरकार ने स्थिति का मुकाबला करने के लिये गत छः महीनों में क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री श्री (ए० सी० जार्ज):(क) रेलवे वैगनों के निर्यातकों के कभी कभी वैगनों का निर्यात करने के लिए पर्याप्त नौवहन स्थान प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना होता है।

(ख) जब कभी नौवहन स्थान संबंधी इन समस्याओं की ओर इस मंत्रालय का ध्यान दिलाया जाता है, तभी स्थान प्राप्त करने के लिए संबंधित नौवहन/कान्फ्रेंस लाइनों से तुरन्त बातचीत की जाती है। डी० जी० शिपिंग संगठन के 4 मुख्य पत्तनों में स्थित भाड़ा अन्वेषक अधिकारी भी निर्यात-कर्त्ताओं को स्थल पर सहायता प्रदान करते हैं।

Classification of Cities

3250. **Shri Shanker Dayal Singh** : Will the Minister of **Finance** be pleased to State :

(*a*) the number and names of 'A, 'B' and 'C class cities in the countries at present; and

(*b*) the basis of classification of the cities and whether Government propose to include certain cities of Bihar in appropriate classes ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (*a*) According to the orders as they existed before the announcement of Government s decisions on the Third Pay Commission s recommendations, the number of cities classified for the purpose of grant of compensatory (city) allowance and house rent allowance to the Central Government employees was 329. The class-wise break-up of this number was as under :—

'A' Class	5
'B-1' Class	6
'B-2' Class	16
'C' Class]	302

A statement showing the names and class of these 329 cities is laid on the Table of the House (Statement I). (Placed in Library see No. L.T. 6443/74.) The list will undergo modifications when orders are issued in terms of Government decisions on the recommendations of the Third Pay Commission.

(*b*) A statement (Statement II) is laid on the Table of the House.

कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र

3251. **डा० कर्णी सिंह :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र से निर्यात क्षमता क्या है ; और

(ख) वर्ष 1973 के दौरान वहां से कितने मूल्य के समान का निर्यात हुआ है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० चार्ज): (क) तथा (ख) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

अयस्क उत्पादन करने वाले देशों का संगठन

3252. **डा० कर्णी सिंह :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सहित अयस्क उत्पादन करने वाले देशों ने पैट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों के संगठन की तरह अयस्क उत्पादन करने वाले देशों का संगठन बनाने के प्रस्ताव पर कोई बातचीत की थी ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) तथा (ख) : जी नहीं। परन्तु भारत लौह अयस्क उत्पादक क्लब का सदस्य है और क्लब के सदस्यों तथा अन्य लौह अयस्क उत्पादक देशों के साथ समय-समय पर परामर्श करता रहता है।

Supply of Raw Rubber to Rubber Oriented Industries

3253. Dr. Laxmi Narayan Pandeya : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(*a*) the quantity of raw rubber supplied to the various rubber oriented industries, including factories manufacturing tyres and tubes of cycles and motor cars in Indore and Ratlam Districts of Madhya Pradesh during the last three years;

(*b*) the names of each of these factories and the locations thereof; and

(*c*) the production of each of these factories during the said years ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) & (b) The names of the manufacturers of rubber goods in Indore and Ratlam Districts of Madhya Pradesh and the quantity of rubber purchased by them during the last three years are given below:—

S.No.	Name of Manufacturers	Rubber purchased	
		Year	Qty (in kgs)
1.	S. Kumar Enterprises (P) Ltd. Industrial Area, Indore. .	1970-71	42,435
		1971-72	22,100
		1972-73	96,158
2.	International Rubber Industries 11 Kibe Compound, Indore.	1970-71	1,100
		1971-72	500
		1972-73	9000
3.	Zhu Sha Enterprises, Bimanagar, Indore. . .	1970-71	NIL
		1971-72	NIL
		1972-73	117
4.	Krishnadas and Sons, Mhow Cantt., Indore. . .	1970-71	NIL
		1971-72	NIL
		1972-73	NIL
	Everlasting Rubber Works Co., Ltd., Jaora, Ratlam Distt.	1970-71	NIL
		1971-72	8,400
		1972-73	2,400

(c) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

सिंचाई परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता

3254. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक और/अथवा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसिया समस्त देश में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं में नई तथा वर्तमान परियोजनाओं के विस्तार में–नई सरकार की सहायता कर रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो दी गई सहायता के स्वरूप और 1972, 1973 और 1974 में दी गई सहायता की राशि सहित तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) विश्व बैंक से संबद्ध आसान शर्तों पर उधार देने वाली संस्था अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने जो आसान शर्तों पर ऋण दिया करती है, शेत्रुन्जी (गुजरात), सालन्दी (उड़ीसा), सोन (बिहार) और पुरना (महाराष्ट्र) की सिंचाई परियोजनाओं और उत्तर प्रदेश की एक नलकूप सिंचाई परियोजना के लिये भी, छटे दशक के प्रारंभिक वर्षों में कुल मिला कर 4.50 लाख डालर की सहायता दी है। हाल ही में इसने गुजरात में कडाना सिंचाई परियोजना और आन्ध्र में पन्चमपाद सिंचाई परियोजना के लिये सहायता दी है। कई राज्यों में छोटी सिंचाई परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता भी दी गई हैं।

(ख) 1972, 1973 और 1974 में बड़ी या छोटी सिंचाई परियोजनाओं के लिये अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से कोई सहायता प्राप्त नहीं की गयी । लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ

ने वर्ष 1970 से 1973 तक 2950 लाख डालर की सहायता प्रदान की जिसमें से 2060 लाख डालर गुजरात आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा तमिलनाडु, करनाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में भूमिगत जल और भूमि विकास द्वारा लघु सिंचाई के विकास के कार्य के लिये हैं।

पश्चिम बंगाल में सूती कपड़ा मिलों को नियंत्रण में लेने के बाद उनमें उत्पादन

3255. **श्री आर० एन० वर्मन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम द्वारा पश्चिम बंगाल में सूती कपड़ा मिलों को नियंत्रण में लेने के बाद उनके उत्पादन में भारी कमी आई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशन्वत राव चव्हाण) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम ने पश्चिम बगाल में किसी कपड़ा मिल को अपने हाथ में नहीं लिया है। परन्तु, दिसम्बर, 1973 के अन्त तक इसके द्वारा छः कपड़ा मिलों को पुर्निर्माण सहायता रूप 184.06 लाख रुपये मंजूर किये गये जिसमें से पांच मिलों को 99.74 लाख रूपये दे दिये गये।

आस्ट्रेलिया के व्यापारिक दल की भारत यात्रा

3256. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रेलिया के एक व्यापारिक दल ने हाल ही में भारत की यात्रा की थी ;

(ख) यदि हां, तो किन किन विषयों पर वचिार हुआ तथा क्या क्या करार हुए ; और

(ग) विदेशी मुद्रा की आय के संदर्भ में उक्त करार भारत के लिए कहां तक लाभप्रद होगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : आस्ट्रेलिया से कोई सरकारी व्यापार दल हाल में भारत नहीं आया। तथापि आस्ट्रेलिया में बहु-विभागीय स्टोरों की एक श्रृंखला मे० डेविड जोन्स प्रा० लि० का मई, 1974 में सिडनी में अपने स्टोरों में कुछ भारतीय माल के संवर्धन की व्यवस्था करने का विचार है। इस प्रयोजनार्थ मे० डेविड जोन्स के एक क्रय दल ने नवम्बर, 1973 में भारत का दौरा किया था तथा लगभग 3 लाख रुपये मूल्य के माल के लिए क्रयादेश दिये थे।

अपरिसकृत पटसन का व्यापार अपने नियंत्रण में लेना

3257. **श्री आर० पी० उलगनम्बी**
श्री ज्योतिर्मय वसु } : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपरिष्कृत पटसन का व्यापार गैर-सरकारी व्यक्तियों से सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लेने के बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) यह सरकार का घोषित उद्देश्य है कि कच्चे पटसन के समस्त व्यापार को धीरे धीरे अपने हाथ में ले लिया जाए ।

श्री लंका के साथ संयुक्त उपक्रम

3258. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका ने उर्वरक, हल्के, (लाइट) इंजीनियरिंग, सूती कपड़े और सहायक क्षेत्रों में कुछ भारतीय उद्योगपतियों को अपने देश में संयुक्त उपक्रम आरम्भ करने के लिये आमंत्रित किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई निर्णय लिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री श्री० ए० सी० जार्ज): (क) तथा (ख) : संयुक्त उद्यम के रूप में श्रीलंका में एक मोटर-गाड़ी संघटक फैक्टरी स्थापित करने के लिए श्रीलंका सरकार तथा टैल्को लि०, बम्बई के बीच बातचीत चल रही है । परियोजना के ब्यौरे अभी तैयार किये जाने हैं ।

भारतीय उद्योगों में विदेशी साम्य पूंजी

3259. **श्री मुस्तियार सिंह मलिक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय उद्योगों में आजकल कितनी विदेशी साम्य पूंजी लगी हुई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : हाल तक उपलब्ध सूचना के अनुसार जो मार्च, 1970 के अन्त तक की है, भारतीय उद्योगों (सेवाओं सहित) में इस समय कुल विदेशी शेयर पूंजी 605.00 करोड़ रुपयों की लगी हुई है ।

ऋण प्रतिबन्धों में उद्योगों को छूट देने के बारे में कर्नाटक सरकार द्वारा किया गया अनुरोध

3260. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने कुछ उद्योगों को ऋण-प्रतिबन्धों से छूट देने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है क्योंकि इससे बेरोजगारी का समस्या और गम्भीर हो जायगी ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे उद्योगों का ब्यौरा क्या है और इस अनुरोध के बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख) : माननीय सदस्य शायद दिसम्बर, 1973 में कर्नाटक लघु उद्योग संघ द्वारा वित्त मंत्री को भेजे गये पत्र की ओर संकेत कर रहे हैं, जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि कर्नाटक के लघु उद्योगों को, बढ़े हुए मार्जिन और सीमाओं पर बैंकों द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों से छूट दे दी जाए ।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को सलाह दी है कि उन्हें ऋण नीति का क्रियान्वयन करने में समुचित सावधानी बरत कर यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि लघु उद्योगों सहित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताएं पर्याप्त रूप से पूरी हों और जो गति इसने पहले प्राप्त कर ली थी वह बनी रहे। ऋणों के क्षेत्रीय वितरण के सबसे हाल के आंकड़ों से यह भी स्पष्ट है कि लघु उद्योगों सहित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को बैंक राशि की गति में 31 दिसम्बर, 1973 को समाप्त होने वाली तिमाही के दौरान, 1972 की उसी अवधि के मुकाबले में काफी वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, रिज़र्व बैंक द्वारा अनुसूचित बैंकों को 24 दिसम्बर, 1973 को दिये गये निदेशों के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रशासित लघु उद्योगों के लिये ऋण गारन्टी योजना के अन्तर्गत लघु औद्योगिक एककों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिक कामकाज के दिनों के दौरान पहले निर्धारित किये हुए बढ़े मार्जिन की परिधि से बाहर रखा गया है। इस प्रकार कर्नाटक के लघु औद्योगिक एककों और अन्य क्षेत्रों के, ऋण की पाबन्दी से प्रभावित होने की कोई आंशका नहीं है।

वर्ष 1972-73 में विदेशों में राज्य व्यापार निगम के कार्यालय स्थापित करना

3261. **श्री के० मालन्ना** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1972-73 में विदेशों में राज्य व्यापार निगम द्वारा स्थापित कार्यालयों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : 1972-73 के दौरान राज्य व्यापार निगम ने विदेशों में दो कार्यालय खोले हैं, एक दारु-ए-सलाम में तथा दूसरा ढाका में।

बिजली के सामान के निर्यात विधेयक समिति का प्रतिवेदन

3262. **श्री के० मालन्ना** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिजली के सामान के निर्यात को बढ़ाने हेतु व्यापक नीति के बारे में सुझाव देने के लिये कोई समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समिति ने कोई प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस समिति की मुख्य सिफारिश क्या हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग). भारी विद्युत्तीय उद्योगों की विकास परिषद् ने बिजली के सामान के निर्यात संवर्धन के संबंध में एक उप-समिति की स्थापना की है। उप-समिति ने अभी तक कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

अहमदाबाद टैक्सटाइल मिल्स द्वारा प्रोसेसिंग विभाग बन्द किये जाने से प्रभावित श्रमिक

3263. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले की भारी कमी के कारण अहमदाबाद टैक्सटाइल मिल्स में प्रोसेसिंग विभाग बंद किये जाने का अनेक श्रमिकों पर प्रभाव पड़ा है; और

(ख) सरकार ने इस संबध में क्या कार्यवाही की है?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) कोयले की भारी कमी के कारण जनवरी तथा फरवरी, 1974 के महीनों में अहमदाबाद को चार वस्त्र मिलों ने कभी-कभी बंद होने की जो सूचना दी उसके परिणामस्वरूप कुछ कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ा था।

(ख) मिलों में मिल मालिक एसोसिएशन कोयला पूल से ऋणों की व्यवस्था करके फिर से काम करना आरम्भ कर दिया। कोयले के लाने ले जाने से संबंधित अधिकारियों से भी अहमदाबाद को तेजी से कोयला पहुंचाने का अनुरोध किया गया था।

इण्डस्ट्रियल प्लांट लिमिटेड को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा दी गई सहायता

3264. **श्री मधु लिमये** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने एक बिड़ला उपक्रम इण्डस्ट्रियल प्लांट्स लिमिटेड को सहायता दी थी;

(ख) क्या खराद मशीनें बनाने वाली इस परियोजना में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से प्राप्त सहायता की अपेक्षा प्रवर्तकों का अपना अंशदान बहुत कम था; और

(ग) यदि हां, तो प्रवर्तकों के शेयर कितने प्रतिशत हैं और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने कितनी सहायता दी है?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) से (ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने मैसर्स इण्डस्ट्रियल प्लांट्स लिमिटेड को उसकी खराद की मशीनों का निर्माण करने की परियोजना के लिए दिसम्बर, 1974 में निम्नलिखित प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता दी है:—

(लाख रुपयों में)

हामीदारी	स्वीकृत राशि		बकाया रकम
सामान्य शेयर . . .	10.00	9.97	9.97
अधिमान्यता प्राप्त शेयर . . .	3.00	2.99	2.99
जोड़	13.00	12.96	12.96

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने, उपर्युक्त कम्पनी को बैंकों द्वारा दिये गए ऋणों के आधार पर 40 लाख रुपए की पुनर्वित सहायता को मंजूरी दी है और भुगतान किया है। इस सहायता में से कोई भी रकम बकाया नहीं है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के अनुसार, परियोजना लागत 183.75 लाख रुपए थी और संयोजकों, निदेशकों/मित्रों, सहयोगियों का अंशदान निम्नलिखित था :—

	लाख रुपयों में
शेयर पूंजी में अंशदान . . .	15.00
संयोजकों, निदेशकों आदि द्वारा हामीदारी प्रबन्ध . .	7.00
शांति लाल थार (बिरला कंपनियों के सहयोगी और प्रासपैक्ट्स के अनुसार निदेशक) .	10.00
अप्रतिभूत जमा .	1.55
आन्तरिक एकत्रित राशियां	57.20
जोड़	90.75

प्रशुल्क आयोग द्वारा आटोमोबीईल एन्सीलियरी उद्योग का पुनरीक्षण

3265. श्री फतह सिंहराव गायकवाड : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रशुल्क आयोग द्वारा आटोमोबाइल एन्सीलियरी उद्योग का पुनरीक्षण करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) मंत्रालय को अंतिम प्रतिवेदन कब तक प्राप्त होने की संभावना है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : टैरिफ आयोग ने इस बीच मोटर गाड़ी अनुषंगी उद्योग से संबंधित, अपनी प्रगति रिपोर्ट भारत सरकार को दे दी है। रिपोर्ट पर सरकार द्वारा जो निश्चित किया गया है उसके साथ वह रिपोर्ट शीघ्र ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

लौह अयस्क का निर्यात

3266. श्री मधु दण्डवते
श्री वसन्त साठे } : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान जैसे देशों को जहाज़ों में लदान की लागत सहित 55 रुपए प्रतिटन के औसत मूल्य पर लोहा अयस्क का निर्यात किया जाता है;

(ख) समृद्ध इस्पात फर्मों से लौह अयस्क के लिए ऊंचे/लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है; और

(ग) निर्यात बढ़ाकर अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निर्यात के मामले में अपनी 'इकानामिक इंटैलिजेंस' को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं । भारत को समुचित कीमतें मिल रही हैं जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा और विदेशी खरीददारों को दी जा सकने वाली निर्यात सुविधाओं से संगत है।

(ख) लदान वाले पत्तनों पर अवस्थापना में सुधार किया जा रहा ताकि बड़े आकार के जहाजों पर लदान करने में सुविधा हो सके। वर्तमान कीमतों में और भी सुधार करने के लिए प्रयत्न जारी हैं।

(ग) विदेशों में भारत के व्यापार प्रतिनिधियों से प्राप्त सूचनाओं के अतिरिक्त खनिज तथा धातु व्यापार निगम के पास भी विदेशों में अपने क्षेत्रीय कार्यालयों, विक्रय अभिकर्ताओं तथा व्यापार सहयोगियों की मारफत आर्थिक जानकारी एकत्र करने की व्यवस्थाएं हैं।

ऋण पर प्रतिबन्ध और कड़ा करने के बारे में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा निदेश जारी किया जाना

3267. **श्री पीलू मोदी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने हाल ही में ऋण पर प्रतिबन्ध और कड़ा करने के बारे में देश की सभी बैंकिंग संस्थाओं को नये निदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में जारी किए गए निदेशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में सहकारी बैंकों पर भी ऋण प्रतिबन्धों को लागू किया गया है; और

(घ) क्या इसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन में कमी होने की संभावना है और यदि हां, तो सहकारी बैंकों पर ऋण प्रतिबन्ध लगाए जाने के क्या कारण हैं?

(क) से (घ). मुद्रा उपलब्धि में अधिक वृद्धि और मूल्यों पर दबाव के सन्दर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक की अधिक रकम काम काज के मौसम की ऋण नीति के अनुसार ऋण नियंत्रण सम्बन्धी उपायों को कड़ा कर दिया गया है। किये गए उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:--

1. अन्न की वसूली से भिन्न क्षेत्रों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए अधिकतम सीमा सितम्बर, 1973 के अन्त से अप्रैल, 1974 के अन्त तक की अवधि के दौरान, सितम्बर, 1973 के अन्त में अग्रिमों के बकाया स्तर का लगभग 10 प्रतिशत होगी;
2. नकदी और नकदी जैसी परिसम्पत्तियों के कानूनी अनुपात को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 32 प्रतिशत करना;
3. 8 दिसम्बर, 1973 और 11 जनवरी, 1974, 12 जनवरी और 5 अप्रैल, 1974 तथा 6 अप्रैल और 31 मई, 1974 के बीच की अवधियों के लिए, रिजर्व बैंक से बैंकों को दिए जाने वाले ऋणों की अधिकतम सीमा को, 28 सितम्बर, 1973 को बैंक की कुल मांग और सामयिक दायित्वों के क्रमश: 1.5 प्रतिशत, 2 प्रतिशत और 1 प्रतिशत के अन्दर-अन्दर निर्धारित करना;
4. नकदी और नकदी जैसी परिसम्पत्तियों के 33 प्रतिशत और उस के कम के शुद्ध अनुपात पर लिए जाने वाले ऋणों के लिए रिजर्व बैंक से ऋणों की अधिकतम दर को 12 प्रतिशत से बढ़ा कर 15 प्रतिशत करना;

5. विशेष रूप से छूट प्राप्त श्रेणियों को छोड़कर बैंक अग्रिमों की न्यूनतम व्याज दर को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 11 प्रतिशत करना (1 दिसम्बर, 1973 से प्रभावी) ।

6. हुण्डियों के वित्तपोषण की न्यूनतम दर को बढ़ा कर 9.5 प्रतिशत करना ;

7. सरकारी और अर्द्धसरकारी निकायों को बिक्री के सम्बन्ध में किताबों में दिखाए गए ऋणों के बदले अग्रिमों के लिए मार्जिन को 10 प्रतिशत अंक तक और अन्य बिक्रियों के संबंध में 20 प्रतिशत अंक तक बढ़ाया जाना ;

8. तालिकाबद्ध वस्तुओं (कच्ची सामग्री, निर्माणाधीन माल और तैयार माल) के बदले अग्रिमों के लिए मार्जिन को 10 प्रतिशत तक बढ़ाया जाना ;

9. चयनात्मक आधार पर ऋण नियंत्रण के अन्तर्गत आने वाली जिसों के लिए ऋण देने की न्यूनतम दर को, अधिकांश मामलों में, 12 प्रतिशत से बढ़ा कर 13 प्रतिशत करना और सूती धागे और कपड़े सहित सूती वस्त्रों को चयनात्मक आधार पर ऋण नियंत्रण उपायों के अन्तर्गत लाया जाना ;

10. बैंकों को अनुरोध किया गया है कि वे बड़ी राशियों की हाल में की गई निकासियों की, विशेषरूप से 25 लाख रूपए से अधिक की राशियों की जांच-पड़ताल करे और ऐसे मामले में राशियों को वापस मांगे जिनमें इस बात का प्रमाण हो कि राशि की निकासी तत्कालिक आवश्यकताओं से पहले की गयी है।

इस बात को सुनिश्चित करने के लिए निर्यात के क्षेत्र को ऋण के दिए जाने पर कोई प्रभाव न पड़े, इस क्षेत्र को दिये जाने वाले ऋण में वृद्धि को, हाल में, अधिक काम-काज के मौसम के दौरान ऋण के विस्तार के लिए मात्रा सम्बन्धी अधिकतम सीमा से छूट दे दी गई है और इस क्षेत्र को कुछ अधिक पुनर्वित्त सुविधाएं दी गई हैं। ऋण गारण्टी योजना के अन्तर्गत आने वाले छोटे पैमाने के औद्योगिक एककों को भी अधिक मार्जिन सम्बन्धी आवश्यकताओं से छूट दे दी गई है।

जहां तक सहकारी ऋण संस्थाओं का सम्बन्ध है, पिछले वर्ष निर्धारित मार्जिन में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर के और ऋण की सीमा को निरपेक्ष रूप से मुद्रा के आधार पर समीति कर के, रूई और कपास के बदले राज्यीय और केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा दिये जाने वाले अग्रिमों पर रोक लगा दी गयी है। न्यूनतम मार्जिन, व्याज की न्यूनतम दरें और ऋण के अधिकतम स्तरों का निर्धारण कर के चुने हुए प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा दिए जाने वाले अग्रिमों को भी ऋण नियंत्रण उपायों के अन्तर्गत लाया गया है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि तुरन्त आय होने लगे, अग्रिमों और ऋणों के स्तर को नीचे लाने के लिए समय तालिका का निर्धारण भी कर दिया गया है।

चूंकि उत्पादनशील प्रयोजनों के लिए अग्रिमों पर कोई रोक नहीं लगाई गयी है और कृषि के लिए प्रत्यक्ष अग्रिमों को भी, प्रत्येक मामले में 50,000 रुपए तक की रकम को न्यूनतम व्याज दरों से छूट दी गयी है इसलिए ऋण सम्बन्धी मौजूदा प्रतिबन्धों का, कृषि, उत्पादन के प्रयोजनों के लिए रकमों के दिए जाने पर किसी प्रकार से भी प्रभाव नहीं पड़ेगा

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों द्वारा एक दिन की सांकेतिक हड़ताल

3268. **श्री पीलू मोदी**
श्री मधु लिमये } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में 28 दिसम्बर, 1973 को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की थी ;

(ख) यदि हां, तो जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की मुख्य मांगें क्या हैं ; और

(ग) उनके सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) : जीवन बीमा निगम के तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की मांगों में वर्तमान वेतनमानों, भत्तों के ऊर्ध्वमुखी संशोधन, तथा सेवा की शर्तों में सुधार की मांगें भी शामिल हैं। इन मांगों पर जीवन बीमा निगम तथा उसके कर्मचारियों के संघों के बीच वार्ता हुई थी और 24-1-1974 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। जीवन बीमा निगम कर्मचारी विनियमों में संगत संशोधनों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है।

तेल उत्पादक शों में जूट कारखाने स्थापित करने के लिए की गई कार्यवाही

3269. **श्री डी० डी० देसाई**
श्री एन० शिवप्पा } : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल उत्पादक देशों में कुछ जूट कारखानों की स्थापना करने की संभावना का पता लगाने के बारे में सरकार ने कोई कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) तेल उत्पादक देशों के पास प्रायः पटसन कारखानों के लिए कच्चा माल नहीं है। भारत से कच्चे माल का निर्यात भी आर्थिक दृष्टि से अलाभकर है, विशेषतः जबकि भारत तैयार उत्पादों का निर्यात करके अधिक इकाई कीमत प्राप्त कर सकता है।

अतः हमारा प्रयत्न इस क्षेत्र को निर्मित पटसन उत्पादों का निर्यात बढ़ाने का रहता है, क्योंकि वहां खाद्यान्न, उर्वरक, सीमेंट, आदि को भरने के लिए बोरे-बोरियों की आवश्यकता को देखते हुए भारी निर्यात संभावनाएं मौजूद हैं।

सरकारी उपक्रमों का कार्यकरण

3270. **श्री डी० डी० देसाई**
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया } : क्या **वित्त मंत्री** यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकरण की मूल समस्याओं का सरकारी उपक्रम ब्यूरो ने कोई अध्ययन किया है ;

(ख) यदि हा, तो इसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) सरकारी उद्यमों के कार्यों पर सरकार बराबर नजर रखती है ताकि जरूरत पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाही की जा सके। सरकारी उद्यमों के कामों को अधिक कुशल ढ़ंग से चलाने में जो कठिनाई पैदा होती है उसका पता लगाने के लिए तथा इस बात की सिफारिश करने के लिए कि ऐसी कठिनाइयों को दूर करने के वास्ते क्या उपाय किया जाना चाहिए, सरकारी उद्यम विषयक एक कार्रवाई समिति भी बनायी गयी है।

(ख) सरकारी उद्यमों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उनमें से कुछ ये हैं—लम्बी अवधियों के बाद लाभप्रद उत्पादन कराना, कुछ जटिल उद्योगों में कार्य-कुशलता का विकास करने में अधिक समय लगना, कच्चे माल, संघटकों तथा बिजली की कमी होना, औद्योगिक संबंध असन्तोषजनक होना और कुछ उद्योगों के मामलों में वस्तुओं की मांग कम हो जाना।

(ग) सरकारी उद्यमों के कामों में सुधार लाने के लिए जो उपाय किए गए हैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण उपाय ये हैं :—

(1) संगठनात्मक ढ़ांचे में सुधार करना तथा कम्पनी में तथा कारखाने में काम का प्रबन्ध करना;

(2) टेक्नालोजी, संचालन प्रणालियों तथा अनुरक्षण के तरीकों में सुधार करना;

(3) क्षमता का अधिक उपयोग करने के लिए उत्पादन में विविधता लाना तथा वस्तुओं का निर्यात करना;

(4) कठिनाइयों तथा असन्तुलन को दूर करने के लिए अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करना;

(5) वस्तुओं की किस्म का सुधार करना तथा देशी वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ाना;

(6) इस उद्देश्य से कि उत्पादन कम न हो, उन वस्तुओं को विदेशों से मांगना जो देश में उपलब्ध न हों;

(7) औद्योगिक संबंधों, संचार व्यवस्था, कार्मिक प्रबन्ध, प्रशिक्षण में सुधार करना तथा विकास करना;

(8) सभी स्तरों पर ज्यादा अच्छे ढ़ंग से प्रोत्साहन/पुरस्कार देने की योजना शुरू करना।

एक निर्यात/आयात बैंक की स्थापना

3271. **श्री डी० डी० देसाई**
श्री फतहसिंह राव गायकवाड़ } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक निर्यात/आयात बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) और (ख) यह प्रश्न कि क्या देश के लिए एक निर्यात-आयात बैंक की आवश्यकता है सरकार के विचाराधीन है।

तेल संकट के कारण विश्व बैंक से ऋण

3272. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल मूल्य में भारी वृद्धि के कारण देश की आर्थिक स्थिरता को खतरे का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो देश की अर्थव्यवस्था को सहायता पहुंचाने के हेतु विश्व बैंक किस सीम तका अतिरिक्त दीर्घावधि ऋण देने को सहमत हुआ है।

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तेल की कीमतों में तेजी से वृद्धि होने से भुगतान सन्तुलन पर बोझ पड़ेगा और निर्यात की आमदनी बढ़ाने तथा आयात पर निरर्भता को कम करने के लिए अधिक से अधिक प्रयत्न करने होंगे ।

(ख) विश्व बैंक ऐसे उपाय ढूंढ रहा है जिनसे वह तेल की कीमतों म वृद्धि से उत्पन्न समस्या से निपटने के लिए विकासशील देशों की सहायता कर सके, परन्तु अभी तक ऐसी कोई ठोस योजना सामने नहीं आई है ।

संकट-ग्रस्त चाय बागानों का अधिग्रहण

3273. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के संकट ग्रस्त चाय बागानों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) चाय उद्योग के विकास तथा चाय निर्यातों के संवर्धन हेतु एक दीर्घावधि नीति तैयार करने के लिए चाय संबंधी जिस कार्मिक दल की स्थापना की गई थी उसने बंद तथा संकटग्रस्त चाय बागानों के पुनः स्थापन के लिए कतिपय उपायों की सिफारिश की है जिन पर सरकार विचार कर रही है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

युवक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये कार्यवाही करना

3274. **श्री वेकारिया**
श्री डी० पी० जदेजा } : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि युवक पर्यटकों को इस देश की यात्रा करने के लिए आकर्षित करने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषी) : सरकार भारत के लिए युवा यातायात को प्रोत्साहित करने के लिए सक्रिय रूचि ले रही है। इस प्रकार के यातायात की वृद्धि के लिए किए गए उपायों में यू० एस० ए०, यूरोप व जापान से भारत से भारत के लिए रियासती विमान किराये लागू करना, विदेश स्थित भारत सरकार के पर्यटन अधिकारियों द्वारा विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रोत्साही कार्यवाही करना, युवा-समुदायों के लिए सस्ते आवास तथा युवा होस्टलों, यात्री लाजों, पर्यटक बंगलों आदि का निर्माण करना भी शामिल है।

पश्चिम एशिया के देशों में भारतीय बैंकों की शाखाएं खोलना

3275. **श्री वेकारिया**
श्री अरविन्द एम० पटेल } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम एशिया के किसी भी देश में भारतीय बैंकों की एक भी शाखा नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उन देशों में भारतीय बैंकों की शाखाएं खोलने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) अभी किसी भी भारतीय बैंक की पश्चिम एशियाई क्षेत्र में बैंक कार्य करने वाली कोई शाखा नहीं है। तथापि भारतीय स्टेट बैंक का एक प्रतिनिधि अधिकारी (अर्थात् बैंक कार्य न करने वाला एक सम्पर्क अधिकारी) 1971 से बैरूत लेबनान में कार्य कर रहा है।

(ख) भारतीय वाणिज्यिक बैंकों का भारत से बाहर पहले किसी उल्लेखनीय परिणाम में विस्तार नहीं हुआ था। पश्चिमी एशिया क्षेत्र के देशों में तेजी से अधिक विकास होने और इनमें से कुछ देशों तथा भारत के बीच व्यापार की मात्रा बढ़ाने से, भारतीय बैंक हाल के वर्षों में इन में से कुछ देशों में अपनी शाखाएं स्थापित करने की संभावना खोजते रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने आबु ढ़ावी, मस्कट और दुबाई में शाखाएं खोलने के लिए पहले ही लाइसेंस जारी कर दिए हैं।

उत्पादन अभिमुख व्यापार अभियान

3277. **श्री रघुनंदन लाल भाटिया** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पादन और निर्यात में वृद्धि करने संबंधी आयात योजना और उत्पादन अभियान अभिमुख व्यापार अभियान प्रारंभ करने का प्रस्ताव उनके मंत्रालय के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या 2 जनवरी, 1974 को उद्योग, व्यापार और श्रमिकों के प्रतिनिधियों की दिल्ली में आयोजित की गई बैठक में उन्होंने इस बारे में कोई प्रस्ताव पेश किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो किए गए निर्णय की मुख्य बातें क्या हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) व्यापार सलाहकार परिषद् की नई दिल्ली में 2 जनवरी, 1974 को जो बैठक हुई थी उसमें उत्पादन तथा निर्यात बढ़ाने के लिए उद्योग, व्यापार तथा श्रमिकों के प्रतिनिधियों ने कई सुझाव दिए थे।

(ग) सरकार पैट्रोलियम तथा तेल उत्पादों के कारण बढ़े हुए आयात बिल को पूरा करने के उद्देश्य से निर्यातों में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित ढ़ंग पर एक वृत कार्यक्रम बना रही है:—

(1) निकट भविष्य में अधिकतम निर्यात संभाव्यता वाले उत्पादों का पता लगाना।

(2) ऐसे गन्तव्य स्थानों का पता लगाना जहाँ इन उत्पादों के निर्यात करने से अधिकतम इकाई मूल्य प्राप्त हो।

(3) ऐसे उपायों का पता लगाना जिनसे घरेलू उत्पादन आधार का विस्तार हो और इन उत्पादों के संबंध में अत्यधिक निर्यात योग्य देशी माल तैयार हो।

चाय की लाभ प्रद कीमतें प्राप्त करने के लिए भारत और श्रीलंका द्वारा सांझी नीति का निर्धारण

3278. **श्री रघुनंदन लाल भाटिया**
श्री एस० कत्तामुत्तु } : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय की लाभप्रद कीमत प्राप्त करने के लिये भारत और श्रीलंका ने अन्य चाय उत्पादक देशों के साथ विचार-विमर्श करना आरंभ कर दिया है ; और

(ख). यदि हां, तो उन्होंने खाद्य तथा कृषि संगठन के बागान निदेशक के साथ उक्त विषय पर कोई चर्चा की थी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) भारत तथा श्रीलंका के बीच फरवरी, 1974 में हुई चर्चा के दौरान यह तय हुआ था कि चाय के लिये लाभप्रद कीमतें प्राप्त करने मार्गोपायों के विषय के बारे में अन्य चाय उत्पादक देशों के साथ विचार-विमर्श किया जाना चाहिए।

(ख) वस्तु स्कंध खाद्यान्न तथा कृषि संगठन, रोम के निदेशक, चाय की कीमतों को स्थिर करने और चाय के निर्माताओं से विदेशी मुद्रा की आय को सुधारने के विषय में खाद्यान्न तथा कृषि संगठन द्वारा गठित निर्यात सब-ग्रुप की अगली बैठक के बारे में चर्चा करने के लिये गत वर्ष स्वतंत्र रूप से भारत आये थे। यह बैठक जून, 1974 में होनी है और उसके पश्चात अंकटांड के साथ सहयोग से चाय के विषय में गहन तदर्थ विचार-विमर्श किया जाना है।

एयर इंडिया का दिल्ली से निकलने वाले अंग्रेजी दैनिक से समझौता

3279. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क). क्या एयर इंडिया ने दिल्ली से निकलने वाले एक अंग्रेजी दैनिक से समझौता किया है जिसके अनुसार वह प्रतिमास के विज्ञापन धन के बदले में अमरीका ले जाने के लिए कुछ समाचार-पत्र खरीदेगी ;

(ख). यदि हां, तो इस बारे में किये गये समझौते अथवा प्रबंध की मुख्य बातें क्या हैं और समाचार-पत्र का नाम क्या है ; और

(ग) इस समझौते से पूर्व कौन सी परिपाटी प्रचलित थी और नये समझौते द्वारा पिछली परिपाटी में क्या सुधार, विशेषरूप से एयर इण्डिया द्वारा होने वाली आय में हुआ है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबाहादुर) : (क) : जी हाँ, एयर इंडिया ने "हिन्दुस्तान टाइम्स" के साथ "न्युज इंडिया" नामक एक विशेष मासिक पत्र के मुद्रण के संबंध में एक करार किया है। यह प्रबंध विज्ञापनों के बदले नहीं किया गया है।

(ख) : करार की मुख्य बातें यह हैं :—

(i) "न्यूज इंडिया" की 20,000 प्रतियों के लिये प्रति प्रतिलिपि लागत 85 पैसे होगी, और 4,000 अथवा अधिक अतिरिक्त प्रतियों की लागत प्रति प्रतिलिपि 60 पैसे होगी ;

(ii) अदायगी रुपयों में होगी ;

(iii) 16 पृष्ठों में से मध्य के दो पृष्ठों का ऊपयोग एयर इंडिया द्वारा विज्ञापनों अथवा अन्य प्रयोजनों के लिए किया जाएगा और इसके लिए कोई प्रभार नही दिया जाएगा;

(iv) "न्यूज इंडिया" पत्र विशिष्तया और अनन्य रूप से एयर इंडिया द्वारा संयुक्त राज्य अमरीका एवं कनाडा में डाक सूची में सम्मिलित वहाँ निवास करने वाले 39,000 शारतीयों में निःशुल्क वितरण के लिए निकाला जाता है। संयुक्त राज्य अमरीका/कनाडा गोलार्द्ध से बाहर 'हिन्दुस्तान टाइम्स' इच्छानुसार इस पत्र का विक्रय कर सकता है ;

(v) एयर इंडिया का पत्र के सम्पादकीय/समाचारों के बारे में कोई उत्तरदायित्व नहीं है;

(vi) समझौता प्रथमतः 12 महीनों की अवधि के लिए है।

(ग) वर्तमान समझौता करने से पूर्व, संयुक्त राज्य अमरीका/कनाडा में रहने वाले भारतीय समाज से सम्पर्क मुख्यतया सीधी भेजी गयी डाक द्वारा किया जाता था। इसे बढ़ते हुए भारतीय समाज की रुचि एवं हितों की पूर्ति के लिए अपर्याप्त पाया गया। नई व्यवस्था से यह सुधार हुआ है कि पत्र में भारत के बारे में ताजे समाचार रहते हैं तथा इससे एयर इंडिया को अधिक प्रभावी विज्ञापन एवं अभिव्यक्ति का अवसर प्राप्त होता है।

यू० एस० ए० में एयर इंडिया ने संयुक्त राज्य अमरीका/कनाडा से भारत की यात्रा करने वाले यात्रियों से अप्रैल/नवम्बर 1973 के दौरान 4.28 करोड़ रुपए का राजस्व कमाया।

पश्चिम बंगाल बन्द के दिनों में इण्डियन एयरलाइंस द्वारा न्यूनतम विमान सेवाओं की व्यवस्था

3280. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 26 जुलाई, और 27 नवम्बर, 1973 के पश्चिम बंगाल बन्द के अवसरों पर कलकत्ता स्थित इण्डियन एयरलाइन्स के कार्यालय ने न्यूनतम सेवाओं की व्यवस्था की थी।

(ख) क्या बन्द दिवसों से पूर्ववर्ती रातों को कलकत्ता में रह रहे सभी विमान कर्मचारियों इंजिनियरों और तकनीशियनों को कलकत्ता के शानदार होटलों में ठहराया गया था और भारी धन-राशि खर्च की गयी थी और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) क्या सार्वजनिक उपयोग की सेवा का संचालन करने के लिये यह भारी खर्च न्यायोचित है।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) कलकत्ता में बंद का आयोजन 27 जुलाई, 1973 तथा 17 नवम्बर, 1973 (26 जुलाई, तथा 27 नवम्बर नहीं) को किया गया था बन्द के इन दिनों इंडियन एयरलाइन्स ने कई सेवाएं परिचालित की जिन में यातायात की आवश्यकता के लिये कुछ मिलायी गयी (कंबाइंड) सेवाएं भी सम्मिलित थीं।

(ख) और (ग) : बन्द के दिनों में नगर के भिन्न-भिन्न भागों से कर्मीदल के सदस्यों को लाने में कठिनायी होने के कारण उन्हें सेवाएं परिचालित करने के लिये किसी होटल में रखने की सामान्य प्रथा है। तदानुसार उड़ान कार्मिकों को जिनमें उड़ान इंजीनियर भी सम्मिलित थे, उनकी हकदारी के अनुसार 27 जुलाई, तथा 17 नवम्बर, 1973 को होटल रिट्ज व ग्रांड होटल में ठहराया गया था। यदि सेवाएं रद्द कर दी गयीं होतीं तो पारगामी यात्रियों को, जिनमें पर्यटक भी सम्मिलित थे, कार्यक्रमों को अत्याधिक अस्त-व्यस्त करने के अलावा सेवाओं को रद्द करने से प्रभावित होने वाले यात्रियों के लिए होटल के आवास के रूप में कारपोरेशन को बहुत बड़ी धनराशि व्यय करनी पड़ती।

इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा कारवेल्स तथा बोइंग-737 के पट्टे पर लेने के लिये विदेशी मुद्रा के रूप में दी गई धनराशि

3281. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हड़ताल के कारण इंडियन एयर लाइन्स को विदेशी मुद्रा के रूप में तीन कारवेल विमानों के लिये प्रतिमास 25,000 डालर और बोइंग 733 के विमानों के लिये प्रति दिन 8,000 रुपए पट्टे की राशि के रूप में देने पड़े ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर): जी नहीं, तालाबन्दी के कारण विमानों को पट्टे पर लेने के लिये विदेशी मुद्रा में अथवा रुपयों में कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं करना पड़ा। इण्डियन एयर लाइन्स ने अपनी जेट क्षमता की कमी को पूरा करने के लिये तालाबन्दी से पहले फ्रांस से तीन कारवेल विमान 25,000 डालर प्रति विमान प्रतिमास पट्टे पर लेने के लिये एक करार पर हस्ताक्षर किये थे। तीन में से दो कारवेल तालाबन्दी से पहले प्राप्त हुए थे तथा उन्हें परिचालन में लगा दिया गया था तीसरा विमान दिसम्बर में प्राप्त हुआ था तथा उसे जनवरी, 1974 में परिचालन में लगा दिया गया था। कोई बोइंग-737 विमान पट्टे पर नहीं लिया गया।

स्टेट बैंक आफ इंडिया और राष्ट्रीयकृत बैंकों के लाभ और हानि के लेखे

3282. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों में, अलग-अलग स्टेट बैंक आफ इण्डिया के लाभ और हानि संबंधी लेखे क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): 31 दिसम्बर, 1971 तथा 31 दिसम्बर, 1972 को समाप्त होने वाले वर्षों में भारतीय स्टेट बैंक की आय व्यय तथा प्रकाशित निवल लाभ इस प्रकार रहा :—

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष के अन्त में	आय	व्यय	प्रकाशित निवल लाभ
31-12-1971	142.06	138.28	3.78
31-12-1972	168.91	165.06	3.85

सुपारी और लौंग के आयात पर राज्य व्यापार निगम को हुआ घाटा

3283. **श्री ज्योतिर्मय बसु**
श्री सी० जनार्दनन } : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीस लाख रुपये मूल्य की सुपारी और लौंग के आयात-व्यापार पर राज्य व्यापार निगम को दस लाख रुपए से अधिक का घाटा हुआ है ; और

(ख). यदि हां, तो इतनी अधिक राशि का घाटा होने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) जी नहीं।

(ख). प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत और उत्तर कोरिया के बीच व्यापार समझौता

3284. **श्री वीरभद्र सिंह**
श्री आर० एन० बर्मन } : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-उत्तर कोरिया के बीच व्यापार और भुगतान समझौते पर शीघ्र ही हस्ताक्षर किये जाने की संभावना है ; और

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क). कोरिया के लोकतंत्रीय जनवादी गणराज्य के साथ व्यापार तथा भुगतान करार पर 18 फरवरी, 1974 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर हुए।

(ख) मोटे तौर पर करार की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(1) करार तीन वर्षों की अवधि के लिये वैद्य रहेगा।

(2) कोरिया के लोकतंत्रीय जनवादी गणराज्य से भारत को और भारत से कोरिया को लोकतंत्रीय जनवादी गणराज्य को माल का निर्यात उन सूचियों के अनुसार किया जायगा जिन पर दोनों पक्षकार प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के लिये सहमत हो जाएं :

(3) दोनों देशों के बीच व्यापार समता तथा पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों के अनुसार होगा।

(4) दोनों देश एक दूसरे को सीमा-शुल्कों और आयात तथा निर्यात संबंधी प्रभारों के विषय में परम मित्र राष्ट्र व्यवहार प्रदान करेंगे।

(5) दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक तथा गैर वाणिज्यिक स्वरूप के सभी भुगतान अपरिवर्तनीय भारतीय रुपयों में होंगे।

फारस की खाड़ी के देशों के लिये नयी निर्यात नीति

3285. **श्री वीरभद्र सिंह**
श्री समर गुह } : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने भारत से निर्यात के बारे में कुवैत और फारस की खाड़ी के अन्य देशों के साथ करार किया है; और

(ख) यदि हां तो इस करार की मुख्य शर्तें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : खाड़ी के देशों में से ईराक कुवैत और ईरान के साथ भारत द्वारा व्यापार और आर्थिक करार किये गये हैं। इन करारों की खास-खास बातें निम्नलिखित हैं :—

भारत-ईराक व्यापार करार और भारत-ईराक आर्थिक और तकनीकी सहयोग करार :

(1) दोनों देशों के बीच व्यापार संतुलित रखने के लिये सभी संभव प्रयत्न किये जायेंगे।

(2) करार के अन्तर्गत भुगतान परिवर्तनीय मुद्रा में किये जायेंगे।

(3) व्यापार मेलों के आयोजन के लिये सुविधाएं देना।

(4) उद्योगों और कृषि के विकास के लिए आपसी सहयोग।

(5) करारों और व्यापार योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा हेतु संयुक्त समिति का गठन तथा निर्धारित अवधि के लिए व्यापार योजनाएं तैयार करना।

भारत-कुवैत व्यापार और आर्थिक करार

(1) दोनों देशों के बीच व्यापार सामान्य व्यापार माध्यमों से होगा और भुगतान किसी भी मुक्त परिवर्तनीय मुद्रा में तय किये जायेंगे।

(2) दोनों देश व्यापार मेले और प्रदर्शनियां आयोजित करने के लिये सुविधाएं देंगे।

(3) तकनीकी प्रशिक्षण और सहायता देकर वैज्ञानिक तथा तकनीकी ज्ञान के आदान-प्रदान और उपयोग को बढ़ावा देने के संबंध में सहयोग।

(4) संयुक्त उद्यमों की संभाव्यताओं का पता लगाना।

(5) निर्धारित समय पर विशिष्ट व्यापार व्यवस्थाएं सम्पन्न करना।

(6) संयुक्त समिति की स्थापना जिससे कि अन्य बातों के साथ-साथ विशिष्ट व्यापार व्यवस्थाएं तैयार की जा सकें और दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग के विस्तार तथा व्यापारिक लेन-देन को बढ़ाने के लिए क्षेत्रों, परियोजनाओं, वस्तुओं आदि का पता लगाया जा सके ।

भारत-ईरान व्यापार करार :

(1) दोनों देशों के बीच व्यापार का विस्तार और वृद्धि किये जाने की संभाव्यताओं का पता लगाना ।

(2) दोनों देशों के बीच आयात और निर्यात की सुविधाएं देना।

(3) व्यापार मेले और प्रदर्शनियां आयोजित करने के लिये सुविधाएं देना।

उत्तर कोरिया से व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल की भारत यात्रा

3286. **श्री वीरभद्र सिंह**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन } : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1974 में लोकतंत्रीय गणराज्य कोरिया से व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भारत आया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसके साथ क्या क्या चर्चा हुई और उसका क्या परिणाम निकला ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क). जी हां।

(ख) कोरिया के लोकतंत्रीय जनवादी गणराज्य के प्रतिनिधिमंडल से जो बातचीत हुई उसके परिणामस्वरूप 18 फरवरी, 1974 को एक व्यापार तथा भुगतान करार पर हस्ताक्षर हुए और यह करार तीन वर्ष के लिये वैध रहेगा।

इसके साथ ही, भारत तथा कोरिया के लोकतंत्रीय जनवादी गणराज्य के बीच 1974 के लिये संलेख पर भी हस्ताक्षर हुए। इसके अनुसार दोनों देशों के बीच 1974 में 26 करोड़ रु० के व्यापार का प्रस्ताव है। भारत 1974 में कोरिया के लोकतंत्रीय जनवादी गणराज्य से इस्पात, जस्ता, सीसा यूरिया, मैंगनीशिया, खंगर आदि का आयात करेगा और उसे वस्त्र, टायरों तथा ट्यूबों, पटसन माल, रबड़ तथा चमड़े आदि का निर्यात करेगा।

दोहरे कर से बचने के लिए भारत और बेल्जियम के बीच समझौता

3287. **श्री वीरभद्र सिंह**
श्री आर० वी० स्वामीनाथन् } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आय के दोहरे कर से बचने के लिये भारत और बेल्जियम ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) और (ख). जी हां। करार पर 7-2-1974 को ब्रुसेल्स में हस्ताक्षर हुए। तथापि इसके प्रवर्तन में आने से पूर्व इसके लिए ऐसे पत्र के आदान प्रदान की औपचारिकता पूरी की जानी है जिनसे यह प्रमाणित हो कि प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनसार समुचित कार्यविधि का अनुपालन किया गया है। इस करार के प्रवर्तन में आते ही इसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी जायगी।

विशाखापत्तनम तथा विजयवाड़ा का दर्जा बढ़ाया जाना

3288. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम्** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1973 के मध्य वर्षीय अनुमान के अनुसार विशाखापत्तनम तथा विजयवाड़ा के जनसंख्या संबंधी आंकड़े क्या हैं।

(ख) क्या इन नगरों को 'सी०' श्रेणी से बढ़ाकर 'बी०-2' दर्जा किए जाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रलय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) 1971 की जनगणना-रिपोर्ट के अनुसार विशाखापत्तनम् नगरपालिका तथा उसके नगरीय समुच्य की जनसंख्या क्रमश: 352,504 और 363,467 थी और विजयवाड़ा नगरपालिका तथा उसके नगरीय समुच्य की जनसंख्या क्रमश:

317,258 तथा 344,607 थी। जनगणना अधिकारियों ने वर्ष 1973 की आबादी के संबंध में कोई अनुमान प्रकाशित नहीं किये।

(ख). जी हां।

(ग). नगर निवास पूर्ति भत्ता और मकान किराया भत्ता के प्रयोजनार्थ नगरों का वर्गीकरण करने के लिये 1971 की जनगणना रिपोर्ट में दी गयी जनसंख्या को आधार माना जाता है। इस आधार पर, इन दोनों नगरों का दर्जा बढ़ा कर उनको बी०-2 श्रेणी में रखना सम्भव नहीं पाया गया है।

इण्डियन एयरलाइंस में लागू किये गये बचत उपाय

3289. **श्री शंकर राव सावन्त**
श्री लम्बोदर बलियार } : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइंस में जारी की गई नई पारी पद्धति की मुख्य विशेषतायें क्या हैं; और

(ख) इंडियन एयरलाइंस में जारी किए गए विभिन्न बचत उपाय कौन से हैं और उनमें से प्रत्येक कितनी वार्षिक बचत होगी।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) नयी शिफ्ट प्रणाली की मोटी-मोटी विशेषताएं निम्न प्रकार है :

(1) परिचालन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शिफ्टों के समय में संशोधन किया गया है।

(2) कर्मचारियों को इस प्रकार से तैनात किया गया है कि अपेक्षित कर्मचारियों की संख्या कार्यभार से मेल खा जाए जिस से कर्मचारियों की कृत्रिम अल्पता एवं बहुलता समाप्त हो जाये।

(ख) मोटे तौर पर, व्यय में किफायत करने के लिए इण्डियन एयरलाइंस द्वारा अपनाये गये अभिप्रस्तावित उपाय निम्न प्रकार हैं :

(1) संशोधित शिफ्ट प्रणाली का प्रवर्तन।

(2) बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास तथा हैदराबाद में यात्री परिवहन के कार्य का अन्य प्राधिकरणों अथवा अभिकरणों को हस्तान्तरण।

(3) मुख्य भोजन परोसना बन्द करने के परिणामस्वरूप बोइंग 737 विमानों पर अधिक सीटों की व्यवस्था।

(4) कुछ अपव्ययी कार्य प्रणालियों की समाप्ति, जैसे :

(क) एक ही ओर की कमान-प्रणाली की समाप्ति;

(ख) गैर-परिचालनात्मक रात्रि विरामों में कमी ;

(ग) विमानचालकों के उपयोग में सुधार; तथा

(घ) अल्पावधि स्थानान्तरणों में कमी।

यद्यपि इस समय बचत की मात्रा का निर्धारण कर सकना सम्भव नहीं है, तथापि यह आशा की जाती है कि एयरलाइंस की लाभदायकता में काफी सुधार होगा।

एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन द्वारा हाल ही में भाड़ा बढ़ाये जाने का प्रभाव

3290. **श्री शंकर राव सावन्त**
श्री धामनकर } : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन द्वारा हाल की भाड़ा वृद्धि का (एक) विमान द्वारा यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या पर, और (दो) इन दो निगमों की वित्तीय स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : इण्डियन एयरलाइंस के किरायों में 1 फरवरी, 1974 से 25 प्रतिशत की वृद्धि की गयी थी। एयर इण्डिया के किरायों में 6 जनवरी, 1974 से 6 प्रतिशतकी वृद्धि की गई थी और 15 मार्च 1974 से 7 प्रतिशत की और वृद्धि की जा रही है। यात्री यातायात पर पड़ने वाले प्रभाव का अभी इतनी जल्दी मूल्यांकन कर सकना संभव नहीं होगा, लेकिन ऐसा अनुमान है कि यह प्रभाव मामूली होगा।

बढ़े हुए किरायों के परिणामस्वरूप पूरे एक वर्ष में इण्डियन एयरलाइंस को अपने राजस्व में लगभग 15 करोड़ रुपये तथा एयर-इण्डिया को लगभग 13.5 करोड़ रुपये की वृद्धि होने की आशा है। परन्तु ये वृद्धियां ईंधन की कीमतों में अत्याधिक वृद्धि के कारण पूर्णरूप से प्रतिसंतुलित हो गई हैं। हाल ही में ईंधन की कीमत में हुई वृद्धि के कारण पूरे एक वर्ष में इण्डियन एयरलाइंस पर लगभग 27 करोड़ रुपये तथा एयर-इण्डिया पर 40 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

Printing of Forms by Nationalised Banks

3291. **Shri Jagannathrao Joshi**
Dr. Laxminarayan Pandey } : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(*a*) the names of the nationalised banks which get their cheques, drafts, deposit receipts, pass books, regular statements and all other types of forms printed in both Hindi and English in compliance with provisions of the Official Languages Act and for how many years they have been doing this;

(*b*) the total number of various types of forms got printed by the Reserve Bank of India and the number of those cut of them, printed in Hindi;

(*c*) the number of publications brought out and circulars addressed by the Reserve Bank to other Banks in which Hindi was also used as also the number of those in which English only was used during the last three years, yearwise; and

(*d*) the time by which Hindi is likely to get its due place in this context ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (*a*) The following 12 banks have introduced in Hindi-speaking areas several forms, such as Pay-in-Slips drawal forms, current account opening forms, loan application forms (particularly applications agricultural loans) etc. both in Hindi and English :

1. Central Bank of India
2. Bank of India
3. Punjab National Bank

4. Bank of Baroda
5. United Commercial Bank
6. Canara Bank
7. United Bank of India
8. Dena Bank
9. Syndicate Bank
10. Union Bank of India
11. Allahabad Bank
12. Bank of Maharashtra

The remaining two banks, namely, Indian Bank and Indian Overseas Bank, are also making arrangements for printing the forms bilingually in Hindi and English.

Reserve Bank of India issued instructions to all commercial banks in 1968 to consider the desirability of having the literature, forms, etc. pertaining to agricultural loans, printed in the regional languages. In compliance with the provisions of the Official Languages Act, 1963 (as amended), the public sector banks have been advised to make available all the forms used by the public bilingually in Hindi and English for use in the Hindi speaking areas.

(*b*) The Reserve Bank of India gets printed/cyclostyled, both in Hindi and English, such of the forms ass are used by the public in their dealings with the Bank e.g. application for exchange of defective notes and correspondence thereon, applications for units of the Unit Trust of India, application for release of foreign exchange for different purposes, application for drafts, etc., objections raised regarding third party cheques, letter advising parties that securities are ready for delivery, Annuity Deposit Certificate forms, etc. The number of such forms in use at present is 136.

(*c*) Reserve Bank of India and its associated institutions have brought out 20 publications both in Hindi and English during last three years :

1971-72	6
1972-73	8
1973-74	6

A section in Hindi has also been added in the monthly bulletin of the Reserve Bank of India since October, 1972.

The Reserve Bank of India have started issuing circulars regarding progressive use of Hindi in the public sector banks both in Hindi and English, from the month of July, 1973. 25 such circulars have so far been issued by the Reserve Bank of India.

(*d*) The banks have been endeavouring to make use of Hindi as far as possible. Appreciable progress has already been made in this regard. Since the task of providing necessary infrastructure facilities like appointment of Hindi translators. typists, stenographers, acquiring of Hindi typewriters and training of staff in Hindi is time consuming, the pace of adoption of Hindi by all the nationalised banks can only be gradual. It is expected that, after the Banks have been provided with these facilities the progress in the introduction of Hindi forms etc. would be more rapid.

Progress in this regard is kept under constant watch by the Official Languages Implementation Committee of the Department of Banking.

राज्य व्यपार निगम द्वारा बनाई गइ निर्यात सहायता योजना

3292. **श्री फतह सिंह राव गायकवाड** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने निर्माता निर्यातकों के लिये प्राथमिकता के आधार पर, कोई निर्यात सहायता योजना बना ई है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मोटी रूपरेखा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) जी हां।

(ख) राज्य व्यापार निगम ने पक्की निर्यात संविदाओं को पूरा करने में राज्य व्यापार निगम के विनिर्याता-निर्यातक सहयोगियों की सहायता करने के लिए एक निर्यात सहायता योजना बनाई है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य व्यापार निगम निर्यात उत्पादन के लिए आयातित कच्चे माल का अग्रिम प्रबंध करेगा और कच्चे माल पर व्यय की गई विदेशी मुद्रा पेशगी/निर्यातों पर अर्जित की गई उतने ही मूल्य की आर० ई० पी० हकदारियां लौटाकर पूरी की जायेंगी।

हिमाचल प्रदेश में भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा शुरू की गई परियोजनाएं

3293. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा कौन कौनसी परियोजनायें शुरू की गई हैं :

(ख) क्या हिमाचल प्रदेश में पर्यटन के विकास के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कुछ और परियोजनाएं शामिल की गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो ये परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री [डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषी] : (क) से (ग) भारत पर्यटन विकास निगम के हिमाचल प्रदेश में 2 यात्री लॉज हैं, एक कुल्लू में (6 कमरे-8 शय्याएं) तथा दूसरा मनाली में (10 कमरे-16 शय्याएं)। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में दोनों प्रायोजनाओं पर 40 लाख रुपये की कुल लागत से प्रत्येक लॉज में 25 डबल-रूम जोड़ कर इन लॉजों का विस्तार करने का प्रस्ताव है। पांचवीं योजना में भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा हिमाचल प्रदेश में प्रारम्भ की जाने वाली अन्य कोई स्कीम नहीं है।

आयात लाइसेंसों की मंजूरी के लिये आवेदन पत्र

3294. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973 की अंतिम तिमाही में आयात लाइसेंस जारी करने के लिये सरकार को कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए ;

(ख) कितने लाइसेंस मंजूर किए गए हैं तथा कितने मूल्य के;

(ग) कितने आवेदन-पत्र अनिर्णीत पड़े हैं और प्रत्येक मामले में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में वर्ष 1972 की अंतिम तिमाही के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) तथा (घ) वर्ष 1973 की आखिरी तिमाही में आयात लाइसेंसों के लिए जितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए और उसके मुकाबले में 1972 की उसी तिमाही जितने प्राप्त हुए थे, उसका ब्यौरा इस प्रकार है :

(1) 1973 की आखिरी तिमाही	56,691
(2) 1972 की आखिरी तिमाही	42,000

(ख) तथा (घ) उपर्युक्त अवधियों में जितने लाइसेंस दिये गये हैं उनकी संख्या और मूल्य इस प्रकार है :

अवधि	दिये गये लाइसेंसों की संख्या	मूल्य (करोड़ में)
अक्तूबर–दिसम्बर 1973	27,729	567.60 करोड़ रु०
अक्तूबर–दिसम्बर 1972	27,469	513.94 करोड़ रु०

(ग) तथा (घ) : आयात लाइसेंसों के आवेदन पत्रों को निपटाने के लिए समय सीमायें निर्धारित कर दी गई हैं जिसके अनुसार आयात लाइसेंसों को (सी जी/एच इ पी को छोड़कर) आवेदन पत्र की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर जारी करना जरूरी होता है। सी जी / एच इ पी आवेदन पत्रों के संबंध में आयात लाइसेंसों का आवेदन प्राप्त होने के सात दिन के भीतर जारी करना आवश्यक होता है। 1973 और 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान क्रमश: 14,448 गौर 10,242 आवेदन-पत्र निपटाने के लिए लम्बित थे। इनमें से क्रमश: 6,838 और 5,226 आवेदन-पत्र एक महीने से कम पुराने थे । आयात आवेदन पत्रों के एक महीने से अधिक समय तक लंबित रहने के कारण इस प्रकार हैं :

लंबित रहने के कारण	आवेदन पत्रों की संख्या	
	31-12-1973 को	31-12-1972 को
(1) ऐसे आवेदन-पत्र जिनमें नये प्रकार से नीति संबंधी निर्णय करने की आवश्यकता थी ।	763	781
(2) ऐसे आवेदन पत्र जो स्पष्टीकरण सिफारिशों के लिए अन्य विभागों/ मंत्रालयों को भेजे गये ।	426	580
(3) आवेदन-पत्रों में कमियों के बारे में पत्र जारी करने के बाद आवेदकों से उत्तर न मिलने के कारण लंबित रहे ।	6318	3559
(4) ऐसी फर्में जो प्रस्तुत अवस्था में हैं या काली सूची में हैं	103	136
जोड	7610	5056

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कृषि प्रयोजन के लिये ऋण दिया जाना

3295. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **वित** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों ने कृषि प्रयोजनों के लिए भी ऋण दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई ऐसी व्यवस्था है कि किसी बैंक द्वारा एक वर्ष में दिए जाने वाले ऋण की कुल प्रतिशत धनराशि कृषि के लिए आरक्षित रखी जानी चाहिए; और

(ग) यदि हां, तो कितने प्रतिशत ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : जी, नहीं। बैंक कृषि सम्बन्धी ऋणों या किसी विशेष क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋणों की पहले से ही कोई निश्चित सीमा निर्धारित नहीं करते। कृषि के लिए दिए जाने वाले ऋण स्थानीय क्षमता, उपलब्ध आधारभूत ढांचे, स्थानीय किसानों में बैंक सम्बन्धी आदतों और बैंक की शाखाओं के ढांचे पर निर्भर करते हैं। फिर भी, सरकारी क्षेत्र के बैंक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों जिसमें कृषि भी शामिल है, की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए अपने वार्षिक सम्पन्न कार्य बजट तैयार करने का प्रयत्न कर रहे हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए कुल ऋणों के अनुपात में कृषि के लिए दिए गए ऋणों (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) की बकाया ऋणों का प्रतिशत जून, 1969 के अन्त में 5.5 था और यह प्रतिशत जून, 1973 में बढ़कर 8.8 हो गया।

वर्तमान विमान रख-रखाव 'शैड्यूल' का पुनरीक्षण करने का प्रस्ताव

3296. **श्री राम भगत पासवान**
श्री एम० राम० गोपाल रेड्डी } : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्तमान विमान रख-रखाव 'शैड्यूल' के पुनरीक्षण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसके लाभ क्या हैं?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री राजबहादुर) : (क) विमान संधारण अनुसूचियों का निरन्तर पुनरालोकन किया जाता है तथा उनका निम्नलिखित आधार पर समय समय पर संशोधन किया जाता है :--

(i) निर्माताओं की सिफारिशें;

(ii) विश्व भर के परिचालकों का अनुभव; तथा

(iii) हमारे राष्ट्रीय वाहकों का परिचालन अनुभव।

(ख) संधारण अनुसूचियों के संशोधन का उद्देश्य होता है--विमानों तथा प्रणालियों की विश्वसनीयता में सुधार, परिचालनों की सुरक्षा तथा विमानों एवं अर्थव्यवस्था का और अच्छा उपयोग।

सरकारी क्षेत्रीय प्रतिष्ठानों के मुख्य कार्यकारियों के चयन के लिये निकाय

3297. **श्री राम भगत पासवान**
श्री प्रसन्नभाई मैहता } : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने सरकारी क्षेत्रीय प्रतिस्ठानों के मुख्य कार्यकारियों के चयन के लिए नये निकाय के गठन का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) योजना आयोग ने ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया है। फिर भी, योजना आयोग के सदस्य की अध्क्षता में सरकारी

उद्यमों सम्बन्धी कार्यकारी समिति ने सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में उच्च प्रबन्धकीय अधिकारियों के चुनाव के बारे में कुछ सुझाव दिए हैं।

(ख) सरकारी उद्यमों सम्बन्धी कार्यकारी समिति की सिफारिशों और अन्य सम्बन्धी बातों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने सरकारी क्षेत्र के लिए एक नयी प्रबन्धकीय कार्मिक नीति के ढांचे के बारे में फैसला लिया है। यह नीति उद्यमों को प्रधान प्रबन्धक से निचले पदों पर नियुक्तियाँ करने में काफी स्वतन्त्रता देने की आवश्यकता पर आधारित है, ताकि विशिसट प्रवीणता के विकास, अधिक निरन्तरता तथा कार्य सम्बन्धी बचनबद्धता और अधिक गतिशीलता को प्रोत्साहन देने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिले। जहां तक सरकार द्वारा इन उद्यमों के बोर्डों में नियुक्तियों किए जाने का सम्बन्ध है, यह निश्चय किया गया है कि पैनल प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जाए। इसके स्थान पर एक उच्च स्तरीय बोर्ड की स्थापना की जायेगी जिसके सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको उच्च स्तर के कर्मचारियों के चुनाव का अनुभव प्राप्त होगा। यह बोर्ड उच्च पदों के रिक्त होने पर उन्हें भरने के लिए उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगा।

चाय के मूल्यों के संबंध में श्रीलंका के साथ हुए समझौते की व्यावहारिकता

3298. **श्री प्रबोध चन्द्र**
प्रो० मधु दण्डवते } : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय के मूल्यों के सम्बन्ध में श्रीलंका के साथ समझौते की व्यावहारिकता के बारे में कुछ सन्देह उत्पन्न हो गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं और उनका समाधान करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) चाय की कीमतों के बारे में भारत और श्रीलंका के बीच कोई समझौता नहीं है। फरवरी 1972 में कोलम्बो में भारत और श्रीलंका के बीच जो विचार-विमर्श हुए थे उनमें इन दोनों देशों ने इस बात को माना था कि चाय की कीमतों में सुधार के लिए संयुक्त कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इंडियन एयरलाइंस की अन्तर्देशीय सेवा चलाने से हुआ लाभ

3299. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय 103 मार्गों में से केवल 15 मार्गों पर विमानों को चला करके भी इंडियन एयरलाइंस की अन्तर्देशीय सेवा से लाभ अर्जित करने का समाचार मिला है;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं; और

(ग) कौन-कौन से उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर): (क) और (ख) वर्ष 1973-74 के लिए परिचालन विषयक अर्थव्यवस्था का मार्गवार विश्लेषण अभी उपलब्ध नहीं है।

तथापि, यह ठीक है कि बहुत से मार्ग घाटे पर चल रहे हैं। इसके अनेक कारण हैं जिनमें ये सम्मिलित है। विमान बेड़े की मिश्रित व्यवस्था, पुराने अलाभप्रद विमानों का परिचालन, छोटे सैक्टर, श्रमिक झगड़ों के कारण सेवाओं का बन्द होना तथा बढ़ते हुए परिचालन व्यय।

(ग) इण्डियन एयरलाइन्स ने अपने परिचालनों को सुव्यवस्थित करने तथा अपव्ययी कार्यप्रणालियों को समाप्त करने के लिए कदम उठाए हैं। इन उपायों से कार्यक्षमता तथा उत्पादिता में काफी सुधार होने की आशा है। तथापि, विमानन ईंधन के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि सतत चिन्ता का विषय है।

रासायनिक निर्यातकर्ताओं को दी जाने वाली आयात पुनः पूर्ति की दरों तथा नकद सहायता के पुनरीक्षण में असाधारण विलम्ब

3300. **श्री गजाधर माझी :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात पुनः पूर्ति की दर तथा नकद सहायता के निर्धारण तथा पुनरीक्षण में असाधारण विलम्ब हो रहा है जिसने रासायनिक निर्यातकर्ताओं के उत्साह को मन्द कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) तथा (ख) नकद सहायता तथा आयात प्रतिपूर्तियों के लिए आवेदन-पत्रों पर विचार निर्यातकों द्वारा निर्यात सम्वर्द्धन परिषदों के माध्यम से विहित फार्म में भर कर भेजी गई जानकारी के आधार पर, तकनीकी विकास महानिदेशक, लघु उद्योग के विकास आयुक्त तथा वित्त मन्त्रालय (व्यय विभाग तथा आर्थिक कार्य विभाग) के साथ परामर्श करके की जाती है। कुछ मामलों में जहां दी गई जानकारी की वैधता में शंका हो, लागत आंकड़े वित्त मन्त्रालय की लागत लेखा शाखा को सौंपे जाते हैं। पूर्ण जानकारी देने के पश्चात मामलों के निबटारे में असाधारण विलम्ब नहीं होता।

केन्दू पत्ते के निर्यात में उड़ीसा सरकार को हुई हानि

3301. **श्री गजाधर माझी :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्दू पत्तों के व्यापार में उड़ीसा सरकार को कोई हानि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) तथा (ख) : यह विषय उड़ीसा की राज्य सरकार से सम्बन्धित है और केन्द्रीय सरकार को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है।

गत दो वर्षों में सरकारी क्षेत्र के (यूनिटों द्वारा निर्यात)

3302. **डा० कर्णी सिंह** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में वर्ग-वार सरकारी क्षेत्र के यूनिटों द्वारा कुल कितने मूल्य का निर्यात किया गया; और

(ख) इसी अवधि में इन यूनिटों द्वारा कुल कितने मूल्य का आयात किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) तथा (ख) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तेल उत्पादक देशों को निर्यात

3303. **डा० कर्णी सिंह :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 तथा 1973-74 में उन तेल उत्पादक देशों को कुल कितने मूल्य का निर्यात किया गया जिनसे भारत ने तेल का आयात किया; और

(ख) विशेषतया निर्यात संवर्धन के लिए बनायी गयी नई योजना के अन्तर्गत आगामी दो वर्षों में इन देशों को किए जाने वाले निर्यात के मूल्य में कितनी वद्धि होने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) (क) निर्यातों (पुनिर्यात सहित) का कुल मूल्य वर्ष 1972-73 में 62.8 करोड़ रु० और अप्रैल-सितम्बर, 1973 के दौरान 37.4 करोड़ रु० था।

(ख) अनुमान है कि पश्चिम एशिया के तेल उत्पादक देशों को निर्यात (पुनिर्यात सहित) उनके 1972-73 के स्तर की तुलना में बढ़कर 1974-75 में लगभग तिगुने और 1975-76 तक चौगुने से अधिक हो जायेंगी।

दीनापुर छावनी तथा खगौल में काम कर रहे कर्मचारियों को मकान-किराया भत्ता तथा नगर प्रतिपूर्ति भत्ता

3304. **श्री रामावतार शास्त्री**
श्री भोला माझी } : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में हयात नगर कल्सा हैदराबाद से कितना दूर है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार के वे कर्मचारी जिनका कार्य स्थान हयात नगर कल्सा है, को उसी दर पर नगर प्रतिपूर्ति तथा मकान किराया भत्ता मिलेगा जो कि हैदराबाद के वर्गीकृत नगर में नियुक्त कर्मचारियों को मिल रहा है ;

(ग) दीनापुर छावनी तथा खगोल में काम कर रहे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को वैसी सुविधायें क्यों उपलब्ध नहीं होती जब कि दीनापुर छावनी, खगोल तथा पटना के बीच की दूरी पटना नगरनिगम (खाजपुरा तथा अनिसाबाद) के पश्चिमी छोर से पांच और चार किलोमीटर है और पटना खास से केवल 8 किलोमीटर और

(घ) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) इस सम्बन्ध में सामान्य आदेशों के अनुसार, नगर निवास प्रतिपूर्ति भत्ता तथा मकान किराया भत्ता किसी वर्गीकृत नगर की सीमाओं के 8 किलोमीटर के भीतर स्थित संस्थापनों में कार्य कर रहे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को देय होता है बशर्ते उस 8 किलोमीटर की सीमा के भीतर और कोई उपनगर नगर-पालिका, अधिसूचित क्षेत्र अथवा छावनी नहीं हो और वह स्थान अपनी आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति के लिए वर्गीकृत नगर पर आश्रित हो। हयात नगर कालसा हैदराबाद नगर की सीमाओं के 8 किलोमीटर के भीतर है और अन्य निर्धारित शर्तें पूरी करता है। तदनुसार, जिन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों का ड्यूटी का स्थान हयात नगर कालसा है वे नगर निवास प्रतिपूर्ति तथा मकान किराया भत्ते उन्हीं दरों पर पाने के हकदार हैं जिन दरों पर ये भत्ते वर्गीकृत नगर हैदराबाद की सीमाओं के भीतर तैनात कर्मचारियों को मिलते हैं।

(ग) तथा (घ). हयात नगर कालसा के विपरीत, दीनापुर छावनी तथा खगौल अपने आप में छावनी / नगर पालिका हैं और इसलिए ये स्थान पटना शहर में लागू दरों पर नगरनिवास प्रतिपूर्ति भत्ता/मकान किराया भत्ता मंजूर करने की शर्तें पूरी नहीं करते।

Advancing Loans by Nationalised Banks to Unemployed Technicians and Educated Persons in Bihar

3305. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether the progress of advancing loans by the nationalised banks in Bihar to unemployed technicians and educated persons for setting up industries is very slow;

(*b*) if so, the number of loan applications submitted by such applicants during the last one year and the number out of them disposed of so far;

(*c*) the minimum and maximum amount of loans given to the applicants whose cases have already been disposed of; and

(*d*) the reasons for slow progress in advancing loans and the time by which banks propose to advance loans to all the applicants ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) ((*a*) to (*d*) **The present arrangements for data flow in the various banks do not provide for compilation of overall information relating to number of applications received or pending with the banks, or in respect of advances to such detailed categories as unemployed technicians and educated persons for setting up industries. Bank's advances to unemployed technicians and educated persons for setting up industries would figure mostly under the priority sector groups "Small-scale industries" and "professional and self-employed persons". The available information regarding the public sector banks' advances to these sectors is set out below :**

	As at end of June, 1972		As at end of June, 1973 (Provisional)	
	Number of accounts	Amount out-standing (Rs. lakhs)	Number of accounts	Amount out-standing (Rs. lakhs)
Small Scale Industries	2229*	1079	4142*	1518
Professional and self-employed persons. .	930	26	2588	55

*No. of units.

2. Unemployed technicians and educated persons are also now eligible for assistance under the 'half-a-million jobs programmes'. The public sector bank have been specifically requested by Government to intensify their efforts in extending credit support for these programmes, which will benefit educated unemployed. The steps taken by the bank's towards this end include, *inter alia*,

(*i*) Ensuring speedy disposal of loan applications on the basis of viability , preferably within two months, and the review of organisation and procedures etc. towards this end;

(*ii*) Charging reasonable rates of interest for such schemes; in cases satisfying the criteria prescribed under the Differential Rates of Interest Scheme, the rate to be charged being only 4 %

(*iii*) Prescribing reasonable margins, which should be kept suitably low in the case of small loans, and for making sustained efforts to ensure larger spread of schemes for technical entrepreneurs for which no margin money is stipulated;

(*iv*) Supplementing the efforts of State Governments and their corporate agencies in providing consultancy and counselling services to small entrepreneurs; and

(*v*) Establishing close liaison with District and State authorities and State Financial and Corporate bodies so that decision-making for providing loan assistance to viable projects is speeded up.

रक्षा लेखा नियंत्रक कार्यालय, पटना के लिए भवन का निर्माण

3306. **श्री रामावतार शास्त्री**
श्री भोला मांझी } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटना में रक्षा लेखा नियंत्रक के कार्यालय के लिए बनाये जा रहे भवन के निर्माणकार्य में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) क्या सरकार का विचार भवन को जगह बदल कर पटना में किसी अन्य स्थान पर बनाने का है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख) पटना में रक्षा लेखा नियंत्रक के कार्यालय के लिये भवन निर्माण के निमित्त बिहार सरकार से तीन एकड़ भूमि खरीदी गई है। उस भूमि के एक भाग पर अनधिकृत कब्जा होने के कारण अब तक सम्पूर्ण खाली प्लाट पर अधिकार पाना सम्भव नहीं हो सका है और अनधिकृत कब्जा हटाने के लिये कार्यवाही की जा रही है। भवन के स्थान को बदलने का कोई इरादा नहीं है।

रक्षा लेखा नियंत्रक, पटना से कार्य का विकेन्द्रीकरण

3307. **श्री रामावतार शास्त्री**
श्री भोला मांझी } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा लेखा नियंत्रक के पटना स्थित कार्यालय से कुछ कार्य वापस लिया जा रहा है ;

(ख) क्या कार्यालय के कार्य भार में हो रही वृद्धि के अनुपात से पटना कार्यालय के कर्मचारियों की संख्या में भी वृद्धि की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो रक्षा लेखा नियंत्रक कार्यालय, पटना के कार्य के विकेन्द्रीकरण के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी नहीं, इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) जी हां। कार्य-भार में वृद्धि को देखते हुए पटना कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या समय-समय पर बढ़ाई गई है ।

(ग) ऊपर (क) को देखते हुए इसका प्रश्न ही नहीं उठता है।

निर्यात व्यापार का पुनरीक्षण

3308. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर**
श्री पी० गंगादेव } : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात व्यापार को नई दिशा देने के लिये जनवरी, 1974 के आरम्भ में नई दिल्ली में सरकार, व्यापार तथा उद्योग के प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या बातचीत के दौरान विदेशी मुद्रा अर्जन को बढ़ाने के उपाय तथा साधनों पर भी विचार किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मख्य विशेषताएं क्या हैं और इन उपायों से देश की अर्थ-व्यवस्था में कहां तक सुधार होगा।

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) निर्यात व्यापार को नई दिशा देने के लिए जनवरी 1974 में कोई विशिष्ट बैठक नहीं बुलाई गई थी। तथापि व्यापार संबंधी सलाहकार परिषद् की छठी बैठक 2-1-1974 को हुई थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, निर्यात व्यापार को नई दिशा देने की आवश्यकता पर चर्चा की गई।

(ख) तथा (ग). बैठक के कार्यवृत की प्रति संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।

तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिये भारत-फ्रांस आयोग की स्थापना

3309. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर**
श्री पी० ए० सांमिनाथन } : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और फ्रांस के बीच तकनीकी और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए एक संयुक्त भारत-फ्रांस आयोग स्थापित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या आयोग निर्णयों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा के लिये समय-समय पर बैठक आयोजित करेगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) जी हां।

(ख) ऐसा निश्चय किया गया है कि प्रस्तावित भारत-फ्रांस संयुक्त आयोग की बैठक प्रत्येक वर्ष और आवश्यकता पड़ने पर, उससे अधिक बार होगी ताकि दोनों देशों के बीच पारस्परिक सहयोग के प्रयत्नों को अमली रूप देने की प्रगति को आगे बढ़ाया जा सके।

वर्ष 1972-73 में तस्करी के सामान का पकड़ा जाना

3310. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1972-73 के दौरान 27 करोड़ रुपए की निषिद्ध वस्तुएं सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा पकड़ी गई थीं, और

(ख) यदि हां, तो पकड़ी गई वस्तुओं के मूल्य का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख). सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा वर्ष 1972-73 के दौरान पकड़ी गई निषिद्ध वस्तुओं का मूल्य तथा ब्यौरा नीचे दिये अनुसार है :—

क्र० सं०	वस्तु का नाम	मूल्य, लाख रुपयों में	
1.	सोना	110	अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा दर पर
2.	मुद्रा	101	भारतीय बाजार दर पर
3.	घड़ियां	318	
4.	संश्लिष्ट धागा	82	
5.	संश्लिष्ट वस्त्र	958	
6.	चांदी	56	
7.	हानिकार औषधि	56	
8.	गाड़ियां पथा जलयान	127	
9.	अन्य वस्तुएं	896	
	जोड़	2704	

राज्य व्यापार निगम द्वारा अखबारी कागज की सप्लाई

3311. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी**
श्री एम० गोपाल रेड्डी } : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन्डियन एन्ड ईस्टर्न न्यूजपेपर्स सोसायटी के **अध्यक्ष** के **अखबारी कागज** की सप्लाई के बारे में राज्य व्यापार निगम के दावे के संबंध में 9 फरवरी, 1974 के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) जी हां ।

(ख) राज्य व्यापार **निगम ने** 1,46,000 म० टन अखबारी कागज के आयात के लिए संविदाएं सम्पन्न की हैं तथा अखबारी कागज की उपरोक्त मात्रा के चालू वर्ष के दौरान भेजे जाने की संभावना है ।

राज्य व्यापार निगम चालू वर्ष में अखबारी कागज की और अधिक सप्लाई प्राप्त करने के लिए और आगे प्रयास कर रहा है । प्रश्नाधीन विचारों से सरकार सहमत नहीं है।

मध्यम तथा निम्न वर्गीय पर्यटकों को सुविधायें

3312. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी:** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्यम तथा निम्न वर्गों के भारतीय पर्यटकों को अच्छी तथा सस्ती पर्यटन सुविधाएं देने के लिये सरकार ने किस प्रकार की कार्यवाही की है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री : (डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषी) : चौथी योजना तथा उस के पश्चात पांचवीं योजना में केन्द्रीय क्षेत्र में पर्यटक रुचि के महत्वपूर्ण स्थानों पर पर्यटक बंगलों, युवा होस्टलों एवं स्वागत केन्द्रों के निर्माण से मध्य तथा निम्न आय वर्गों के पर्यटकों के लिये सस्ती सुविधायें प्राप्त हो सकेंगी । पर्यटन विभाग के इस प्रयत्न की राज्यों के पर्यटन विभाग द्वारा भी इस वर्ग के पर्यटकों के लिए आवास तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था कर के अनुपूर्ति की जाती है।

रुई के मूल्यों में वृद्धि

3313. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि इस वर्ष के आरम्भ से रुई की एक गांठ के मूल्य में 300 रुपये से 700 रुपये तक वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो रुई के मूल्य में अत्याधिक वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां । आरम्भ में प्रत्याशित फसल की अपेक्षा कम फसल तथा मिलों द्वारा अपेक्षाकृत अधिक खपत के कारण कीमतें बढ़ी हैं ।

(ख) उद्योग तथा व्यापार पर रिज़र्व बैंक आफ इंडिया ने ऋण नियंत्रण लगा दिया है । भारतीय रुई निगम के कार्य भी इस दृष्टिकोण से किये जाते हैं कि कीमतों में स्थिरता बनी रहे । तथापि कीमतों में तीव्र वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार विचार कर रही है कि कौन से उचित उपाय आवश्यक तथा संभव है ।

जीवन बीमा निगम का लाभ

3314. **श्री एम० सुदर्शनम**
श्री यमुना प्रसाद मंडल } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) वर्ष 1971, 1972 और 1973 में अलग-अलग जीवन बीमा निगम को कुल कितना लाभ हुआ ; और

(ख) इस लाभ को पालिसीधारियों में उनके प्रीमियम को घटाकर तथा उनके बोनस में वृद्धि करके, वितरित न किए जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) (क) और (ख) भारत के जीवन बीमा निगम के मामले में, लाभों को आम तौर पर सरप्लस कहा जाता है और परिसम्पत्तियों तथा देनदारियों का दो वर्ष में एक बार बीमांकित मूल्यांकन करने के बाद उसको निश्चित किया जाता है । 31 मार्च 1971 को किये गये मूल्यांकन से 118.13 करोड़ रुपये और 31 मार्च 1973 को किये गये मूल्यांकन से 154.57 करोड़ रुपये का सरप्लस निकला । जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 की धारा 28 की शर्तों के अनुसार, इस सरप्लस का 95 प्रतिशत बोनस के रूप में भागीदार पालिसी-धारियों को आवंटित किया गया है ।

उर्वरकों का आयात करने हेतु खनिज तथा धातु व्यापार निगम का सहायक निगम स्थापित करने का प्रस्ताव

3315. **श्री एम० सुदर्शनम**
श्री राम सहाय पांडे } : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उर्वरकों के आयात के सम्पूर्ण व्यापार के लिए खनिज धातु व्यापार निगम का एक सहायक निगम बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

Reduction in the number of flights by Indian Airlines due to shortage of Aviation fuel

3316. **Shri Onkar Lal Berwa**
Shri Biswanarayan Shastri } : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether due to shortage of aviation fuel the Indian Airlines is reducing the number of its flights ;

(b) if so, the number and names of such services with date on which the flight were stopped;

(c) the amount of loss likely to be suffered by the Corporation as a result thereof ; and

(d) whether any airport is going to be closed for non-operation of the services ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur) : (a) to (d). The services of Indian Air Lines have inevitably been affected by the current fuel crisis and till the position stabilises it is not possible to assess the impact precisely. For the present they have been compelled to discontinue services to the following stations :

1. Kamalpur
2. Kailashahdr
3. Keshod
4. Kandla
5. Porbandar
6. Port Blair
7. Nasik
8. Gaya
9. Allahabad
10. Muzaffarpur
11. Cooch-Behar
12. Jamshedpur
13. Jodhpur
14. Kulu
15. Pantnagar
16. Rangoon

Furthermore frequencies to the following stations are being reduced for the time being :—

1. Indore
2. Belgaum
3. Baroda
4. Dacca
5. Kathmandu
6. Poona
7. Colombo
8. Nagpur
9. Tezpur
10. Bombay
11. Calcutta
12. Madras

For the same reason the corporation has had to stop operating with Viscounts and Dakotas. These aircraft consume disproportionate quantities of fuel as compared to their revenue earning capacity. However, the corporation is keeping a watch on developments and will endeavour to resume services to these stations as early as possible.

Import of Foreign liquor

3317. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(*a*) whether foreign liquor is being consumed in India in large quantity for which foreign exchange is required to be spent : and

(*b*) if so, the economy in foreign liquor consumption proposed in the present plan ?

The Dupty Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. Gerorge) (*a*) No, Sir. The extent of import of Alcoholic beverages since 1969-70 is as follcws :—

Year	Value (Rs lakhs)
£969-70	49·10
1970-71	29·11
1971-72	24·06
1972-73	19·96
1973-74 (upto August, 1973)	8·27

(*b*) Imports are already being reluced progressively.

कूच-बिहार जिले में तम्बाकू व्यापारी

3318. श्री बी० के० दास चौधरी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कूच-बिहार राज्य के पश्चिम बंगाल में विलय से पूर्व भी कूच-बिहार जिले मे छोटे तम्बाकू व्यापारियों का ऐसा वर्ग था, जो "पैकर" नाम से जाना जाता था;

(ख) क्या कार्यकारी आदेशों द्वारा छोटे व्यापारियों को नये लाइसेंस देना बन्द कर दिया गया है और यदि हां, तो किस तिथि से और क्यों ;

(ग) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय उत्पादनशुल्क तथा नमक अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बनाये गए नियमों में संशोधन करने का है जिससे कि बिहार जिले के छोटे तम्बाकू व्यापारियों को लाइसेंस दिए जा सकें; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां, "पैकारी" प्रथा को सामान्यत: निरुत्साहित करने के लिए तथा उसे शनैः शनैः समाप्त करने के लिये जुलाई, 1954 में आदेश जारी किए गए थे । उपर्युक्त कार्यवाही का कारण यह था कि केन्द्रीय उत्पादनशुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944 तथा उसके अधीन बनाए गए नियम, भारत सरकार के अधिनियमन हैं, जो सम्पूर्ण भारत पर लागू हैं । वर्ष 1949 में कूच-बिहार का पश्चिम बंगाल के साथ विलय होने के पश्चात्, तथा उस वर्ष में केन्द्रीय उत्पादनशुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944 के उस क्षेत्र में लागू होने पर यह आवश्यक था कि उस क्षेत्र में तम्बाकू के व्यापार से संबंधित व्यक्तियों को केन्द्रीय उत्पादनशुल्क कानून के उपबन्धों के अन्तर्गत लाया जाय । "पैकारों" को, जो तम्बाकू के गोदामों के लाइसेंसधारियों तथा तम्बाकू सिझाने वालों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य कर रहे थे, उपर्युक्त पद्धति के अंतर्गत लाना अनिवार्य था । तथापि, उनके व्यापार को सहसा अस्त-व्यस्त करना अथवा जिस व्यापार से वे अनभिज्ञ थे उन्हें उसमें ढकेलना चूंकि वांछनीय नहीं समझा गया, इसलिए उन्हें कतिपय रियायतें दी गई तथा अपना व्यापार जारी रखने की अनुमति प्रदान की गई । साथ ही, चूंकि इस प्रणाली से सरकारी राजस्व के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता था, इसलिए यह निर्णय किया गया कि नए लाइसेंस जारी नहीं करके तथा उन व्यक्तियों के भी लाइसेंस रद्द करके जिन्होंने केन्द्रीय उत्पादनशुल्क कानूनों आदि के खिलाफ अपराध किए हैं, "पैकारी" प्रणाली को धीरे धीरे समाप्त किया जाय।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) ऐसा करना न तो कानून की एकरूपता की दृष्टि से और न ही राजस्व विषयक हितों की दृष्टि से वांछनीय है ।

कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली और मद्रास हवाई अड्डों से इंडियन एयरलाइन्स तथा एयर इंडिया के विमानों द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या

3319. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) गत तीन वर्षों में कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली और मद्रास हवाई अड्डों में से प्रत्येक से इंडियन एयरलाइंस तथा एयर इंडिया के विमानों से कितने-कितने यात्रियों ने यात्रा की; और

(ख) इसी अवधि में इण्डियन एयरलाइंस तथा एयर इण्डिया के कितने-कितने विमानों ने कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली और मद्रास हवाई अड्डों से उड़ाने भरीं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) इण्डियन एयरलाइस एवं एयर-इण्डिया द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली और मद्रास विमानक्षेत्रों से विमानक्षेत्र-द्वार वाहित यात्रियों की संख्या :—

	1971	1972	1973
इण्डियन एयरलाइंस			
कलकत्ता	*2,40,003	3,57,477	3,48,144
बम्बई	4,36,664	5,61,305	5,61,932
दिल्ली	3,42,443	4,40,234	4,26,387
मद्रास	1,64,939	1,98,509	2.14,879

*मार्च, 1971 के आंकड़े शामिल नहीं हैं ।

एयर इण्डिया			
कलकत्ता	5,000	6,000	7,000
बम्बई	99,500	1,07,000	1,41,500
दिल्ली	21,500	32,000	42,000
मद्रास	8,000	11,000	8,500

(ख) इण्डियन एयरलाइंस एवं एयर-इण्डिया द्वारा गत तीन वर्षों में कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली और मद्रास से परिचालित कुल विमान सेवाओं की संख्या :—

	कलकत्ता	बम्बई	दिल्ली	मद्रास
इण्डियन एयरलाइंस*	21,171	26,844	20,492	9,335
एयर इण्डिया	1,061	4,784	3,390	978

*कुछ महीनों के आंकड़े शामिल नहीं हैं क्योंकि ये आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई और मद्रास से लन्दन तक रियायती किराये

3320. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्री को दिल्ली, बम्बई अथवा मद्रास की अपेक्षा कलकत्ता से/तक की विमान यात्रा के लिए इकोनोमी क्लास में अधिक किराया देना पड़ता है और यदि हां, तो इस अन्तर के क्या कारण ह;

(ख) क्या सरकार का विचार भारत के सभी हवाई अड्डों से लन्दन की यात्रा के लिए किरायों को युक्तिसंगत तथा एक समान करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) से (ग) भारत के स्थानों से संसार के विभिन्न स्थानों तक के विमान किराये भिन्न-भिन्न हैं जो ऐसे तत्वों पर आधारित हैं, जैसे मार्ग का स्वरूप (पेटर्न), उद्गम स्थान तथा गंतव्य स्थानों के बीच की दूरी आदि। कलकत्ता से भारत के पश्चिम की ओर स्थित स्थानों तक के, जिनमें लन्दन भी सम्मिलित हैं, किराये बम्बई, दिल्ली अथवा मद्रास से उन स्थानों तक के तदनुरूपी किरायों से अधिक हैं क्योंकि उनके बीच की दूरी अधिक है।

कलकत्ता-कूच-बिहार के बीच इंडियन एयरलाइंस द्वारा सेवा पुनः चालू किया जाना

3321. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता-कूच-बिहार के बीच इण्डियन एयरलाइंस द्वारा उन सेवाओं को शीघ्र पुनः चालू करने के प्रश्न पर विचार कर लिया है जिन्हें इण्डियन एयर-लाइंस द्वारा तालाबंदी के समय से रद्द कर दिया गया था;

(ख) क्या सरकार ने कलकत्ता/रूपरानी/कूच-बिहार/हशामारा/कलकत्ता को जोड़ने वाली एक दैनिक सेवा चालू कर कलकत्ता-कूच-बिहार क्षेत्र में मितव्ययिता के सुझाव पर भी विचार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार का क्या निर्णय है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). विमानन ईंधन के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण इंडियन एयरलाइंस के लिए अपने विमान बेड़े में से डकोटा तथा वाइकाउंट विमानों को क्रमशः सेवा से हटाना आवश्यक हो गया है और इसीलिए कूच-बिहार के लिए सेवा पुनः चालू नहीं की जा रही है। इस स्टेशन पर जैसी परिचालन सुविधाएं उपलब्ध हैं उनमें इंडियन एयरलाइंस के विमान-बेड़े के किसी अन्य विमान द्वारा सेवाएं परिचालित नहीं की जा सकतीं।

मात्र विदेशी पर्यटकों के लिए विमान सेवायें चलाने का प्रस्ताव

3322. **श्री डी० पी० जदेजा**
श्री एस० ए० मुगनन्तम } : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मात्र विदेशी पर्यटकों के लिए विमान सेवायें चलाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का मुख्य ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख). ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि देशी एवं विदेशी दोनों प्रकार के पर्यटकों की सुविधा के लिए इंडियन एयरलाइंस से भिन्न परिचालकों द्वारा कुछ सेवाएं परिचालित करने की आवश्यकता हो सकती है।

कुवैत के साथ दीर्घकालीन व्यापार करार

3323. श्री डी० पी० जदेजा
श्री अरविन्द एम० पटेल } : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने कुवैत के साथ एक दीर्घकालीन व्यापार तथा आर्थिक करार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). 13 फरवरी, 1974 को कुवैत के साथ एक व्यापार तथा आर्थिक करार पर हस्ताक्षर किए गये। इसकी विस्तृत रूपरेखा इस प्रकार है:—

(1) दोनों देशों के बीच व्यापार सामान्य व्यापार माध्यमों से होगा और भुगतान किसी भी मुक्त परिवर्तनीय मुद्रा में तय किये जायेंगे।

(2) स्थानीय नियमों के अधीन दोनों देश के एक दूसरे को व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों का आयोजन करने की सुविधाएं प्रदान करेंगे।

(3) तकनीकी प्रशिक्षण और सहायता देकर वैज्ञानिक तथा तकनीकी ज्ञान के आदान-प्रदान और उपयोग को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में सहयोग।

(4) संयुक्त उद्यमों की संभाव्यताओं का पता लगाना।

(5) निर्धारित समय पर विशिष्ट व्यापार व्यवस्थाएं सम्पन्न करना।

(6) संयुक्त समिति की स्थापना जिससे कि अन्य बातों के साथ-साथ विशिष्ट व्यापार व्यवस्थाएं तैयार की जा सकें और दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग के विस्तार तथा व्यापारिक लेन-देन को बढ़ाने के लिए क्षेत्रों, परियोजनाओं, वस्तुओं आदि का पता लगाया जा सके।

फिल्म उद्योग में काला धन लगाया जाना

3324. श्री प्रियरंजन दास मुंशी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि फिल्म उद्योग में भारी मात्रा में काला-धन लगाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सम्पूर्ण फिल्म उद्योग में, विशेषकर, बम्बई में, गत तीन वर्षों में धनराशि लगाये जाने के समस्त साधनों, कलाकारों को भुगतान तथा प्रदर्शन करने वालों, वितरकों और फिल्म निर्माताओं की शुद्ध आय तथा पूंजी निवेश के बारे में जांच कराने का है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जब भी विशिष्ट सूचना मिलती है, तो व्यक्तिगत मामलों में सदैव ही जांच की जाती है और कानून में दिये अनुसार कार्यवाही की जाती है। काले धन की समस्या फिल्म उद्योग के लिए ही विशेष रूप से नहीं है। कर अपवंचन और इसके समाधान की पद्धतियों के संबंध में अन्तिम सामान्य जांच प्रत्यक्ष कर जांच समिति ने की थी, जिसने अपनी रिपोर्ट 1971 में दी थी। फिल्म उद्योग में कर अपवंचन के प्रश्न पर, उस समिति ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 2.214 से 2.218 में विचार किया था। मामले की लगातार समीक्षा की जाती है।

जीवन बीमा निगम करार पर हस्ताक्षर करने में विलम्ब

3325. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस से संबद्ध जीवन बीमा निगम यूनियन द्वारा पिछली तालाबंदी के दौरान जीवन बीमा निगम करार पर हस्ताक्षर करने में विलम्ब करने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : अखिल भारतीय राष्ट्रीय जीवन बीमा कर्मचारी संघ ने, जो 'इंटक' के साथ संबद्ध है, 24 जनवरी 1974 को समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी असमर्थता प्रकट की, क्योंकि जैसा कि उन्होंने बताया, वे अपनी कार्यकारी समिति के साथ परामर्श करना चाहते थे। संघ ने समझौते पर 6 फरवरी 1974 को हस्ताक्षर किये।

इण्डियन एयरलाइंस में तालाबन्दी के दौरान हुई हानि तथा रद्द की गई उड़ानें

3326. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर**
श्री रण बहादुर सिंह } : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन एयरलाइंस में तालाबंदी से कुल कितनी हानि हुई; और

(ख) तालाबंदी के दौरान कितनी उड़ानें रद्द की गई थीं?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) इंडियन एयरलाइंस को तालाबंदी की अवधि के दौरान विमानन तथा मोटर परिवहन ईंधन और कर्मचारियों को वेतन तथा भत्तों की अदायगी न करने आदि के कारण हुई 473 लाख रुपए की बचत की तुलना में, 24 नवम्बर, 1973 से 31 जनवरी 1974 तक तालाबंदी के कारण हुई हानि का अनमान 276 लाख रुपए लगाया गया है।

(ख) 24 नवम्बर 1973 से फरवरी 1974 के अंत तक तालाबंदी की अवधि के दौरान रद्द की गयी उड़ानों की संख्या 9229 थीं।

एकमात्र निर्यात निरीक्षण प्राधिकरण की स्थापना

3327. **श्री राम प्रकाश:**
श्री यमुना प्रसाद मंडल } : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में एकमात्र निर्माता निरीक्षण प्राधिकरण की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस का संभावित गठन किस प्रकार का होगा और इसके कृत्य क्या होंगे?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

विदेशी मुद्राओं की कीमतों में अस्थिरता का मुकाबला करने सम्बन्धी योजना

3323. **श्री राम प्रकाश :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पौण्ड स्टर्लिंग, अमरीकी डालर तथा जर्मन मार्क के दीर्घकालीन मुद्रा-उतार-चढ़ाव के खतरों से बचाव हेतु बीमा योजना चालू करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या लाभ होंगे ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) : भारतीय निर्यातकर्ताओं को दीघ-कालीन मुद्रा उतार-चढ़ाव के खतरों से बचाये जाने की योजना शुरू करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

आयकर की बकाया राशि को घटाने के लिए इनाम की योजना

3329. **श्री राम प्रकाश** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आयकर की बकाया राशि बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या बकाया राशि की वृद्धि को रोकने के लिये इनामों की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) 31 मार्च, 1972, 31 मार्च, 1973 और 31 दिसम्बर, 1973 को आयकर (निगम कर सहित) की सकल और शुद्ध बकाया निम्नानुसार है :—

(करोड़ रुपयों में)

निम्नलिखित तारीखों को आय-कर की बकाया	सकल बकाया	शुद्ध बकाया
31-3-72	805.37	438.60
31-3-73	790.02	483.10
31-12-73	714.10	527.43

उपर्युक्त आंकड़ों से पता चलेगा कि सकल बकाया में उत्तरोत्तर कमी की जा रही है । फिर भी इस तथ्य के बावजूद कि इस बकाया को वसूल करने के लिये संगठित प्रयास किये जा रहे हैं, कुछ मुख्य तत्व जो करों की बकाया की वसूली में बाधक बनते हैं, निम्नानुसार हैं :--

(i) दोहरे आयकर से राहत का फैसला होने तक के लिये रकमें अनिर्णीत पड़ी हैं।

(ii) ऐसी कम्पनियों की तरफ रकमे बकाया हैं जो परिसमापनाधीन हैं।

(iii) ऐसे व्यक्तियों की ओर रकमें बकाया हैं, जो भारत छोड़ गये हैं।

(iv) रकमें अपीलों में विवादग्रस्त हैं, हालांकि वे स्थगित नहीं हुई हैं और न ही किस्तें बंधी हैं ।

(v) परिसंपत्तियां अभिग्रहीत हैं, लेकिन उनके बेचने में कठिनाइयां हैं। उदाहरणार्थ :--

(क) अभिग्रहीत सम्पत्तियों का स्वामित्व विवादग्रस्त है, जिनमें लम्बे अरसे से मुकदमेबाजी हो रही है ।

(ख) जब अभिग्रहीत अचल संपत्तियों को नीलाम किया जाता है तो या तो उनका कोई खरीदार नहीं होता अथवा बोली बहुत कम लगती है ।

(ग) प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के शेयरों की बिक्री कठिन होती है, क्योंकि शेयर मुक्त रूप से हस्ताँतरणीय नहीं होते और उस दशा में कोई खरीदार नहीं होते जब शेयर खरीदने पर खरीदार को कम्पनी में बहुत कम हकदारी मिलती हो ।

(ख) और (ग) करों की वसूली में सर्वोत्तम कार्य के लिये अधिकारियों/कर्मचारियों को इनाम देने की एक योजना तैयार की गई है ताकि करों की बकाया की समस्या को, अतिरिक्त प्रेरणा की व्यवस्था करके, हल किया जा सके । इस संबंध में 68 प्रादेशिक इनाम और दो अखिल भारतीय इनाम रखने का प्रस्ताव है । ये इनाम, बकाया की वसूली और उसे कम करने के संबंध में प्रत्येक आयुक्त के कार्यक्षेत्र में ऐसे कर संग्रहण एकक [जिसमें आयकर अधिकारी (वसूली) और उसके अधीन कार्य करने वाले श्रेणी III और श्रेणी IV के कर्मचारी होते हैं] और कर-वसूली एकक (जिसमें कर वसूली अधिकारी और उसके अधीन कार्य करने वाले श्रेणी III और श्रेणी IV के कर्मचारी होते हैं) को दिये जायेंगे जो सर्वोत्तम परिणाम दिखायेंगे। देश में सर्वोत्तम कार्य के लिये भी एक कर-संग्रहण एकक और एक कर-वसूली एकक को इनाम दिया जायेगा । इनाम की रकम की संगणना, निर्धारित सीमाओं के अधीन रहते हुए एकक में कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन के आधार पर की जायगी।

ये इनाम, इस प्रयोजन के लिए गठित समितियों की सिफारिशों के आधार पर मंजूर किये जायेंगे ।

देश में विमान सेवायें बढ़ाने का प्रस्ताव

3330. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में और विमान सेवायें प्रारम्भ करने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे स्थान कौन-कौन से हैं जो आगामी तीन वर्षों में देश के विमान-सेवा नक्शे में शामिल किये जायेंगे; और

(ग) इस प्रयोजन के लिये सरकार द्वारा कितनी राशि आवंटित की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) से (ग). इण्डियन एयरलाइंस का प्रारम्भ में अपने मार्ग-तंत्र का विस्तार करने का विचार था । किन्तु अब वर्तमान ईंधन संकट को दृष्टि में रखते हुए स्थिति पर पुनर्विचार किया जा रहा है।

पेंशन नियमों में पुनरीक्षण के बारे में पेंशनभोगी संगठनों द्वारा की गई मांग

3331. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में हुई भारी वृद्धि के फलस्वरूप पेंशन नियमों के पुनरीक्षण के लिए देश के विभिन्न पेंशनभोगी संगठनों ने सरकार को अध्यावेदन दिये हैं; और

(ख) क्या सरकार ने इस मामले पर विचार किया है और यदि हां, तो इस बारे में किस प्रकार का निर्णय किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण पत्र सदन-पटल पर रखा गया है।

विवरण

तृतीय वेतन आयोग द्वारा सिफारिश की गयी महंगाई भत्ते की योजना केन्द्रीय सरकार के सेवारत कर्मचारियों को लागू होती है । परन्तु तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की तारीख अर्थात् 1 जनवरी 1973 को अथवा उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के मामले में आयोग ने जीवन निर्वाह सूचकांक में वृद्धि होने के कारण राहत की मंजूरी के लिये एक अलग योजना की सिफारिश की है। आयोग की सिफारिशों के अनुसार यह राहत सभी भावी पेंशनरों को मंजूर की जाती है, चाहे उनकी पेंशन की रकम कुछ भी हो। यह राहत उनकी पेंशन के 5 प्रतिशत की दर से दी जायगी जिसकी न्यूनतम रकम 5 रु० प्रति मास और अधिकतम रकम 25 रु० प्रति मास होगी । अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960=100) के 12 महीनों के औसत में जब-जब 16 अंकों की वृद्धि होती है तब तब इन दरों पर राहत दी जानी है । 216 अंकों पर राहत पहले ही 1 अगस्त, 1973 से और 232 अंकों पर 1 जनवरी, 1974 से देय हो चुकी है। आयोग ने सिफारिश की थी कि इस योजना को 1 मार्च, 1973 से लागू किया जाय परन्तु उदारता के रूप में सरकार ने श्रेणी II, III और IV के कर्मचारियों के संबंध में इस योजना को लागू करने की तारीख 1 जनवरी, 1973 नियत की है ।

2. यद्यपि आयोग की सिफारिशें केवल भावी पेंशनरों पर लागू होती हैं, तथापि आयोग की इस सिफारिश से संबंधित लाभ को उन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को भी देने का निर्णय किया गया है जो 1-1-1973 से पूर्व सेवा-निवृत्त हुए थे ।

3. वर्तमान केन्द्रीय सरकारी पेंशनरों को, अर्थात् जो 1 जनवरी, 1973 से पूर्व सेवा-निवृत्त हुए थे, अतिरिक्त राहत देने के उपाय के रूप में और सेवारत केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के

के लिए पेंशन संबंधी लाभ देने के मामले में तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने इस प्रकार के पेंशनरों को 1 जनवरी, 1973 से निम्नलिखित तदर्थ राहत प्रदान करने का निर्णय भी किया है :—

पेंशन रेंज	पेंशन में तदर्थ वृद्धि
85 रु० से नीचे	15 रु०
85 रु० से 209 रु० तक	21 रु०
210 रु० से 499 रु० तक . . .	25 रु०
500 रु० तथा उससे ऊपर . . .	35 रु०

इस मामले में आवश्यक आदेश जारी किये जा रहे हैं।

कम्पनियों को पूंजी लेने की अनुमति

3332. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने कितनी और किन-किन कम्पनियों को गत तीन वर्ष के दौरान सार्वजनिक अंशदान के माध्यम से धनराशि लेने की अनुमति दी;

(ख) क्या सरकार को इस बात का पता है कि ये कम्पनियां सार्वजनिक अंशदान की राशि का एक विशेष अवधि तक उपयोग करती हैं, मुनाफा कमाती हैं, और फिर तकनीकी तर्क के आधार पर बहुत बड़ी संख्या में शेयरों के आवेदन-पत्र रद्द कर देती हैं और बिना किसी ब्याज के, लम्बे अरसे के बाद धन लौटा देती हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस कदाचार को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) भारत सरकार ने गत तीन वर्षों में जिन कम्पनियों को जनता में शेयर बेचकर धन जुटाने की अनुमति प्रदान की है, उनकी संख्या इस प्रकार है :—

1971 (जन०—दिस०)	35
1972 (जन०—दिस०)	55
1973 (जन०—दिस०)	97

इन कम्पनियों के नाम सभा पटल पर रखे गए विवरण में दिये गये हैं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये सख्या एल० टी० 6444/74]

(ख) और (ग). कम्पनी अधिनियम, 1956 में यह विधान है कि सरकारी कम्पनियां जो विवरण-पत्रिका द्वारा जनता द्वारा खरीदी जाने के लिये हिस्सा पूंजी जारी करती है, उनके लिये यह जरूरी है कि वे आवेदन-पत्र के साथ भेजी जाने वाली रकम किसी अनुसूचित बैंक के अलग खाते में रखें, जिस पर ब्याज मिलता हो। आवंटन पत्रों/शेयर प्रमाण-पत्रों के प्रेषण की अवधि और जहां पर आवंटन नहीं किया जाता है अथवा जहां आंशिक आवंटन किया जाता है आवेदन पत्र सम्बन्धी

रकम की वापसी को भी हर हालत में विवरण पत्रिका में दिखाया जाता है। जहां निर्गम से अधिक रकम प्राप्त हो जाती है, जहां सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मार्ग दर्शक सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए सम्बद्ध शेयर बाजारों से परामर्श करके शेयरों के आवंटन के आधार का निर्णय किया जाता है। फिर भी, कुछ मामलों में शेयरों का आवंटन और आवेदन पत्र सम्बन्धी रकम की वापसी में देरी की सूचना मिली थी और जांच पड़ताल से पता चला है कि बहुत से मामलों में ऐसी देरी विभिन्न कारणों से हुई थी जिन पर कम्पनियों का पूर्ण नियन्त्रण नहीं था।

भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त व्यापार आयोग का गठित किया जाना

3333. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापार और आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहन देने के लिये हाल ही में संयुक्त आयोग गठित किया गया है जिसमें फ्रांस और भारत के प्रतिनिधि शामिल हैं, और

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जी नहीं । जहां तक भारत तथा फ्रांस के बीच व्यापार सम्बन्ध/सहयोग बढ़ाने का सम्बन्ध है, इस विषय में, अक्तूबर, 1959 में फ्रांस के साथ हुए व्यापार करार के अन्तर्गत एक आयोग पहले से ही मौजूद है।

स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा आयातित कारों की खरीद

3334. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **वित** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि स्टेट बैंक आफ इण्डिया ने हाल ही में छः आयातित कारें खरीदी हैं और यदि हां, तो उनकी लागत क्या है;

(ख) उन अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जो इनका उपयोग करते हैं; और

(ग) क्या इन कारों की खरीद के लिये स्टेट बैंक आफ इण्डिया ने सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त की थी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचना दी है कि इस समय उसके पास विदेशों से मंगाई गई जो 12 मोटर गाड़ियां हैं, उनमें से पहली गाड़ी, जो इस्तेमाल शुदा थी, 1953 में तथा आखरी जो वह भी इस्तेमाल शुदा थी 1969 में खरीदी गयी थी और अभी हाल में उसने कोई ऐसी गाड़ी नहीं खरीदी है जो विदेश से मंगाई गई हो।

बैंक ने विदेशों से मंगाई गई इन मोटर गाड़ियों में से एक-एक गाड़ी चेयरमैन, प्रबन्ध निदेशक तथा दो उप-प्रबन्ध निदेशकों को दी है तथा बाकी मोटर गाड़ियां बैंक के केन्द्रीय कार्यालय तथा स्थानीय मुख कार्यालय में स्टाफ कारों के रूप में उपयोग की जा रही हैं । चेयरमैन, प्रबन्ध निदेशक तथा उप प्रबन्ध निदेशक अपनी-अपनी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार, सरकारी कामों के लिए बैंक की मोटर गाड़ियों का निशुल्क उपयोग करने के हकदार हैं । यदि ये अधिकारी ऐसी मोटरगाड़ियों का उपयोग निजी कामों के लिए करते हैं, जो 16 या उससे अधिक अश्व शक्ति वाली हों, तो उन्हें बैंक को 125 रुपये प्रतिमाह देने पड़ते हैं और यदि 16 अश्व शक्ति से कम वाली मोटर गाड़ियां हों तो उन्हें 75 रुपये प्रतिमाह देने होते हैं।

भारतीय स्टेट बैंक ने यह और सूचना दी है कि विदेशों से मंगाई गई उन गाड़ियों के बदले, जो पुरानी हो गयी हैं, भारत में बनी छोटी गाड़ियां खरीदने की कार्रवाई की गयी है। चूंकि स्टेट बैंक एक निगम के रूप में काम करता है इसलिए उसके लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह भारतीय अथवा विदेशी मोटर गाड़ियों की खरीद के लिये सरकार से पहले अनुमति प्राप्त करे।

उत्तर बंगाल में चाय बागानों का सरकारीकरण

3335. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर बंगाल के कुछ चाय बागानों का सरकारीकरण करेगी; और

(ख) यदि हां, तो उन चाय बागानों के नाम क्या हैं और उनका सरकारीकरण कब किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) तथा (ख). चाय उद्योग के विकास तथा निर्यात संवर्धन हेतु आर्थिक रूप से कार्यक्रम तथा दीर्घावधि नीति तैयार करने के लिये चाय सम्बन्धी जिस टास्क फोर्स की स्थापना की गई थी उसने समस्त देश में बन्द तथा संकटग्रस्त चाय बागानों के पुनः-स्थापन के लिये सिफारिशें की हैं जिन पर सरकार अभी विचार कर रही है।

बंगला देश के साथ व्यापार समझौता

3336. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश के साथ जनवरी 1974 में एक और व्यापार समझौता किया गया है; और

(ख) यदि हाँ तो क्या उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के बीच विषमता

3337. **श्री एस० एम० बनर्जी**
श्री ए० के० एम० इसहाक } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के संबंध में तृतीय वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किये गये वेतनमानों के बारे में कोई अंतिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा अन्य प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के बीच व्याप्त विषमताओं को दूर करने के लिए भी कोई निर्णय लिया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) इन मामलों पर अभी तक कोई निर्णय नहीं किये गये हैं।

कानपुर में हवाई अड्डे के निर्माण का निर्णय

3338. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर में हवाई अड्डा बनाने का अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो कार्य आरम्भ न करने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) कानपुर में किसी नये विमान क्षेत्र के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि नगर विमानन महानिदेशालय द्वारा पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान भारतीय वायु सेना के वर्तमान विमान क्षेत्र में एक सिविल एन्क्लेव का निर्माण करने की संभावना है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में पर्यटन केन्द्र विकसित करने की योजना

3339. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में पर्यटन केन्द्र विकसित करने की सरकार की कोई योजना नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री [डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषी] : (क) और (ख) केन्द्रीय क्षेत्र में दार्जिलिंग में वर्तमान पर्यटक बंगले के विस्तार एवं एक युवा होस्टल के निर्माण का काम हाथ में लिया गया है। इसके अतिरिक्त, जलदापाड़ा में एक फोरेस्ट लाज निर्माणाधीन है। पांचवीं योजनावधि के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा सिलीगुड़ी में एक मोटल के निर्माण का, कलकत्ता विमानक्षेत्र पर अपनी शुल्क-मुक्त दुकान तथा कलकत्ता में अपने परिवहन बेड़े के विस्तार का, तथा दमदम में अपने होटल के निर्माण-कार्य को पूरा करने का प्रस्ताव है।

Compensation for Burnt Currency Notes

3340. **Shri Panna Lal Barupal** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(*a*) the procedure followed in regard to compensation for the currency notes burnt partly or wholly, some of them half-burnt but retaining their number on one side, as a result of major fires breaking out in villages, towns and cities ;

(*b*) the procedure followed for exchange of currency notes eaten by white ants, with their numbers also eaten up on one or both the sides ; and

(*c*) the amount paid in respect of such currency notes by the different branches of Reserve Bank of India during 1973-74.

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) (*a*) & (*b*) Payment of value in respect of fully burnt or partially burnt or badly damaged notes, inclusive of notes affected by white ants are made strictly according as the notes fall under the category of mutilated, half, mis-matched, obliterated or altered notes as defined in the Reserve Bank of India (Note Refund) Rules, 1935. Ordinarily, the tenderor is required to lodge the notes over the Bank's counter and in the Claims Section where, after being counted, examined and affixed with appropriate stamp, they are put up for

adjudication by prescribed officers. In the case of large tenders consisting of burnt notes and notes affected by white ants enquries as regards the genuineness of the claim are made and production of certificates from the Fire Brigade/Police/Surpanch etc. is insisted upon before taking of adjudication of notes. Claims in respect of Rs. 1000/- denomination note and above are not considered if their serial and general numbers are not identifiable or if the claiments are not able to declare and prove the numbers. In respect of notes upto and inclusive Rs. 100 denominations, the value is paid depending on the genuineness of the claim and the condition of the notes with reference to their identifying features.

(*c*) The total value paid in regard to such currency notes by the different branches of the Reserve Bank of India during 1973-74 is indicated below :—

R.B.I. Office	Total value paid (Rs.)
Nagpur	36,689
New Delhi	14,81,394
Calcutta	16,565
Bangalore	50,305
Hyderabad	1,17,517
Bombay	1,26,301
Byculla	6,65,564
Madras	33,956

Figures in respect of Kanpur and Patna offices are being collected and will be Laid on the Table of the House shortly.

Financial Assistance to Rajasthan

3341. **Shri Panna Lal Barupal :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(*a*) the amount of grant and loan to the Rajasthan Government by the Central Government during 1971-72 and 1972-73 , separately; and

(*b*) whether the Rajasthan Government are not in a position to repay these loans and if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) :

(*a*)	Amount of grant and loan to the Rajasthan Government by the Central Government	
(*i*) Loan	140·91	186·03
(*ii*) Grants	41·98	54·12

(*b*) No, Sir. Rajasthan Government will be in a position to repay these loans.

चालू फसल के दौरान भारतीय पटसन निगम द्वारा खरीदा गया पटसन

3342. **श्री एस० एन० सिंह देव :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय पटसन निगम ने चालू फसल के दौरान वास्तव में कितना पटसन खरीदा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : चालू मौसम के दौरान भारतीय पटसन निगम ने 16-2-1974 तक 11.32 लाख क्विंटल कच्चे पटसन की खरीद की है ।

पश्चिम बंगाल में हथकरघा उद्योग में संकट

3343. **श्री एस० एन० सिंह देव** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धागा न मिलने और धागे तथा 'प्रासेसिंग' रसायनों के मूल्य अधिक होने के कारण पश्चिम बंगाल में हथकरघा उद्योग को संकट का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति के समाधान के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सरकार के पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बाढ़ राहत कार्यों के लिये पश्चिम बंगाल को वित्तीय सहायता

3344. **श्री एस० एन० सिंह देव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में बाढ़ राहत कार्यों के लिये पश्चिम बंगाल को कोई राशि मंजूर की है;

(ख) यदि हां, तो यह राशि कितनी है;

(ग) इस बारे में पश्चिम बंगाल सरकार की मांग क्या थी;

(घ) क्या बाढ़ों से हुई हानि के बारे में योजना आयोग द्वारा कोई जांच इस बीच की गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष रहे?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ङ). पश्चिम बंगाल की सरकार के अनुरोध पर, योजना आयोग के कार्यक्रम परामर्शदाता की अध्यक्षता में केन्द्र के अधिकारियों के एक दल ने सितम्बर, 1973 में राज्य का दौरा किया था ताकि पश्चिम बंगाल में बाढ़ की स्थिति का मूल्यांकन किया जा सके और केन्द्रीय सहायता के प्रयोजनों के लिये राहत और मरम्मत सम्बन्धी विभिन्न कार्यों पर व्यय की अधिकतम सीमा के बारे में सिफारिश की जा सके। राज्य सरकार के 26.36 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय के मुकाबले केन्द्रीय दल ने, केन्द्रीय सहायता के प्रयोजनों के लिये, निम्नलिखित शीर्षों के अधीन 10.03 करोड़ रुपये के अधिकतम व्यय की सिफारिश की थी :

राहत कार्य	2.72	करोड़ रुपये
मरम्मत कार्य	7.31	करोड़ रुपये
जोड़	10.03	करोड़ रुपये

दो करोड़ रुपये की रकम राज्य सरकार को जारी कर दी गयी है। अतिरिक्त सहायता की रकम, स्वीकृत अधिकतम सीमा के अनुसार किये जा रहे व्यय के आधार पर जारी की जायेगी।

कलकत्ता हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाये रखने के लिये कार्यवाही

3345. **श्री एस० एन० सिंह देव :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विमान ईंधन उदग्रहण (अपटेक) में कटौती करने के सरकार के निर्णय के कारण कुछ ऐसी अंतर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों ने अपनी उड़ान-सेवा बन्द करना आरम्भ कर दिया है जो कलकत्ता होकर बहुत सी गैर-अनुसूचित उड़ानों का, अधिकांशत: माल वहन सेवाओं का संचालन कर रही थीं।

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप कलकत्ता अंतर्राष्ट्रीय हवाई-अड्डा नहीं रहेगा; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार कलकत्ता हवाई-अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाये रखने हेतु कोई कदम उठा रही है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) संसार भर में अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं को प्रभावित करने वाले ईंधन संकट का हमारे विमान क्षेत्रों के लिए अथवा ये परिचालित होने वाली सेवाओं पर भी प्रभाव पड़ा है। एयरलाइनों ने ईंधन की खपत में अधिकत किफायत बरतने की आवश्यकता को स्वीकार किया है तथा वे इस दशा में अपना सहयोग दे रही है।

(ख) और (ग) . जी, नहीं। कलकत्ता का महत्व केवल अनुसूचित उड़ानों के परिचालन पर ही आधारित नहीं है। इस समय, हमारे राष्ट्रीय वाहकों के अतिरिक्त, सात विदेशी एयरलाइनें अर्थात एयरोफ्लोट, बंगलादेश विमान, ब्रिटिश एयरवेज़, बर्मा एयरवेज़, रायल नेपाल एयरलाइंस कार्पोरेशन, स्केंडिनेवियन एयरलाइंस सिस्टम तथा थाई एयरवेज़ कलकत्ता के लिए/से होते हुए अनुसूचित सेवाएं परिचालित कर रही हैं।

सरकार कलकत्ता के लिए/से होते हुए विदेशी परिचालकों द्वारा अपने अपने अधिकारों के अनुरूप अनुसूचित सेवाएं परिचालित करने का स्वागत करती है तथा उसे आशा है कि संबंधित एयरलाइनें इस संबंध में आवश्यक उद्यम करेंगी।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता

3346. **श्री एम० एस० पुरती**
श्री सी० के० जाफर शरीफ } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल्य सूचकांक में वृद्धि को देखते हुए महंगाई भत्ते की एक और किश्त केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को देय हो गई है; और

(ख) उस पर कितनी धनराशि व्यय होगी और सरकार ने 1972-73 में महंगाई भत्ते की अदायगी पर कितना धन व्यय किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का 12 महीने का औसत दिसम्बर 1973 में 232 अंकों को पार कर गया था, इसलिए केंद्रीय सरकार के श्रेणी II, III और IV के उन कर्मचारियों को जिनका संशोधित वेतनमानों में वेतन 900 रुपये तक है, 1 जनवरी 1974 से महंगाई

भत्ते की एक अतिरिक्त किस्त मंजूर करने के आदेश जारी किये जा चुके हैं । मूल्य सूचकांक में और अधिक वृद्धि होने के कारण महंगाई भत्ते की एक और किस्त मंजूर करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को 1 जनवरी 1974 से मंजूर किये गये अतिरिक्त महंगाई भत्ते से वर्ष 1973-74 में राजकोष पर 8.09 करोड़ रुपये का खर्च पड़ने का अनुमान है । वर्ष 1972-73 में कर्मचारी अधिकांशतः उन वेतनमानों में वेतन पा रहे थे जो तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित होने से पहले विद्यमान थे । संशोधित वेतनमान 1 जनवरी 1973 से लागू हुए हैं । तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने के फलस्वरूप महंगाई भत्ते का ढांचा भी बदल गया है । एतदनुसार, वर्ष 1972-73 में दिये गये महंगाई भत्ते की रकम से कोई अर्थपूर्ण तुलना नहीं की जा सकती । तथापि, विभिन्न मंत्रालयों द्वारा अब तक प्रस्तुत की गयी विवरणियों के आधार पर उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1972-73 में, महंगाई वेतन सहित महंगाई भत्ते पर किया गया खर्च कोई 302 करोड़ रुपये का था । इसमें सशस्त्र सैनिक कर्मचारियों के संबंध में किया गया महंगाई वेतन तथा महंगाई भत्ते का खर्च शामिल नहीं है ।

पोलैंड से यूरिया तथा अमोनियम फास्फेट का आयात

3347. **श्री राम कंवर**
श्री एम० एस० संजीवी राय } : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दोनों देशों के बीच हुए एक व्यापारिक समझौते के अन्तर्गत पौलैंड की सरकार भारत को काफी अधिक मात्रा में यूरिया और अमोनियम फास्फेट देने के लिये मान गयी है; और

(ख) इस समझौते के अन्तर्गत कुल कितने यूरिया तथा अमोनियम फास्फेट का आयात किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) व्यापार संकल्प 1974 के अधीन उर्वरक प्राप्त करने के लिए भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम लि० तथा पौलिश विदेश व्यापार उद्यमियों के बीच बातचीत चल रही है और अभी तक संविदा सम्पन्न नहीं हुई है ।

चाय व्यापारियों पर आर्थिक भार

3348. **श्री राम कंवर :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय व्यापारी प्रायः भारी करों की शिकायत करते रहते हैं ;

(ख) क्या भारी करों के परिणामस्वरूप चाय का निर्यात करने के लिए अधिक प्रोत्साहन नहीं मिलता है;

(ग) विश्व बाजार की तुलना में भारतीय चाय के मूल्य क्या हैं; और

(घ) क्या चाय उद्योग पर आर्थिक भार को कम करने के लिये कोई प्रस्ताव है ताकि चाय निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) चाय पर लगाये गये कराधान के सम्बन्ध में चाय उद्योग और व्यापार द्वारा समय-समय पर अभ्यावेदन दिये गये हैं।

(ख) जी नहीं। चाय पर निर्यात शुल्क निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से 1 मार्च 1970 से समाप्त कर दिया गया था। साथ ही चाय के सम्बन्ध में क्षेत्रीय उत्पादनशुल्क की दरें बढ़ा दी गईं और निर्यात करने पर उत्पादन शुल्क में कीमतों के अनुरूप अलग अलग दरों पर रिबेट देना आरंभ कर दिया गया।

(ग) वर्ष 1972 तथा 1973 के दौरान लन्दन के नीलामों में भारतीय चाय, कीनिया और श्रीलंका की चायों तथा समस्त चायों की औसत कीमतें निम्नलिखित हैं :—

	ये आंकड़े नई पैन्सों में प्रति कि० ग्रा० के लिए हैं	
	1972	1973
भारत .	42.70	45.42
श्रीलंका	45.47	45.42
कीनिया	43.56	44.32
समस्त चायें	42.24	43.29

(घ) सरकार चाय के निर्यात बढ़ाने के सन्दर्भ में चाय पर लगाये जा रहे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में संशोधन करने के प्रश्न की निरंन्तर समीक्षा करती रहती है।

अखबारी कागज का आयात

3349. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अखबारी कागज के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नारियल जटा तथा नारियल जटा उत्पादनों के निर्यात में कमी

3350. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के प्रथम छः मास के दौरान गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में नारियल जटा तथा नारियल जटा के उत्पादों के निर्यात में कमी हो गयी; और

(ख) यदि हां, तो कितनी कमी हुई है तथा उसके कारण क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख): अप्रैल-सितम्बर, 1973 तथा 1972 की इसी अवधि में कयर उत्पादों के निर्यात का ब्यौरा नीचे दिया जाता है;

अप्रैल-सितम्बर, 1972 21,196 मै० टन जिनका मूल्य, 6.28 करोड़ रु० था

अप्रैल-सितम्बर, 1973 19,151 मै० टन जिनका मूल्य 6.25 करोड़ रु० था

कयर उत्पादों के निर्यात में कमी का मुख्य कारण श्रमिक हड़ताल था जिससे जून के महीने में कोचीन पत्तन का कार्य ठप हो गया था। ब्रिटेन को कयर धागा के निर्यात में भी गिरावट आई है जिसका मुख्य कारण है श्री लंका में हाल में स्थापित किये गए यंत्रीकृत कयर उद्योग से कड़ी प्रतिस्पर्धा है।

किसानों को आर्थिक सहायता देने के सम्बन्ध में स्टेट बैंक आफ इण्डिया, कुट्टानाड की विशेष योजना

3351. **श्री सी० जानार्दनन** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इण्डिया ने केरल राज्य में कुट्टानाड में किसानों की सहायता देने हेतु कोई विशेष योजना शुरू की है; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य बातें तथा उद्देश्य क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमति सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय स्टेट बैंक ने मानसून में अधिक बाढ़ तथा गर्मी के मौसम में पानी के खारेपन की समस्या को दूर करने के लिए, जो इस क्षेत्र में धान की खेती के लिए हानिकारक है, केरल राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी तथा केरल भूमि विकास निगम द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली, कुट्टानाड परियोजना का वित्त-प्रबन्धन करना स्वीकार कर लिया है। परियोजना में लगभग 2000 किलोमीटर लम्बे स्थायी जल में मग्न हो सकने वाले बांध के निर्माण की परिकल्पना की गयी है जिसमें से लगभग 370 किलोमीटर बांध के निर्माण का काम 1973-74 तथा 1974-75 के प्रथम चरण में पूरा किये जाने का प्रस्ताव है। इस पर 375 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। बैंक द्वारा केरल भूमि विकास निगम को सावधिक शर्तों पर ऋण दिये जाने के अलावा परियोजना के अन्तर्गत सामान्य शर्तों पर किसानों को उनकी फसल सम्बन्धी ऋण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहायता भी दी जाएगी। बैंक का विचार कुट्टानाड़ क्षेत्र में 6 कृषि विकास शाखाएं खोलने का है जिसमें से इदथुआ तथा छंगनचेरी में दो-दो शाखाएं पहले ही खोली जा चुकी हैं। परियोजना के शुरू हो जाने के बाद प्रतिवर्ष 10 करोड़ रुपये के मूल्य की 1.49 लाख मैट्रिक टन धान्न की उपज तथा लगभग 60 लाख रुपये के मूल्य के नारियल के उत्पादन के बड़ जाने की सम्भावना है। इस परियोजना से लगभग 5000 राज मिस्त्रियों तथा 10,000 मजदूरों को रोजगार दिये जाने की सम्भावना है।

इंजीनियरों एवं डाक्टरों को सवारी-भत्ता

3352. **श्री शंकर देव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोल कारों तथा अतिरिक्त पुर्जों के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि हो जाने के बावजूद इंजीनियरों एवं डाक्टरों के मोटरकार सवारी भत्ते में 1965 से कोई संशोधन नहीं किया गया है ; और

(ख) फील्ड ड्यूटी पर लगे डाक्टरों एवं इंजीनियरों की कठिनाई को कम करने के विचार से सरकार का इन दरों का कब संशोधन करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) जी, हां।

(ख) दरों में संशोधन करने के प्रश्न की जांच की जा रही है।

मोटरकार सवारी भत्ता

3353. **श्री शंकर देव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय वेतन आयोग ने अपने प्रतिवेदन में जिन मोटरकार सवारी भत्तों की सिफारिश की है, वे पूर्णतः तदर्थ है और बिना किसी तर्कसंगत आधार के हैं ; और

(ख) क्या पेट्रोल के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि को देखते हुए इस बारे में सरकार तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों में परिवर्तन करना चाहती है :

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तृतीय वेतन आयोग ने सवारी भत्ते की संशोधित दरों की सिफारिश करने में इस तथ्य को ध्यान में रखा था कि 'प्रवर्तमान' दरें 1961 में नियत की गई थीं और उनको 'वर्तमान समय' के परिवहन खर्च के अनकल बनाने के लिये संशोधित करने की आवश्यकता थी।

(ख) दरों में संशोधन करने के प्रश्न की जांच की जा रही है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा सम्बन्धी सुधार

3354. **श्री मधु दण्डवते** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा की पांच बड़ी शक्तियां अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा सम्बन्धी सुधार के प्रश्न पर विकासशील देशों के हितों की अवहेलना करने का प्रयास कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो विकासशील देशों के हितों को नुकसान पहुंचाने वाली उनकी नीतियों की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख) बीस सदस्यों की समिति, जिसका सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा सुधारों से है, विनियम दर, समयोजन प्रक्रिया, विशेष निकासी अधिकार की भूमिका जैसे कुछ बुनियादी मामलों पर सहमत हो गयी है। लेकिन फिर भी, अनेक मामलों में विकसित देशों में आपस में तथा विकासशील देशों और एक-या दूसरे विकसित देशों में मतभेद हैं। रोम में जनवरी, 1974 में हुई बैठक में समिति ने, आने वाले महीनों में, परिष्कृत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली की मुख्य बातों के सम्बन्ध में अपने काम को पूरा करने का अपना निश्चय व्यक्त किया। समिति इस बात से भी सहमत हुई कि विश्व की अर्थ-व्यवस्था में हाल में हुए विकासों की दृष्टि से, विकसित तथा विकासशील दोनों वर्ग के देशों के हितों पर प्रभाव डालने वाले सुधारों के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि उन्हें शीघ्र क्रियान्वित किया जा सके। सुधारों के अन्य पहलुओं के सम्बन्ध में इस बात पर सहमति हुई कि उनकी कार्यान्विक व्यवस्था का विकास किया जाना चाहिए तथा बाद में उन्हें क्रियान्वित किया जाना चाहिए। भारत तथा 20 सदस्यों की समिति में शामिल अन्य विकासशील देशों की कोशिश होगी कि व्यवस्थाओं के सुधार के उन प्रस्तावों को शामिल कर लिया जाय, जो विकासशील देशों की विशेष आवश्यकताओं, जिनमें वास्तविक साधनों को विकासशील देशों में अन्तरित करने के उपाय, निधि में 'कोटे' का संशोधन और निर्णय प्रक्रिया में सुधार शामिल हैं, से सम्बन्धित होंगे।

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के मजदूर संघों के साथ हुई बातचीत

3355. **श्री मधु दण्डवते** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी 1974 में जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के पांच मजदूर संघों के साथ द्विपक्षी बातचीत हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उस बातचीत से जो प्रस्ताव बने उनकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इन प्रस्तावों पर पांच मजदूर संघों की क्या प्रतिक्रिया थी ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग): जीवन बीमा निगम के तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की मांगों में वर्तमान वेतनमानों, भत्तों के उर्ध्वमुखी संशोधन तथा सेवा की शर्तों में सुधार की मांग भी शामिल हैं। एक समझोते पर 24 जनवरी 1974 को हस्ताक्षर किये गये थे जिसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

श्रेणी IV के पदों जैसे झाड़ूकश, क्लीनरों, सिपाहियों तथा ड्राइवरों के पदों के वेतनमान तथा श्रेणी III में रिकार्ड लिपिकों, सहायकों, आशुलिपिकों, अनुभागाध्यक्षों उच्चतर ग्रेड के सहायकों तथा अधीक्षकों के वेतनमानों को संशोधित कर दिया गया है।

मकान किराया भत्ता : मकान किराया भत्ता मूल वेतन का 10 प्रतिशत होगा जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के मामलों में कम से कम 22 रुपये प्रतिमास तथा तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के मामलों में 28 रुपये प्रतिमास होगा और सभी मामलों में अधिक से अधिक 40 रुपये प्रतिमास होगा।

नगर निवास प्रतिपूर्ति भत्ता : तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को निगम के जिन केंद्रों पर फिलहाल नगर निवास प्रतिपूर्ति भत्ता मंजूर किया जा रहा है, उनमें 20 रु० प्रतिमास की दर से यह भत्ता मंजूर किया जायेगा।

भविष्य निधि अंशदान : विशेष वेतन सहित मूल वेतन के 10 प्रतिशत की दर से अंशदान किया जायगा।

उपदान : उपदान भुगतान अधिनियम 1972 का लाभ तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के सभी कर्मचारियों को दिया जायेगा चाहे वे कितना ही वेतन लेते हों। अदा किये जाने वाले उपदान की रकम 20,000/- रुपये से अधिक नहीं होगी।

बोनस : लाभ में हिस्सेदारी का कोई वोनस देय नहीं है।

तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के सभी कर्मचारियों को (विशेष वेतन तथा महंगाई भत्ता सहित) उनके वार्षिक वेतन के 15 प्रतिशत की दर से वार्षिक नकदी बोनस दिया जायगा।

चिकित्सा संबंधी लाभों में सुधार, छुट्टी के दौरान यात्रा रियायत तथा भविष्य निधि अंशदानों में अतिरिक्त सुधार की मांगों पर सहमति नहीं हुई है परन्तु निगम की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने पर निगम के अध्यक्ष इन मांगों पर, समझौता चालू होने के बाद, तीसरे और चौथे वर्ष में विचार करेंगे, बशर्ते तीसरे वर्ष में इस पर अतिरिक्त खर्च एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं हो और चौथे वर्ष में तीसरे वर्ष के खर्च के अतिरिक्त एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं हो ;

यह समझौता एक अप्रैल 1973 से 31 मार्च 1977 तक चार वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा (इस समझौते से प्रति वर्ष 6 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय होगा)।

काले धन को रोकने के लिए कार्यवाही

3356. श्री समर गुहा
श्री चन्द्रभालमनी तिवारी } :क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काले धन का पता लगाने अथवा उसे विनियमित करने सम्बन्धी वांचू समिति के प्रतिवेदन को लागू कर दिया है ;

(ख) देश में काले धन के वर्तमान चलन के बारे में सरकार का अनुमान क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सौ रुपये वाले नोटों के विमुद्रीकरण के मामले पर पुनर्विचार किया है ; और

(घ) देश में काले धन का पता लगाने, उस पर नियंत्रण करने, उसे विनियमित करने अथवा उसमें वृद्धि न होने देने के लिये सरकार द्वारा क्या अन्य कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) काले धन का पता लगाने के लिए वांचू समिति ने तीन सिफारिशें की :—

(i) तलाशी और माल पकड़ने का अधिकाधिक उपयोग और उसके लिए अधिकाधिक शक्तियां;

(ii) समझौता-तंत्र तैयार करना; और

(iii) मुद्रा का विमुद्रीकरण कराधान कानून (संशोधन) विधेयक 1973 में तलाशी और माल पकड़ने की बढ़ी हुई शक्तियों तथा समझौता तंत्र के बारे में व्यवस्था है। तलाशी की बढ़ी हुई शक्ति का भी उपयोग किया जा रहा है। मुद्रा के विमुद्रीकरण का जहां तक संबंध है सरकार विमुद्रीकरण को काले धन की समस्या का समाधान नहीं समझती। समिति ने स्वेच्छा से धन की घोषणा-योजनाओं के माध्यम से काले धन को नियमित करने अथवा उसे कतिपय विशिष्ट क्षेत्रों में लगाने के विरुद्ध मत व्यक्त किया।

(ख) देश में जो काला धन परिचालन में है, सरकार ने उसका कोई अनुमान नहीं लगाया है। विद्यमान परिस्थितियों को देखते हुए देश में जो काला धन परिचालन में है उसकी मात्रा का किसी भी अंश तक सही-सही निर्धारण करना संभव नहीं है।

(ग) विमुद्रीकरण के बारे में सरकार के निश्चय में कोई परिवर्तन नहीं है।

(घ) काला धन और कर-अपवंचन आपस में गहरे तौर पर जुड़े हुए हैं। काले धन और कर-अपवंचन के विरुद्ध लड़ाई जारी है। जो उपाय किये गये हैं अथवा किये जाने का प्रस्ताव है, उनमें से निम्नलिखित का उल्लेख किया जा सकता है :—

(i) कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1972 के माध्यम से ऐसे मामलों में अचर सम्पत्तियों के अभिग्रहण की व्यवस्था की गई है, जिनके अन्तरण के समय न्यून-मूल्यांकन किया गया है क्योंकि न्यून-मूल्यांकन से काले धन की उत्पत्ति और उसका परिचालन सुविधाजनक हो जाता है ;

(ii) कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1972 के माध्यम से ऐसी व्यवस्था की गई है कि किसी बेनामी सम्पत्ति के अधिकार के मामले में किसी न्यायालय में तब तक कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकेगा जब तक उस सम्पत्ति को आयकर विभाग में घोषित नहीं किया जाता । इसी अधिनियम में विभाग के मूल्यांकन-तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए कुछ उपाय भी दिये गये हैं ताकि न्यून-मूल्यांकन के माध्यम से कर-अपवंचन रोका जा सके ।

(iii) वित्त अधिनियम 1973 में कृषि-आय को कृषि-भिन्न आय में, कर प्रयोजनों के लिए आँशिक रूप से मिला देने की व्यवस्था है जिसके अभाव में कर-अपवंचन को लाभकर स्रोत मिलता रहा है ।

(iv) कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 1973 में काले धन को रोकने के लिए कई उपबंध किये गये हैं, जैसे--तलाशी व माल पकड़ने की बढ़ी हुई शक्तियां; कर-अपवंचन के लिए दंड और इस्तगासे की कठोरतर व्यवस्थाएं, सर्वेक्षण की अतिरिक्त शक्तियां, लेखों को अनिवार्य रूप से रखना और लेखा परीक्षा कराना और कर-कानूनों की बहुत सी कमियों को दूर करना ।

(v) वित्त विधेयक 1974 के माध्यम से आयकर की दरों में कमी करने का प्रस्ताव कर-अपवंचन कम करने में सहायक होना चाहिए ।

(vi) वित्त विधेयक 1974 में आयकर प्रयोजनों के लिए छूट-सीमा 5,000 रु० से 6,000 रु० तक बढ़ाने और वेतन-भोगी कर-दाताओं को (जिनकी आय 18.000 रु० तक है) आय-विवरणी भरे जाने के संबंध में विकल्प देने का प्रस्ताव भी बड़े मामलों में अपेक्षाकृत अच्छी जांच-पड़ताल करने के लिए, उपलब्ध जन शक्ति का उपयोग करने में सहायक होना चाहिए ।

यहां निम्नलिखित प्रशासनिक उपायों का भी उल्लेख कर दिया जाय :—

(i) सबसे बड़े व्यापर-गृहों में से कुछ के मामलों में जांच-पड़ताल करने के लिए निरीक्षण निदेशालय (जांच-पड़ताल) में एक विशेष सेल स्थापित किया गया है ।

(ii) कर-अपवंचन के स्पष्ट मामलों में आय छिपाने के लिए इस्तगासे की कार्यवाहियां की जा रही हैं ।

(iii) शहरी क्षेत्रों में नयी बनी हुई सम्पत्तियों के बारे में व्यापक सर्वेक्षण का आदेश दिया गया है ।

(iv) सर्वेक्षण के लिए आयकर अधिनियम की धारा 23ए के अन्तर्गत शक्तियों का भी अपेक्षाकृत बार-बार प्रयोग किया जा रहा है ।

(v) कर अपवंचन के अपेक्षाकृत बड़े-बड़े मामलों अधिक सक्रिय रूप से कार्यवाही करने के लिए असूचना प्रशाखाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है ।

छोटे साबुन बनाने वालों को सप्लाई करने हेतु राज्य व्यापार निगम के साथ हुए ठेके के अन्तर्गत बकरे की चर्बी/ताड़ के तेल से ग्लेसिरीन निकाला जाना

3357. **श्री श्याम सुन्दर महामात्र** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम के साथ किये गये ठेके के अन्तर्गत एक गैर-सरकारी उद्यमी द्वारा बकरे की चर्बी/ताड़ के तेल से ग्लिसिरीन निकाला जा रहा है और वची हुई सामग्री के लिये गारंटी सरकार/राज्य व्यापार निगम द्वारा दी जाती है;

(ख) इस ग्लिसिरीन निकालने वाली एजेंसी के साथ किन-किन शर्तों पर ठेका किया गया है और ग्लिसिरीन की बिक्री से कितना राजस्व प्राप्त होगा ;

(ग) क्या सरकार का विचार पूरा अनुसन्धान तथा जांच किये जाने तक गैर-सरकारी उद्यमी द्वारा इस प्रकार ग्लिसिरीन निकाले जाने को रोकने का है और इस योजना की सरकारी या सहकारी क्षेत्र में चलाने का है; और

(घ) क्या कुछ साबुन बनाने वालों ने ग्लिसिरीन निकाले जाने का इसलिये विरोध किया है कि उन्हें परिष्करण में बड़ी देर लगती है और सप्लाई किये गये माल के अंशों तथा किस्म की गारंटी राज्य व्यापार निगम/सरकार द्वारा नहीं दी जाती ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) चर्बी/ताड़ के तेल का विखंडन करने वाले अभिकरणों को उनके द्वारा 410 रु० प्रति मै० टन की चालू दर से वहन की गई वास्तविक लागत को ध्यान में रखते हुए साधित करने के दाम दिये जाते हैं । निकाली गई ग्लेसिरीन और वसीय अम्ल आयात-निर्यात के मुख्य नियंत्रक और अन्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों द्वारा जारी किये गये आयात लाइसेंसों या रिलीज़ आर्डरों के आधार पर वास्तविक उपयोक्ताओं को दिये जाते हैं ।

(ग) जी नहीं । इस समय कोई राजकीय या सहकारी एकक नहीं चल रहा है ।

(घ) कुछ सामान्य शिकायतें प्राप्त हुई थीं जो मुख्यत: आरम्भिक अवस्था में विलम्ब के बारे में लघु पैमाने के साबुन निर्माताओं से आई थीं । चूंकि वसा विखंडन और वसीय अम्ल/ग्लेसिरीन की डिलीवरी का त्रियाविधियां सरल और कारगर वना दी गई हैं, अत: किसी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नही हुई है ।

छोटे साबुन निर्माताओं को राज्य व्यापार निगम द्वारा सप्लाई किया गया कच्चा माल

3358. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब छोटे साबुन निर्माताओं को कच्चे माल के रूप में राज्य व्यापार निगम द्वारा ताड़ तेल (पाम् आयल) लगभग 5,000 रुपये प्रति मीट्रिक टन पर सप्लाई किया जा रहा है जबकि उन्हें बकरे की चर्बी लगभग 3,000 रुपये प्रति मीट्रिक टन दी जा रही थी और यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ख) नये ड्रमों तथा पुराने ड्रमों में प्रति टन ड्रम की लागत का अन्तर क्या है और इसकी सप्लाई नये ड्रमों में करने के क्या कारण है जबकि पुराने ड्रम बाजार में उपलब्ध हैं;

(ग) क्या छोटे साबुन निर्माताओं ने अधिक लागत के कारण नये ड्रमों में सप्लाई किये जाने का विरोध किया है और यदि हां, तो इस मामले में संरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या बड़े क्षेत्र के तथा वनस्पति निर्माताओं के कुछ सुझावों के आधार पर ताड़ तेल आयात किया गया था और क्या यह अब छोटे साबुन निर्माताओं को जबरदस्ती दिया जा रहा है जबकि बकरे की चरबी बड़े साबुन निर्माताओं को दी जा रही है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) राज्य व्यापार निगम द्वारा विशाल और लघु दोनों क्षेत्रों के साबुन निर्माताओं को ताड़ का तेल विपुल परिमाण में सप्लाई के मामले में 4520 रु० प्रति मे० टन और पुराने ड्रमों में 4820 रु० प्रति मे० टन की रिलीज़ कीमत पर दिया जा रहा है।

अगस्त 1973 तक चर्बी 3050 रु० प्रति मे० टन दी जा रही थी क्योंकि उसे अपेक्षाकृत कम कीमतों पर आयात किया गया था। बाद में यह विदेशी बाजारों में उपलब्ध नहीं थी।

(ख) दोनों किस्मों के ड्रमों में लगभग 250 रु० प्रति मे० टन का अन्तर है। अच्छी क्वालिटी के पुराने ड्रम न मिलने पर पुराने ड्रमों में सप्लाई की जाती है।

(ग) यदि और माल लेने के लिए साबुन निर्माताओं द्वारा ड्रम दिये जाते है तो उन्हें ड्रम की लागत के बराबर कीमत में छूट दे दी जाती है।

(घ) राज्य व्यापार निगम को ताड़ का तेल या चर्बी का जो भी सस्ती या उपलब्ध हो, आयात करने की अनुमति है। विशाल और लघु दोनों क्षेत्रों के साबुन निर्माताओं को माल, चाहे वह चर्बी हो या ताड़ का तेल, प्राप्यता के अनुसार सप्लाई किया जाता है।

बुनकरों और कतइयों को विस्कोस फिलामेंट यार्न का वितरण

3359. **श्री डी० बी० चन्द्रगौड़ा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विस्कोस फिलामेंट यार्न के वितरण के लिये बुनकरों और कतइयों की क्षेत्रीय समिति की अध्यक्षता केन्द्रीय सरकार के नामित व्यक्ति द्वारा किये जाने के सुझाव को स्वीकार नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : कत्तिनों तथा बुनकरों के बीच एक स्वैच्छिक करार के फलस्वरूप कत्तिनों तथा बुनकरों की केन्द्रीय समिति द्वारा विस्कोस फिलामेंट धागे के बुनकरों तथा कंत्तिनों की क्षेत्रीय समितियां बनाई गई हैं। यह एक संविदा संबंधी करार है जिसमें केन्द्रीय सरकार का कोई हाथ नहीं है। इस लिए केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय समितियों में अध्यक्षता करने के लिए अपने प्रतिनिधि नामित नहीं कर सकती। तामिलनाडु की क्षेत्रीय समिति के सम्बन्ध में केन्द्रीय समिति से संबंधित बुनकरों तथा कत्तिनों के प्रतिनिधि इस बात से सहमत है कि हथकरघा निदेशक, तमिलनाडु, तमिलनाडु की क्षेत्रीय समिति की अध्यक्षता करें चूंकि करार में एक ऐसे अध्यक्ष की नियुक्ति

की व्यवस्था है जो दोनों संविदाकारी पार्टियों से सम्बन्धित न हो । कर्नाटक के संबंध में इसी प्रकार के सुझाव पर केन्द्रीय समिति सहमत नहीं हुई । इस समय दोनों पार्टियों के बीच एक नये करार पर बात-चीत हो रही है ।

विदेशी पर्यटकों को भारत में दोबारा आने की पेशकश

3360. **श्री डी० बी० चन्द्रगौड़ा**
श्री विश्वनाथ झुंझुंनवाला } : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 24 नवम्बर, 1973 से 31 जनवरी, 1974 तक भारत में आने वाले सभी विदेशी पर्यटकों को कुछ अवधि के लिये 'भारत में दोबारा आने' की पेशकश की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रोत्साहन योजना की रूपरेखा क्या है और इस पर विदेशी पर्यटकों की प्रतिक्रिया क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषी) : (क) "भारत की पुनर्यात्रा" योजना के अन्तर्गत घोषित रियायतें केवल उन विदेश से आने वाले यात्रियों पर लागू होती हैं जो 24 नवम्बर 1973 से 31 जनवरी, 1974 तक की तालाबन्दी की अवधि के दौरान अपने यात्रा-कार्यक्रम को पूरा नहीं कर सके ।

(ख) " भारत की पुनर्यात्रा" स्कीम की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं :—

(1) जो व्यक्ति 24 नवम्बर 1973 तथा 31 जनवरी 1974 की अवधि के दौरान भारत आया हो और विमान सेवाओं के ठप्प हो जाने के कारण जो भारत दर्शन के अपने यात्रा-कार्यक्रम को पूरा न कर सका हो, उसके प्रवेश की तिथि से अधिकतम 15 दिन की अवधि के लिए इण्डियन एयर लाइंस के अन्तर्देशीय सेक्टरों पर किरायों में 50 % की छूट ।

(2) प्रत्येक नगर में सहभागी (पार्टिसिपेटिंग) होटलों में अधिकतम 3 दिन की अवधि के लिए कमरे के किराये में 50% की छूट । यह छूट प्रवेश की तिथि से अधिकतम 15 दिन के लिए होगी ।

(3) प्रत्येक नगर में एयरपोर्ट से होटल तथा वापसी की दो यात्राओं तथा सहभागी यात्रा अभिकर्त्ताओं द्वारा एक बार नगर के दर्शनीय स्थल दिखाने की सुविधा पर 50%की छूट ।

इस स्कीम के अन्तर्गत भारत की पुन: यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों की हकदारी का निर्धारण उन के द्वारा दिये गये प्रमाणों के आधार पर भारत सरकार के विदेश स्थित कार्यालयों द्वारा किया जाएगा ।

यह सुविधा 31 दिसम्बर 1975 तक रहेगी । जो व्यक्ति भारत की एक बार यात्रा करते हैं वे सामान्यतया तुरंत पुन : यात्रा नहीं करते हैं । ऐसे यात्रियों को पुन : यात्रा का इरादा बनाने में कुछ महीने लग जायेंगे ।

पांचवीं योजना के दौरान केरल में होटलों के निर्माण का प्रस्ताव

3361. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल के किन-किन स्थानों पर पर्यटकों के लिए होटल और बंगले बनाने का सरकार का प्रस्ताव है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषी : भारत पर्यटन विकास निगम, जो कि एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, कोवालम् में 100 कमरों का एक होटल बना रहा है जो कि मई 1974 में चालू किया जाना है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोवालम् में होटल क्षमता को 150 कमरे और बनाकर बढ़ाने तथा 50 कमरों वाली और कुटीरें जोड़ने का प्रस्ताव है । पर्यटन विभाग का एक युवा होस्टल भी त्रिवेनद्रम में निर्माणाधीन है ।

रबड़ बोर्ड के कर्मचारियों को बोनस की अदायगी

3362. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रबड़ बोर्ड के कर्मचारियों को बोनस अदा करने के बारे में कोई अंतिम निर्णय किया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) रबड़ बोर्ड के कर्मचारियों को बोनस की अदायगी के लिए कानूनी आधार की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है ।

(ग) तथा (घ) : इस संबंध में रबड़ बोर्ड के कर्मचारियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और सरकार बोनस के लिए उनके दावे के कानूनी पहलू पर विचार कर रही है ।

प्राकृतिक रबड़ के निर्यात में वृद्धि

3363. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में प्राकृतिक रबड़ का कितना वार्षिक उत्पादन होता है ;

(ख) क्या भारत के प्राकृतिक रबड़ के निर्यात में शीघ्र काफी वृद्धि होने की सम्भावना है; और

(ग) यदि हां, तो अनुमानतः कितनी वृद्धि हो जायेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) चालू वर्ष (1973-74) के लिये प्राकृतिक रबड़ का अनुमानित उत्पादन 125,000 मे० टन है ।

(ख) क्योंकि विदेशी बाजारों में प्राकृतिक रबड़ की अच्छी मांग है, अतः भारत से प्राकृतिक रबड़ के निर्यात बढ़ाने की संभावनाऐं हैं ।

(ग) सरकार ने स्वदेशी उत्पादन तथा खपत पर विचार करने के पश्चात, फिलहाल 5,000 मे० टन माल का निर्यात करने की अनुमति देने का फैसला किया है ।

रिजर्व बैंक की ऋण नीति का पुनरीक्षण

3364. **श्री श्रीकिशन मोदी**
श्री पी० गंगादेव : } : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऋण विस्तार को नियंत्रित करने और वाणिज्यिक बैंकों के नकदी अनुपातों को बढ़ाने की रिजर्व बैंक की नीति का पुनरीक्षण किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) (क) और (ख) गत नवम्बर में भारतीय रिजर्व बैंक ने अधिक काम काज के दिनों के लिए ऋण संबंधी जो नीति घोषित की थी और जिसमें और बातों के साथ साथ कानूनी नकदी अनुपात को 30 प्रतिशत से 32 प्रतिशत तक बढ़ाने की बात कही गयी थी वह जारी है। तथापि स्थिति की इस विचार से निरन्तर समीक्षा की जाती है कि उस में ऐसे परिवर्तन किये जा सकें जो उत्पन्न स्थिति के अनुसार जरूरी समझे जाएं।

अन्य देशों को मूंगफली का निर्यात

3365. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व मंडी में कमी को देखते हुए भारतीय एच० पी० एस० मूंगफली की विदेशों खरीददारी में भारी मांग है ;

(ख) क्या विश्व मंडी में भारत के मुख्य प्रतिद्वंदी नाइजीरिया में मूंगफली की फसल खराब होने से इस देश से मूंगफली खरीदने वाले ब्रिटेन, पश्चिम तथा पूर्व यूरोपीय देशों तथा जापान की इसकी सप्लाई करने का विश्वसनीय श्रोत एकमात्र अब भारत ही है, और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1973 में विदेशी मुद्रा के रूप में इससे कितनी आय हुई है और हमारे देश के निर्यातकों द्वारा इसके आकर्षक मूल्य प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास किये गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) ब्रिटेन, पश्चिम तथा पूर्व यूरोपीय देशों तथा जापान को मूंगफली की सप्लाई के लिए भारत के अलावा अन्य स्रोत भी है, जैसे कि सं० रा० अमरीका, ब्राजील, नीदरलैंड , सूडान आदि।

(ग) जनवरी-सितम्बर, 1973 के दौरान हाथ से चुनी तथा छांटी हुई मूंगफली के निर्यात 8 करोड़ रुपये मूल्य के हुए हैं। सितम्बर, 1973 के बाद के निर्यात आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। निर्यातकों ने आकर्षक कीमतें प्राप्त करने तथा निर्यात को अधिकतम बढ़ाने के लिये सभी संभव प्रयास किये हैं।

वर्ष 1972-73 में पकड़ा गया तस्करी का सामान

3366. **श्री जी० वाई० कृष्णन**
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1972 और 1973 के वर्षों में प्रतिदिन औसतन कितना तस्करी का सामान पकड़ा गया है; और

(ख) क्या बहुत से राज्यों के नगरों में विदेशी सामान आसानी से उपलब्ध होता है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा वर्ष 1972 तथा 1973 के दौरान प्रतिदिन पकड़े गये तस्करी के माल का औसत मूल्य, सोने सहित सभी वस्तुओं के मूल्य को भारतीय बाजार दर पर हिसाब में लेकर, क्रमशः लगभग 7.6 लाख रु० तथा 9.7 लाख रु० है।

(ख) बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा दिल्ली जैसे बड़े शहरों के बाजारों में तस्करी का माल उपलब्ध है।

त्रिपुरा के बेरोजगार स्नातकों को ऋण दिया जाना

3367. श्री दशरथ देव : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों ने वर्ष 1971, 1972 और 1973 के दौरान त्रिपुरा के बेरोजगार स्नातकों को कोई ऋण दिया है, और

(ख) यदि हां, तो कितना ऋण दिया गया और उसे कितने व्यक्तियों ने प्राप्त किया?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) (क) और (ख) : इस समय बैंक ऋण देने के बारे में ब्यौरेवार श्रेणीगत ऐसी सूचना नहीं रखते कि जिसमें बेरोजगार स्नातकों को दिये गये ऋण के आंकड़े दिये गये हैं। ये ऋण साधारणतया प्राथमिकता के क्षेत्र वाले ऋणों के आंकड़ों में दिखाये जायेंगे जैसे "लघु उद्योग", "फुटकर व्यापार तथा छोटे व्यापार", "व्यावसायिक तथा स्वयं रोजगार में लगे लोग", आदि। त्रिपुरा में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिता वाले क्षेत्रों को दिये गये ऋणों के बारे प्राप्त सूचना नीचे दी जा रही है :—

(लाख रुपयों में)

श्रेणी	जून, 1972 के अन्त तक		जून, 1973 के अन्त तक (अनन्तिम)	
	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि
लघु उद्योग	66†	4	54†	6
फुटकर व्यापार तथा छोटे व्यापार	355	39	365	40
व्यवसायिक तथा स्वयं रोजगार में लगे लोग	15	1	19	1

†एककों की संख्या

जापान द्वारा विकासशील देशों को दी जाने वाली सहायता पर रोक

3368. श्री पी० एम० मेहता : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व में उत्पन्न हुए तेल संकट के कारण जापान ने विकासशील देशों को दी जाने वाली सहायता पर कोई रोक लगा दी है;

(ख) यदि हां, तो इससे भारत किस सीमा तक प्रभावित होगा;

(ग) क्या इस बारे में जापान से कोई स्पष्टीकरण मांगा गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, नहीं । हमें ऐसी रोकों की कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) से (घ) सवाल पैदा ही नहीं होता ।

गुजरात में बैंकिंग कार्य

3369. **श्री पी० एम० मेहता** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में हाल के खाद्य झगड़ों के पश्चात् बैंकिंग कार्य ठप्प हो जाने से व्यापार और वाणिज्यक क्रिया कलापों पर बुरा प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में स्थिति को सुधारने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) गड़बड़ी/बन्द, कर्फ्यू लगाये जाने तथा सामान्य कानून और व्यवस्था की स्थिति के परिणामस्वरूप, जनवरी, 1974 से अहमदाबाद में अनेक बैंक कार्यालयों तथा गुजरात राज्य के कुछ अन्य व्यापारिक केन्द्रों के सामान्य कार्य में बाधा पड़ी । इससे राज्य के प्रभावित क्षेत्रों में व्यापार और कारोबार की गतिविधियों पर स्वभावत: प्रभाव पड़ा ।

(ख) बैंकों द्वारा अपना सामान्य कार्य करने में महसूस की जाने वाली कठिनाइयों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य सरकार के अधिकारियों के ध्यान में लाया गया । राज्य सरकार के अधिकारियों ने सूचित किया है कि बैंकों को पुलिस की पर्याप्त सहायता दी जा रही है । भारतीय रिजर्व बैंक तथा वाणिज्यिक बैंकों, दोनों के द्वारा वर्तमान परिस्थितियों में अधिकतम सुविधाएं देने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

इण्डियन एयरलाइंस से तालाबंदी हटाने का प्रस्ताव

3370. **श्री भोगेन्द्र झा**
श्री देवेन्द्र सिंह गरचा } : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का इण्डियन एयरलाइंस से पूरी तालाबंदी हटाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) 24-11-73 से इंडियन एयरलाइंस में घोषित तालाबंदी को 21-12-1973 से व्यक्तिगत रूप से उन कर्मचारियों के लिए समाप्त कर दिया गया जो संशोधित शिफ्ट प्रणाली, जहां कहीं लागू होती हो, के अनुसार काम करने तथा अपव्ययी कार्य प्रणालियों को समाप्त करने के लिये

प्रबंधकवर्ग से सहयोग करने का आश्वासन देने को तैयार थे। इस आधार पर कर्मचारियों की एक बहुत बड़ी संख्या ने व्यक्तिगत शपथ-पत्रों पर हस्ताक्षर किये और कार्य पर उपस्थित हुये।

जो कर्मचारी निम्न संगठनों/यूनियनों के सदस्य हैं, उनके बारे में भी संगठनों के सामने दी गई तारीखों से, इन संगठनों के साथ संशोधित शिफ्ट प्रणालियों के अनुसार काम करने तथा अपव्ययी कार्य-प्रणालियों को समाप्त करने के लिये प्रबंधकवर्ग से सहयोग करने के विषय में समझौता हो जाने पर, तालाबंदी समाप्त कर दी गई थी :—

संगठन/यूनियन का नाम	तालाबंदी समाप्त करने की तारीख
(1) इंडियन एयरक्राफ्ट तकनीशियंस एसोसियेशन	10-12-1973
(2) एयरलाइंस ग्राउंड इंस्ट्रेक्टर्ज एसोसियेशन	21-12-1973
(3) इंडियन फ्लाइट इंजीनियर्ज एसोसियेशन	23-12-1973
(4) आल इंडिया एयरक्राफ्ट इंजीनियर्ज एसोसियेशन	10-1-1974
(5) इंडियन कमर्शियल पाइलट्स एसोसियेशन	21-2-1974

उपर्युक्त आधार पर 12-3-1974 को 15,977 कर्मचारियों में से 15,934 कर्मचारी काम पर लौट आये थे, अतः केवल 43 कर्मचारी तालाबंदी से प्रभावित थे जो कि 'एयर कारपोरेशन्स एम्लाईज़' के सदस्य हैं। यही एक मात्र संगठन है जिसके साथ अभी तक समझौता नहीं हुआ है।

हुबली धारवा निगम का दर्जा बढ़ाया जाना

3371. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुबली-धारवाड़ निगम को 'सी' श्रेणी नगर से (बी) श्रेणी नगर बनाने के सम्बन्ध में कोई अध्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी हां।

(ख) : 1971 की जनगणना के अनुसार हुबली-धारवाड़ निगम की जनसंख्या 4 लाख से कम है, जो किसी नगर की बी-2 श्रेणी में शामिल करने के प्रयोजनार्थ न्यूनतम अर्हता प्रदायी सीमा है। इसलिये, हुबली-धारवाड़ का दर्जा बढ़ाकर उसकी बी-2 श्रेणी में रखना सम्भव नहीं पाया गया है।

Seizure of Fake Currency Notes from a Press in Muzaffarnagar.

3372. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(*a*) whether a large number of fake note printing blocks and printed fake currency notes were seized from a press in Muzaffarnagar in January, 1974; and

(*b*) the action taken by Government in this connection and the particulars of fake currency notes so recovered ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (*a*) & (*b*) : The information is being collected from the Government of Uttar Pradesh and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

कोचीन हवाई अड्डे के स्थापना-स्थल का चयन

3373. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक अध्ययन दल ने कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के स्थापन-स्थल का चयन करने के लिये जनवरी, 1974 के प्रथम सप्ताह में केरल की यात्रा की थी;

(ख) क्या अध्ययन दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया और यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है; और

(ग) यह कार्य कब प्रारम्भ होने की सम्भावना है?

पर्यटन और नागर विमानन् मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) नागर विमानन विभाग के एक अधिकारी तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के एक सिविल इंजीनियर ने उस क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिये कोचीन की यात्रा की जहां विमानक्षेत्र की स्थापना का सुझाव दिया गया था; किन्तु उन्होंने उस क्षेत्र में विमानक्षेत्र के निर्माण के लिये कोई उपयुक्त स्थान नहीं पाया। कोचीन में किसी अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र के विकास का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) : फिलहाल प्रश्न नहीं उठता।

गत 6 मास में कच्चे काजू का आयात

3374. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 6 महीनों में कितना कच्चा काजू आयात किया गया;

(ख) उसमें से केरल को कितनी मात्रा का आवंटन किया गया; और

(ग) चालू वर्ष में कुल कितना कच्चा काजू आयात किये जाने का विचार है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 51,866 मे० टन।

(ख) 40,700 मे० टन।

(ग) लगभग 1,80,000 मे० टन (जनवरी से दिसम्बर, 1974)।

त्रिपुरा में छोटे किसानों और छोटे उद्योगपतियों को दिये गए ऋण

3375. **श्री वीरेन दत्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1971, 1972 तथा 1973 की अवधि में त्रिपुरा में छोटे किसानों और छोटे उद्योगपतियों को कितनी राशि के ऋण दिये गये?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा छोटे किसानों को दिये जाने वाले अग्रिमों की वर्षवार सूचना उपलब्ध नहीं है। फिर भी, त्रिपुरा में सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने 5 एकड़ तक की जोत-भूमि वाले किसानों को (जिसमें

छोटे किसान शामिल हैं) कृषि सम्बन्धी दिये गये अग्रिमों की बकाया राशि मार्च, 1973 के अन्त में 0.97* लाख रुपया थी (इसमें कृषि से संबद्ध क्रियाकलापों के लिए दिये गये अग्रिम शामिल नहीं हैं)।

त्रिपुरा में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा मार्च, 1971 से लघु उद्योगों को दिये गये अग्रिमों के आंकड़े इस प्रकार हैं:—

	बकाया राशि (लाख रुपयों में)
मार्च 1971	4.50
मार्च 1972	5.33
मार्च 1973	7.55
सितम्बर 1973 (सबसे हाल के उपलब्ध आंकड़े)	8.58*

*आंकड़े अनन्तिम हैं।

Loans Advanced by Nationalised Banks to Farmers of Flood Affected Areas.

3376. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(*a*) the total amount of loans advanced by the nationalised banks to the farmers of the flood affected areas; and

(*b*) the terms and conditions on which those loans have been given ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (*a*) & (*b*) : The public sector banks have been providing credit facilities to cultivators for various agricultural development purposes in the country including flood-affected areas. In such areas, the banks generally reschedule, in hard cases, instalments of repayments as a measure of relief to the legitimate borrowers. Figures of advances exclusively for these areas are not available. State-wise figures for direct agricultural advances for farmers by the public sector banks, outstanding as at the end of june, 1973, are given in the statement annexed.

Statement

Statement showing State-wise position of direct advances to agriculture by the public sector banks as at the end of June, 1973.

Name of the State	Amount outstanding* (Rs. in lakhs)
(1)	(2)
1. Andhra Pradesh	2931·59
2. Assam	99·78
3. Bihar	1103·83
4. Gujarat	3169·64
5. Haryana	951·37
6. Himachal Pradesh	44·32
7. Jammu & Kashmir	17·82
8. Kerala	1241·14
9. Madhya Pradesh	1110·95

(1)	(2)
10. Maharashtra	5013·19
11. Manipur	6·24
12. Meghalaya	14·11
13. Karnataka	2773·21
14. Nagaland	0·22
15. Orissa	177·40
16. Punjab	938·07
17. Rajasthan	1189·56
18. Tamil Nadu	3894·65
19. Tripura	4·05
20. Uttar Pradesh	2680·28
21. West Bengal	1431·63
Union Territories	474·28
Total	29267·33

*Provisional

इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा कोचीन में भवन का निर्माण

3377. **श्री बखालार रवि :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस ने कोचीन में अपना भवन बनाने के लिए वहां भूमि का प्लाट खरीदा है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) क्या प्रगति में कोई विलम्ब हुआ है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : यद्यपि भवन के लिए भूमि 1966 में अधिगृहीत की गयी थी, वित्तीय साधनों के परिसीमित होने के कारण निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा सका।

रेयन उद्योग के वितरण की नीति

3378. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेस्क्स प्रतिमाह लगभग 50 लाख से 60 लाख किलोग्राम धागा वितरित करता है तथा यह धागा कताई करने वालों तथा बुनकरों के बीच स्वैच्छिक करार के अन्तर्गत प्राप्त होता है;

(ख) क्या रेयन धागे का बाजार भाव रियायती मूल्य की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक है जबकि रेयन कपड़ों के निर्यातकर्ताओं को उनके निर्यात पर रियायती दर पर धागा सप्लाई किया जाता है और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में कोई जांच की है तथा उस सम्बन्ध में सरकार की पुनरीक्षण नीति की रूपरेखा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जी हां। रेयक्स रेयन वस्त्रों के निर्यातकों को एक स्वैच्छिक करार के अंतर्गत तय की गई कीमत पर प्रतिपूर्ति के रूप में लगभग 5 से 6 लाख किग्रा रेयन फिलामेंट धागे का वितरण करता है।

(ग) रेयन फिलामेन्ट धागे पर कोई कानूनी कीमत तथा वितरण नियंत्रण नहीं है। कत्तिनों तथा बुनकरों के बीच एक स्वैच्छिक करार के अंतर्गत, कत्तिन अपने उत्पादन का एक भाग खुले बाजार में बेच सकते हैं। प्रतिपूर्ति के लिए धागे की तय की गई कीमत रेयन फिलामेन्ट धागे की वास्तविक प्रयोक्ता कोटा कीमत तथा अंतर्राष्ट्रीय कीमत से कम है। खुले बाजार की कीमतें मांग तथा पूर्ति के आधार पर चलती हैं। तय की हुई कीमतों तथा खुले बाजार की कीमतों के बारे में किसी प्रकार की जांच करने का प्रश्न नहीं उठता।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

Calling Attention to a Matter of Urgent Public Importance

बिजली घरों को कोयले की सप्लाई की गम्भीर स्थिति का समाचार

श्री बसंत साठे (अकोला) : मैं इस्पात तथा खान मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं तथा उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"उत्तर प्रदेश, गुजरात, आसाम, पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों में बिजलीघरों को कोयले की सप्लाई की गंभीर स्थिति तथा उसके परिणामस्वरूप बिजली संकट उत्पन्न हो जाने के खतरे के समाचार"

इस्पात और खान मंत्री (के० डी० मालवीय) : यद्यपि सन् 1972 से कोयले के उत्पादन में वृद्धि हो रही है और 1973-74 में लगभग 790 लाख टन कोयले के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जो 1972-73 के उत्पादन से 26 लाख टन अधिक तथा 1971-72 के उत्पादन से 66 लाख टन अधिक है। देश भर के उपभोक्ताओं को विभिन्न समयों में, पूर्ति की स्थिति संतोषजनक न होने से, कोयले की कमी का सामना करना पड़ा है। कोयला उत्पादक संगठन कोयले और कोक का उत्पादन और लदान बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और रेलवे द्वारा भी विभिन्न स्थानों को अधिक से अधिक कोयला और कोक पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे है किन्तु विभिन्न क्षेत्रों के रेलवे कर्मचारियों द्वारा लगातार आंदोलन हड़ताल करने तथा 'धीरे काम करों' की नीति अपनाने से इन प्रयासों में बाधा पड़ी है। गत कुछ दिनों से हालत बहुत नाजुक हो गई है। फिर भी, यह सही है कि कोई भी बड़ा बिजली घर वास्तव में बन्द नहीं हुआ है; यद्यपि कुछ बिजली घरों जैसे हरदुआगंज, कानपुर के नदी वाले, नासिक पारस और एन्नोर बिजली घरों में कोयला स्टाक की स्थिति अधिक संतोषजनक नहीं है।

2. कोयले की अधिकतम पूर्ति में उचित समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए कलकत्ते में एक संयुक्त सैल काम कर रहा है जिसमें रेलवे तथा कोयला उत्पादक एजेंसियों के प्रतिनिधि हैं। रेल बोर्ड के मुख्यालयों में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है ताकि किसी भी बिजली घर को कोयला-स्टाक की दयनीय स्थिति उत्पन्न होने पर, तत्काल कोयला

पहुंचाने के लिए आपाती कार्रवाई की जा सके । इन प्रयासों के फलस्वरूप बिजली-घर बराबर चल रहे हैं। जैसे ही रेल-यातायात की स्थिति में सुधार हो जाएगा तो केवल बिजली घरों को ही नहीं, अपितु कारखानों, ईंट भटटों तथा घरेलू उपभोक्ताओं को भी कोयले की पूर्ति बढ़ाना संभव हो जायगा ।

4. जहां तक विभिन्न राज्यों में बिजली कटौती के समाचार का संबंध है, उल्लेखनीय है कि आसाम के किसी भी बिजली घर में कोयले का इस्तेमाल नहीं होता है तथा पंजाब और हरियाणा में बहुत कम बिजली घर कोयले का इस्तेमाल करते हैं। इन राज्यों में अधिकांश बिजली की पूर्ति पन-बिजली घरों से की जाती है। यदि इन राज्यों के लिए बिजली की कटौती की गई है तो वह कोयले की कमी के कारण नहीं है। उत्तर प्रदेश और गुजरात में भी, जैसा कि बताया जा चुका है, कोई भी बिजली घर कोयले की कमी से बन्द नहीं हुआ है और जिन बिजली घरों में कोयला स्टाक की दयनीय स्थिति हुई है, उन्हें तत्काल कोयले की पूर्ति की गई है।

4. रेलवे में बिगड़े हुए औद्योगिक संबंधों के बाजजूद, सरकार द्वारा बिजली घरों को कोयले की सप्लाई सुनिश्चित रूप से बनाए रखने हेतु समन्वित रूप से सभी प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान परिस्थिति में, मैं सदन के सभी सदस्यों से अपील करुंगा कि वे रेलवे की कार्यप्रणाली को सामान्य बनाने में सहायता दें ताकि बिजली घरों तथा अर्थ-व्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कोयले की सप्लाई बनाई रखी जा सके।

श्री बसंत साठे (अकोला) : मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर तथ्यों से दूर है। वक्तव्य में कहा गया है कि कोई भी महत्वपूर्ण बिजली घर वास्तव में बन्द नहीं हुआ है, जबकि हर--दुआगंज जैसे बिजली घरों के स्टाक की स्थिति बहुत संतोषजनक नहीं है।

'हिन्दुस्तान टाइम्स' के 13 तारीख के संवाद में कहा गया है कि राज्य में कोयला सप्लाई की विषम परिस्थिति के कारण उत्तर प्रदेश में बिजली के ठप्प हो जाने का भय हैं।

इस मामले की ओर गम्भीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए कि कोयले के अभाव के कारण न केवल बिजली उत्पादन अपितु उर्वरकों के उत्पादन, सिंचाँई तथा कपड़ा मिलों पर भी प्रभाव पड़ेगा। यह सब मामले एक दूसरे से संबद्ध हैं। काफी समय से हमारे देश में बिजली का संकट बना हुआ है।

महाराष्ट्र और गुजरात समेत पश्चिमी क्षेत्र में तो इसका प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है और धीरे धीरे पंजाब, हरियाणा, आसाम और उत्तर प्रदेश में भी इसका प्रभाव होने लगेगा। पूर्वी क्षेत्र में 1972 के पहले छः महीनों में उत्पादन में 9 करोड़ रुपया की कमी हुई और विदेशी मुद्रा की 5 करोड़ रुपया की हानि हुई।

मंत्री महोदय ने तथा रेलवे मंत्री ने भी श्रमिकों की निन्दा की है । हमने श्रमिकों का सहयोग पाने के लिये क्या कार्यवाही की है। जब हम सेना को बुला कर श्रमिकों को कुचलते है तब हम उनका सहयोग कैसे पा सकते है। सरकार को श्रमिक वर्ग का विश्वास

प्राप्त करना चाहिए । ऐसा करने पर वे कोई भी बलिदान देने को उद्यत होंगे और चमत्कार कर दिखायेंगे। मेरा प्रश्न है कि सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है।

अध्यक्ष महोदय : नियम द्वारा एक ही प्रश्न पूछा जा सकता है।

श्री **बसन्त साठे :** आप देश में ऐसी स्थिति कब पैदा करेंग जब उद्योगों एवं बिजली घरों में एक महीने का कोयले का स्टाक जमा रहा करेगा।

श्री के० डी० मालवीय : मैं अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं । मुझ कोई गलत जानकारी नहीं दी जाती । अधिकारी वर्ग एवं मंत्री महोदय के बीच भद करना संगत नहीं है क्योंकि वे एक ही सरकारी तंत्र के भाग हैं। मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता कि सेवाओं द्वारा गलत जानकारी दी जाती है।

जहां तक हरदुआगंज बिजली घर का प्रश्न है उसमें 13 माच को आधे दिन के लिय कोयला था तथा और कोयला आ रहा था। यह बिजली घर कोयले की कमी के कारण बन्द नहीं हुआ था अपितु उसके अन्य ही कारण थे। कोयले के कारण बिजली घरों को बन्द नहीं होने दिया जायेगा। मैं यह नहीं कहना चाहता कि श्रमिकों के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं है। यदि सरकार उत्पादन बढ़ाना चाहती है तो श्रमिक वर्गों के निर्वाह की स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए ।

सैंकड़ों कर्मचारी दिल्ली आ रहें है और मैं समझता हूं कि उनके साथ कोई समझौता हो जायेगा। मैं इस सभा के सभी श्रमिक नेताओं से सहयोग के लिये अपील करता हूं ताकि उत्पादन बढ़ सके।

यह सच है कि यदि औद्योगिक कारखानों को बिजली नहीं दी जाती तो उद्योग स्थापित नहीं होगें। यहां तक सरकार का प्रश्न है उसे नीति को क्रियान्वित करना है श्रमिकों को संतुष्ट करना है तथा उत्पादन बढ़ाना है।

श्री पी० एस० मेहता (भावनगर) : चिरकाक से कोयले की गम्भीर कमी राष्ट्रीयकृत कोयला खानों एवं रेलवे प्रशासन में कुप्रबन्ध के फलस्वरूप हुई है।

रेल मंत्री का यह वक्तव्य कि माल-डिब्बों की कमी नहीं है, कहां तक उपयुक्त है।

गुजरात में कोयले की कमी के कारण कपड़ा मिलों के 5,000 कर्मचारी बेकार हो गए हैं। अकेली महालक्ष्मी मिल्स के 1,500 कर्मचारी बेकार पड़े हैं। न केवल कपड़ा उद्योग अपितु सीमेन्ट उद्योग, लघु उद्योग, इन्जीनियरिंग कारखानों, भट्ठों आदि पर भी इसका प्रभाव पड़ा है।

उन्होंने रेलवे कर्मचारियों को दोष देने की चेष्टा की है। रेलवे कर्मचारियों और स्थानीय लोगों को पर्याप्त अनाज नहीं मिला इसलिए उन्होंने आंन्दोलन शुरू किया है।

सरकार ने कोयला खान कर्मचारियों की समस्याओं पर मौन साधा हुआ है। कर्मचारियों में गम्भीर असन्तोष है। कोयले की कमी के बावजूद सरकार ने बंगलादेश को 1974 के लिए 4,47,000 टन कोयला देने का करार किया है। 1973 में बंगलादेश को कितना कोयला दिया गया।

श्री के० डी० मालवीय : मैं कुछ संगत प्रश्नों का ही उत्तर दूंगा।

श्री पी० एम० मेहता : मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं । उन्होंने कहा है कुछ प्रश्न संगत नहीं हैं। वे इसका निर्णय कैसे कर सकते हैं?

अध्यक्ष महोदय : श्री मेहता, मैंने आपसे यह आशा नहीं रखी थी।

श्री के० डी० मालवीय : सरकारी अधिकार में लिए जाने के पश्चात् कोयला खानों की कार्यकुशलता कर्मचारियों के सहयोग से बढ़ी है। हम उनके जीवन स्तर में सुधार के यत्न करते रहेंगे। उत्पादन वृद्धि में हमारा लक्ष्य और बढ़ाया जा रहा है।

जहां तक गुजरात के संकट का प्रश्न है यह सच है कि कपड़ा एवं सीमेन्ट मिलों पर बुरी तरह प्रभाव पड़ा है। कुछ तत्वों ने इस परिस्थिति से अनुचित लाभ उठाने की चेष्टा की है और सारी व्यवस्था को भंग कर दिया। श्रमिकों का इसमें कोई हाथ नहीं है।

कर्मचारियों को अनाज की पूर्ति की स्थिति में सुधारों की आवश्यकता को मैं स्वीकार करता हूं। सरकार राज्य सरकारों के सहयोग के साथ ऐसा करने जा रही है।

श्री पी० एम० मेहता : मंत्री महोदय ने बंगला देश को 4,42,000 टन कोयले की पूर्ति के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

श्री के० डी० मालवीय : मेरे सहयोगी ने मुझे बताया है कि हम प्रतिवर्ष 40,000 से 50,000 टन कोयला सप्लाई करने के लिए बचनबद्ध हैं। जांच करने के बाद मैं सही आंकड़े बताऊंगा।

Shri S. M. Banerji (KauPur) : The hon. Minister has relevated in his statement that there is nothing to cause anxiety. The fertilizer factories and cotton mills of Kanpur have been severely effected. Due to shortage of coal about 50 to 60 thousand workers have been rendered jobless. Not even the 25% of the demands of the employees are met.

Every Secretary knows that no Minister is going to hold his portfolio for more than 6 months. If the Government tries to establish goods relations it would succeed.

A parliamentary committee may be appointed to find out and the reasons. The people should be able to know whether the coal is available are not.

Action may also be taken against responsible high level officers of Railway Board as well as Mining Ministry.

The Government, in cooperation with the State Government, should anncunce that 50,000 workers who have been rendered jobless would be paid wages.

Shri K. D. Malaviya : I do not think there is any necessity for a Parliamentary Committee. One is the consultative process in a democracy we have to go stand. There might be certain elements who do not like the public section to prosper and so they try to sabotage. However, it is difficult to identify such elements. But I feel that the Railway board and high officers of our Ministry are doing excellent jobs.

The principle of accountability should apply right from top to the bottom. We are constantly trying to bring about improvements in the situations.

At present atmosphere of scarcity is prevailing. Some strike on the other is always going on. The number of wagons reduces due to labour shortage on some other reasons.

श्री एस० एम० बनर्जी : उन्होंने मेरे अन्तिम प्रश्न का उत्तर नहीं दिया । वे लोग बिना किसी कारण के कष्ट उठा रहे हैं।

Shri K. D. Malaviya : I shall pass on this suggestion to my colleague Labour Minister for reply.

Shri Naval Kishore Sharma (Dausa) : It is apparent from the statement that during 1973-74 26 lakhs tons of coal was produced more and during 1972-73 66 lakhs tons of coal was produced more. It is strange that in spite of the increase in production the difficulties of the common man have increased. Has the Government been able to achieve the targets fixed for the production of coal ?

In view of the rise in price of crude and its shortage, it has become imperative for us to ensure the timely movement of coal. Will the hon. Minister make alternative arrangements for the transportation of coal which is possible to do through coastal shipping ?

The functioning of power house located at Panki has been suspended due to shortage of coal. I want to know whether this report is correct ?

Will the Minister give an assurance that every power house will have 15 days coal quota in advance ?

Shri K. D. Malaviya : Panki Power House had coal stock for six days i. e. the 13th instant. As usual, Government will see to it that functioning of the Power Houses is not disrupted due to shortage of coal.

The State Electricity Boards should improve the maintenance work in power houses. Presumably, maintenance work of Panki Power House was not satisfactory.

The work of transporting coal through coastal shipping is not easy. Before we do it, rivers have got to be cleared for shipping which is the function of the Transport and Shipping Ministry. We are consulting them also. We are facing the difficulty of acquiring ships. In addition, there are some other difficulties also.

I agree that coal production should increase. Coal production is increasing by two lac tons every year. I hope that we will increase the production of coal further for which we are going to import necessary machinery. We are also trying to improve the industrial relations. We are also trying to manufacture gas from coal. The figures given by me about coal are correct. We are doing our best to increase the production of coal.

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

Re MOTION FOR ADJOURNMENT

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Mr. Speaker, kindly ask the hon. Health Minister to make a statement regarding causes of the deadlock in the negotiations with the Junior Doctors Is it due to the fact that Government want to punish the Doctors ?

श्री ज्योतिमय बसु (डामड हार्बर) : हम तथ्यों पर आधारित वक्तव्य चाहते हैं । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इस बात को मंत्री महोदय तक पहुंचा दिया जायेगा।

श्री समर गुह (कन्टाई) : हमें यह जानने का हक है कि इस बारे में क्या हो रहा है ?

Mr. Speaker : The House should be informed about the latest position regarding this issue.

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं इस बात को उन तक पहुंचा दूंगा।

श्री एस० एम० बैनर्जी : (कानपुर) : इन्होंने प्रेस को बता दिया है। यहां वक्तव्य क्यों नहीं दिया जा सकता ? **(व्यवधान)**

श्री समर गुह : गुजरात से राज्य सभा के लिए चुनावों के बारे में क्या हो रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें।

श्री समर गुह : यह सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है...

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता। आपको कार्य-सूची का भी ध्यान रखना चाहिए। हर समय आपको खड़ा नहीं हो जाना चाहिये।

मुझे यह देख कर आश्चर्य होता है कि सदन के बाहर वह कितने अच्छे हैं और सदन के अन्दर उनका व्यवहार क्या है।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : आप भी तो सदन से बाहर बहुत अच्छे हैं।

"पैट्रियाट" दिल्ली के सम्पादक के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न
QUESTION OF PRIVILEGE AGAINST THE EDITOR OF THE PATRIOT, DELHI

अध्यक्ष महोदय : श्री पी० जी० मावलंकर ने, दिल्ली के दैनिक "पेट्रियाट" के 12 मार्च 1974 के अंक में उनके बारे में की गई कुछ टिप्पणियों को लेकर, 13 मार्च, 1974 को विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की अनुमति मांगी थी।

मैंने कहा था कि इस दैनिक समाचार के सम्पादक से इस बारे में पूछताछ करूंगा कि उन्हें इस बारे में क्या कहना है। "पेट्रियाट" के सम्पादक ने अपने 14 मार्च 1974 के पत्र में कहा है कि :—

> "रिपोर्ट में संसद की कार्यवाही को गलत रूप से प्रकाशित नहीं किया गया है। जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया है, श्री मावलंकर का भाषण, जो गुजरात सम्बन्धी राष्ट्रपति की उद्घोषणा पर था, हमारे संवाददाता के अनुसार "हृदयस्पर्शी" था और उस दिन की विशेष बात थी। यह स्पष्ट है कि रिपोर्ट में श्री मावलंकर की सत्यनिष्ठा पर किसी प्रकार का आक्षेप लगाने का इरादा नहीं था।"

यह भी स्पष्ट है कि पंक्ति के शेष जिन भागों पर आपत्ति की गई है, वे संसद की कार्यवाही से सम्बन्ध नहीं रखते। उस पत्र में आगे कहा गया है कि हम लोग सभा के अध्यक्ष को आश्वासन देना चाहते हैं कि इस रिपोर्ट को प्रकाशित करके हमारा इरादा सभा के किसी सदस्य का विशेषाधिकार भंग करने का नहीं था। हम श्री मावलंकर को भी आश्वासन देना चाहते हैं कि इस प्रकार हमारा उनके चरित्र या सत्यनिष्ठा पर आक्षेप करने का कोई इरादा नहीं था।

"पेट्रियाट" के सम्पादक के इस स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए मामले को समाप्त समझा जाना चाहिए।

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

रक्षा सेवाएं प्राक्कलन, 1974-75

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं श्री यशवंतराय चव्हाण की ओर से वर्ष 1974-75 के लिए रक्षा सेवाएं प्राक्कलन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल टी० 6429/74]

मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन, वर्ष 1972-73 के लिए रेलवे के विनियोग लेखे आदि और सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं।

(1) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत भारत के नियन्त्रक और महालेखा-परीक्षक के वर्ष 1972–73 के संबंध में प्रतिवेदन––केन्द्रीय सरकार (रेल)–– की एक प्रति।

(2) वर्ष 1972–73 के लिए विनियोग लेखे, रेल––भाग-1––समीक्षा––की एक प्रति।

(3) वर्ष 1972–73 के लिये विनियोग लेखे, रेल, भाग-2––विस्तृत विनियोग लेखे––की एक प्रति।

(4) वर्ष 1972–73 के लिए रेल के ब्लाक लेखे (जिसमें ऋण लेखे समेत पूंजी विवरण शामिल हैं), संतुलन पत्र और लाभ तथा हानि लेखे, की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी०–6430/74]

(5) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 29 के अन्तर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम के 31 मार्च, 1973 तक 9वें मूल्यांकन प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 6431/74]

(6) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत आय-कर (संशोधन) नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 28 फरवरी, 1974 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 128 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 6432/74]

(7) दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में यथा प्रवृत्त बंगाल वित्त (विक्रय कर) अधिनियम, 1941 की धारा 26 की उपधारा (4) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एफ० 4 (18)/73/-फिन (जनरल) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिल्ली राजपत्र दिनांक 21 फरवरी, 1974 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें अधिसूचना संख्या एफ––4(18)/73/-फिन (जी), दिनांक 6 दिसम्बर, 1973 का शुद्धिपत्र दिया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 6433/74]

(8) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 98(ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो भारत के राजपत्र दिनांक 1 मार्च, 1974 को प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० सां० नि० 113(ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो भारत के राजपत्र दिनांक 1 मार्च, 1974 को प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० सां० नि० 239 (हिन्दी संस्करण) जो भारत के राजपत्र दिनांक 2 मार्च, 1974 में प्रकाशित हुए थे, तथा जिसमें अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 29(ङ) दिनांक 2 फरवरी, 1974 के हिन्दी संस्करण का शुद्धि-पत्र दिया गया है।

[ग्रंथालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी० 6434/74]

(9) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 204 जो भारत के राजपत्र दिनांक 23 फरवरी, 1974 को प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० सां० नि० 53 (ङ) से 65 (ङ), 67 (ङ), 68 (ङ), 70 (ङ), से 72 (ङ), 74 (ङ) से 77 (ङ), 79 (ङ) से 92 (ङ), 95 (ङ) और 96 (ङ) जो भारत के राजपत्र दिनांक 1 मार्च, 1974 को प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० सां० नि० 238 जो भारत के राजपत्र दिनांक 2 मार्च, 1974 को प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रख गये देखिये संख्या एल० टी० 6435/74]

कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पत्र

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : मैं ओ० ए० सी० जार्ज की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों **(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)** की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय परियोजना और उपकरण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1972–73 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) भारतीय परियोजना और उपकरण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1972–73 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी० 6436/74]

———

राज्य सभा से संदेश

MESSASE FROM RAJYA SABHA

महासचिव : मैं राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त इस संदेश की सूचना देता हूं कि राज्य सभा 12 मार्च, 1974 की अपनी बैठक में एस्सो (भारत में उपक्रमों का अर्जन), विधेयक, 1974 से, जो लोक-सभा द्वारा 5 मार्च, 1974 को हुई अपनी बैठक में पास किया गया था, बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

98वां प्रतिवेदन

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 1970–71 के प्रतिवेदन केन्द्रीय सरकार (सिविल), उत्पाद-शुल्क से संबंधित राजस्व प्राप्तियों के संबंध में लोक लेखा समिति के 90 वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का 98वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सूती कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा सूती धागे के निर्यात पर लगाई गई लेवी के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : LEVY IMPOSED BY COTTON TEXTILES EXPORT PROMOTION COUNCIL OF YARN EXPORTS

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : मैं एक वक्तव्य सभा-पटल पर रखता हूं।

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चटोपाध्याय) : अध्यक्ष महोदय, 25–2–1974 को माननीय सदस्य श्री मधु लिमिये ने सूत के निर्यात पर सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा हाल ही में लगाये गये 1 रुपया प्रति किग्रा० के प्रभार का हवाला दिया और इस प्रभार के लगाये जाने के सम्बन्ध में परिषद की सक्षमता पर आपत्ति की। सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (टक्सप्रोसिल) निर्यात संवर्धन अभिकरण के रूप में सरकार द्वारा प्रायोजित और मान्यताप्राप्त निकाय है। परिषद सूती वस्त्रों के निर्यातकों को बाजार-जानकारी देकर और बल्क आर्डरों के सौदे करके उपयोगी सेवा प्रदान करती रही है। परिषद् कोटे वाले देशों को सूती वस्त्रों के निर्यातों का विनियमन भी करती रही है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कोटा निर्धारित स्तर से नहीं बढ़े और अलग-अलग आयातक देशों द्वारा स्वीकृत निर्यात की सीमित मात्रा से ही अधिकतम विदेशी मुद्रा मिल सके। इस बात का श्रेय परिषद को ही है कि पिछले तीन वर्षों में सूती वस्त्रों के निर्यात में भारी वृद्धि हुई है जो निम्न-लिखित आंकड़ों से प्रकट होती है :—

वर्ष	मूल्य (करोड़ रु० में)
1971	110
1972	150
1973	194

जैसाकि माननीय सदस्य को विदित ही है, 1972 में टैक्सप्रोसिल ने सोवियत संघ के मैसर्स एक्सपोर्टल्जोन के साथ संपरिवर्तन सौदा किया था जिसके द्वारा मैसर्स एक्सपोर्टल्जोन द्वारा 20,000 मै० टन रूई सप्लाई की जानी थी और परिषद द्वारा 1270 लाख वर्ग मीटर वस्त्र तथा 44.83 लाख अदद तौलिये सप्लाई किये जाने थे । देश के भीतर रूई और सूती वस्त्र की बाजार स्थिति में परिवर्तन हो जाने से इस संपरिवर्तन सौदे में परिषद को भारी हानि हुई है।

पता चला है कि परिषद् ने उठाई गई हानि को कुछ अंश तक पूरा करने के लिए दिसम्बर, 1973 से निर्यात किये गये सूत पर 1 रु० प्रति किग्रा० का प्रभार लगा दिया है। परिषद द्वारा निर्यातक समुदाय को प्रदान की जा रही सेवाओं और परिषद् की वित्तीय कार्यक्षमता को बनाये रखने की जरूरत को देखते हुए माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि परिषद् द्वारा लगाया गया प्रभार बगैर औचित्य के नहीं है।

माननीय सदस्य ने इस बात का भी उल्लेख किया कि इंडियन काटन मिल्स फैडरेशन आयातित रूई पर प्रीमियम तथा स्पिण्डल लूम लेवी/टर्नओवर लेवी एकत्रित कर रहा है सरकार उद्योग पर जोर डालती रही है कि बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए सूती वस्त्रों के आयात बढ़ाने की आवश्यकता है। 1973 के उत्तरार्द्ध तक हमारे सूती वस्त्रों के आयात कुल मिलाकर अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतियोगी नहीं थे। इस लिए उद्योग के लिए यह आवश्यक समझा गया कि कुछ नकद प्रोत्साहन दे कर सूती वस्त्रों के निर्यातकों को सहायता की जाए। इन प्रोत्साहनों का वित्त-पोषण इंडियन काटन मिल्स फैडरेशन द्वारा बनाई गई निर्यात संवर्धन निधि से किया गया है। इस निधि का सृजन आयातित रूई पर प्रीमियम तथा स्पिण्डल-लूम/टर्नओवर लेवी के रूप में उद्योग से स्वैच्छिक रूप से धन एकत्र करके किया गया है। अध्यक्ष महोदय, आप मुझ से सहमत होंगे कि यदि उद्योग इस निर्यात प्रयास के समर्थन के लिए स्वैच्छिक रूप से धन एकत्रित करता रहा है तो सरकार के लिए इस सम्बन्ध में हस्तक्षेप करने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके अतिरिक्त, मैं यह कहना चाहूंगा कि संदर्भाधीन निर्यात संवर्धन निधि के लेखे का भारत सरकार के वाणिज्य, निर्माण तथा विविध महालेखाकार द्वारा हर वर्ष आडिट किया जाता है । अब तक कोई मुख्य अनियमिततायें नहीं देखी गई हैं। इसके अलावा, निर्यात की विभिन्न वस्तुओं पर प्रोत्साहन की दरें वस्त्र आयुक्त की अध्यक्षता में एक पैनल द्वारा निर्धारित की जाती हैं। इस प्रकार, प्रोत्साहनो की दरें निर्धारित करने में या निर्यात संवर्धन निधि का उपयोग करने में कोई स्वेच्छाचारिता नहीं है।

अन्त में, माननीय सदस्य ने इंडियन काटन मिल्स फैडरेशन द्वारा एकत्रित की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति की उप-समिति द्वारा कुछ वर्ष पूर्व की गई टिप्पणियों का जो उल्लेख किया है उसके सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि मन्त्रालय के तत्कालीन सचिव उप-समिति के सामने उपस्थित हुए थे और उन्होंने बताया था कि स्वैच्छिक रूप से ये धनराशि किस संदर्भ में एकत्रित की जा रही है अर्थात् सूती वस्त्रों के निर्यात बढ़ाने के लिए की जा रही है और उप-समिति का यह समाधान हो गया था कि धनराशि एकत्रित करने का मूलाधार ठीक है।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं घोषणा करता हूं कि सोमवार, 18 मार्च, 1974 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान निम्नलिखित कार्य लिया जायेगा--

(1) वर्ष 1974–75 के लिए बजट (सामान्य) पर आगे सामान्य चर्चा।

(2) वर्ष 1974–75 के लिए लेखानुदानों की मांगों (सामान्य) को सभा में मतदान के लिए पेश किया जाना।

(3) चर्चा तथा मतदान :--

वर्ष 1974–75 के लिए अनुदानों की मांगों (रेल)

वर्ष 1973–74 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगों (रेल)

वर्ष 1971–72 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (रेल)

वर्ष 1973–74 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगों (सामान्य)

(4) वर्ष 1974–75 के लिए गुजरात के बजट पर सामान्य चर्चा।

(5) चर्चा तथा मतदान :--

वर्ष 1974–75 के लिए गुजरात राज्य के सम्बन्ध में लेखनुदानों की मांगें

वर्ष 1973–74 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (गुजरात)।

(6) निम्नलिखित विधेयकों पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) संशोधन विधेयक 1974, उनको पारित करना।

गुजरात राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैंने अपने एक मित्र, श्री गुप्ता के साथ 9345 म० यू० पर संसदीय पत्र भेजे, उन्हें प्रवेश करने से रोक दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मुझे यकीन है।

श्री समर गुह (कन्हाई) : मैंने आपका ध्यान ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा नियम 377 के अन्तर्गत सूचना के माध्यम से पश्चिम बंगाल में चल रही कालेज के अध्यापकों की आम हड़ताल की ओर दिलाना चाहा था। वहां कालेजों में लगभग 500 अध्यापकों को गिरफ्तार कर लिया गया है और सभी कालेज तथा विश्वविद्यालय बंद कर दिए गए हैं।

यह मामला केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित है। पश्चिम बंगाल में चलाये गये आन्दोलन का सम्बन्ध विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मिलते-जुलते अनुदान तथा अन्य अनुदानों से है। शिक्षा मंत्री को वक्तव्य देना चाहिए कि आन्दोलन के कारण क्या हैं तथा क्या वह इस मामले को निपटाने में अपने पद का उपयोग कर सकते हैं।

मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह वक्तव्य दें और यदि संभव हो तो कलकत्ता जाकर कालेजों के अध्यापकों के साथ वार्तालाप करके मामले को निपटायें।

जब स्वर्गीय श्री मोहन कुमार मंगलम इस्पात मंत्री थे तब उन्होंने दुर्गापुर मिश्र इस्पात संयंत्र के विस्तार के बारे में सभा में आश्वासन दिया था। आज दुर्गापुर मिश्र इस्पात संयंत्र के सैंकड़ों कर्मचारी बोट-क्लब पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उस आश्वासन के बारे में अभी तक कुछ नहीं किया गया है। जिसके परिणामस्वरूप रोजगार की स्थिति बिगड़ रही है और उत्पादन सम्बन्धी समस्याएं बढ़ रही हैं। अतः मैं नये इस्पात और खान मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें।

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : The Higher Secondary School Teachers are staging *Dharna* from 7·00 A. M. to 7·00 P. M. to-day. Their only demand is that education should be included in Concurrent List and essential commodities supplied to them at subsidised rates, D.A. equal to others should be given and all the private schools nationalised.

The Government should be asked to come out with a statement in this regard.

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : Everybody should be given equal opportunity in respect of recruitment in military services. Preference should not be given to a particular region or a particular community. The Government should give a statement in this regard.

The Members of the U. P. S. C. recruit their own men.

Prices of oil have gone up considerably. I request the Minister of Parliamentary Affairs to make some arrangement thereby all the hon. Ministers are available in their rooms at a certain time so that we are able to apprise them of our grievances.

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : अहमदाबाद तथा गुजरात में हालत और बिगड़ती जा रही है और कल चार व्यक्तियों को गोली के कारण मृत्यु हो गई। 168 विधायकों ने त्याग-पत्र दे दिये हैं।

कांग्रेस (संगठन) के नेता श्री मोरारजी भाई देसाई गत चार दिन से अनशन कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री स्थिति स्पष्ट करते हुए वक्तव्य दें।

गत सप्ताह मैंने आपके माध्यम से यह कहा था कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना पर इस संसद ने विचार-विमर्श नहीं किया है। इस सप्ताह मंत्री महोदय ने मुझे बताया कि पांचवीं योजना अभी तक तैयार नहीं हुई है और गत सप्ताह संसदीय कार्य-मंत्री ने मुझे बताया कि वह एक वक्तव्य देंगे परन्तु अभी तक वक्तव्य नहीं दिया गया है।

मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय और सरकार शीघ्र कार्यवाही करें तथा विधान-सभा को भंग करें ताकि और रक्तपात को रोका जा सके।

श्री एस० एम० बैनर्जी : मैं आपकी अनुमति से दो बातें उठाना चाहता हूं। एक, मैं श्री रामावतार शास्त्री की मांग का समर्थन करता हूं कि हायर सैकेंडरी स्कूल के अध्यापकों की मांगों के बारे में शिक्षा मंत्री वक्तव्य दें।

दूसरे, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि श्री के० आर० गणेश यहां हैं। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दो अतिरिक्त महंगाई भत्ते देने का निर्णय तो सरकार ने कर लिया है परन्तु अभी तक आदेश जारी नहीं किये गये हैं। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह श्री चव्हाण से अनुरोध करें कि वह एक वक्तव्य आगे विलम्ब किये बिना दें।

गार्डों द्वारा नियमानुसार काम करने के आन्दोलन के सम्बन्ध में मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह गार्डों की मांगों के बारे में एक वक्तव्य दें।

शहडोल, मध्य प्रदेश स्थित कोयला खान प्राधिकार लिमिटेड के पश्चिमी डिविजन के बुरहार संख्या 1 में हुई दुर्घटना के फलस्वरूप 7 कोयलाखान कर्मकारों की मृत्यु के बारे में वक्तव्य

STATEMENT V E. DEAHTS OF SEVEN COAL MINERS IN AN ACCIDENT AT BURHAR NO. 1 MINE OF COAL MINES AUTHORITY LTD. IN SHAHDOL, M.P,

इस्पात तथा खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : मुझे सदन को यह सूचित करते हुए खेद है कि मध्य प्रदेश के शाहडोल जिले में स्थित कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड की बुरहार खान संख्या 1 में 11 मार्च, 1974 को सायं 5.45 बजे एक गम्भीर दुर्घटना हुई। इस दुर्घटना में 11 भूमिगत मजदूर फंसे थे, जिस में से 7 मजदूर मर गए तथा शेष 4 को मालूली चोटें आईं। यह दुर्घटना स्तम्भ रहित खण्ड में छत गिरने के कारण हुई। गिरे हुए छत का कुल क्षेत्र लगभग 15′×20′ तथा मोटाई 1-1/2′ थी।

2. नागपुर क्षेत्र के खान सुरक्षा निदेशक इस दुर्घटना की पहले ही जांच कर चुके हैं और उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। कोयला खान प्राधिकरण के पश्चिमी प्रभाग के प्रबन्ध निदेशक, जिन्होंने दुर्घटना के तुरन्त बाद घटना-स्थल का मुआयना किया था, ने सूचना दी है कि दुर्घटना के समय खान में पूरा पर्यवेक्षक स्टाफ था और वहां खान विभाग द्वारा अनुमोदित तरीकों के दृढ़ अनुपालन के अनुसार ही काम चल रहा था।

3. मृत व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को तदर्थ मुआवजे के रूप में 1,000 रुपये की राशि पहले ही दी जा चुकी है और उन्हें यह आश्वासन भी दिया गया है कि मृत व्यक्तियों के पुत्रों को नौकरियां भी दी जायेंगी। घायल व्यक्तियों को उनकी चोटों की स्थिति को देखते हुए, हल्के काम पर लगाया जाएगा।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : The accident took place on the 11th and it is 15th I want to know as to when did the hon. Minister receive information ?

The Minister of Steel and Mines (Shri K. D. Malviya) : I received the information yesterday in the evening and to-day I have presented it.

सामान्य बजट 1974–75—सामान्य चर्चा

GENERAL BUDGET 1974-75 GENERAL DISCUSSION

Shri Mulki Raj Saini (Dehradun) : This Budget is not socialistic nor it can be taken as welfare budget to some extent.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

[Mr. Deputy-Speaker in the Chair.]

The budget of the country does not provide any solution to the situation of scarcity. Inflation is there in the country. Although the deficit shown in the budget is only of Rs. 125 crores, there are apprehensions that this deficit will go up to Rs. 1000 crores. When there is deficit, taxes are imposed and the worst hit is the common man.

23 crores of persons in the country are living below the poverty line. There is no plan for them nor there is any provision in this budget for their problems. The Government should consider it seriously.

Unemployment is increasing. The Government should pay attention to this situation.

The gulf between the poor and the rich is widening. This gulf should be bridged up.

There are no well-defined nations policies to check inflation, to remove unemployment an to propagate education.

The Income-tax limit has been raised to six thousand rupees. It has been reduced to 77 per cent in case of big tax-payers. It is reported that the vested interests will invest some money in developmental works. The idea appears to be good but what will be its result—only the future will tell it.

Emphasis has been laid on the indirect taxes in this budget. I think the emphasis should have been given on the direct taxes.

The taxes imposed on post-card, tooth-paste, soap etc. are a burden to common man. Taxes should always be imposed on luxury goods.

The proposals to increase production in various fields of the budget are welcome.

The Government should be vigilant about increasing production in the industries because a conspiracy is being hatched in our country to flout the efforts of the Government and to disrupt the transport system.

A very wrong tradition is continuing. The Railways is the largest public sector industry but whenever there is deficit in the Railways, it is met from the General Budget. This tendency is not good for the economy of the country.

There are certain sections of the society who manage to send their words to the public schools while others are not able to do this. The sections, educationally backward, are not able to seek employment.

I am giving a suggestion to solve the unemployment problem. The villages should be connected with the cities by roads. The employees will be able to reach their offices by bus, taxi or cycle. They will not have to settle at two places. They will live in villages and develop their villages. Also, the Housing problem will be solved.

Shri Attal Bihari Vajpayee (Gwalior) : If we look into the backgrounds of the budgets presented so far, I shall have to say with regret that our development has not only come to a standstill but we are lagging behind in certain fields. The national progress has deteriorated and the value of rupee has come down. Per capita income has dwindled and even the per capita consumption of the essential commodities has also come down.

Social imbalance is on increase. Agricultural labour is increasing fast. In U. P. there were 22 lakh agricultural labour in 1951. This number has gone up to 52 lakh in 1971. The marginal farmers are not able to live on agriculture. They are turning labourers.

The Minister of Finance has stated about self-sufficiency. I agree that self sufficiency is our national aim but when the report of the World Bank comes and highlights our dependence on foreign countries, our national pride is hurt. Foreign aid to India is likely to amount to Rs. 1,200 crores. We are taking oil, fertilizers, news-print from Soviet Union. What will be their prices as compared to the International rates. This House should be taken into confidence in this regard. Dependence is perilous, be it in the reference of the U.S.A. or the U.S.S.R. Aid is never without strings.

Inspite of the desirability of stability in prices, the fact that tax proposals would lead to further price rise can not be denied. The hon. Minister of Finance is in a fix. The actual financial conditions of the country demand that he should take positive steps to increase production and investment in various industries. The steps taken by him regarding reduction in income tax and development rebate are conducing to stock exchange.

Even the Governments having faith in capitalism have changed their attitude. It is the first and foremost duty of a Government, whether having capitalistic approach or socialistic apporach, to meet minimum requirements of the people. It has been observed that in certain countries socialistic Governments having facing defeat because of the fact that people have realised that this system of Government make people uninspired, inactive and dependent.

The present Government want to solve economic problems politically. This is a defective approach. It is quite strange that 14 nationalised banks could not maintain their rates of profitability. I remember the statement given by Shri Jagjiwan Ram in Muradabad in regard to admitting the defeat of vary purpose of bank nationalisation. Apart from the drastic reduction in the profitability some of the nationalised banks are facing economic crisis. Various types of malpractices are being committed so far as the deposit targets and advances are concerned. Black money is being converted into white money with the help of their banks by the people. These banks should not be allowed to exercise such ierrgularities. If hon. Minister desires I would give him more information in this regard. It does not mean that we want to give back nationalised banks to the private sector. No party would like it. No doubt in certain fields these banks have started advancing loans for development purposes. But it is also necessary for the Government to do away with all the irregularities which are being committed in the banks.

Increase in bank credit both to the Government and the big business houses has caused inflation resulting in adverse effect on our economy. I would like to state that while calculating the amount of deficit Government have not taken into consideration the amount of net credit. The Government have estimated that the amount of deficit is Rs. 125 crores which is not correct. The amount of deficit will certainly increase in view of the fact that Government will have to offer increased prices of agricultural products. Agricultural price Commission have agreed to give increased prices of foodgrains to the farmers. State Governments have also suggested that higher price should be given to the farmers for their produce. I hope that a common price policy would be formulated in the Chief Ministers' Conference.

So far as the levy is concerned I think no body is opposed to it. It has been observe that big farmers evade levy with the help of officers. I would like to suggest that Government should evolve a National Food Policy so that farmers could get due prices of their products and the foodgrains can be distributed to the consumers at reasonable rates.

We were opposed to the restriction on inter state movement of foodgrains because that leads to artificial scarcity and corruption. Therefore while taking any steps towards imposition of control they should think over the consequences seriously on the basis of the actual and practical position of our economy. There is a great need of changes in our economic structure. Disparities must be minimised. The Government should evolve some practical measures to bring healthier change.

It has also been observed that State Governments are preparing deficit budgets. They are also not following the rules laid down by Reserve Bank of India regarding overdrafts. I suggest that the hon. Minister should issue certain instructions to the effect that they should prepare their development plans according to their own resources.

As compared to the last year, the allocation for agriculture is less by one crore rupees. The allocations for water, power and drought affected areas have also been reduced. The schemes for providing employment in rural areas have not been implemented. Even the minimum needs programme in the rural areas has been suspended. On the one hand the allocations for social and community development services have been reduced, and on the other hand, the allocation for C.R.P. has been increased from Rs. 7 crores to Rs. 40 crores.

The price of post card has been increased by 50 per cent, though the price of the envelope has not been increased equally. This is quite objectionable. This proposal should be withdrawn.

The minimum limit of exemption from income tax has been raised to Rs. 6000/-, which should have been increased to Rs. 7500/-. If the increase in prices is taken into consideration, this exemption should have been fixed at Rs. 10000/-.

The reduction in income tax has not provided uniform benefit at each level. The persons in the middle income group have not been given that much of exemption as the people in the upper income groups have been given. It is unfair.

Fourthly, the Government should decide and declare that they would not allow the money supply to be increased by more than 5 per cent in a year, as recommended by the economists. There should not be uncontrolled expansion of currency as it would simply lead the economy to ruination.

Finally, the Government should reduce the public expenditure also. If unproductive expenditure is reduced and an atmosphere of austerity is created, we might be able to tide over the present economic crisis.

Shri Nathu Ram Mirdha (Nagaur) : Today our country is facing many problems. There is shortage of all the commodities in our country and the money supply has also increased. The agricultural production has declined during the last two years. This year it has improved a little and there is hope of further improvement in future. More funds should have been allotted during the first year of the Fifth Plan for agriculture and agricultural programmes. Inspite of the fact that sufficient funds were allotted for power and fertilisers in the Plan, the target of production in both the sectors could not be achieved. Government should give thought to it.

In the Fifth Five Year Plan, the annual growth rate has been fixed at 4·7 per cent only. This is not enough. It should be raised and efforts should be made to achieve the fixed targets. It is more important that the Plan schemes are implemented and, therefore, the Government should ensure their implementation.

The Raj Committee has submitted a report in regard to agricultural income. The recommendations of this Committee are absolutely impracticable. I would suggest that tax should be levied only on those who have got the capacity to pay. Itwould be a great injustice if every poor farmer is taxed. The Government should not to put such burdens on poor farmers.

Although Government has agreed to raise the procurement price, yet it should be raised still further to give a remunerative price to the producers. The price of the post card has been increased by 50 per cent which should be withdrawn.

I would request the Hon'ble Minister to be courageous and take bold decisions and implement them with strictness.

Shri Swami Brahmanandji (Hamirpur) : I support this Budget as this is in accordance with the party's principles to which I belong.

Our present Constitution needs drastic changes. Unless our Constitution is thoroughly amended, the present structure of the society cannot be changed. The present system of justice is very costly and time consuming. The common man is unable to get justice. I would suggest that the power of the dispensing justice should be delegated to the village panchayats. The Legislatures should act as high courts and Parliament should act as Supreme Court so that the costly system of justice should be done away with.

There is corruption, inefficiency and nepotism amongst the Government employees. The Government should see that the functioning of the Government machinery is streamlined. The present system of education should be changed.

We all should work hard so that we may increase production. At present juncture hard work is needed to increase production. If we follow Gandhian policies, all our problems would be solved.

All the acts of violence should be stopped, as these would not solve the problems faced by our country.

श्री जी० विश्वनाथन (वाण्डीवारा) : चार पंच वर्षीय योजनाओं को कार्यान्वित करके और 50,000 करोड़ रुपये से अधिक राशि खर्च करके, गत 20 या 25 वर्षों में हमने कोई विशेष प्रगति नहीं की है। देश में सभी वस्तुओं के मूल्यों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है मूल्यों का सामान्य सूचकांक जो 1955 में 71.1 था, वह जुलाई 1973 में बढ़कर 248.8 हो गया। अब चालू वर्ष में यह 45.9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रहा है। 26 वर्षों तक शासन करने के पश्चात्, सरकार की यही उपलब्धि है।

सरकार ने हमें बताया था कि इस बजट के पश्चात् मूल्यों में सीमान्त वृद्धि होगी, किन्तु ऐसा नहीं हुआ। भारतीय उपभोक्ता परिषद् द्वारा किये गये सर्वेक्षण से पता चलता है कि मूल्य-वृद्धि का कराधान से कोई सम्बन्ध नहीं है। बजट के पश्चात् अधिकतर उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य 20 से 60 प्रतिशत बढ़े हैं। हम बताया जाना चाहिए कि सरकार ने मूल्यों और मुद्रा-स्फीति को नियंत्रित करने के लिए क्या किया है?

पिछले वर्ष सरकार ने 87 करोड़ रूपये के घाटे का बजट पेश किया था, किन्तु वास्तव में यह घाटा बढ़कर 650 करोड़ रूपये हो गया। वर्ष 1970–71 और 1973 के बीच मुद्रा के प्रचलन में 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि उत्पादन 5 प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ा। इसकी जिम्मेदारी सरकार को अपने ऊपर लेनी चाहिये। वित्त मंत्री महोदय को अर्थशास्त्रियों के परामर्श पर ध्यान देना चाहिए और सभा को यह आश्वासन देना चाहिए कि घाटे की अर्थव्यवस्था को 125 करोड़ रुपये से बढ़ाया नहीं जायेगा।

सरकार ने सोचा था कि ऋण पर नियंत्रण लागू करने से मुद्रास्फीति पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, किन्तु इस नीति के कारण छोटे उद्योगों के लिए बड़ी कठिनाई पैदा हो गई है। मैं अनुरोध करता हूं कि सरकार लघु उद्योगों पर इस नीति को लागू न करे। इससे अधिक रोजगार पैदा होने की बजाये अधिक बेरोजगारी पैदा हो रही है। सेलम इस्पात संयंत्र के लिये 15 करोड़ रुपये के परिव्यय का अनुमान लगाया गया था, परन्तु इसे कम करके 3 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस कारण हम संयंत्र पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और लगभग 7500 लोग बेरोजगार हो जायेंगे। तमिलनाडू के लोग तथा सरकार इस सम्बन्ध में बहुत ही चिन्ति तथा उत्तेजित हैं। सरकार को चाहिए कि वह इस पर पुनः विचार करे और मूल परिव्यय के अनुसार ही धन का नियतन करे।

जहां तक पूंजी निवेश तथा आय का संबंध है, आजकल इस देश में आर्थिक नीतियों का बिल्कुल ही पालन नहीं किया जा रहा है। यदि हम तीव्र गति से पूंजी का निवेश करते हैं, तो इसका अभिप्राय यह है कि हमारी प्रति व्यक्ति आय अधिक होनी चाहिए। वास्तव में हम खर्च तो अधिक कर रहे हैं, किन्तु प्रतिव्यक्ति आय इस खर्च के अनुसार नहीं बढ़ यही है। 1971 में समाप्त होने वाले पिछले दो दशकों में जापान की प्रति व्यक्ति आय 10.2 गुना बड़ी है। ताइवान में यह साढ़े तीन गुना बढ़ी है। थाईलैण्ड में यह वृद्धि 93 प्रतिशत की हुई है। परन्तु भारत में 1960–71 में यह वृद्धि 1.2 प्रतिशत हुई है। यह इस सरकार की बड़ी उपलब्धि है।

अमीर और गरीब के बीच तथा नगरीय और ग्राम्य क्षेत्रों के बीच आय में बड़ी असमानता पाई जाती है। इस असमानता को दूर किया जाना चाहिए।

कृषि की पूर्णतः उपेक्षा की गई है। किसानों को कीटनाशक दवाइयां और उर्वरक उपलब्ध नहीं कराये जाते। उर्वरक, कीट नाशक दवाइयों और बीजों की पर्याप्त उपलब्धता के बिना हम आने वाले अनेक वर्षों तक खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर नहीं हो सकते।

काला धन और लाल धन देश की तबाही का कारण बन रहा है। लाल धन बाहर से आता है और काला धन देश में ही बनता है। सरकार को चाहिये कि वह काले धन का पता लगाये और लाल धन को देश में आने से रोके, अन्यथा देश की अर्थव्यवस्था नष्ट हो जायेगी।

हम लोगों पर अधिक अप्रत्यक्ष कर लगाये जा रहे हैं। यह कराधान के सभी सिद्धान्तों के विरुद्ध है। वित्त मंत्री महोदय को चाहिए कि वह उन अप्रत्यक्ष करों को कम कर दें जो जन साधरण और मध्यम वर्ग के लोगों पर सीधा प्रभाव डालते हैं।

सरकार को एक राष्ट्रीय आर्थिक परिषद् का गठन करना चाहिए, जिसमें उन सभी समस्याओं के बारे में, जिनका देश सामना कर रहा है, प्रमुख अर्थशास्त्रियों से परामर्श किया जाय और उनकी सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया जाये।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट पेश किया है, वह वास्तविक और साहसपूर्ण बजट है। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति पर उस के सामर्थ्य के अनुपात से कर लगाया है। इसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होने रक्षा के लिए बजट के प्रावधान को बढ़ाकर सराहनीय काम किया है। गत चार वर्षों से हमें बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं का शिकार होना पड़ रहा है। हमें शरणार्थियों की समस्या का तथा आखिर में एक युद्ध का भी सामना करना पड़ा, जिसके कारण हमारी अर्थ-व्यवस्था पर बड़ा दबाव पड़ा।

****उपाध्यक्ष महोदय** : आप मित्र देशों का इस प्रकार उल्लेख क्यों कर रहे हैं इसका बजट के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : जहां हमें तेल के लिए 200 करोड़ रुपया देना पड़ता था, वहां अब हमें 1,000 करोड़ रुपया देना पड़ेगा।

गत 4 वर्षों में कृषि का उत्पादन केवल 1.5 प्रतिशत बढ़ा है, जबकि जनसंख्या में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह बात देश के लिए बहुत ही हानिकारक है। जनसंख्या 130 लाख प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है।

मुझे यह मालूम नहीं है कि परिवार नियोजन के लिए पर्याप्त धनराशि नियतन किया गया या नहीं। मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे देश का केवल एक वर्ग ही परिवार नियोजन कर रहा है और कुछ समुदाय इस पर बिल्कुल अमल नहीं कर रहे हैं। समुदायों के बीच इस बात के लिए प्रतिद्वंद्व चल रहा है, ताकि वे अपनी संख्या को बढ़ा सकें।

विकसित देशों में 150 वर्ष में आबादी दुगनी होती है, जबकि हमारे देश में 25 साल में आबादी दो गुनी हो जाती है। पहले प्रति व्यक्ति और भूमि का अनुपात $1\frac{1}{2}$ एकड़ था, जो अब घटकर $\frac{3}{4}$ एकड़ प्रति व्यक्ति रह गया है।

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

**Expunged as orderd by the Chair.

इसलिए सरकार का मुख्य लक्ष्य परिवार नियोजन होना चाहिए और परिवार नियोजन प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य बनाया जाए। दो बच्चों से अधिक सन्तान जिस व्यक्ति के हों, उसे दो से अधिक बच्चों के लिए कोई सरकारी सुविधा न दी जाए। ऐसा किए बिना देश के भविष्य का निर्माण नहीं हो सकता।

देश में चीनी के कुल 45 लाख टन उत्पादन में से 10 लाख टन चीनी का निर्यात किया जाना चाहिए, तभी हम विदेशी मुद्रा की आवश्यकता की पूर्ति कर सकेंगे। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें हर सम्भव प्रयत्न करना चाहिए। हमें विदेशों से अधिक मात्रा में उर्वरक आयात करना चाहिए, तभी हम कृषि उत्पादन में वृद्धि कर सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नियम 41 (xix) का उल्लेख करना चाहता हूं, जिसके अनुसार मित्र राष्ट्र के प्रति अशिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता, अत: श्री रेड्डी द्वारा अरब राष्ट्रों के प्रति कहे गए शब्दों को कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

श्री के० बालकृष्णन (अम्बलपुजा) : बजट प्रस्ताव निरर्थक हैं, क्योंकि यह किसी को भी नहीं पता कि इनका वास्तविक स्वरूप क्या होगा। कुछ राशि की घाटे की अर्थ-व्यवस्था का इस बजट में प्रावधान किया गया है, परन्तु पिछले वर्ष के अनुभव से पता चलता है कि जितने घाटे की अर्थ-व्यवस्था का इस बजट में प्रावधान रखा गया है, उससे कई गुना घाटे की अर्थ-व्यवस्था करनी होगी। प्रस्तावों और वास्तविक आंकड़ों के इस अन्तर से स्पष्ट पता चलता है कि सरकार के कार्यकरण में मूलभूत कमियां हैं। यह बजट यथार्थ को प्रतिबिम्बित नहीं करता, क्योंकि इसमें जीवन की आर्थिक प्रक्रियाओं के घटना चक्र का ध्यान नहीं रखा गया है।

सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने अपने भाषण की शुरूआत यह कहकर की है "मैं बजट का समर्थन करता हूं," परन्तु सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों ने भी बजट प्रस्तावों की किसी न किसी दृष्टि से कटु आलोचना की है।

इस बजट में सरकार ने आत्म समर्पण कर दिया है। बजट तैयार करने से पहले अनेक प्रकार से सरकार पर दबाव डाला जा रहा था। बजट प्रस्ताव पेश किए जाने पर यह देखा गया कि प्रत्यक्ष करों के मामले में काफी राहत दी गई है। उच्च आय-वर्ग को अधिक राहत दी गई है और उन्हें धन-संग्रह करने की छूट दी गई है। कम आय वर्ग की आय में कमी होती जा रही है। अगर यह हालत जारी रही, तो इससे एक ऐसा आर्थिक संकट उत्पन्न होगा जिसे यह सरकार और सभी संसद सदस्य मिलकर भी नहीं संभाल पाएंगे।

Shri Satpal Kapur (Patiala) : I would like to say first of all that a serious discussion has not taken place about the problems facing the country. The real problem at present in the country is the crisis of production.

The policy of take over of whole sale trade in wheat is not bad in itself, but the targets could not be achieved, as the persons responsible for the implementation of the policy did not have political will and administrative capacity to do so. There was corruption at lower level also. My submission is that this policy of take over of whole sale trade must be continued.

The problems of agriculture in the country could not be solved, until the Government considers agriculture as an Industry. The prices of agriculture produce must be linked up with the prices of agricultural inputs.

A large amount of Hydro-electric power could be derived, if dams are constructed on the rivers. The central Government should resolve the inter-state disputes expeditiously. All the

major irrigation projects should be constructed by the Central Government, as the entire money has to be spent by the Centre. There is no dispute about the construction of projects. The dispute regarding distribution of water could be resolved later on. If the inter-state water dispute are not resolved, the agricultural production cannot increase.

The Government had taken 100 crores of rupees from Pakistan, but free water is being supplied to Pakistan for the last three years. The disputes between Punjab, Haryana and Himachal Pradesh have not been resolved.

There is very much overlapping of work in our offices. The role of Finance Ministry needs to be revised. When Ministry of Finance has allocated certain amount for a particular Ministry, the file should not go to the Finance Ministry once again.

The new I.A.S. and I.P.S. Officers from among the Hippy boys are sent to the rural areas as Deputy Commissioners, who are totally ignorant of the agricultural problems. It is necessary to change the examination system of Public Service Commission. Twenty five per cent seats in I.A.S. might be reserved for the persons living in rural areas.

The levy on cutting tool industry, which comes under the Small Sector may be withdrawn. The newly-imposed tax on Soda-water factories, running on half horse power motor may also be withdrawn.

It is very unfortunate that about eight per cent of our national income is being spent on our public sector units instead of 11·3 per cent. The investment on public sector units should not be reduced.

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बधी समिति

37वां प्रतिवेदन

COMMITTEE ON PUBLIC MEMBER'S BILLS AND RESOLUTIONS—37th Report

श्री अमरनाथ चावला : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 37वें प्रति वेदन से, जो 13 मार्च, 1974 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत हैं।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

" कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पो सम्बन्धी समिति के 37वें प्रति वेदन से जो 13 मार्च, 1974 को सभा में प्रस्तुत किया गया था सहमत है "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष चुनावों के बारे में संकल्प

Resolution Re Free and Fair Elections

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रस्ताव के लिए मूलत: दो घण्टे का समय निर्धारित किया गया था । बाद में एक घण्टा समय बढ़ा दिया गया था । अब केवल 25 मिनट बचे हैं ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के चुनावों के अनुभवों को देखते हुए समय में वृद्धि की जानी चाहिए ।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : इस महत्वपूर्ण संकल्प पर चर्चा के लिए समय में वृद्धि की जानी चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : कितनी वृद्धि की जाए ।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : दो घण्टे समय बढ़ा दिया जाए ।

श्री के० रघुरामैया : ठीक है ।

उपाध्यक्ष महोदय : दो घण्टे के लिए समय में वृद्धि की जाती है । श्री समर गुह अपना भाषण जारी रखें ।

श्री समर गुह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार मैंने गायघाटा चुनावों की धांधली का मामला उठाया था । मैंने सदन को यह भी बताया था कि मैंने राष्ट्रपति और मुख्य चुनाव आयुक्त को भी अभ्यावेदन भेजे थे ।

[**डा० हेनरी आस्टिन** पीठासीन हुए]

[DR. HENRY AUSTIN *in the Chair*]

लोक सभा सचिवालय और विधि, न्याय और कम्पनी कार्य-मंत्रालय से मुझे एक नोट मिला है, जिसमें 11 चुनाव बूथों पर जबरदस्ती कब्जा किए जाने की बात स्वीकार की गई है। इस नोट के अनुसार सशस्त्र लोगों ने मतदान अधिकारी से जबरदस्ती मत छीन कर मतपेटियों में डाले। इस वजह से मतदान केन्द्रों पर मतदान स्थगित कर दिया गया । आगे नोट में यह भी कहा गया है कि इन सशस्त्र-लोगों के बारे में यह पता नहीं है कि वे किस राजनैतिक पार्टी के थे । मुख्य चुनाव आयुक्त ने राज्य के चुनाव आयुक्त से पांच मुद्दों पर जांच करने के लिए कहा है, जिनमें एक मुद्दा यह है कि इन ग्यारह मतदान केन्द्रों पर कितनी पुलिस तैनात थी और बदमाशों द्वारा बल-प्रयोग को रोकने के लिए पहले से कार्यवाही क्यों नहीं की गई । आश्चर्य की बात तो यह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त राज्य के चुनाव आयुक्त से जांच करके 15 मार्च से पहले रिपोर्ट देने के लिए कहा है, परन्तु गायघाटा निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव परिणाम पहले ही घोषित कर दिया गया है ।

इस सदन में मेरे कुछ मित्रों ने 1972 में पश्चिम बंगाल में चुनावों की गड़बड़ी की बात कही थी, उस समय जनता विभिन्न प्रकार की हिंसक गतिविधियों के कारण इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थी। अब लोगों को पता चल गया है कि चुनावों की धांधली का क्या अर्थ होता है । अब सत्तारूढ़ पार्टी उप चुनावों में भी धांधली करके विरोधी पार्टियों को हरा सकती है । पश्चिम बंगाल की कांग्रेस पार्टी भी दो गुटों में विभाजित है, जिनमें से एक गुट में समाज विरोधी तत्व है। कांग्रेस के दो गुटों के झगड़े के कारण ही गायघाटा के उप चुनाव में निर्वाचित विधायक श्री चांदी मित्रा हिंसक झगड़े के शिकार हो गए । अगर पश्चिम बंगाल में ऐसी स्थिति जारी रही, तो यदुवंश की तरह कांग्रेस पार्टी भी समाप्त होने वाली है ।]

मैं इस सामयिक प्रस्ताव को पेश करने के लिए श्री अटल बिहारी बाजपेयी को बधाई देना चाहता हूं । देश में यह एक धारणा बन गई है कि देश में निष्पक्ष, उचित और शान्तिपूर्ण ढंग से चुनाव नहीं हो सकते। अब चुनावों में धन, सत्ता और प्रशासनिक मशीनरी का बोलबाला है ।

लोक सभा और विधान सभा के चुनावों पर होने वाले व्यय की एक सीमा निर्धारित है। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मणिपुर, पाण्डिचेरी के आम चुनावों और अन्य उप-चुनावों में कांग्रेस उम्मीदवारों के चुनावों के दौरान कितना धन खर्च किया गया ।

सरकार के पास राजनैतिक शक्ति ही नहीं, बल्कि आर्थिक शक्ति भी है। इसी लिए सरकारी पार्टी विरोधी पार्टियों की अपेक्षा सैकड़ों गुना और हजारों गुना अधिक धन व्यय करने की स्थिति में है ।

लोगों में यह भावना है कि कांग्रेस पार्टी को जनता का प्रबल बहुमत मिला हुआ है और वह देश का शासन चला रही है। पिछले 25 वर्षों के चुनाव परिणामों से यह पता चलता है कि लोक सभा अथवा विधान सभा के चुनावों में कभी भी कांग्रेस पार्टी को 50 प्रतिशत वोट भी नहीं मिल सके। यह सरकार का भ्रम है कि जनता का बहुमत उसके साथ है। जनता का अल्पमत ही सरकार के साथ है और देश की हिंसा, आन्दोलनों और अव्यवस्था का यही कारण है।

चुनाव के सिद्धान्तों, चुनाव-पद्धति और समानुपातिक प्रतिनिधित्व आदि की जांच करने के लिए एक उच्चाधिकार-प्राप्त आयोग की नियुक्ति की जानी चाहिए। समानुपातिक प्रतिनिधित्व के कारण पार्टियों की संख्या में वृद्धि होती है। इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि क्या मध्य विक्टोरिया युग का लोकतन्त्र हमारी समाज-व्यवस्था के अनुरूप है या इसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए।

आज यह कहा जाता है कि देश की स्थिरता का मतलब है कांग्रेस शासन की स्थिरता। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर चुनाव के ढांचे और चुनाव-प्रणाली में परिवर्तन नहीं किया गया, तो देश के लोकतन्त्र का भविष्य अन्धकारमय है। पंचायती राज के आधार पर नए लोक तन्त्र का ढांचा बनाया जाना चाहिए।

Shri Narsingh Narain Pandey (Gorakhpur) : We should discuss this motion without going into party politics and should try to find out ways and means to strengthen democratic systems.

It has been mentioned in the motion that democratic system should be protected and free and fair elections should be held. Under the present system, only the rich could contest the elections and the poor, who might be having patriotic feelings could not contest any election for wan of funds.

The corrupt practices have been explained in detail in the Representation of People's Act. It seems that the mover of the motion wants that the role of money in elections must be minimised. I would like to ask the mover of the motion whether he himself of his party has acted according to the section 121 of the Representation of the People's Act.

Shri Vajpayee perhaps forgot that his own party violated the provisions of the Representation of the People's Act. The District Magistrate of Gorakhpur convened a meeting on castes basis in support of a candidate of Shri Vajpayee's party.

Shri Phool Chand Verma (Ujjain) : 40 Russian girls were propagating in support of Congress in Hardwar and Rishikesh on the plea that if Russia would not have given wheat to India, the people would have been starved. The Congress Party has misused the Official machinery.

Shri Narsingh Narain Pandey : The District Magistrate of one particular caste had convened a meeting of the people belonging to a particular caste. These 24,000 people were secular in their ideas. and always voted according to their free will. Shri Vajpayee should enquire into this matter and if it is found correct, the person elected to the assembly must resign, otherwise I am prepared to suffer the punishment. The manner in which Election have been held in U. P. cannot allow any Party to claim that only legitimate means have been adopted therein. I want to know the forces which want to carry the nation backwards by playing upon communalism, casteism etc. ? We have only two ways to choose from socialism and Secularism on the one hand and and casteism and communalism on the other. I am happy that the U. P. electorate has rejected the reactionary forces. I want to give a warning that the country would go to pieces if it chooses the path of casteism and communalism.

The list system which was referred here cannot succeed in a vast country like ours. Regarding criticism of use of helicopters and plans by the Prime Minister, I feel that in countries like U.S.A. and U. K. also adequate arrangements for security of Prime Minister exist under the rules.....(*Interruptions*)

विधि मंत्रालय में उप मंत्री **(Shri Nitiraj Singh Chaudhry)** : I want to know whether interruptions by Shri Phool Chand Verma is essential in the motion moved by Shri Vajpayee ?

सभापति महोदय : मेरा सदस्य महोदय से अनुरोध है कि वह इस प्रकार बाधा न डालें। उन्हें बोलने का अवसर दिया जाएगा ।

Shri Narsingh Narain Pandey : I was referring to security arrangements for Prime Minister and I may therefore clarify that she uses these modes of transport for security only.

Regarding use of radio and TV for election propaganda by the opposition, the matter was sought to be discussed by the Election Commission with them but the Jan Sangh want to have its own media for which they have gone to courts. Let us see what is the outcome thereof.

Regarding free and fair elections, we are also all for it, but the opposition cannot evade its own responsibility to ensure that. It is hardly fair to raise a hae and cry after tasting defeat at the hustings.

I, therefore, feel that this resolution should be withdrawn as its spirit is already contained in the existing Act.

श्री पी० के० देव : (कालाहांडी) : लोकतंत्र के तीन स्तंभों में से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सब से महत्वपूर्ण है ।

उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के हाल के चुनावों में कुछ चौंका देने वाली घटनाओं का पता चला है । हेलीकाप्टर का प्रयोग न केवल प्रधानमंत्री द्वारा किया गया बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री और कांग्रेसी नेताओं ने भी किया है । इसके साथ-साथ रेडियो और टेलीविज़न जैसे संचार साधनों का भी सत्तारूढ़ दल द्वारा अपने प्रचार के लिए बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हुआ है यद्यपि हमने यहां अनेक वार इन साधनों के निगम बनाने का अनुरोध किया है ।

इन चुनावों में धन की शक्ति का भी खुल कर दुरूपयोग हुआ है । हरियाणा और राजस्थान से असंख्य जीपें उड़ीसा भेजी गईं और पूछने पर पता चला कि पुलिस तथा अन्य विभागों की इन जीपों के नम्वर बदल दिए गए हैं.....(**व्यवधान**)

श्री के० नारायणराव (बोविली) : यह बहुत गंभीर आरोप हैं और यदि वह इसे सिद्ध नहीं कर सकते तो ये आरोप न लगाएं ।

श्री पी० के० देव : मैं इसे सिद्ध कर सकता हूं । इसके अतिरिक्त स्वतंत्र दल के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस द्वारा किराए पर रखे गए गुंडों द्वारा बड़े पैमाने पर डराने धमकाने, बंदूकों लाठियों और बमों के प्रयोग की घटनाएं हुई हैं। इन गुंडों ने उक्त कार्यकर्त्ताओं की जीपें, घर और सम्पत्ति को क्षति पहुंचाई । इन घटनाओं की सूचना उड़ीसा के राज्यपाल को दी गई है विशेषकर लौइसिंगा, बोलाँगी नवापाड़ा, केसिंगा और बौध निर्वाचन-क्षेत्रों के बारे में । सभा के एक सदस्य श्री आर० एस० सिंह देव इन गुंडों के हाथों घायल हो कर अस्पताल में पड़े हुए हैं।.....(**व्यवधान**) स्वयं प्रधानमंत्री ने राज्य में धमकी दी थी कि कांग्रेस को सत्तारूढ़ न करने पर राज्य को केन्द्रीय सहायता से वंचित रखा जाएगा ।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सदस्य महोदय केवल संकल्प के बारे में ही बोल सकते हैं न कि सभी प्रकार के आरोपों का उल्लेख भी कर सकते हैं चाहे उनका विचारार्थ विषय से कोई सम्बन्ध हो या न हो ?

सभापति महोदय : आशा है वह इस की भावना का आदर करेंगे ।

श्री पी० के० देव : मैं श्री वाजपेयी के संकल्प का पूरा-पूरा समर्थन करता हूं । मेरे कुछ सुझाव ह । उड़ीसा में चुनाव की तारीख दो दिन आगे बढ़ाना गैर-कानूनी है । कांग्रेसी सदस्य के कहने पर चुनाव अधिकारी का बदला जाना भी अनुचित है और चुनाव आयोग को इसे नोट करके कार्यवाही करनी चाहिए ।

दोहरे और जाली मतपत्रों का प्रयोग करके चुनावों में भ्रष्टाचार किया गया है । यदि इसी तरह के भ्रष्टाचार चलते रहे तो जनता के पास या तो गुजरात का तरीका या हिंसात्मक विद्रोह का तरीका ही रह जाता है । मेरा यह भी सुझाव है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व का भी उपबन्ध किया जाए ताकि जनता की सही इच्छा प्रतिबिम्बित हो सके ।

मैं चुनाव अनुदानों के सुझाव का भी समर्थन करता हूं । रेडियो प्रसारणों में सभी दलों को समय देने की वांचू समिति की सिफारिश भी मानी जानी चाहिए । मतदान-आयु भी घटा कर 18 वर्ष की जानी चाहिए । विमानों हैलीकाप्टरों आदि के प्रयोग पर रोक लगाई जाए और मतों की गणना बूथवार और मतदान समाप्त होते ही आरम्भ होना चाहिए जैसा कि ब्रिटेन में होता है ।

अन्त में मैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का उच्चस्तरीय आयोग गठित करने का अनुरोध करता हूं जो उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के चुनावों की जांच करे ।

श्री बी० आर० शुक्ल (बारायच) : मैं श्री बाजपेयी के संकल्प का आंशिक समर्थन करता हूं । 1971 और 1972 और 1974 के चुनावों ने सिद्ध कर दिया है कि मतदाता धन और आन-बान से प्रभावित न हो कर नीतियों के बल पर अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं ।

जहां तक सरकारी तंत्र के दुरुपयोग की बात है, यह आरोप निराधार सिद्ध हो जाता है जब हम ने देखा है कि अनेक मंत्री चुनावों में धराशाही हुए हैं ।

जहां तक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को चुनाव अनुदान देने की बात है मैं इसका समर्थन नहीं करता क्योंकि निदलीय सदस्यों की कोई पूछ नहीं चाहे वे श्री कूजड़ या कृष्ण मेनन जैसे सदस्य ही क्यों न हों, और यदि यह उपबन्ध कर दिया जाए तो उनके प्रति यह भेदभाव होगा । फिर, यह धन मिलने पर दलों के सर्वेसर्वा कुछ सदस्यों को जो उनके चहीते हों अधिक धन दे दें और कुछ को जिन से वे नाराज हों थोड़ा धन दें और उनके चुनाव असफल कर दें। साथ ही गैर-मान्यता प्राप्त दलों के साथ भी यह अन्याय ही होगा । फिर वर्तमान आर्थिक स्थिति में भी यह अनावश्यक बोझ ही होगा ।

मैं चाहूंगा कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को समान रेडियो समय देने सम्बन्धी संयुक्त समिति का सुझाव माना जाना चाहिए ।

मैं चुनाव आयोग को बहु-सदस्यीय बनाने के सुझाव का समर्थन नहीं कर सकता क्योंकि बहुदा यह आयोग निष्पक्ष ही रहा है ।

मतदान-आयु घटा कर 18 वर्ष करने का सुझाव की अवांछनीय है क्योंकि इस आयु के लोग बहुत भावुक होते हैं ।

सूची व्यवस्था से भी सभी पार्टियों को प्रभुत्व का अनाधिकार मिल जाएगा जो ठीक नहीं है।

मैं बूथ-वार मतगणना के सुझाव का समर्थन करता हूं क्योंकि इससे दलों को प्रत्येक स्थान पर अपनी शक्ति दुर्बलता का पता लग जाता है ।

इन शब्दों के साथ मैं श्री वाजपेयी को अपना संकल्प वापस लेने का अनुरोध करता हूं यद्यपि मह उनके आभारी हैं कि उन्होंने इतने महत्वपूर्ण विषय की ओर सभा का ध्यान खींचा है ।

Shri Mool Chand Daga (Pali) : Sir, I cannot agree with my preceding Speaker because today a Youth of 18 years enjoys all the privileges available to an adult therefore, he cannot and should not be denied the right to vote. We have to concede that today because of costly elections, an honest man having modest means at his command cannot dream of entering public life simply because of prohibitive expenditure of elections. Therefore elections have to be made less costly and therefore we have find ways and means to ensure that every candidate has equal resources at his disposal.

We have to raise our voice against exploitation in the name of religion and casteism.

I take this opportunity to urge upon Government to implement the recommendations of the Joint Committee, the report of which is already with the Election Commission.

श्री सी० एच० मुहम्मद कोया (मंजेरी) : अब समय आ गया है कि देश की चुनाव प्रणाली बदलने पर विचार किया जाये क्योंकि यह प्रणाली ब्रिटिश तर्ज की है जो जनता की इच्छा का सच्चा प्रतिनिधित्व नहीं करती । उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 29 या 30 प्रतिशत मत ले कर भी बहुमत ले गई है अतः उन्हें जनता का सच्चा प्रतिनिधित्व नहीं कहा जा सकता ।

मैंने स्वयं उत्तर प्रदेश में देखा है कि गत चुनावों में काफी काला धन प्रयुक्त हुआ है और यह धन बड़े-बड़े व्यापारियों और उद्योगों से सरकारी प्रभाव द्वारा प्राप्त किया गया है ।

मेरा सुझाव है कि चुनाव से पूर्व सरकारें भंग कर दी जायें और सभी पार्टियां एक ही स्तर पर चुनाव लड़ें । साथ ही यह भी व्यवस्था की जानी चाहिये कि सरकारी अधिकारियों के स्थान पर चुनाव आयोग अपने अधिकारी निर्वाचन अधिकारी के तौर पर नियुक्त करे क्योंकि सरकारी अधिकारी सत्तारूढ़ दल के लिये ही कार्य करते हैं जैसा कि कुछ स्थानों पर हुई घटनाओं से स्पष्ट है। सहारनपुर में एक प्रत्याशी 400 मतों से आगे था जब बिजली चली गई । बिजली आने पर कांग्रेस का प्रत्याशी 300 मतों से जीत गया और उसे आकाशवाणी ने 1700 मतों से जीता हुआ बताया । पीलू मोदी की तरह हम भी फाड़े गये मतपत्र पेश कर सकते हैं ।

[श्री वसंत साठे पीठासीन हुए]

[SHRI VASANT SETHI *in the Chair*]

राय बरेली में तो चार बार मतगणना हुई और हर बार प्रणाम भिन्न रहा अन्त में कांग्रेसी उम्मीदवार को 32 वोटों से जीता हुआ घोषित किया गया जबकि मोरादाबाद में हारने वाले प्रत्याशी के पुनः मतगणना के अनुरोध को नहीं माना गया ।

चनाव पूर्णतया निर्बाध और निष्पक्ष ढंग से कराये जायें और इसके लिये मेरी बातों पर ध्यान दिया जाये ।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : There are certain good points in the resolution moved by Shri Vajpayee. The expenditure on elections should be reduced. Official machinery should not be misused for this purpose.

There are certain parties which fought elections on the basis of religion. The people are now sufficiently awakened.

A ban should be imposed on fighting elections on communal basis. No party should be formed on communal basis.

There have been cases of atrocities on Harijans. It should be condemned by all parties.

Persons, having attained the age of 18 should have the right to vote. It will have healthy effect on the minds of our young people.

Facilities for fighting elections should be provided to all, as recommended by Wanchoo Committee.

Election expenses should certainly be reduced.

Shri Nawal Kishore Sharma (Dausa): I rise to support the Resolution partially. I welcome the feelings expressed in the present resolution. No one can deny the fact that elections in our country have become more and more expensive. Candidates belonging to ruling party as well as opposition spend more than their prescribed limit on elections.

Election expenditure should be reduced. Wanchoo Committee has given a praiseworthy suggestion in this regard. It will be really good if the recognised political parties are given money to fight elections. The Government should implement this suggestion.

There cannot be two opinions in this regard that our elections should be free and fair. Official machinery should not be allowed to be misused in the elections.

The official machinery should act impartially. by and large, our official machinery is impartial. But there may be a few. instances of ireegularities. Officerss in involved in such malpractices should be strictly dealt with.

Every person should be allowed to vote. In certain villages majority communities do not allow minorities to exercise their votes. It is a very dangerous practice. This matter- sheould be taken seriously. Every voter should have the opportunity to exercise his vote accoirding to his free will. Revolutionary changes should be effected in our election laws.

The counting of votes should be booth-wise. Voting age should be reduced to 18. When a person having attained the age of 18 is considered a major, he should be given the right to vote also.

श्री सुरेन्द्र महन्ती (केन्द्रपाड़ा) : यह सच है कि केन्द्रीय स्तर पर निर्वाचन आयोग के सदस्य सहज निष्ठा वाले होते हैं परन्तु राज्य स्तर पर इस व्यवस्था ने जिस प्रकार कार्य किया है उससे यह अनुभव होता है कि उक्त स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव केवल मात्र आडम्बर और धोखा ही रह गये हैं।

उड़ीसा सत्ताधारी दल के अनेक सदस्यों द्वारा यह कहना उचित प्रतीत नहीं होता कि हम उड़ीसा में पराजित हो गये थे, इसलिये हम आज हेराफेरी के आरोप लगाकर अपने मन को सांत्वना दे रहे हैं ।

उड़ीसा में गत चुनावों में बड़े पैमाने पर हेराफेरी हुई है । वहां भी बंगाल की भांति सशस्त्र गुण्डों ने मतदान केंद्रों पर कब्जा कर लिया था ।

मतगणना की प्रक्रिया अनुचित है । मैं इस प्रस्ताव का पूर्ण समर्थन करता हूं कि मतों की गणना मतदान केंद्र-वार की जानी चाहिये । पहले भी यही प्रथा लेकिन इसे अचानक समाप्त कर दिया गया और चुनाव आयोग ने मतपत्रों को एक जगह एकत्र करना आरम्भ कर दिया, जिससे इस प्रकार की गड़बड़ी करना आसान हो गया है । वर्तमान मतगणना प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिये ।

प्रधान मन्त्री द्वारा चुनावों में हेलीकाप्टरों का प्रयोग किया जाना आपत्तिजनक है ।

मुझे खेद है कि रक्षा मंत्री ने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया है । यदि निर्वाचनों में सेना के हैलीकाप्टरों तथा अन्य वाहनों का उपयोग होता है तो हमारे लोगों को कुछ उम्मीद नहीं हो सकती । इस लिये संसद एवं राज्य विधान सभाओं में ताले लगा दिये जाये । इस प्रकार की संसदीय प्रणाली हमारी समस्याओं को हल नहीं कर सकती । मैं श्री वाजपेयी की इस मांग का समर्थन करता हूं कि वांचू समिति की सिफारिशों के अनुरूप संगठित राजनीतिक दलों को निर्वाचन अनुदान दिये जायें ।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तपुजा) : मुझे खेद है कि मैं इस संकल्प का समर्थन नहीं कर सकता । इसके एक भाग में यह स्वीकार किया गया है कि भारत में निर्वाचन निष्पक्ष रूप से एवं न्यायपूर्ण नहीं होते । इसके उपचारी उपायों द्वारा निर्वाचनों को मुक्त और निष्पक्ष बनाना है । मेरा तर्क है कि यह दोनों बातें गलत हैं ।

मैं समझता हूं कि यह मुक्ति एवं निष्पक्षता मतदाताओं के लिए है । अर्थात् मतदाताओं को जिसे वे चाहें मत देने की स्वतन्त्रता होनी चाहिये । मतदान गुप्त रहना चाहिये ।

देश में कई बार कांग्रेस हारी भी है । कई बार नदी कर तरह धन बहाने वाले व्यक्तियों को हारते हुए देखा गया है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे देश में प्रजातन्त्र वास्तविक है ।

उप खंड (चार) में कहा गया है कि मतगणना केंद्र वार की जानी चाहिये । परन्तु विचार का विषय यह है कि वर्तमान व्यवस्था क्यों रखी गयी है । केवल निर्बल वर्ग की सुरक्षा के लिये । इसके द्वारा व्यक्ति, की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो जाती है । प्रस्तुत प्रस्ताव की व्यवस्था छोटे वर्ग के विरुद्ध जाती है ।

मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को निर्वाचन उपदान देने से समस्या का हल कैसे होगा ? यह भली प्रकार विदित है कि व्यय स्वीकृत व्यय सीमा से बहुत अधिक किये जाते हैं । यदि सरकारी अनुदान दिये जाते हैं तो यह कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है कि और धन नहीं लगाया जायेगा । कोई उम्मीदवार यह आश्वासन नहीं दे सकता कि एक निश्चित राशि से अधिक राशि निर्वाचन पर नहीं लगायी जायेगी । चुनाव अभियान में उम्मीदवार की जानकारी के बिना भी धन का व्यय तो होगा ही । निर्वाचनों में धर्म के आधार पर धर्माधिकारियों द्वारा मतदाताओं की स्वतंत्रता का अपहरण किया जाता है । समस्या धन की न होकर सभी प्रकार के बाह्य आक्षेपों के रोके जाने की है ।

Shri Amarnath Vidyalankar (Chandigarh) : Oppose this Resolutio Shri Vajpayee's party had electoral alliance with Muslim League. They have last the U. P. elections and advance

false reasons for their defeat. Even the other political parties have fought elections in the name of religion. Whatever laws you may enact, your cannot put on an end to religious and racial influence being exercised during the elections. Even in sports there is an understanding among the participant parties to follow certain rules. All of them adhere to the rules. Our political game should also be played in a sports man's spirit.

It is not a fact the Ministers get advantage of the official machinery.

It is not correct to say that all the malpractices in the previous elections were done by the Congress. So long as the opposition parties are themselves engaged in mal-practices there is no use asking the ruling party not do so.

The use of money was first done by Swatantra and all the mere by Jan Sangh.

Shri Madhu Limaye (Banke) : There is nothing in Shri Vajpayee's Resolution that the ruling party should be so much annoyed. If you want to protect the dignity of democracy this resolution should be accepted. The position today is that the voters have no check on legislatures and the legislatures have no check on the Ministries. The democracy today is facing this trouble and a change in the entire process is the need of the hour.

By getting 32% votes they command such a vast majority in the legislatures. In order to do justice towards the people the principle of some sent of peparation proportic nate representation would have to be adopted. If the Government is not prepared to accept it the voters be given the right to give their second preference. Then only item be seen how easy the Congress parties sticks to power.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : श्री बाजपेयी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में बहुत सी बातें हैं ।

परन्तु श्री बाजपेयी ने अपने भाषण में मतदान की आयु के बारे में कुछ नहीं कहा है ।

सर्वप्रथम उन्होंने मान्यता प्राप्त दलों को निर्वाचन अनुदान की बात रखी है जैसा कि वांचू समिति की सिफारिशों में निहित है । जापान और पश्चिम जर्मनी का उल्लेख इस सम्बन्ध में किया गया है । वे देश धनी है तथा वहां पर थोड़ी सी राजनीतिक पार्टियां हैं ।

हमारे देश में लोक सभा के लिये 35000 रुपये तथा राज्य सविधान सभाओं के लिये 12000 रुपये निर्धारित हैं । श्री वाजपेयी की गणना के हिसाब से केवल लोक सभा के लिये व्यय 5 करोड़ रुपये बैठता है । जबकि वास्तव में यह 8 करोड़ 27 लाख बैठता है । राज्य सभा के बारे में भी उनका हिसाब ठीक नहीं है । यह व्यय 18 करोड़ 56 लाख रुपये बैठता है ।

सभा को विदित है कि निर्वाचन नियमों के लिये जो संयुक्त समिति गठित हुई थी उसने कुछ सिफारिशें निर्वाचन व्ययों को कम करने के लिये की थी । इस बारे में सरकार ने पहले ही एक विधेयक रख दिया है । श्री वाजपेयी ने रेडियो का समान समय दिये जाने की बात कही थी । इस बारे में मुख्य निर्वाचन आयोग ने एक फारमूला 1962 में तैयार किया था । एक संशोधित फारमूला भी तैयार हुआ परन्तु विरोधी दलों में मतैक्य के अभाव में उसे क्रियान्वित नहीं किया जा सका ।

1967 में भी एक फारमूला तैयार किया गया और 1971 के निर्वाचनों से पूर्व भी रेडियो प्रसारणों के लिये नियम बनाये गये परन्तु राजनीतिक दलों में मतैक्य के अभाव में उन्हें फिर क्रियान्वित नहीं किया जा सका ।

फिर यह सुझाव दिया गया कि 300 मिनट के समय को राजनीतिक दलों में उनकी लोक सभा में सीटों एवं उनके द्वारा लड़े जा रहे निर्वाचनों के अनुसार बांट दिया जाये ।

प्रसारणों के सम्बन्ध में ब्रिटेन से आंकड़े उपलब्ध किये गये हैं । वहां पर भी रेडियो और टेलीविजन द्वारा दलों की स्थिति एवं उनके द्वारा लड़े जा रहे चुनावों के आधार पर समय दिया जाता है ।

यह कहा गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त केवल विधि सचिव को ही नियुक्त किया जाता है । हमारे चौथे मुख्य निर्वाचन आयुक्त इस समय विश्व न्यायालय में न्ययाधीश है ।

संयुक्त निर्वाचन समिति ने क्षेत्रीय निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की सिफारिश की है । हमने इस पर विचार किया है कि यदि बहुत से आयुक्त भिन्न-भिन्न स्थानों पर नियुक्त किये जाते हैं तो आवश्यकता पड़ने पर उनसे राय नहीं मांगी जा सकेगी ।

लिरूप पद्धति केवल कुछ ही देशों में लागू है जिनके मतदाताओं की सूची 70000-80000 है । इन बातों को ध्यान में रखते हुए अभी इसे अपनाना सम्भव नहीं है ।

जिन लोगों ने कहा है कि सरकार अल्प मतों का प्रतिनिधित्व करती है स्वयं यहां पर अल्प मत लेकर चुनकर आये हैं ।

यहां तक सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग किये जाने का प्रश्न है । इसकी पहले से ही व्यवस्था है । समिति ने सुझाव दिया है कि इसे विधि में संशोधन द्वारा न करके परम्पराओं द्वारा किया जाये ।

रक्षा मंत्रालय के हैलीकाप्टर तथा विमान प्रधान मंत्री को अपने पद के कारण मिलते हैं कांग्रेस के नेता होने के कारण नहीं ।

इस प्रकार यह कहना कि सरकारी मशीनरी का उपयोग किया जाता है बिल्कुल गलत है ।

मतों की गणना के बारे में संयुक्त समिति ने ध्यान दिया है । समिति ने कोई ऐसी सिफारिश नहीं की है ।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्य से अपने प्रस्ताव को वापस लेने को कहता हूं ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : The statement of the hon. Minister has surprised me. The Joint Select Committee had recommended that an Expert Committee should be constituted to look into the feasibility of list system. But this Committee has not yet been constituted The hon. Minister now states that the list system has no utility for the country. Does this mean that the recommendation of the Select Committee has been thrown in the waste paper basket.

Regarding the All India Radio, is it not correct that the ruling party rejected the suggestion of Election Commissioner. The Congress Party has stated that they are opposed to any such formula which gives other parties the as much time for Radios Broadcasting as has been given to them. The political parties have not been consulted before the election. The ruling party has been utilizing the All India Radio for its own ends.

The Wanchoo Committee had suggested that political parties should be given funds from exchequer during the elections. But it has been rejected on the plea that it will be too expensive.

Allocating Rs. 8 crores for Lok Sabha elections and Rs. 10 crores for State legislatures elections is not too heavy. The country should be prepared to bear this expenditure to save democracy.

It has surprised me that the hon. Minister does not agree with the suggestion that the Election Commission should have more than one member. He agrees that the responsibilities of the Election Commission have increased. Regarding the election of the Chief Election Commissioner, we should adopt a flawless system we can appoint a retimed judge of Supreme Court as Chief Election Commissioner. And such person should not be allowed to seek any job after retirement. If there are more than one member in the Commission then their decision can be more justifiable.

It pains me that the Congress members have not understood the motive of the proposed system. We are concerned only with the alternation of the present system of the election. Any party can be benefitted by this. Today the system of the election is such that unfair means are adopted in the election. If the system is changed then all political parties will get chance to behave properly. Some hon. Member were as lavelling mischievous charges on Bhartiya Jan Sangh. I am prepared to resign if such charges are proved.

I have not brought forward this resolution with any political end. We want that the election should be free and fair. We want to same democracy. Democracy cannot run unless elections are conducted in free and impartial manner. I request that my resolution may be accepted.

समापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1 और 3 मतदान के लिए।

रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

Amendment Nos. 1 and 3 were put and negatived.

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : I want to withdrawn my amendment.

संशोधन संख्या 4 सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

Amendment No. 4 was, by leave withdrawn.

सभापति महोदय :—क्या आप अपना संकल्प वापिस ले रहे हैं ?

श्री अटलबिहारी बाजपेयी : जी नहीं, ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि

"यह सभा चुनावों में धन शक्ति के बढ़ते हुए प्रभाव और शासकीय साधनों के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त करती है और स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने हेतु सरकार को निदेश देती है कि :—

(एक) मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को, वांचू समिति की सिफारिश के अनुसार चुनाव अनुदान दिये जायें।

(दो) मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए समान रेडियो समय देने, निर्वाचन आयोग को बहु-सदस्यीय निकाय बनाने, मतदान आयु को कम करके 18 वर्ष करने और सूची पद्धति को अपनाने की संभाव्यता पर उच्च शक्ति प्राप्त समिति द्वारा जांच कराये जाने के बारे में निर्वाचन विधि में संशोधनों सम्बन्धी संयुक्त समिति की सिफारिशें क्रियान्वित की जायें ;

(तीन) मंत्रियों के लिए शासकीय सुविधाओं जैसे वायुयानों, हेलीकाप्टरों, वाहनों आदि का प्रयोग तब तक वंजित रहे जब तक कि अन्य मान्यता-प्राप्त राजनीतिक दलों को भी समता के आधार पर ये सुविधायें उपलब्ध न हों; और

(चार) मत गणना मतदान-भण्डपवार की जाये।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The Motion was not granted

मूल्यों तथा कृषि उत्पादन संबंधी नीति के बारे में संकल्प

Resolution re Policy in respect of Prices and Agricultural Production

सभापति महोदय : अब हम दूसरा प्रस्ताव लेते हैं; श्री मधु लिमये ।

श्री मधु लिमये (बाका) I moye :--

"कि इस सभा कि राय है कि सरकार को मूल्यों के सम्बन्ध में अपनी नीति को इस प्रकार से पुर्नानिर्धारित करना चाहिए कि :--

(क) आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएं उत्पादन लागत, जिसमें परिवहन प्रभार, कर तथा लाभ शामिल हैं, से 1/2 गुणा मूल्य पर बेची जायें ;

(ख) औद्योगिक माल तथा कृषि उत्पाद के मूल्यों के बीच समानता हो ;

(ग) खाद्यान्नों के मूल्यों में 15 प्रतिशत से अधिक उतार चढ़ाव न हो ;

(घ) सरकार उत्पादन लागत तथा किसानों के लिए उचित लाभ को ध्यान में रख कर कपास, गन्ना, कच्चा पटसन, खाद्यान्नों तथा अन्य उत्पादों को समर्थित मूल्यों पर खरीदने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लें ;

(ङ) कृषि प्रयोजनों के लिए बिजली की प्रति यूनिट दर 10 पैसे से अधिक न हो, और

(च) 10 एकड़ से कम जोतों वाले किसानों को राज सहायता प्राप्त दर पर उर्वरक उपलब्ध कराया जाये और सिंचाई की दरों में 25 प्रतिशत की कमी की जाये।"

मतदान आयु कम करने के लिए संविधान में संशोधन

Amendment of Constitution in arder to Lower the Voting Age

सभापति महोदय : अब हम आधे घंटे की चर्चा उठायेंगे । श्री सी० के० चन्द्रप्पन

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लिचेरी) : एक प्रश्न के उत्तर में कि क्या मतदान आयु कम करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, मंत्री महोदय ने "हां" में उत्तर दिया था और अब इसी विषय पर आधे घंटे की चर्चा में भी मंत्री महोदय ने वही उत्तर दिया है, वर्ष 1971 के चुनावों में सरकार ने यह वचन दिया था कि मतदान की आयु कम करके 18 वर्ष तक कर दी जाएगी । सरकार ने भारी बहुमत के मिलने के बाद भी इस दिशा में कुछ नहीं किया ।

सरकार ने श्री वाजपेयी के तर्क को काटने के लिए चुनाव आयोग संबंधी संशोधनों पर संयुक्त समिति की एक सिफारिश का उल्लेख किया था । परन्तु उसी समिति ने मतदान की आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष करने की सिफारिश भी की थी । मैं जानना चाहताहूं कि क्या सरकार उस समिति की सिफारिश स्वीकार करेगी । इसके अतिरिक्त चौथी लोक सभा की याचिका समिति ने भी मतदान की आयु 18 वर्ष करने की स्वीकृति की थी ।

श्री वाजपेयी के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अनेक सदस्यों ने यह आशंका प्रकट की थी कि मतदान की आयु 18 वर्ष करने से विद्यार्थियों के अध्ययन में व्यवधान पड़ेगा और इसका परिणाम अच्छा

---

*आधे घंटे की चर्चा ।

*Half-an-hour Discussion

नहीं होगा परन्तु मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि ऐसे विद्यार्थियों का प्रतिशत ही कितना है। आज अधिकांश व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र तक स्कूल नहीं जा पाते हैं, इसलिए इसका भय नहीं होना चाहिए। प्रश्न यह है कि क्या आप उन वास्तविकताओं को स्वीकार करते हैं जिन्हें काफी सीमा तक सभी देशों ने स्वीकारा है, यह वास्तविकता है कि आज का युवा वर्ग हर कार्य में साझी बनना चाहता है, आपको यह वास्तविकता स्वीकार करनी होगी कि आज का युवा वर्ग अपेक्षाकृत अधिक जागरूक, शिक्षित और अपने अधिकारों के प्रति अधिक सचेत है, ब्रिटेन, अमेरिका, बंगलादेश, श्रीलंका में मतदान की आयु 18 वर्ष है।

मैं इस संबंध में मंत्री महोदय से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं। यदि वे अस्पष्ट उत्तर देते हैं तो उनका यह कार्य युवा वर्ग के साथ विश्वासघात करना होगा। मैं उन्हें चेतावनी देना चाहता हूं कि ऐसा होने पर देश का युवा वर्ग सरकार के विरुद्ध एकजुट होकर संघर्ष में कूद पड़ेगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार को स्पष्ट उत्तर देना चाहिए।

Shri Mool Chand Daga (Pali) : It would be better if the Government accept the recommendations of Joint Committee. Otherwise the Youth would get the demands conceded by the Government by force. If you deny their rights then the whole world would get the chance to say that this Government is flouting the genuine demand of the the Youths. It would be better if you accept the recommendations of Joint Committee.

Mr. Chairman : I also want a clarification from the hon. Minister. Legally if a person become father at the age of eighteen years then why he cannot have a right to vote.

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Nitiraj Singh Chaudhary) : Firstly, I want to remove misunderstanding of the mover. He has stated that if decision is taken after the delimitation of constituencies then there is a possibility of rigging in the election of 1976. But I want to say that delimitation depends not on the number of voters but it depends on the population. Only the question will come who will be the voters. For this the joint Committee has made an arrangement. Now Ist January, Ist April, Ist July and Ist September of the year will be qualifying dates on which basis the voters list will be changed. The ensuing elections will be held on that basis. Therefore there is no need of casting any doubts over this.

Regarding the question of taking decision over this matter the situation has not changed since my reply in 1972 during half an-hour discussion. There are certain difficulties and without solving them it is not proper to take any decision. It is true that in certain countries like Bangla Desh, Ceylon, U.S.A. U.K. the voting age is 18 years. We are also looking into this matter. But there are certain difficulties which read need attention.

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मेरा सीधा प्रश्न है कि क्या वे वर्ष 1976 से पूर्व निर्णय लें लेंगे ?

श्री नीति राज सिंह चौधरी : सरकार इस मामले पर विचार कर रही है और कठिनाइयों के हल होने पर निर्णय ले लिया जायेगा।

इसके पश्चात् लोकसभा सोमवार 18 मार्च, 1974/27 फाल्गुन, 1895 (शक) तक के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha *then adjourned till* Eleven of the clock on *Monday, March* 18, 1974/*Phalgun* 27, 1895 (Saka).

M162LSS/74—GIPF.

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]